Six Series Vol. IV No. 26

Monday, July 11, 1977
Asadha 20, 1899 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Series)

Vol. IV

[July 05 to 15, 1977/ Asadha 14 to 24, 1899 (Saka)]

Second Session, 1977/1899 (Saka)

(Vol. IV contains Nos. 21 to 30)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

CONTENTS

(Sixth Series, Volume IV, Second Session 1977)

No. 11, *Monday, July* 11, 1977/*Asadha* 20, 1899 (*Saka*)

	COLUMNS
Member Sworn	1
Oral Answers to Questions :	
*Starred Questions No. 405 to 407, 409 and 410	1—30
Short Notice Question No. 15	30—39
Written Answers to Questions :	
Starred Questions No. 408 and 411 to 424	39—60
Unstarred Questions No. 3013 to 3047, 3049 to 3077, 3079 to 3089, 3091 and 3093 to 3146	60—197
Papers laid on the Table	197—99
Question of Privilege against Shri Kishore J. Tanna of Jamna Dass Madhavji and Company, Bombay—	199—201
Demands for Grants, 1977-78—	
Ministry of Industry—	201—230
Shri George Fernandes	202—28
Ministry of Labour—	229—362
Shri Vasant Sathe	231—42
Shri Ram Dhari Shastri	250—61
Shri Ugrasen	261—70
Shrimati Ahilya P. Rangnekar	270—80
Shri G. Narsimha Reddy	280—84
Shrimati Chandravati	284—89
Shri P. Thiagarajan	290—92
Shri Y. P. Shastri	293—306

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

	COLUMNS
Shri Vayalar Ravi	306—14
Prof. Shibban Lal Saksena	314—20
Shri Ahsan Jafri	321—28
Shri Manohar Lal	328—35
Shri K. A. Rajan	336—41
Shri Chitta Basu	341—45
Shri Ram Awadhesh Singh	346—51
Shri K. Ramamurthy	351—55
Shri Harikesh Bahadur	355—59
Shri N. Sreekantan Nair	359—62

LOK SABHA

Monday, July 11, 1977/Asadha 20, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MEMBER SWORN

SHRI NIRANJAN PRASAD KESHARWANI (Bilaspur)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राजस्थान के रेगिस्तान की रोकथाम के लिए विदेशी सहायता

405. **श्री लालजी भाई :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बढ़ते हुए रेगिस्तान की रोकथाम संबंधी योजना को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्र संघ से या अन्य देशों से कोई सहायता उपलब्ध कराई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लालजी भाई : अध्यक्ष जी, राजस्थान में बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ? मैं नहीं कहता कि इस के लिए कोई विदेशी सहायता ली जाये न ली जाय, लेकिन क्या सरकार इस रेगिस्तान को रोकने के लिए कोई योजना बनाने जा रही है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इसमें कई योजनाएं हैं । एक तो राजस्थान के 9 जिलों में ड्राट प्रोन प्रोग्राम चलाया जा रहा है । उसमें 17 लाख रुपया चौथी योजना में खर्च किया गया फिर 14 करोड़, 47 लाख रूपये खर्च किये गये, 39 करोड़, 90 लाख रुपये और खर्च किये जाने की आशा है ।

श्री लालजी भाई : उपाध्यक्ष जी, यह जानकारी दी गई कि तनी इतनी राशि योजनाओं पर खर्च की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार राष्ट्र संघ या विदेशी एजेंसियों से भी कोई सहायता मांगेगी इस कांम के लिए ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सवाल यह किया गया था —

> "seeking to control the march of desert of Rajasthan, which contemplates march of the desert in adjoining areas or adjoining States".

इसका मैंने जवाब दिया है । राजस्थान के रेगिस्तान को ठीक करने के लिए, जमीन को काश्तकारी के लायक बनाने के लिए बहुत सी स्कीमें चल रही हैं । इनमें से कुछ स्कीमें हिन्दुस्तान की सरकार और सूबे की सरकार दोनों मिल कर चला रही हैं और कुछ के लिए आई०डी०ए० से मदद ली जा रही है । इन स्कीमों में से एक केनाल

कमाण्ड एरिया डवलपमेंट प्रोजक्ट है जिसके लिए आई० डी० ए० की ओर से 83 मीलियन डालर खर्च किया जा रहा है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं जानना चाहता हूं कि सुरक्षा मंत्रालय ने जोधपुर में जो एरिड जोन डवलपमेंट स्कीम चला रखी है, और जो स्कीमें आपने चला रखी हैं जिससे डेजर्टको रोका जा सके, क्या इन स्कीमों में कोई तालमेल है या नहीं है ? जोधपुर डिविजन में बबूल उगाने की एक स्कीम चलाई गई थी जो कि महाराजा के समय से चलाई गई थी, क्या इस प्रकार का कोई विशेष कार्यक्रम सरकार के पास है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इसके लिए मुझे नोटिस देना पड़ेगा ताकि मैं इसकी जानकारी ले सकूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : संसार में एक ही देश ऐसा है जिस ने अपने यहां रेगिस्तान की समस्या का समाधान कर लिया है और वह है इजराइल। हमारे संबंध उसके साथ सीधे तो नहीं है परन्तु क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उससे इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चेष्टा की गई है, जिस तरह से उसने रेगिस्तान पर काबू पाया है और अपनी भूमि को उपजाऊ बनाया है इसका ज्ञान प्राप्त करने की सीधे या यू एन ओ के द्वारा प्रयास किया गया है, यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जैसे ताल्लुकात उनके हमारे साथ हैं उनको देखते हुए सीधा तो प्रयास नहीं हो सका है लेकिन जो ज्ञान कहीं भी होता है, किसी देश में भी होता है वह दूसरे देशों के पास आता है। जो हमारे पास आ रहा है खास कर डेजर्ट एरिया को ठीक करनें के लिए उससे फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : किस देश के द्वारा आ रहा है ?

श्री चतुर्भुज : रेगिस्तान को रोकने के लिए आपने करोड़ों अरबों खर्च किया है मैं जानना चाहता हूं कि इस खर्च से आप कितने क्षेत्र को डैजर्ट बनने से रोक सके हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बहुत से हिस्सों में काम हुआ है। नहरों के एरिया में काम हो रहा है, एफारिस्टेशन का काम हो रहा है, केचमेंट एरिया का काम हो रहा है, बहुत से जंगल नए लगाए गए हैं। इनसे पहले से डेजर्ट रोकने में मदद मिली है।

चौधरी बलबीर सिंह : सरकार की अपनी रिपोर्ट क्या है ? जहां रूका है उससे ज्यादा एरिया में बढ़ रहा है या कम में ? क्या आप कोशिश करेंगे इसको रोकने की और क्या इजराइल ने जैसे मेरे एक साथी ने कहा है भारत सरकार को इस काम में मदद देने की आफर दी थी ? क्या सरकार ने उससे मदद लेंने की कोशिश की थी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जैसे मैंने बताया है कि डेजर्ट बढ़ने के बजाय उसको ठीक करने का ज्यादा प्रयास किया जा रहा है, उसी की ज्यादा कोशिश हो रही है। जहां तक इजराइल द्वारा आफर देने का सवाल है वह जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री विनायक प्रसाद यादव : जो कल्टीवेबल लैंड है और जिस पर अभी खेती नहीं की जा रही है उस पर खेती करने के लिए सरकार के पास कोई विशेष योजना है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जिन स्कीम्ज का जिक्र किया है वे उसके नीचे हैं, ड्राउट प्रोन एरियाज हैं, केनाल कमांड एरिया डिवैलेपमेंट प्राजैक्ट्स हैं, डेजर्ट प्राजैक्ट है। ये उसी के लिये बनाई गई है।

Violation of Agreement by the Indian Crafts Society, New Delhi

*406. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) who are the office bearers of Indian Crafts Society who held exhibition at Windsor Place, New Delhi in 1975-76;

(b) what action has been taken against the Society for not paying licence fee and not furnishing the bank guarantee;

(c) what action has been taken by Government against the Society for violation of the agreement including non-furnishing the audited accounts;

(d) how much amount was collected and how much has been deposited in the P.M.'s fund; and

(e) who were the V.I.Ps. who recommended the allotment of the land to the Society?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The Society filed a list containing names of members of governing Council for 1973, with the Registrar of Societies, Delhi. List of Office-bearers for 1975-76 was not field. On the letterhead of the Society, on which it requested for allotment of land on the 16th October, 1975, the following officer-bearers were mentioned.

1. Smt. Kailash Kapoor—President.
2. Major Kapil Mohan—Vice-President.
3. Shri Radha Raman—Vice-President.
4. Shri H. N. Rathi—Secretary General.
5. Shri M. L. Goyal—Secretary.
6. Shri Sagar Suri—Secretary.
7. Shri Sudhir Sareen—Treasurer.

(b) and (c). Since the Society did not comply with the terms of allotment, the occupation of the site by the Society was unauthorised. Necessary action is being taken against the society.

(d) No amount has been deposited by the Society in P.M.'s Relief Fund. The amount collected by the Society is not known to Government.

(e) There is nothing on record to suggest anything in this direction.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: If you see the list, Shri Radha Raman is the former CEC, Shri Kapil Mohan is the Director of the Maruti, Mr. Sagar Suri is the Director of Maruti. Mrs. Kailash Kapoor might have some relation with Mr. Yashpal Kapoor. I do not know.

It is a clear case of embezzlement and misappropriation of lakhs of rupees. May I know from the hon. Minister that it being a criminal case, does he propose to file a case with the police so that action may be taken against them? Secondly, I want to know why no action was taken by the Government when there was unauthorised occupation by the society.

SHRI SIKANDAR BAKHT: The Law Ministry has been consulted. They have, of course, declared that the possession of the Society was unauthorised. Necessary action is being taken in regard to the default of the Society.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: My pointed question was whether he proposes to file a case with the police and what is the definite action that he proposes to take.

SHRI SIKANDAR BAKHT: I can tell him the definite action that we can take at the moment. According to the Act which governs the registration of Societies, no penal action

is possible. The land was given to the Society on a licence fee of Re. 1 per month which it did not deposit.

लेकिन जो रेट रेगुलर लिया जाता है एग्जिबिशन के लिये जब लैंड दी जाती है तो उसका किराया 1 रु० 88 पैसे पर स्क्वायर यार्ड प्रति महीने हैं जो उनसे रिक्वर किया जायगा। उसके अलावा और भी कंडीशन्स उन्होंने पूरी नहीं की तो 5 रु० प्रति माह के हिसाब से उनसे रुपया वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी। टोटल अमाउन्ट जो उनसे रिकवरेबिल है इन दोनों मदों में वह 2 लाख 69 हजार 184 रु० हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय ने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया ।

मेरे ख्याल से उसमें कंडीशन यह भी थी कि जो रुपया आयेगा टिक्टों के जरिये से वह पी० एम० फंड में जमा होगा। और आज तक यह नहीं आपको मालूम है कि कितना रुपया आया है, आपने नहीं बताया ।

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने बताया कि हमें नहीं मालूम ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने कहा कि आपको नहीं मालूम कि कितना रुपया आया। और उस नुमायश को खत्म हुए साल से भी ज्यादा हो गया होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ़ फंड का पैसा था उसको ऐग्रीमेंट के मुताबिक उन्होंने मिसऐप्रोप्रिएट किया, और जो अकाउन्ट देना था वह भी उन्होंने नहीं दिया। और इसके अलावा जो शर्तें थीं वह भी पूरी नहीं की। तो आपने ला मिनिस्ट्री से जो राय ली होगी वह तब ली होगी जब यह लोग प्रिवलेज्ड क्लास थे तो मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि आप ने यह जो कार्यवाही शुरू की है वह कौन सी तारीख से शुरू की ? क्या यह ठीक है कि यह सवाल जाने के बाद ही शुरू हुई, या आप के मंत्री पद सम्भालने से पहले कुछ कार्यवाही हुई थी ? और जो इस प्रकार से सोसायटियों को जमीन दी जाती है उसके क्या नियम हैं, और उन अफसरों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही हुई जिन्होंने बैंक गारन्टी न होते हुए भी उनको जमीन दे दी।

SHRI SIKANDAR BAKHT: There are so many questions which the hon. Member has put. I would like to answer one by one. Firstly, as to what were the conditions on which the land was given, there were a number of them.

मैजर कंडिशनस यह थी कि लाइसेंस फी 1 रु० महीने के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी मेजर कंडीशन वह थी कि वह अपनी बैंक गारन्टी देंगे जितना अमाउन्ट बनता है 5 रु० पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से टोटल अमाउन्ट का।

तीसरी शर्त यह है कि अपनी एग्जिबिशन खत्म होने के एक महीने के अन्दर अन्दर अकाउन्ट देंगे, वह रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जायेगा ।

वैसे छोटी-छोटी 9 कंडीशनज हैं। उनमें से उन्होंने किसी एक कंडीशन को भी पूरा नहीं किया। उनके खिलाफ कार्यवाही हर किस्म की शुरू की जा रही हैं।

यह भी मैं बता दूं कि यह तमाम लैंड 1974 में लैण्ड एण्ड डैवलपमैंट आफिसर ने डी० डी०ए०को केयर एण्ड मन्टेनेन्स के लिए दे दी थीं। इन्होंने 16 अक्तूबर, 1975 को एप्लाई किया कि यह लैंड एग्जिबिशन के लिये दे दी जाये। उनको किसी किस्म की कोई अथौरीटी डी० डी० ए० या एल० एण्ड डी० ओ० से नहीं दी गई। उन्होने जमीन पर कब्जा कर लिया, किन्तु एक चिट्ठी 11 नवम्बर, 1975 को मिनिस्ट्री की तरफ से डी० डी० ए० को गई कि इन-इन शर्तों के मातहत यह जमीन 20 अक्तूबर, 1975 से 15 जनवरी, 1976 तक इनको दे दी जाये, हमको एतराज नहीं है। एक तरह से पिछले कब्जे, के रैगुल-

राइजेशन के लिये थी। मगर यह ठीक है, कब्जा कर लेने के बाद यह हुआ। कब्जा इनका जारी रहा, और हम प्रेज्यूम करते हैं कि एग्जिबिशन इनकी 30 अप्रैल को खत्म हो गई, लेकिन एकस्टेन्शन का लैटर 7 मई को दिया गया, जो कि रैगुलराइजेशन थी।

यह जरूर अर्ज करूंगा कि जो मुखतलिफ पहलू है कि कब्जा उन्होंने किया बगैर अथौराइजेशन के और पहले अफसरों पर क्या कार्यवाही की गई, तो उन सब पर अब गौर हो रहा है।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने कहा कि उन्होंने बगैर मर्जी के कब्जा कर लिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन अफसरों ने पहले कार्यवाही नहीं की, उनके खिलाफ अब आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात यह है कि उनके खिलाफ कार्यवाही कौनसी तारीख से शुरू की गई, आपके मंत्री बनने से पहले से या आपके मंत्री बन जाने के बाद से?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं यही कह सकता हूं कि कार्यवाही की जा रही है, तारीख तो याद नहीं है कि किस तारीख से शुरू हुई है।

AN HON. MEMBER: He is evading the question.

SHRI SIKANDAR BAKHT: No, I am not evading the question. In fact, I do not know the date.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The hon. Minister has talked about Mrs. Kapoor. Would he kindly enlighten this House as to whether Mrs. Kapoor happens to be the wife of Shri Yash Pal Kapoor, a close and confidant of Mrs. Indira Gandhi the former Prime Minister of this country?

SHRI SIKANDAR BAKHT: I am trying to locate Mr. Yash Pal Kapoor and find out if she is his wife.

श्री उग्रसैन : मंत्री जी ने यह कहा है कि उन्हें यह मालूम नहीं है कि कितना रुपया उसमें से प्रधान मंत्री कोष में जमा होना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदर्शनी से कुल कितना लाभ हुआ, जिसका कि कई जगह बंटवारा होना था? कुल कितनी रकम प्रदर्शनी से प्राप्त हुई?

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने अर्ज किया कि मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उस रकम की जानकारी करने के लिये सरकारी साधन काम में लाये जा रहे हैं।

श्री उग्रसैन : उनसे हिसाब मांगा है या नहीं?

श्री सिकन्दर बख्त : हिसाब मांगा गया है, लेकिन दिया नहीं है।

श्री उग्रसैन : हिसाब दिया नहीं, तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री सिकन्दर बख्त : कार्यवाही की जा रही है।

SHRI K. SURYANARAYANA: As far as grabbing of land is concerned, I want to know whether any officer concerned has raised any objection; if so, what is the reaction of the concerned Minister who was incharge of those days?

SHRI SIKANDAR BAKHT: It was very late in the day that the DDA on the 2nd January, 1976, wrote to the society that they had not fulfilled any condition of the allotment of land and that they should do now. Even then the society did not do anything.

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि भारत सरकार का मंत्री कहे कि बिना एलाटमेंट पाये हुए कोई सरकारी जमीन पर दखल कर लेता है और कई महीने तक उस पर

काबिज रहता है, और वह भी कोई अननोन प्लेस नहीं है, बल्कि यह घटना विडसर प्लेस जैसी जगह पर हुई है, जहां मिनिस्टरों और अफ़सरों की बराबर नजर रहती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की शक्ति झुग्गी-झोंपड़ी वालों के घर उजाड़ने तक ही सीमित रहती है, और क्या ऐसे लोगों पर भी उसकी नजर जाती है या नहीं, जो जबर्दस्त समझे जाते हैं और बिना एलाटमेंट के जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। क्या उन को इस जमीन से हटाने की कोशिश की गई है या नहीं, यदि नहीं; तो क्यों नहीं?

श्री सिकन्दर बख्त : जहां तक सरकार का ताल्लुक है, यह तो एक बड़ा कान्टीन्यूअस प्रासेस है। अगर सदन मुझे हक़ दे, तो मैं कहूं कि आपका यह ख़ादिम, और यह सरकार, उस वक्त नहीं थे। पिछली सरकार की तरफ़ से जवाबदेही करना मेरे लिए मुश्किल है। मैंने आपके सामने फ़ैक्ट्स रख दिये हैं। जिन्होंने ग़लती की थी, अब उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही की जायेगी।

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: May I know, if the occupation was not authorised under rules, the society, would be deemed to be trespassers and prosecuted for criminal trespass?

SHRI SIKANDAR BAKHT: Now it is not possible to treat them as trespassers as a letter, though late, has already been issued regarding heir possession from 20th October to 30th April, 1976.

श्री रामनरेश कुशवाहा : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो उदारता इस जमीन के बारे में बरती गई है—बिना एलाटमेंट के कब्जा होने के बाद उसको रेगुलराइज कर दिया गया है और इस अनियमितता की जांच नहीं हुई है, क्या वही उदारता उन जगहों के सम्बन्ध में भी बरती जायेगी, जहां गरीबों ने कब्जा कर रखा है, और क्या झुग्गी-झोंपड़ी वालों को भी नियमित कर दिया जायेगा।

SHRI SIKANDAR BAKHT: It does not flow from this Question.

श्री यज्ञदत्त शर्मा : इस सदन में लगभग अस्सी के करीब सदस्य ऐसे हैं, जिनके पास निवास नहीं है, क्योंकि उनके लिए निश्चित मकानों पर अनधिकृत कब्जा है। क्या मंत्री महोदय उस अनधिकृत कब्जे को समाप्त करने और उन मकानों को ख़ाली कराने के बारे में दिलचस्पी लेंगे?

SHRI SIKANDAR BAKHT: It does not flow from this Question.

श्री यज्ञदत्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सवाल की आत्मा है अनधिकृत कब्जा और मेरा सवाल उसके अन्तर्गत आता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: It does not directly flow from this but the hon. Member's question has been taken note of.

Butter Oil from E.E.C./Western Countries

*407. DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large consignments of butter oil had been received by the Indian Dairy Corporation as free gift from the European Economic Community or some Western countries;

(b) if so, the names of the countries and the quantities received from each country in 1975, 1976 and 1977 together with the terms on which this was received;

(c) whether butter oil was sold first at Rs. 70 per 5 kg. by the Mother Dairy and then the price was raised to Rs. 85; and

(d) if so, the reasons for increasing the price?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) A consignment of butter oil has been received by the Indian Dairy Corporation as free gift from the European Economic Community.

(b) The supply of butter oil was received from the European Economic Community and not from individual countries in the E.E.C. From the E.E.C. in the year 1974-75, a gift supply of 2,590 tonnes of butter oil was received. Another consignment of 3,000 tonnes of butter oil is expected to be received shortly.

This has been gifted to Government of India under Food Aid Programme of E.E.C. and the sale proceeds of butter oil are to be utilised for financing dairy development projects.

(c) Yes, Sir.

(d) The price of butter oil was originally fixed at a low level to test consumer acceptance for this new product. The price was subsequently raised keeping in view the prevailing price of edible oil and ghee to ensure that there may be no cornering of stocks and other mal-practices like mixing with ghee.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Very important questions arise from the statement the hon. Minister has just now made. Point number one is this. He says that this was a free gift. May I enquire, when the European Economic Community gave us a free gift, whether this powder was tested chemically to see if it was fit for human consumption. Secondly, you say that it was shipped. Who paid for the shipping and if we did it, whether it was paid for in foreign exchange.

Thirdly, you have said that the price was kept as low as Rs. 14 per kilogram in the beginning for testing the acceptance of the consumer. That means you wanted to make it a permanent feature of the Indian human society. You want us to consume here butter-oil which is surplus and which is unfit for human consumption in Western countries. Is the Government of India acting as the Sole Selling Agents of the E.E.C. that it should test the acceptability of its products in the Indian market?

Another point is this. At the time the price was fixed at Rs. 14 per kilogram initially, there was no shortage of edible-oil in the country. Then why was such a price fixed?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: My Hon. friend has framed many questions. Firstly, he has mentioned butter-oil powder. It is not a powder. This is mixed with skimmed milk for recombination to be used as milk subsequently. We have been getting this as a gift, as mentioned earlier, under the Food Aid Programme of the EEC. It is not that we are begging for it: it is given under the aid programme given to various countries and we also get some of it. Now, a huge quantity was lying with us and it was not possible to supply it as milk because it had become unfit for being used for recombination, but it could however be used for direct consumption as cooking medium. It was only for that reason that it was sold in the market. Because it could not be recombined it does not mean that it was unfit for human consumption. It was fit for this purpose and that is why it was being sent here and that is why it was brought into the market and sold.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: The second part of my question about the price has not been answered.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: We get it free up to the port in Europe and from there we have to bring it here.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Now, is it a fact that a consignment worth crores of rupees was destroyed in a fire at the godown in Bombay and if so has any enquiry been held in this respect?

Secondly, it has been brought to the notice of various Members of Parliament through the press that sometimes spoilt butter-oil was mixed with milk and supplied to the consumers through the Delhi Milk Scheme—that is, butter-oil which was spoilt and unfit for consumption was mixed with the milk and sold.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Regarding the last part of the question, it is not a fact that it had become unfit for human consumption at the time when it was mixed with skimmed milk and supplied to the people.

So far as the first part of the question is concerned. I will require separate notice so that I may find out whether there has been any such incident or not.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि यह जो हमें फ्री गिफ्ट के तौर पर मिलता है उससे हम पैसा कमाएं और बाजार में जा कर उसको बेचें ? अगर वह गरीब बच्चों के लिए दूध बनाने के काम में आ जाय या किसी और ऐसे काम में आ जाय वह तो समझ में आता है लेकिन दूसरे मुल्कों से फ्री गिफ्ट लेकर दिल्ली मिल्क स्कीम उसमें उससे दस गुना ज्यादा पानी मिला कर उससे दूध बना कर लोगों को देता है और उससे पैसा कमाता है, क्या यह मुनासिब है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह बजर आइल जैसा मैंने अर्ज किया कुछ बच गया था वह बेचा भी गया और बाकी इसे स्किम्ड मिल्क के साथ मिला कर उसे दूध बना कर बेचा जाता है।

The amount realised from that sale is used for cattle and dairy development. It is not used for any other programme but for this very programme of improvement of cattle and the dairy through which we supply milk to the public.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: We are a great nation and a self-respecting nation. I appreciate the concern of the Government of India to import this butter-oil for the time being, but I would like to know whether the Government would like to review the entire policy of accepting gifts like this, because these gifts always have some intention behind them. As a self-respecting nation we should not accept such gifts. As is known to the hon. Members and the hon. Minister, when a great calamity, an earthquake, took over China, they refused to accept any gift from any country as a self-respecting nation? Will the Government of India like to review the entire policy of accepting free gifts from other countries?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: As far as I know, the offer for this aid was made when my hon. friend was there in the Ministry.

SHRI C. M. STEPHEN: The question is whether the Government would review the position and he must answer that.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: We are dealing with the legacy that we have inherited. For the time being, the same policy is being pursued.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I would like to know from the hon. Minister, when the butter oil was offered to our country, when and how much was received and when it was a

free gift, why it was not distributed free through the many charitable institutions in our country.

• SHRI SURJIT SINGH BARNALA: In so far as the quantity received is concerned, in 1974-75, we received from EEC 2590 metric tonnes and from WFB 8212 metric tonnes. In 1975-76 we did not receive anything from EEC, but we received 7165 metric tonnes from WFP. In 1976-77, we have received 1782 metric tonnes only from WFP. It was not sent for distribution through charitable institutions, as it was meant for augmenting the milk production in the country and that is what is being done.

श्रीमती मृणाल गोरे : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जो बटर आयल आप मंगाते हैं और जो आपकी "आपरेशन फ्लड" की स्कीम थी—इनसे दूध के धन्धे को कोई फायदा होने के बजाय दूध का धन्धा कम हो गया है, दूसरी तरफ़ कन्ज्यूमर को बास–आने वाला खराब दूध का इस्तेमाल मजबूरन करना पड़ता है ? मिल्क स्कीम को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे बटर-आयल का उपयोग क्यों करे जिससे बास आती है जब दूध में उसका इस्तेमाल होता है—इन बातों को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार इसके बारे में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इसका इस्तेमाल करने से उपज में कोई कमी नहीं हुई है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। दूध का धंधा करने वालों को कोई नुकसान हुआ हो, ऐसी बात भी नहीं है। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि जब बासी गंध आती है तब उसको मिला कर दे दिया जाता है। जब ठीक कंडीशन में होता है तभी मिलाया जाता है ।

श्री मनी राम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने जो बात कही है वह हमने सुनी नहीं है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह सुनाई नहीं दिया इसलिए कृपा करके उसको दोबारा सुनवा दें।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने हाउस के सामने अर्ज किया था कि जैसा आनरेबल मेम्बर ने फर्माया कि जब बटर आयल खराब हो जाता है, उसमें बासी सुगंध आने लगती है उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है तो यह बात गलत है और ऐसा नहीं होता है। (**व्यवधान**) घी के लिए तो मैं सुगंध ही कहूंगा, दुर्गंध नहीं कहूंगा क्योंकि घी में सुगंध ही आती है। तो जब तक उसमें सुगंध आती है उसको इस्तेमाल किया जाता है और जब दुर्गंध आने लगती है तब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तब वह काबिले इस्तेमाल ही नहीं रहता।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: We got the butter oil as a gift....

SHRI JYOTIRMOY BOSU: We are trying to catch your eye.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: .... In that case, why should you price it?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: We wanted to get money out of it for improving the dairy industry and the milch cattle.

MR. DEPUTY SPEAKER: Next question—Shri Mavalankar not here. Shri Nawab Singh Chouhan.

हिन्दी को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं

***409. श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के अधीन कितनी संस्थाएं सीधे हिन्दी को बढावा देने के लिए कार्य कर रही

हैं और उनने अध्यक्षों तथा चेयरमैनों का दर्जा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा दो ऐसी संस्थाएं हैं जो सीधे इस मंत्रालय के अधीन हैं । केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के भी अध्यक्ष हैं । वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष के पद का वेतनमान 2250–2500 रुपये है । केन्द्रीय हिन्दी सस्थान के निदेशक का वेतनमान 1500–2500 रुपये + 250 रुपये विशेष वेतन के रूप में है ।

श्री नवाब सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, 1960 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार इस आयोग की स्थापना हुई थी और उस समय कल्पना की गई थी कि इस आयोग को स्वायत्तशासी संस्था बना दिया जायेगा तथा इसके जो अध्यक्ष होंगे उनको सेक्रेटरी का दर्जा दिया जायेगा किन्तु ऐसा नहीं किया गया । इस आयोग के सदस्यों को पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाए—कुछ दिनों तक यह बात चली लेकिन बाद में वह नहीं हुआ । कभी आयोग को निदेशालय में मिलाया गया और कभी निदेशालय को उसमें मिलाया गया । मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार इस बात को सोच रही है कि इसको स्वायत्तशासी संस्था बनाया जाये और इसके अध्यक्ष को सेक्रेटरी का दर्जा दिया जाये ? यदि ऐसा नहीं सोच रही है तो और किस बात पर विचार कर रही है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने कहा है कि जो कुछ उनका पद है और जो तनख्वाह है वह उसके बराबर है । इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता ।

श्री नवाब सिंह चौहान : क्या मंत्री महोदय समझते है कि हिन्दी का काम विभिन्न मंत्रालयों में बिखरा हुआ पड़ा है और उसमें कोई सहयोग तथा समन्वय नहीं है ? हिन्दी जो सम्पर्क और राज भाषा बन गई है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए क्या मंत्री महोदय के पास ऐसी योजना है कि इस संस्था को पूर्ण स्वायत्तशासी बनाया जाये और उसके अन्तर्गत तमाम हिन्दी का काम सौंप दिया जाये और उसके अध्यक्ष को सेक्रेटरी का दर्जा दिया जाये ? मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा चल रहा है या नहीं ? यदि नहीं चल रहा है तो क्या आप ऐसा करने को तैयार है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं जांच कराऊँगा ।

DR. HENRY AUSTIN: Will the hon. Minister please let me know whether efforts are being made to promote regional languages in States where Hindi is in vogue under the three language formula. There is a feeling that adequate steps are not taken to popularise regional languages under the three language formula.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I respectfully submit that this charge is not correct because about Rs. 1 crore has been offered to the State Government for the purpose of publication of books in regional languages. Apart from that we find that there are other institutions for promoting regional languages. We have a society for promotion of modern Indian languages sponsored by the Central Government.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Is one crore of rupees for the whole country? I am seeking clarification.

MR. DEPUTY SPEAKER: You please take your seat.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I want to know....

MR. DEPUTY SPEAKER: You have already said that. He will answer.

SHRI C. N. VISVANATHAN: How many institutions are running in Tamilnadu for Hindi Prachar Shaka and how much money is being spent?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I would like notice for the details.

For the information of this House I may say that Central Hindi Directorate is running correspondence course for teaching Hindi through Tamil. Originally it was planned for 500 students. Now there are 4000 students learning Hindi through correspondence course through the medium of Tamil.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The hon. Minister said rupees one crore. Is this sum for the whole country or for a particular State? If it is for a particular State, which is that State? Rs. one crore for 600 million people for the development of regional languages is a ridiculously low amount.

MR. DEPUTY SPEAKER: He requires notice.

SHRI SAMAR GUHA: As per Constitution Hindi has a double status. It is a national language as well as an official language. All languages are national languages. I have no grouse whatever is spent for the development or promotion of Hindi as it is an accepted official language of our country. Will hon. Minister give us the break up of the figures of the expenditure for improvement and development of other national languages in our country?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I require notice for that.

SHRI SAMAR GUHA: The hon. Minister could say that he would reply later on. There is no question of giving notice. My query comes from the previous question put to him. Will you direct the hon. Minister to say that the information would be furnished later?

MR. DEPUTY SPEAKER: He will furnish it later. He himself said.

SHRI SAMAR GUHA: He said he will need notice. I asked for furnishing information. These two are different things. Information should be given, not asking for notice.

श्री हुकम चन्द कछवाय : हिन्दी पढ़ाने वाली संस्थायें इस देश में कितनी चल रही है और उनके नाम क्या है और उन पर अलग अलग कितना खर्च किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि काफी प्रयास करने के बाद भी हिन्दी के प्रति आपके कार्यालय में अफसर लोग हीन भावना दिखाते है ? क्या यह सही है जो कि हिन्दी भाषी राज्य है उन के साथ भी पत्र व्यवहार हिन्दी में न हो कर अग्रेजी में होता है ? जब इस प्रकार की भावना केन्द्र की रहेगी तो कैसे आप मानकर चलते है कि हिन्दी को देश में बढ़ावा मिलेगा ?

श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र : जैसे मैंने पहले कहा है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से दो संस्थायें चल रही है । इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी हिन्दी को बढ़ाने के लिए संस्थायें चलाती हैं । कितना रुपया खर्च होता है मैं अभी नहीं कह सकता, इसके लिए मुझे नोटिस चाहिये । राज्य सरकारों से कभी कभी हिन्दी में भी पत्र व्यवहार होता है और अग्रेजी में भी होता है । बंगलौर में मैं गया था । वहां लोगों की शिकायत थी कि कन्नड़ भाषा में नहीं होता है । इस तरह से काम कैसे चलना चाहिये आप समझ सकते है ।

SHRI K. LAKKAPPA: It is a very sensitive issue. We can't have controversy. Our friends said that equal respect should be given to all the languages, and that Government should also promote all languages equally. A sort of shift is given by the present Government. The other day Mr. Raj Narain said something. I am happy that the hon. Prime Minister rightly intervened and said about it. Any sort of imposition of any language would create sharp reaction from southern States. It is an important question. I want to know whether the hon. Minister will give attention to promote all the languages along with the national language, Hindi. Will he promote them and also spend money for promoting these regional languages? I want to know about the reaction of the government on this important issue.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Answer to this question will also cover answer to some of the points raised by Mr. Jyotirmoy Bosu: Rs. 1 crore for each regional language is paid. This is done through autonomous State Textbook Board set up in the regional language area. It is for each regional language.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: May I know whether the amount spent for development of regional languages is for translation into regional languages? What are the steps taken for propagating regional South-Indian language (Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada) in the North?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: There is the Institute for Development of Modern Indian Languages which is being supervised by the Indian Government. Apart from that help is given to each regional language for text-book writing in the regional languages.

So, that is for the promotion of text-books for the study by the students.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: Sir, my question has not been answered.

SEVERAL HON. MEMBERS: *rose*

MR. DEPUTY-SPEAKER: If four of you get up simultaneously, nobody can answer.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: Sir, my question is: what are the steps taken by Government in the Hindi region for promoting the South Indian languages?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Sir, in the three-language formula, a suggestion has been offered to the State Governments for the introduction of the South Indian languages in Hindi area. But, then, it is for the State Governments to carry out the direction.

As regards the regional languages, apart from the institutions run directly by the Central Government, there is Sahitya Academy which also encourages the regional languages by awarding prizes to the writers who have been writing in a better way in those regional languages. Moreover, prizes are also being awarded to the people writing in their mother-tongue. They have also been writing in Hindi. In this way, a lot of encouragement is being given to all the different modern languages in India.

श्री हुकम देव नारायण यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह पता है कि जो माननीय सदस्य क्षेत्रीय भाषा की प्रधानता स्थापित करने के लिये सरकार के सामने मांग रखते हैं ऐसे सदस्यों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा सरकार के पास कोई योजना है जिससे उनके हृदय में स्वयं अपनी मात् भाषा के प्रति श्रद्धा पैदा हो और इस सदन में अपनी मातृभाषा को व्यवहार करें जिस से उनकी क्षेत्रीय भाषा का विकास हो सके ? क्या ऐसी योजना सरकार के पास है कि उनके हृदय में यह भावना पैदा कर सकें ?

श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र : इस तरह का कोई प्रस्ताव मेरे पास नहीं है ।

Mechanization of Agriculture

*410. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) steps Government have taken to further mechanise agriculture.

(b) whether Government have taken concrete steps to increase the inputs in agriculture; and

(c) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Government have adopted a policy of selective mechanisation, which, without seriously affecting employment opportunities in agriculture, can help farmers to take to intensive cropping with higher yields from the same land. Most of the agricultural machinery required by farmers is being manufactured in the country. Since it is not possible for small farmers to own many such machines, agro-service centres and custom hiring centres are being set up for giving such mechines on hire. Small and marginal farmers are provided subsidy on improved implements in selected areas under the Small Farmers' Development Agency Programme, Drought Prone Areas Programme and Tribal and Hill Areas Development Programme.

(b) and (c). Important steps taken by the Government to increase the availability and consumption of major inputs, namely, seeds, fertilizers and pesticides and irrigation water, are as follows:—

SEEDS

Keeping in view the expected increase in the requirement of quality seeds for major cereal crops in the coming years, Government have evolved a national programme which seeks to integrate the various stages of seed production, from research institutions to farmers' fields, and provide necessary infrastructural facilities to cater to seed processing, storage, quality control and marketing. Under this programme, it is intended to broadbase and diversify quality seed production and also to build up a reserve stock of seeds for use during periods of inadequate availability. Programmes are also being drawn up to strengthen the facilities for production of vegetable seeds and seeds of commercial crops.

FERTILISERS

To meet the rising demand for fertilisers, the total availability is being increased by expanding the level of production in the country and arranging necessary imports. The imported fertilisers are stored in over 600 buffer points in the country. Efforts are being made to open additional retail outlets in the interior areas, which now number about one lakh, so as to make fertilisers easily available to the cultivators. The State Governments are also being encouraged to set up composite input distribution centres, so that farmers may get seeds, fertilisers and pesticides under one roof, wherever possible. An Intensive Fertiliser Promotion Campaign has been taken up in the current kharif season in 68 selected districts, where the level of fertiliser consumption is low at present, but the potential for increasing the consumption is good.

PESTICIDES

The manufacturing capacity of the pesticides industry as well as consumption of pesticides has considerably increased over the years. All plant protection materials are, by and large, easily available within the country through approximately 52000 sales points. Subsidy under various schemes is being given to small and

marginal farmers for the purchase of plant protection equipments. Financial assistance for ground and aerial spraying against pests and diseases of commercial crops is also being extended to the farmers.

IRRIGATION

Realising the important role of irrigation programmes, efforts are being made to accelerate their implementation to the maximum extent possible. The Public Sector outlays are being supplemented by institutional funds in the case of minor irrigation. For 1977-78, it is expected that an additional irrigation potential of 1.79 million hectares from minor irrigation and 1.3 million hectares from major and medium irrigation would be created.

SHRI P. K. KODIYAN: Sir, the hon. Minister has made a written Statement. From the statement, I find that Government have adopted a policy of selective mechanisation, which, without seriously affecting employment opportunities in agriculture, can help farmers to take to intensive cropping with higher yields from the same land.

Now, Sir, we find in relation to mechanisation, that it is confined to a small section of the rural peasants. So far as ordinary peasants are concerned, they are not even getting the improved implements; they are not in a better financial position. Though in the statement it has been stated that agro-service centres are being set up to cater to the requirements of the small farmers, the fact is that a number of small marginal farmers in our country are denied the benefit of these modern agricultural implements. On the other hand, the mechanisation which is confined to selective areas often leads to unemployment among the agricultural workers.

So, my question is about the two aspects of mechanisation—use of agricultural machines like the harvester combines in the State of Punjab and Haryana has often led to increase in unemployment among the rural workers. This is one aspect. The other aspect is the one to which I have referred just now, namely, the inability of the ordinary farmers, marginal farmers and other rural sections of the society, to use the improved agricultural implements.

I want to know whether Government are taking any serious steps in order to reduce the unemployment as far as possible....

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you go on extending this question, then the Question Hour will be over.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: As my hon. friend has pointed out, I had mentioned that holdings all over the country are growing smaller and smaller; already we have about 13 million holdings with an area of 1 is equal to 2 hectares and 13 million holdings between 2 is equal to 5 hectares. That is why larger machines cannot be purchased by the farmers and operated by them. So we have started agro service centres. At present there are 2900 agro service centres from where they can hire machines. Similarly there are 310 centres of state agro industries corporation; they are also working. My hon. friend also pointed out about harvesting. Machines used in Punjab and Haryana and he says these cause the problem of unemployment of agriculture labour; that is incorrect. The machines are used to vacate the fields so that the next crop may be sown after that otherwise the season would be lost. People are in a hurry. In Punjab and Haryana there is no problem of unemployment of agriculture labour as such in harvesting season.

SHRI P. K. KODIYAN: With regard to agriculture inputs the hon. Minister has mentioned a series of steps. I want to know whether any steps are being taken to reduce the

additional irrigation potential proposed to be created in the next year from major irrigation is about 1.3 million hectares. Will the additional irrigation potential be utilised by the farmers fully?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: So far as the first question is concerned, while replying to the debate in the House on the demands, I had mentioned that for this crop (i.e. Kharif) we are not in a position to reduce the price of fertilisers. However, we are keeping a watch on the prices. Regarding the second question, I have mentioned that about 3 million hectares of land is being brought under irrigation, small, medium and major. I shal see that maximum utilisation is made of this entire land under irrigation. Our effort is to utilise as much as possible all the existing irrigation facilities.

श्री शिव नारायण : मैं फूड मिनिस्टर से जानना चाहता हूं कि यू० पी० में पिछली गवर्नमेंट ने रेट 3 रुपये से 15 रुपये कर दिया और उसके बाद चलते-चलते 12 रुपये किया। जो कि अब भी बहुत ज्यादा है । क्या मंत्री जी स्माल सैक्टर के अडैवलपमेंट, सिंचाई वगैरा की सुविधाएं छोटे-छोटे लोगों को बढ़ाने के लिये क्या इस रेट को कम करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह प्रश्न मेरी समझ नहीं आया कि किस चीज का 11, 12 रुपये किया ?

श्री शिव नारायण : बिजली के रेट के बारे में कहा है ।

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: That does not arise out of this question.

श्री दौलत राम सारण : कृषि सेवा केन्द्र कई जगह राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये गये हैं। मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि क्या यह सही है कि इन कृषि सेवा केन्द्रों से मिलने वाले कृषि यंत्रों के मूल्य प्राइवेट तौर पर बेचने वालों के मूल्यों से अधिक हैं, जिसकी वजह से यहां से यंत्र खरीदना किसान को पौसाता नहीं है । क्या यह यंत्र वहां समय पर उपलब्ध भी नहीं होते हैं?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह मैं पता कर लूंगा, अगर ऐसी बात है तो ।

SHORT NOTICE QUESTION

Discussion between U.S.A. and U.S.S.R. on limitation of Military activities in the Indian Ocean

\+

S.N.Q. 15 DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI VAYALAR RAVI:
SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO:
SHRI CHITTA BASU:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the *Statesman* of June 29, 1977 in which it has been reported that the Governments of U.S.A. and U.S.S.R. have discussed the question of limitation of military activities in the Indian Ocean region; and

(b) if so, the reaction of the Indian Government thereon?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India hope that the dialogue will continue and the participants will adopt a constructive and positive approach to the problem and achieve results which would facilitate the establishment of the Zone of Peace in the Indian Ocean in accordance with the U.N. resolutions.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: It is a very important queseion relating to Indian security. May I ask the Minister to inform the House whether the opinion of the Indian Government was sought at any level at any stage by any of these two Super Powers regarding this vital matter and if so, what steps the Government of India are taking for maintaining Indian Ocean as a zone of peace either singly or in conjunction with the littoral countries directly related with the Indian Ocean?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, it depends on the Super Powers viz., the USA and the USSR to arrive at an agreement so that Indian Ocean can be made a zone of peace. India is being consulted informally. Our views are well known and whenever the occasion arises, we have impressed upon both the Super Powers the desirability of expediting the negotiations in this regard.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Now in view of the development of the very dangerous weapons like neutron bomb and laser beam i.e., death-ray, what precautions are the Government of India taking for safeguarding the misuse of these weapons from the military bases situated in Indian Ocean?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: This hardly arises out of this question. If there is demilitarisation in the Indian Ocean and if there is an agreement between the two Super Powers on the limitation of the armaments, so far as the Indian Ocean is concerned, I hope this danger, which my hon. Friend is pointing out, will not be there.

SHRI VAYALAR RAVI: It is surprising that the Minister leaves the entire question of peace in Indian Ocean to the Super Powers *viz.*, the USA and the USSR. It is primarily and basically a matter concerned with the littoral States especially India. Right from Ethiopia upto Australia there are 8 military bases of the United States. There is a real threat to the littoral States from these military bases. Soviet Union, in the 31st Session of United Nations Assembly, declared that they do not have any military base in the Indian Ocean. It is for you to verify. The United States are holding 8 military bases especially very close to India like Diego Garcia where they have extended the run-way to 12000 ft. They have even threatened to use the newly developed neutron weapons. How can you leave this matter to those two States alone? In this connection, I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that the United States are negotiating with Bangladesh to have a naval base at St. Martin Island. Then India will be covered by two very close naval bases maintained by the United States and it is a real threat to the peace. What is the reaction of the Government of India to it? Secondly, I would like to know whether the Government of India will take continuous initiative and leadership to mobilise the forces of littoral States to see that the entire demilitarisation and the demolition of the military bases in Indian Ocean is done.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE. I entirely agree with the hon. Member that it is the littoral and hinterland countries which are vitally concerned with the question of Indian Ocean being made a zone of peace. The overwhelming majority of the littoral countries have made their views known through the United Nations,....and the forum of Nonaligned nations. We would like all bases in the Indian Ocean to be dismantled and all military presence of the Super Powers eliminated. But we have to face facts as they are. It is for the Super Powers to come to some sort of agreement on this question. So far as the pressure of the littoral and hinterland countries is concerned, it is being felt. I think it is the pressure of the Non-Aligned Group and other countries which has led to the

negotiations by the Super Powers on the Indian Ocean question. I hope the talks will succeed and the Indian Ocean will eventually become a zone of peace. So far as the question of America acquiring a base in the Bay of Bengal is concerned, I am sorry I have no information at the moment.

SHRI VAYALAR RAVI: These negotiations are not regarding military bases. They are about keeping it as a zone of peace. How do you depend upon these negotiations?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I am not depending on anything; I am only depending on the strength of my country.

SHRI VAYALAR RAVI: I have not made any insinuation. I am sorry I have been misunderstood. I want a clarification....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chitta Basu.

SHRI CHITTA BASU: May I know whether the Minister is aware of the fact that (a) there has been a fresh rise in the US build-up in Diego Garcia, (b) there have been voyages of US fleet consisting of nuclear-powered aircraft carrier task force and P-3 task force, and (c) there has been new acquisition of bases in Masirah by USA, even after Mr. Carter's declaration about demilitarisation of the Indian Ocean? In this conext, may I know whether the Government of India is considering to express firmly and unequivocally the opinion that the USA should immediately dismantle all the bases in the Indian Ocean and stop all voyages into the Indian Ocean in order to create a pre-condition for demilitarisation of the Indian Ocean and successful conclusion of the USA-USSR talks? Secondly, may I know whether the attention of the Government of India has been drawn to an opinion expressed by the Institute for Defence Studies and Analysis of our country in an article contributed by Mr. J. P. Anand and published in the *Tribune* of 2nd February, which reads as follows:

> "The Soviet Navy sends one suadron in winter months, compared to an annual average of three task forces by the US Navy. The Soviet aim, according to some western analysts, is political rather than military. The Soviet presence is basically reactive and defensive in nature."

May I know the reaction of the Government to this opinion expressed by the Institute of Defence Studies?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, I am grateful to the hon. Member for all the information that he has given to me. I have also read the article in *Tribune*. So far as the question of developing facilities in Diego Garcia is concerned, the Government of India is aware that recently $ 7 million have been allocated for the extension of Diego Garcia by the United States of America.

The hon. Member referred to Masirah. Masirah is an air base in Oman built by the United Kingdom. The U.S.A. is reported to be negotiating for using these facilities for its aircraft. So far as the question of India's position being made unequivocably and unmistakably clear, I do not think that there is any doubt in the world about India's position and I hope the hon. Member will not have any doubt in this regard.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the hon. Minister kindly tell us that in spite of the fact that the United Nations had adopted a Resolution very clearly stating that Indian Ocean should be kept as a zone of peace, the Americans are building up without any restraint in Diego Garcia and in many other places. If you get the map of the world defence, you will be able to see the military build-up that they are going through. In that context, would you kindly tell us what pressure has the Government of India

put on the United States of America to include China in the dialogue in keeping the Indian Ocean as a zone of peace.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, India would like to use persuasion instead of pressure in international affairs. So far as the question of China is concerned, India will be happy if all Big Powers and major maritime powers including China join hands in making the Indian Ocean a zone of peace.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: The hon. Minister said that it is between the two Super Powers to come to some kind of arrangement. When it is absolutely clear from the statement made by the Soviet Union at the U.N. General Assembly when the Resolution referred to by Mr. Jyotirmoy Bosu was being discussed that they have never had and have no intention of having military bases in the Indian Ocean and the only thing is that they need this highway for the European part of the USSR to have sea connection with the far-eastern part of the USSR, I would like to know how it is that the Minister said that informal discussions have taken place when in the joint Indo-Soviet communique issued during Mr. Gromyko's visit in April, 1977 there is a specific reference to the Indian Ocean, where it says:

> "The two sides reaffirm their readiness to participate together with all States concerned on an equal basis and in conformity with the generally recognised rules of international law in efforts leading to the early establishmest of the Indian Ocean as a zone of peace. Both sides stand for the elimination of all existing military bases from the Indian Ocean and the prohibition of new ones."

MR. DEPUTY SPEAKER: I would appeal to the hon. Members not to keep on giving quotations.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: It was necessary because of his saying 'informal consultations'.

MR. DEPUTY SPEAKER: If you start quoting in the Question Hour, it will be difficult.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: This has arisen out of his reference to informal consultations. Since this discussion has taken place before the issuing of this communique, what has the Indian Government done, from its side, to pursue the commitment that is there in this communique, viz. that efforts will be made in order to have a conference of the littoral States on equal footing, in order to bring about a solution? It is not only the Super Powers—as he calls them; I do not call them so—which are concerned.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE. I do not see any contradiction in my reply to Dr. Murli Manohar Joshi, which was in the context of talks which were held recently between the USA and USSR. India has been kept informed informally about the talks; but the lady Member referred to the joint communique (*Interruptions*)—most hon. lady Member. For a bachelor, some ladies are more honourable than others. But all the lady Members in the House are honourable—after the visit of the Soviet Foreign Minister. On the question of Indian Ocean; our views coincide—both Soviet Russia and India agree that all foreign bases should be dismantled and foreign military presence eliminated. So far as question of calling a conference of littoral countries is concerned, I am afraid no useful purpose will be served, unless all the great powers and major maritime users agree to join such a conference. A Committee of the United Nations is working in this direction. I hope the efforts will succeed and such a conference will take place.

DR. HENRY AUSTIN: Is the Government aware of the statement

issued by the Australian Prime Minister Mr. Fraser recently after his meeting with the U.S. President that the military preparations being made in Diego Garcia will be continued? We know that some time after the American President had assumed office, he is on record as sying that the installations in Diego Garcia would be dismantled. But after this interview with the Australian Prime Minister, it seems he has softened his position; and he is also on record now as saying according to report that those installations will be maintained. The Moscow talks have been, not for the purpose of dismantling them in pursuance of his earlier statement, but only for maintaining the *status quo*, or perhaps for having a *modus vivendi* with other powers, to keep the *status quo*—if I can put it that way. This is not an isolated question. It has been mentioned in the declaration of the Independence of Djibouti by France that they will maintain a military force there. (*Interruptions*) There are reports from Iran that they have negotiated with the U.S. to get seven airborne radar sysems. All these are connected with Diego Garcia. Also, in Pakistan it is stated that 25 nuclear processing installations are going to be set up as part of a phased programme.

MR. DEPUTY SPEAKER: What is your question?

DR. HENRY AUSTIN: Is the Government aware of the fact that the decision of the U.N. to keep the Indian Ocean a zone of peace is completely ignored by the escalation of military preparation in Diego Garcia?

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE: I have seen the statement made by the hon. Prime Minister of Australia, to which the hon. Member made a reference. I would like to say that President Carter has never promised to dismantle Diego Garcia. All that he has promised is that there should be demilitarisation and that there should be limitation on the military presence of big powers in the Indian Ocean.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Who will check all that?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: So far as the littoral countries are concerned, the resolution of the United Nations is there and we would welcome if all bases are dismantled.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I want information on three aspects of the matter. The first one is whether the objective before the Working Group set up by Moscow and Washington remains complete demilitarization of the Indian Ocean zone, as declared by President Carter, or it is now limited to stabilising the *status quo*, or achieving a freeze of the balance in the Indian Ocean. The second is whether it is the Government's opinion that there is less of competition now in the Indian Ocean area. Thirdly, I want to know whether the two Super Powers have expressed any desire to hold talks, consultations, with India on this separately.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: At the beginning, President Carter in a statement on March 9, 1977, indicated that he favoured the demilitarization of the Indian Ocean and listed it among the questions to be taken up by his Secretary of State in Moscow. The talks were held between June 22 and 27 but no formal statement has been issued after the talks. However, the Soviet news agency *Tass* issued a statement, which brought out that the two sides discussed "limitation of armaments in the Indian Ocean" and that they "agreed to meet again".

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: So, it is down-graded?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Yes, that is what it appears. It is very difficlut for me to say anything definite on the second point.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: The third question remains unanswered whether the super-powers have expressed a desire to hold separate consultations with India on this subject.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Both Super Powers have had consultations with India separately.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: There are two parts to my question. According to our Government's information, what is the present military strength naval base etc. of USA and USSR in the Indian Ocean? Secondly, the hon. Minister has just now stated that he will be happy if there is agreement. I cannot agree with the hon. Minister on this, because they can agree on the limitation of naval base; that is possible. So, can he assure this House that the Government will not be satisfied unless this zone is made completely a peace zone?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: May I reply to the second part of the question first by saying emphatically "Yes"? India will not be satisfied with anything less than the Indian Ocean being made a zone of peace. But so far as the details of the ships in the Indian Ocean or the relative strength of the big powers is concerned, I am sorry, I do not have the details.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Kutch Desert

*408. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the desert of Kutch is steadily extending southwards in the Saurashtra region of Gujarat;

(b) if so, facts thereof;

(c) whether the State Government of Gujarat have prepared certain schemes and projects to arrest such an extension of the desert and whether the proposals have been forwarded by the State Government to the Central Government for their urgent consideration, approval and financial assistance; and

(d) if so, Government's response thereto?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). On the basis of the available information and appraisal of the general terrain conditions of the desert areas of Kutch, it is felt that the desert of Kutch is not showing any perceptible indications of movement southwards in the Saurashtra region. However, there are problems of salinity ingress along the Runn Border. During the summer, winds from the desert carry dust and clay particles laden with salt and deposit the same on fertile inland agricultural tracts.

(c) The State Forest Department is implementing a programme of afforestation along the borders of Runn of Kutch. The plantations are being raised from the beginning of First Five Year Plan. An area of 28697 ha. has been planted up upto the end of IV Plan, to serve as a buffer green belt to protect marginal fields against deposition of fine salt-laden dust particles picked up from the Runn by strong winds. The Fifth Plan target is planting up of 5000 has of additional area at a cost of Rs. 41.29 lakhs. There is no afforestation scheme inside the Runn as experiments done so far have not proved successful under the conditions prevailing in the Runn.

The State Government of Gujarat have sent the following proposals:—

(i) Provision of irrigation facilities in Kutch, Saurashtra and large tracts of North Gujarat.

(ii) Close plantation of Prosopis juliflora which reduces the salinity thereby making the area suitable for raising agricultural crops.

(d) The proposals of the State Government are under consideration.

Agricultural Service Recruitment Board

*411. SHRI DHARAMVIR VASISHT: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the date on which Agricultural Services Recruitment Board was constituted and on whose advice;

(b) the functions of the Board;

(c) the method of assessing the merits of the agricultural scientists together with the number of officers selected during the last three years; and

(d) whether selections of the Board were invariably accepted by the Government, and if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA)): (a) The Agricultural Scientists Recruitment Board was set up as a result of the decision of the Government of India on the recommendations of a group of Ministers appointed by the Central Cabinet under the Chairmanship of the Minister of Agriculture, the late Shri Fakhruddin Ali Ahmed. The Board came into existence on the 7th December, 1973.

(b) The functions of the Board, which is an independent recruiting Agency for the Indian Council of Agricultural Research, are:—

(i) to make recruitment to posts in the Agricultural Research Service and to such other posts and services as may be specified by the President of the Council from time to time;

(ii) to render such other assistance to the Council in personnel matters including promotion, as may be required by the President; and

(iii) to advise the Council in disciplinary matters relating to personnel recruited/appointed either by the Council itself or in consultation with the Board.

(c) A statement giving the requisite information is laid on the table of the House.

(d) Yes, Sir. Recommendations of the Agricultural Scientists Recruitment Board have been accepted by the President of I.C.A.R., who is the Controlling Authority for Agricultural Research Service.

Statement

Appointments to the Agricultural Research Service are made by—

(a) direct recruitment to Grade S-1 of the Service in the scale of Rs. 700—1300 through open competitive examination;

(b) Lateral entry through advertisement and interview; and

(c) promotion on the basis of merit, irrespective of occurrence of vacancies through a system of five-yearly assessment of performance of the existing scientists.

2. The Agricultural Scientists Recruitment Board have held two competitive examinations so far and have selected 897 scientists for Grade S-1 of the Service. The Board have also selected 510 scientists for various higher grades of the Service by advertisement and interview. As these selections were made post by post, only the names of the scientists who were found most suitable were recommended for appointment to the Council by the Agricultural Scientists Recruitment Board.

3. As regards appointments by promotion, irrespective of occurrence of vacancies, the Agricultural Scientists Recruitment Board have taken up the

first five-yearly assessment of all eligible scientists of the Service. So far, the Board have recommended promotion of about 450 scientists and are considering the case of several hundred more scientists. The assessment is being done through Committees of eminent scientists belonging to various disciplines. Emphasis in the assessment is being laid on the contributions and achievements of the individual in relation to the requirements of the job and the duties assigned to the post for which he was recruited. The documents which are taken into consideration while making the assessment are—

(i) Five-year Assessment proforma filled by the concerned scientists and reviewed by the senior scientist under whom he worked;

(ii) Research Project File maintained by the scientist;

(iii) Bio-data and career information of the scientists; and

(iv) Confidential Character Rolls for the past five years.

Opportunity is also given to the scientist to appear before the Assessment Committee for a personal discussion if he so desires. The discussion is not of a routine or formal type of interview to judge the theoretical knowledge and academic calibre of tunity to him to project his work but is intended to provide an oppor the scientist, and achievements during the period under assessment as well as to clarify and elaborate any specific aspect of his work.

Increase in number of Seats in Engineering College in Maharashtra

*412. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether there is a big increase in the number of students passing Inter Science and XII standard. Exams. in Maharashtra during 1977-78;

(b) whether the sanctioned strength of seats in Engineering Colleges of Maharashtra is insufficient to accommodate the increased demand; and

(c) what decision Government have taken on the proposal by the Maharashtra State Government to increase the number of seats in Engineering Colleges?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The matter was discussed with the State Government to whom certain suggestions were made. In the light of these discussions, the State Government is working out the details of increasing the intake for this year.

Crop Rotation

*413. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Scientists of Haryana Agricultural University are of the view that continuous crop rotation impairs the soil fertility if balanced fertilisation is not done; and

(b) if so, facts thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) In the trials conducted by the Scientists of Haryana Agricultural University, in plots which received Nitrogen and Potassium only, wheat grain yield continued to show a downward trend, from 29.3 q per ha in 1971-72 to 13.4 q per ha in 1975-76. In plots which received the three major nutrients namely Nitrogen, Potassium and Phosphorus, the yields were above 32.3 q/ha. So also application of Zinc sulphate at 25 Kg per ha. in

addition to NPK, gave on an average additional yield of 3 to 5 q/ha of wheat, over the application of full doses of NPK.

The above data illustrate the need for judicious and balanced fertilisation of crops.

Government Accommodation for employees owning houses

*414. CHOWDHRY BALBIR SINGH:
SHRI MEETHA LAL PATEL:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government have allowed the house owning employees of Central Government to retain their Government accommodation;

(b) whether certain associations of employees of Central Government have protested against this decision; and

(c) whether Government propose to reconsider this decision?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The house-owning officers are eligible for allotment of Government accommodation on certain terms and conditions.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

Rehabilitation of refugees in Andaman and Nicobar Islands

*415. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether many refugees from former East Pakistan, who have been kept for years in different refugee camps made repeated appeals to the Government for their rehabilitation in Andaman and Nicobar group of Islands;

(b) whether the Central Government had constituted a very high powered Committee to study in depth the issue of rehabilitation of former East Pakistan refugees in Andaman Islands;

(c) whether that Committee recommended to the Government for taking steps to rehabilitate 150,000 refugees by 1972 in Andaman Islands;

(d) if so, facts about the recommendation of the Central High Power Committee and the extent of implementation of its recommendation; and

(e) the present policy and programme of rehabilitation of East Pakistan refugees in the Andaman Islands?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir. Some representations were received from refugees of two camps, viz., Deoli and Tawa Projects, for rehabilitation in Andaman Islands.

(b) Yes, Sir. An Inter-Departmental Committee was constituted in 1964.

(c) No, Sir. That Committee recommended reclamation of land in Andaman Island for rehabilitating about 6250 families of migrants/repatriates by the end of IVth Plan.

(d) The Committee also recommended for subsequent Plans the reclamation of land for resettlement of about 10,000 migrant/repatriate families.

The upto-date extent of implementation is as below:

Name of Island	Area reclaimed	Families settled
(i) Middle Andaman . . .	2050 acres	339 migrant families from former East Pakistan.
(ii) Neil	1090 acres	100 migrant families from former East Pakistan.
(iii) Little Andaman . . .	2284 acres	381 families (366 migrant families from former East Pakistan and 15 repatriate families from Sri Lanka).
TOTAL .	5424 acres	820 families

(e) The present policy is to undertake rehabilitation only to the extent land is released for deforestation for this purpose, which is regulated by consideration of ecological factors. During the current financial year, 415 acres of land have been released to rehabilitate sixty migrant/repatriate families in Little Andaman.

Sites allotted or sold to All India Congress Committee

*416. SHRI SHIV SAMPATI RAM: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number and other particulars of various sites allotted or sold to All India Congress Committee and its different wings;

(b) the price at which sold or the rent being charged for the sites so allotted or sold;

(c) whether Government have ensured that this price or rent is not too low;

(d) the extent to which the AICC or their different wings are in arrears of rent or have not so far paid the sale price and the steps taken to recover the same; and

(e) whether Government propose to look into each such case of sale or allotment and take appropriate action, and if so, the particulars thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) to (e). 7792.251 sq. metres of land in Dr. Rajendra Prasad Road institutional area was allotted to Jawahar Bhavan Trust for All India Congress Committee Headquarters and bungalows No. 3, Raisina Road and Nos. 2 & 4, Dr. Rajendra Prasad Road were sold to them.

In addition, a number of residential units were allotted on rent to A.I.C.C. and its wings as per statement enclosed.

Land was allotted at the rate of Rs. 149.50 per sq. metre and the bungalows were sold at the depreciated cost mentioned below:

(i) Rs. 96,212/- for 3, Raisina Road.

(ii) Rs. 1,18,980/- for 2 & 4 Dr. Rajendra Prasad Road.

The rate for land is too low. Residential units were given on rent as per policy of Government and deviations made have been indicated in the statement laid on theTable of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-660/77].

Premium for land, depreciated cost of bungalows and ground rent for one year have been paid by the A. I. C. C. for the Dr. Rajendra Prasad Road institutional area plots. They are, however, in arrears of rent to the extent of Rs. 30,161.21 in respect of the

buildings rented out to them by this Ministry. Necessary action is being taken towards recovery of the arrears.

The Government propose to look into these cases and take appropriate action after the examination is complete.

Uniform Service Conditions of Universities' employees

*417. SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are considering to form uniform service conditions/rules for non-teaching employees of the Universities all over the country; and

(b) if so, when and details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के लेखों की लेखा-परीक्षा

*418 **श्री रघुवीर सिंह मछण्ड** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी को दिये गये अनुदान के लेखों को पिछले चार वर्षों से लेखा परीक्षा नहीं की गई है ;

(ख) क्या इसके बावजूद अकादमी को अनुदान दिये गये अथवा दिये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल के 1974–75 तक के लेखों की मनदी लेखापाल द्वारा विधिवत लेखापरीक्षा हो चुकी है तथा वर्ष 1975–76 के लेखों की लेखापरीक्षा का कार्य चल रहा हैं । महालेखापाल मध्य प्रदेश ने अकादमी के वर्ष 1973–74 तक के परीक्षित लेखों की जांच भी कर ली है ।

विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तक निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की जाती है । राज्य सरकार मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी को अनुदान देती है ।

कालागढ़, तुमड़िया तथा अन्य बांधों के निर्माण के कारण जल की कमी

*419. **श्री मही लाल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कालागढ़, तुमड़िया तथा अन्य बांधों के निर्माण के फलस्वरूप इन बांधों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय तथा सिंचाई जल का अभाव हो गया है जिस से इस क्षेत्र में कृषि भूमि में सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है और मनुष्यों एवं पशुओं के पीने के पानी का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में उत्पन्न इस संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) और (ख). जहां तक कालागढ़ में रामगंगा बांध के नीचे के क्षेत्रों का संबंध है, बांध के नीचे नदी तल में निर्माण कार्य हाथ में लिए जाने के कारण मई और जून, 1977 में सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जा सका । जहां तक तुमड़िया बांध से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों का प्रश्न है, इस वर्ष कम वर्षापात के कारण प्राकृतिक जल-प्रवाह कम रहा । इस प्रकार उपलब्ध जल से केवल रबी की आवश्यकताएं ही पूरी की जा सकती थीं । इन दोनों बांधों की सिंचाई प्रणालियों में पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने की विशिष्ट रूप से व्यवस्था नहीं है । बहरहाल, सिंचाई के लिए जल की सप्लाई से कुओं और तालाबों में जल की सप्लाई की मात्रा बढ़ जाती है। कालागढ बांध के मामले में जो स्थिति पैदा हुई है वह नदी तल में निर्माण कार्य की विशेष आवश्यकताओं के कारण हुई है । यह स्थिति सामान्य नहीं है इसलिए स्थिति में सुधार करने के लिए किसी विशेष कदम उठाने की जरूरत नहीं है । तुमड़िया बांध के संबंध में स्थिति यह है कि यहां पर जल की उपलब्धता प्राकृतिक प्रवाह पर निर्भर करती है । बहरहाल, यहां की स्थिति में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोसी सिंचाई स्कीम को हाथ में लिया है जिससे कोसी के पानी के व्यपवर्तन द्वारा तुमड़िया बांध में जल संचय में वृद्धि होगी ।

1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान आए सिंध के शरणार्थियों का पुनर्वास

*420. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के भारत पाक युद्ध के समय सिंध से कितने शरणार्थी भारत आये और कहां-कहां पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में बसाया गया है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन शरणार्थियों पर कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है;

(ग) क्या इन शरणार्थी शिविरों में शीत के प्रकोप से बचने के लिये ओढ़ने व बिछाने की पूरी व्यवस्था की गई है; और

(घ) क्या इन्हें स्थायी रूप से बसाने की भारत सरकार की कोई योजना है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भारत-पाक संघर्ष 1971 के परिणामस्वरूप सिंध से राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र में 74,753 व्यक्ति आए । इन व्यक्तियों में से 53,117 राजस्थान राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालौर जिलों में गुजरात राज्य के कच्छ तथा बनासकंठा जिलों के शिविरों में राहत सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) राजस्थान तथा गुजरात के शिविरों में इन विस्थापित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 250 लाख रुपये वार्षिक खर्च किये जा रहे हैं।

(ग) राहत सहायता के भाग के रूप में शिविरों में विस्थापित व्यक्तियों को ऊनी कम्बल रजाईयां दी जाती हैं।

(घ) जैसे ही स्थिति में सुधार हो जाएगा ये विस्थापित व्यक्ति सुरक्षा तथा सम्मान सहित पाकिस्तान लौटने के हकदार हैं। इसलिए उन के स्थायी पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ योजनाएं

हाल में ही मंजूर की गई हैं ताकि शिविरों में वे लगातार ही बेकार न रहते रहें।

गोबर गैस संयंत्र

*421. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोबर गैस योजना, कृषि विकास तथा ग्रामों के लिये आवश्यक समझती है और यदि हां, तो इसका द्रुतगति से प्रसार तथा प्रचार करने के लिये क्या किया जा रहा है;

(ख) क्या इस योजना में शौचालयों की व्यवस्था अनिवार्य नहीं की गई है और न इसके लिये कोई अनुदान दिया जाता है और यदि हां तो क्या सरकार का इस योजना में सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई है जिससे कम खर्चीले गोबर गैस संयंत्र की स्थापना की जा सके; और

(घ) वर्ष 1976–77 और 1977–78 के दौरान इस योजना का विस्तार करने के लिये सरकार ने कितना व्यय किया है तथा कितने गैस संयंत्र लगाये गये तथा देश में इन संयंत्रों को लगाने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। गोबर गैस संयंत्रों से अच्छी किस्म की खाद तथा रसोई के लिये गैस और मकानों व गलियों के लिये रोशनी मिलती है। इसके अलावा इन संयंत्रों से गांवों में स्वच्छ वातावरण बनता है। कृषि तथा ग्राम-विकास में इसकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए पांचवीं पंच वर्षीय योजना में 100,000 गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने की एक योजना शुरू की गई है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों, कृषि उद्योग निगमों और खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रोत्साहन के रूप में छोटे संयंत्रों (60 और 100 घन फुट के) के लिये पूंजीगत लागत पर 25 प्रतिशत, बड़े आकार के संयंत्रों के लिये 20 प्रतिशत तथा पर्वतीय एवं आदिवासी क्षेत्रों में लगाए गए संयंत्रों के लिये 50 प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक गैस संयंत्र लगाने के लिये पूंजीगत लागत पर 33 प्रतिशत आर्थिक सहायता भी उपलब्ध है। राष्ट्रीयकृत बैंक गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने के लिये ऋण सहायता प्रदान कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपने नियमों में संशोधन किया है ताकि सहकारी बैंकों के जरिये गोबर गैस संयंत्रों के कार्यक्रम के लिए आसानी से धन की व्यवस्था की जा सके। कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम भी राष्ट्रीयकृत तथा भूमि विकास बैंकों को, गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए मुहैया किये गये ऋणों पर, पुनर्वित्त सुविधाएं मुहैया करने को राजी हो गया है। इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये प्रदर्शनों की व्यवस्था, विस्तार कर्मचारियों के प्रशिक्षण, प्रोत्साहनात्मक साहित्य के मुद्रण आदि प्रोत्साहनात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

(ख) इस समय मल से प्राप्त गैस को भोजन पकाने के लिये और मलमूत्र युक्त घोल को खाद के रूप में प्रयोग करने के प्रति एक आम घृणा-सी दिखाई देती है। अतः योजना में शौचालयों की व्यवस्था को आवश्यक बनाने से प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है जिससे कार्यक्रम की प्रगति में बाधा पड़ सकती है। तथापि मल पर आधारित गैस के उत्पादन के लिये सामुदायिक आधार पर,

महाविद्यालयों, छात्रावासों वाले स्कूलों, आवासीय बस्तियों, डेरी बस्तियों, ग्राम पंचायतों आदि चुने हुए स्थानों में कुछ मार्गदर्शी परियोजनाएं प्रारम्भ करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) जी हां। विज्ञान और तकनीकी विभाग ने जैवि–गैस तकनीक और उपयोगिता संबंधी एक अखिल भारतीय समेकित परियोजना तैयार की है। इस परियोजना के अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत जैव-गैस तकनीक और उपयोगिता से सम्बद्ध पहलू आते हैं, जिसमें सस्ते गोबर गैस संयंत्र का नमूना तैयार करना भी शामिल है। तमिलनाडु और पंजाब के कृषि विश्वविद्यालयों ने भी गोबर गैस संयंत्रों के सस्ते नमूनों की रूपरेखा बनाने का कार्य आरम्भ किया है।

(घ) पांचवीं पंच वर्षीय योजना में एक लाख गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। 1976–77 में स्थापित किये गये गोबर गैस संयंत्रों की संख्या 16,328 और निर्मुक्त की गई राज-सहायता 102.71 लाख रुपये थी। 1977–78 के दौरान 25,000 संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1977–78 में स्थापित किये जाने वाले संयंत्रों के लिये की जाने वाली राज-सहायता के बारे में स्थिति तभी मालूम होगी, जब क्रियान्वित करने वाली एजेन्सियों से राज-सहायता के सम्बन्ध में मांग की जायेगी।

Grant to Sri Aurobindo Centre, Delhi

*422. DR. KARAN SINGH: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have sanctioned a grant for the proposed Sri Aurobindo Centre in Delhi; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) No, Sir. However, during the last three years a sum of Rs. 25,000/- has been given to Sri Aurobindo Society for the development of its library.

(b) Does not arise.

Per hectare yield of sugarcane

*423. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the per hectare yield of sugarcane at present in the various States in the country; and

(b) the steps Government have taken to encourage the small farmers to grow more sugarcane so far as the question of distribution of seed is concerned?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Average yields of sugarcane in tonnes per hectare in important sugarcane-growing States of India during 1975-76 were as follows:—

State	Yield (Tonnes per hectare)
Sub-tropical region	
Assam	37·0
Bihar	36·7
Haryana	43·2
Madhya Pradesh	30·8
Punjab	53·7
Rajasthan	38·8
Uttar Pradesh	40·1
West Bengal	58·5
Tropical region	
Andhra Pradesh	69·5
Gujarat	55·2
Karnataka	75·9
Kerala	53·9
Maharashtra	88·4
Orissa	65·0
Tamil Nadu	95.5
ALL INDIA AVERAGE	51·2

(b) The sugarcane-producing States and the Central Government have various programmes relating to sugarcane development. Seed production of approved varieties of cane and distribution thereof to the cane-growers is the most important component of these programmes. These are supplemented by the sugar factories also in many areas. All these schemes benefit primarily the small sugarcane-growers.

The programmes are:—

(i) State Governments under their normal sugarcane development programmes raise sugarcane nurseries for distribution of seed cane of improved varieties to cane-growers, most of whom are small farmers.

(ii) To supplement the efforts of the State Governments, the Government of India have also launched a Centrally Sponsored Scheme for sugarcane development during the Fifth Five Year Plan. The Scheme envisages development of sugarcane in a 2,000 hectare area around each sugar factory in the sub-tropical sugarcane belt and 1,000 hectare area around each sugar factory in the tropical belt. Saturation of the entire area covered, with distribution of healthy seed cane of approved varieties once every 4 years, is the most important component of the Scheme.

(iii) Most of the Cooperative Sugar Factories, whose membership consists predominantly of small farmers, extend facilities by way of

arranging production credit to their member-growers. The production credit covers purchase of seed cane also.

(iv) Some of the public sector and joint stock sugar factories also extend facilities to cane-growers for sugarcane cultivation, by arranging loans from nationalised banks, recoverable at the time of cane supply.

भारतीय खाद्य निगम के पास आयातित और देशीय गेहूं का स्टाक

*424. श्री राधवजी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1977 को भारतीय खाद्य निगम के पास आयातित और देशीय गेहूं का कितना स्टाक था;

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान और अप्रैल तथा मई, 1977 में कुल कितना गेहूं आयात किया गया; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास ऐसा 31 मई, 1977 को कितना गेहूं था जो एक वर्ष से अधिक अवधि से निगम के पास पड़ा हुआ था ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 31 मई, 1977 को लगभग 40 लाख मीटरी टन आयातित गेहूं और लगभग 62 लाख मीटरी टन देशी गेहूं पड़ा था।

(ख) 1976-77 के दौरान 49 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात किया गया था। अप्रैल और मई, 1977 के दौरान गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास 31 मई, 1977 को गोदामों में पड़े गेहूं में से 40 लाख मीटरी टन गेहूं से थोड़ी अधिक मात्रा एक वर्ष से ज्यादा पुरानी थी।

Veeranam Water Supply Project in Tamil Nadu

3013. SHRI S. D. SOMASUNDARAM:
SHRI M. KALYANASUNDARAM:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the findings of the Expert Committee set up by the Government of Tamil Nadu in regard to the efficacy of the pipes being used in the Veeranam Water Supply Project and also in proceeding with the utility of the scheme;

(b) whether the scheme would be speeded up/abandoned/slowed down;

(c) if the scheme is to be speeded up, the target date fixed for completion of the project; and

(d) the capital investment so far made and that which is yet to be invested for completion?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). The Technical Committee has observed that the VACRETE technology is inherently sound. It has, recommended the continued used of the VACRETE technology with adequate safeguards.

However, divergent views have been expressed about the VACRETE technology by the Consultants appointed by the UNDP/WHO Team on Pre-Investment studies of Madras Water Supply and Sewerage, who feel that the quality of about 60,000 metres of pipes already manufactured with VACRETE technology is inadequate

to allow their use under high pressure segment of pipeline. Adviser (PHEE) in the Ministry of Works and Housing has also suggested that the project can be reactivated on the basis of indigenous technical know-how and technology well tried out in the country and that the 60,000 metre pipes already manufactured could be utilised in the last reach of the conduit towards the city where the pressure will not be so high. The whole matter relating to the reactivation of the project, is under the active consideration of the State Government, who will take all these views into account.

(c) After the decision is taken approximately thirtysix months would be needed to complete the project from the date of recommencing the work on it.

(d) So far, Rs. 22.68 crores have been spent on the project. Revised estimates of costs are being worked out by the State Government.

Fishing Harbours in Goa

3014. SHRI EDUARDO FAIEIRO: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have planned to set up any fishing harbours in Goa; and

(b) if so, the broad outlines of these projects and progress made in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) The Fishing harbour is designed to facilitate operation of 250 mechanised boats of size ranging from 11—16 metres. It envisages construction of breakwaters, 440 metres of wharf, slipway with side slipping arrangements and shore facilities such as auction hall, water supply, roads, buildings etc. The project is estimated to cost Rs. 289.36 lakhs.

The Government of Goa have been requested in January 1976 to confirm availability of the site and acceptability of designs and estimates relating to the project proposal. The matter is reported to be still under consideration of the Government of Goa.

Shortage of Exercise Books

3015. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the acute shortage of exercise books; and

(b) if so, what action is being taken to ensure supply of exercise books to the students at reasonable prices?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). No Reports from State Governments about shortage of exercise books have been received. However, to ensure easy availability of exercise books to students at the opening of academic sessions, 30120 tonnes of white printing paper has been allotted to State Governments/Union Territories for the quarter April-June, 1977 for conversion into exercise books. The paper mills have also been advised to give top priority to the requirements of the educational sector and to step up the production, if need be, in order to ensure that there is no shortage of exercise books.

U.G.C. Grants for Furniture and Building Expansion to Private Managed Colleges

3016. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether no grant is given by the U.G.C. for furniture and building expansion to private managed recognised colleges in Himachal Pradesh, Punjab and Haryana;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the U.G.C. is contemplating to give such grant; if so, the details thereof and by when the grant will be given and to what extent; and

(d) the amount earmarked for the purpose during the current financial year?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) to (d). The University Grants Commission provides financial assistance to Colleges for their development programmes. All Colleges, whether managed by Government or Private Bodies, are given this assistance provided they fulfil the conditions of eligibility laid down by the Commission relating to enrolment, faculty strength etc. The Commission's assistance is available for construction of buildings, books and equipment, faculty improvement etc. No separate grant is given for furniture, but in the case of teaching accommodation, and library and laboratory buildings, 10—20 per cent of the cost of construction is accepted for providing furniture in such buildings.

The Commission has so far approved the building programmes of 15 Colleges (8 in Punjab, 6 in Haryana and 1 in Himachal Pradesh) involving a total assistance of Rs. 15.97 lakhs during the Fifth Plan period. Prior allocation is not made by the Commission for assisting Colleges in each State but proposals, as and when received, from the Colleges through the Universities concerned, are considered on merits.

Training of Farmers on methods of Irrigation in Arid Areas and Dry Farming

3017. SHRI G. Y. KRISHAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Associated Cement Companies (ACC) Organised a programme to train farmers on methods of irrigation in arid areas and dry farming practices under its Village Welfare scheme at its Wadi Demonstration Farm in Karnataka;

(b) whether Government are satisfied with its achievements regarding its media of lectures, demonstrations model designs, group discussions and films; and

(c) if so, whether Government propose to introduce this scheme in other States also?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The Associated Cement Companies (ACC) is a private organisation not responsible to the Government of India. The Government have received no specific information about the training in question organised by them in Karnataka.

(b) and (c). Do not arise in view of reply to part (a)

Irrigation Facility for Food Production in Andaman and Nicobar Islands

3018. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the irrigational facilities provided for increase in agricultural production in Andaman and Nicobar Islands;

(b) whether Government propose to undertake any scheme for providing irrigational facilities in single crop grower Agriculturists of Andaman and Nicobar Islands; and

(c) if so, main features of the Scheme?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Some irrigation facilities are being provided in Andaman and Nicobar Islands through minor irrigation works during the last three years.

(b) and (c). Six schemes, envisaging hydro-power generation, irrigation and water supply benefits are at present under investigation. Details of these Schemes will be available after the investigations are completed and decision to implement them are taken.

An amount of Rs. 10 lakhs has been provided in the Fifth Five Year Plan of Andaman and Nicobar Islands for minor irrigation programme comprising construction of wells, installation of pumpset, small lift irrigation schemes etc.

Requests from States for Additional Foodgrains

3019. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether a number of State Governments have requested the Central Government for additional foodgrains allocation to tide over the existing shortages in their respective States; and

(b) if so, the action Government have taken thereon?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) Yes, Sir.

(b) The demands of the State Governments/Union Territories for wheat and milo are being met in full. Consistent with the overall availability of rice in the Central Pool, maximum possible allotments of rice are also being made to the States/Union Territories to meet their reasonable requirements of the public distribution system.

इंजिनियरिंग कालेज तथा विश्वविद्यालय

3020. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मान्यताप्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या पृथक्-पृथक् कितनी हैं और वे कहां-कहां हैं; और

(ख) आगामी शिक्षा वर्ष से सरकार का विचार कितने नये इंजीनियरिंग कालेज तथा विश्वविद्यालय खोलने का है और वे कहां कहां खोले जायेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) इंजीनियरी कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के दो अलग-अलग विवरण सभा पटल पर रखे गए है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एलटी–661/77]

(ख) शैक्षिक वर्ष 1977–78 के दौरान कोई नया इंजीनियरी कालेज अथवा विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers

3021. SHRI HAREN BHUMIJ: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the amounts sanctioned by the Government of India to the State of Assam for loan and subsidy under Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers for the financial years 1976-77 and 1977-78 respectively;

(b) the amounts utilised so far and the number of Plantation Workers who had been given loans and subsidy during the above financial years;

(c) what is the basis for giving such loan and subsidy under the Scheme; and

(d) the present position of the availability of funds?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) In 1976-77, a sum of Rs. 7.00 lakhs as loan and Rs. 8.00 lakhs as subsidy was sanctioned to the Government of Assam for the implementation of the Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers. In addition, the Government of Assam had at their disposal, the unspent balance of Rs. 9.42 lakhs as loan and Rs. 16.02 lakhs as subsidy out of funds released in earlier years. As regards 1977-78, the State Governments have been requested to indicate their requirements of funds. Allocation of funds will depend on the programme of works and the requirements of funds during this years by the State Governments.

(b) A sum of Rs. 22.78 lakhs as loan and Rs. 25.02 lakhs as subsidy have been utilised by the Government of Assam during the year 1976-77. Upto 31-3-1977, the cumulative total of amounts utilised by the Government of Assam was Rs. 136.59 lakhs as loan and Rs. 77.17 lakhs as subsidy and sanction was given by the Government of Assam for construction of 8608 houses. Funds under the Scheme are given to the Plantation owners through the State Governments for construction of houses, and not directly to the Plantation Workers.

(c) To help the planters to meet their statutory obligation under the Plantations Labour Act, 1951, to provide rent-free accommodation to resident plantation workers, funds made available to them for construction of houses for their eligible workers to the extent of 87½ per cent (50 per cent as loan and 37½ per cent as subsidy) of the actual or audited cost of construction or the precribed ceiling cost, whichever is the least.

(d) In the budget for 1977-78, a provision of Rs. 2.10 crores has been made for the implementation of this Scheme in the whole country.

Approach to World Bank for Financing the Dastur Plan

3022. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to approach the World Bank for financing 'the Dastur Plan' for generation of power and control of floods in the country;

(b) if so, the steps so far taken by Governments; and

(c) the reaction of the World Bank thereto?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Dastur Plan is conceptual. There is no proposal for seeking assistance from the World Bank for the schemes envisaged in the Dastur Plan.

(b) and (c). Do not arise.

Reclamation of Alkaline Soil

3023. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of AGRICULTURE & IRRIGATION be pleased to state:

(a) break-up of area of alkaline soil existing in different States and whether there has been an increasee in its total area and if so, reasons thereof;

(b) whether Government propose to draw a scheme to reclaim such land and if so, its salient features; and

(c) whether Government are aware that excessive use of chemical fertilisers in agriculture cause a gradual rise in making the soil alkaline and steps proposed to check it?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) No detailed survey has been carried out, but it is

estimated that the total area under alkali soils in the country is approximately 2.5 million ha. Out of this, Uttar Pradesh alone has nearly 0.9 million ha.; Punjab has 0.45 million ha.; and Haryana 0.35 million ha.; and the remaining 0.8 million hectares is distributed in other States.

No evidence is available to indicate that there has been any further increase in the areas under alkali soils.

(b) Yes, Sir.

The Department of Agriculture has taken up a Centrally Sponsored Scheme on Pilot basis for reclamation of alkali soils during the current Five Year Plan. Under this, an allocation of Rs. 7|- crores has been made for reclaiming 64,000 ha. of alkali soils in the States of Uttar Pradesh, Punjab and Haryana. The programme has been undertaken in those areas where sufficient water of good quality is available on assured basis.

The Scheme provides for 50 per cent subsidy towards the cost of amendment material to small and marginal farmers having land holdings upto 3 ha. and 25 per cent subsidy to others. In addition, the State Governments are expected to provide 25 per cent subsidy from their own resources to both the above categories of farmers. The remaining cost of reclamation work will be borne by the farmers themselves.

(c) No Sir. On the other hand, use of Chemical Fertilisers such as Ammonium Sulphate has been found useful in reclamation of alkali soil.

DELHI UNIVERSITY EXAMINATION RESULTS IN NEWSPAPERS

3024. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it has come to the notice of the Government that the Delhi University results of various examinations do not appear in all the leading newspapers; and

(b) if so, the facts thereabout and the steps proposed to be taken to ensure that all the results of Delhi University appear in all the leading newspapers?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). According to the information furnished by the University of Delhi, copies of result notifications of the University are sent regularly to all the leading newspapers in Delhi for favour of publication. The newspapers are further requested that if for any reasons it is not possible for them to publish the results, they may, at least, give in the news column, the names of the examinations for which the results have been declared, so that the students may contact the institutions concerned to whom the result notifications are also sent for display at the notice board. Copies of the result notifications are also sent to Special Information Bureau, Samachar, Yuv Vani and Youth Bulletin for giving wide publicity.

Profit and loss of the Gujaranwala House Building Cooperative Society, Delhi

3025. SHRI RAM KANWAR BERWA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the total profit and loss of the Gujaranwala House Building Cooperative Society, Delhi as revealed by Audit Reports from 1967-68 to-date;

(b) the total amount credited to the Development Fund of the Society;

(c) whether Government are aware that this amount is being utilized by the Society for purpose other than Development of land;

(d) if so, steps being taken by Government to ensure that the said amount is not spent by the Society for purpose other than the Development of land for the left out members of the society?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) to (d). Information is being collected.

National Seeds Project

3026. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the full facts about the National Seeds Project set up with the aid of the World Bank;

(b) the work done so far under this project; and

(c) whether the Agriculture Ministry and the Planning Commission are now viewing it with disfavour and, if so, the reasons thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). A proposal for setting up/assisting State Seeds Corporations in Punjab, Haryana, Andhra Pradesh and Maharashtra with necessary supporting facilities/programmes was posed to the World Bank.

The project contemplates certified seed production in compact areas having distinct production advantages, by the State Seeds Corporations with the active participation of share-holder growers. It would produce seeds of identified cereals and other major crops for consumption within the States as well as for sale to other States. It seeks to encourage individuals and cooperatives desirous of producing/processing certified seeds. The project would provide funds to create enlarge/strenthen necessary infrastructure for production, processing, quality control, storage and marketing of seeds to cater to the increased requirements in the coming years. The project proposals were appraised by the World Bank and negotiated. These were then also considered by the Planning Commission and the Ministry of Finance. In the light of their views, the revised project is now under consideration of the Government of India.

Removal of restrictions imposed on building constructions

3027. SHRI VAYALAR RAVI:
SHRI N. SREEKANTAN NAIR:
SHRI K. KUNHAMBU:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether due to the restrictions imposed on building construction this activity is at a very low speed in the country;

(b) if so, whether Government propose to remove the restrictions imposed on building constructions; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) No restrictions have been imposed on building construction. However, immediately after the enactment of the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976, there was a slackening in the building activity throughout the country.

(b) and (c). The guidelines to the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act are under review with a view to take such administrative measures as may be required to give an impetus to the building activity, without violating the Act.

Development work in the Triloki Colony, Delhi

3028. SHRI KACHRULAL HEMRAJ JAIN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the progress of development work in the acquired area of the Triloki Colony (Bapu Park), Kotla Mubarakpur, Delhi;

(b) when the development work of the said acquired area is likely to be completed;

(c) whether the development work for the non-acquired area of the said colony is also being contemplated; and

(d) if so, how it is proposed to get this non-acquired area developed, especially when the coloniser has not completed it for over a decade much to the detriment of plot/house owners?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) No development work is in progress in the acquired area known as Triloki Colony (Bapu Park), Kotla Mubarakpur.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले

3029. **श्री ईश्वर चोधरी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा निश्चय किया गया है कि केवल उन्हीं छात्रों को इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश दिया जायेगा जिन्होंने अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की है;

(ख) क्या हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के साथ उतीर्ण छात्र इस सुविधा से वंचित रहेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) इस प्रकार का कोई निर्णय अखिल भारतीय तकनीकी परिषद् अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Pending inter-State water disputes

3030. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to initiate any new steps to settle the inter-State water disputes which are pending for several decades; and

(b) if so, details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The approach of the Government has been to resolve water disputes by negotiations. Efforts in this direction are proposed to be intensified in future. Government is also keen to evolve in consultation with States suitable modalities for expeditious settlement of water disputes.

(b) The matter is under examination.

Registered House Building Cooperative Societies in Delhi not allotted land

3031. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of House Building Cooperative Societies registered in Delhi which have not been allotted land so far; and

(b) the reasons thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). The information is being collected.

रांची जिले में लाख की खेती

3032. **श्री कड़िया मुण्डा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रांची जिले में हजारों किसान लाख की खेती करने में लगे हैं;

(ख) क्या लाख की पूरी खपत सुनिश्चित करने और उसके लिए विशेष उद्योग स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या सरकार का विचार रांची में कोई लाख उद्योग स्थापित करने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की व्यवस्था करने का है जिसके अन्तर्गत रांची जिले में उत्पन्न लाख का देश के लाख उद्योग में कच्चे माल के रूप में पूरा उपयोग किया जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). रांची में अथवा देश के किसी अन्य भाग में लाख का कच्चे माल रूप में कोई विशेष उद्योग स्थापित करने के लिए फिलहाल सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Survey regarding Unauthorised and Unrecognised Schools

3033. SHRI D. B. CHANDRA GOWDA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any survey regarding the unauthorised and unrecognised schools in the country;

(b) if so, the details thereof Statewise; and

(c) whether Government are aware that particularly primary schools run by the private managements are very costly and their management is also not satisfactory?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) There is no such classification as unauthorised schools but only unrecognised. A sample study was undertaken by NCERT in Hyderabad, Secunderabad and Delhi and an attempt was also made by NCERT to collect information about unrecognised schools in the Third All-India Education Survey but the information cannot be said to be complete for the reason that these institutions are under no obligation to furnish information.

(b) The information in respect of the number of unrecognised schools and enrolment as supplied by the States/Union Territories under Third

All India Educational Survey is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-662/77].

(c) It is generally true that Primary Schools run by the Private Managements are costly as compared to Government Schools but it is not possible to make a general statement that their management is not satisfactory.

Former Executive Councillors of Delhi in Occupation of Government Accommodation

3034. SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the names of former Executive Councillors of Delhi who are still in occupation of Government accommodation;

(b) the monthly rent being charged from each of them and since when each of them is residing there after paying market rent; and

(c) steps taken to get the accommodation vacated from these persons under the Public Premises Eviction Act?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The following former Executive Councillors of Delhi are still in occupation of Government accommodation:—

1. Shri Radha Raman
2. Shri Mange Ram
3. Shri O. P. Bahl

(b) Shri Mange Ram is liable to pay market rent at the rate of Rs. 923 per month with effect from 4th May, 1975. The other two will have to pay market rent with effect from 6th May, 1977 at rates which are under assessment.

(c) Eviction proceedings against all the three have been initiated under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971.

Demands of Workers of Modera Bakeries, Edappally

3035. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the workers of Modern Bakeries at Edappally went on an indefinite strike since 3rd June this year to press their demands; and

(b) if so, what are their demands and the measures taken to settle the dispute?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) A statement indicating the demands and the measures taken by the Management to settle the dispute is attached.

Statement

(b) The main demands of the Cochin Unit of the Modern Bakeries Employees Union are as follows:—

1. Revision of the pay scales of the employees.

2. Enhancement of D.A., House rent allowance, transport subsidy, canteen subsidy and certain other allowances and also payment of City Compensatory allowance.

3. Change in the working hours of the office staff, increase in the number of days of casual leaves, holidays etc.

4. Introduction of promotion policy and upgrading after a certain number of years of service and introduction of incentive bonus.

5. Grant of house building loan and the children education allowance.

2. In an effort to settle the dispute conciliation proceedings were initiated but they have failed. Thereafter discussions were held with the workmen representatives in Cochin which also did not yield any result. The Company has now set up a high powered committee to further negotiate with the representatives of workers Union/Federation on their charter of demands and these discussions are in progress.

World Bank Assistance for Irrigation Projects

3036. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the number of irrigation projects in the country for which the World Bank is giving assistance; and
(b) the names of the projects?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). Two major irrigation projects namely Godavari Barrage and Nagarjunasagar Project in Andhra Pradesh are receiving credit assistance from the World Bank. The agreement for assistance to Nagarjunasagar Project includes command area development.

The World Bank is also providing credit assistance for the following projects:—

(i) Rajasthan Canal Command Area Development.

(ii) Chambal Command Area (Madhya Pradesh).

(iii) Chambal Command Area (Rajasthan).

Minor irrigation works form a component of the International Development Association credit projects operating in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal.

Expulsion of President, Students' Union from J.N. University

3037. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the President of Jawaharlal Nehru University Students' Union Shri D. P. Tripathi was expelled from the University by the Vice-Chancellor for exercising his right to attend the Academic Council Meeting in his capacity *ex-officio* member of the Council:

(b) whether Government propose to probe into the violation of University academic norms by the Vice-Chancellor; and

(c) if so, the steps taken so far?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) According to the information furnished by Jawaharlal Nehru University the term of the Students Union of the Jawaharlal Nehru University expired on the 22nd October, 1975. The *ex-officio* membership of the Academic Council held by the President of Jawaharlal Nehru University Students' Union, therefore, ceased on that date Shri D. P. Tripathi, the retiring President of the Students' Union was informed accordingly on the 6th November, 1975. When the Academic Council assembled at 4.00 p.m. on the 7th November, 1975 to transact its business, Shri Tripathi came and occupied a seat and caused disruption despite repeated requests from the Chair to leave the Council meeting. Thereafter, he gathered 25 or so of his supporters at about 4.45 p.m. and raised slogans near the venue of the meeting of the Academic Council. Consequently, the Vice-Chancellor ordered his suspension from the rolls of the University for a period of six months with immediate effect.

(b) and (c). Do not arise.

Uniform retirement age for College Teachers

3038. SHRI OM PRAKASH TYAGI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether his Ministry has received representations for introducing a uniform retirement age for all college teachers in the country; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Yes, Sir.

(b) In the scheme of revision of salary scales, communicated to the State Governments, it was suggested that the age of superannuation of teachers as well as Principals may be 60 years and it has left to the State Governments who are the competent authority in this matter to take the final decision. Since the ultimate responsibility for the maintenance of colleges is that of the State Governments, the decision in this matter is left to them.

मकान बनाने के लिए गुजरात सरकार को आबंटित धनराशि

3039. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :**
श्री अहमद एम० पटेल :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 और 1976–77 में गुजरात सरकार की मकान निर्माण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और गुजरात सरकार ने उक्त अवधि में कितनी धनराशि खर्च की; और

(ख) वर्ष 1977–78 में गुजरात सरकार का कितनी धनराशि से कितने मकान बनाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) गुजरात के लिए 'आवास' के अन्तर्गत वर्ष 1975–76 और 1976–77 के लिए योजना परिव्यय क्रमशः 543 लाख रुपये और 419 लाख रुपये था। वर्ष 1975–76 के लिए 872 लाख रुपये था तथा वर्ष 1976-77 के लिए प्रत्याशित व्यय 801 लाख रुपये था। इसके अतिरिक्त 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान गुजरात राज्य के विभिन्न आवास अभिकरणों के लिए आवास तथा नगर विकास निगम ने कुल मिला कर क्रमशः 466.53 लाख और 910.097 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया। आवास तथा नगर विकास निगम ने मंजूर किए गए ऋण की तुलना में 1975–76 के दौरान 398.43 लाख रुपये और 1976–77 के दौरान 266.48 लाख रुपये दिये।

(ख) वर्ष 1977–78 के लिए गुजरात में आवास के लिए 865 लाख रुपये का योजना परिव्यय है। गुजरात सरकार ने 1977–78 के दौरान बनाये जाने वाले मकानों की संख्या के बारे में सूचना नहीं भेजी है। चालू वर्ष में (30–6–1977 तक) आवास तथा नगर विकास निगम ने 450 रिहायशी एककों के निर्माण के लिए 106.12 लाख रुपये की राशि का ऋण मंजूर किया और 17.88 लाख रुपये दिये।

Subsidiary Corporation in Kerala under Plantation Corporation of India

3040. SHRI M. N. GOVINDAN NAIR:
SHRI C. K. CHANDRAPPAN:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Plantation Corporation of India has prepared a comprehensive Scheme for the expansion of Cashew Cultivation in 30,000 acres of land in Kerala;

(b) if so, whether a subsidiary corporation is proposed to be formed under Plantation Corporation for the very purpose of this new Scheme; and

(c) whether the State Government or the said corporation have sought for any financial assistance for this Scheme from the Union Government?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). No Corporation has prepared any such Scheme. However, keeping in view the urgent need for increasing indigenous production of raw Cashewnuts, the Government of India have themselves formulated and sanctioned a Centrally Sponsored Scheme, for raising cashewnut plantations in 85,000 hectares of private lands and 60,000 hectares of Government lands in different States. Under this scheme, a total Central assistance of Rs. 1.25 crores to the Government of Kerala has been approved as subsidy for plantation of cashew in 25,000 ha. of private lands and 10,000 ha. of Government lands, in Kerala, in a phased manner over a period of six years.

Area under Sugarcane Cultivation

3041. SHRI JYOTIRMOY BOSU. Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state acreage under sugarcane cultivation, State-wise, during 1974-75, 1975-76 and 1976-77?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): A statement giving the estimates of area under sugarcane, State-wise, during 1974-75 and 1975-76, is enclosed. Firm estimates of area under Sugarcane during 1976-77 is not yet available. However, an idea of the likely increase or decrease in area in 1976-77 over 1975-76 in different States, based on preliminary estimates, is given in the enclosed statement.

Estimates of area under sugarcane during 1974-75 and 1975-76 and likely change in 1976-77 over 1975-76.

State	Area (thousands hectares)		Likely increase (+) or Decrease (—) in 1976-77 over 1975-76 (Percentage)*
	1974-75	1975-76 (Final Estimates)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Andhra Pradesh	195·1	135·6	(—)6·9
Assam	41·9	41·2	(+)10·1
Bihar	140·7	133·7	(+)7·4

(1)	(2)	(3)	(4)
Gujarat	40·8	37·7	(+38·2
Haryana	161·4	159·0	(+)6·1
Karnataka	124·1	131·3	(—)3·7
Kerala	9·5	9·4	(—)1·0
Madhya Pradesh	80·7	69·1	(+)5·0
Maharashtra	185·2	216·8	(+)26·5
Orissa	44·0	46·0	(+)3·0
Punjab	123·0	115·0	(—)5·6
Rajasthan	51·3	40·1	(+.4·4
Tamil Nadu	160·4	154·9	(+)3·3
Uttar Pradesh	1491·5	1450·4	(+)0·6
West Bengal	29·0	29·3	(+)5·4
Others	15·6	20·2	(+)2·2
All-India	2894·2	2789·7	(+)3·0

*Based on preliminary figures given in the all-India second estimate of Irrigation, 1976-77, which covers the period upto the middle of October, 1976.

Conversion of old system of allotment of land on lease basis to Free-hold Basis

3042. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there is a proposal with the Government to convert the old system of allotment of land on lease basis to free-hold basis;

(b) if so, whether it is not a fact that such a step will push up the prices of the land; and

(c) if so, the reasons therefore, remedial measures proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). All aspects of the matter will be considered before taking a final decision.

Import and distribution of Fertilizer

3043 SHRI AHMED M. PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the total quantity of fertilizer imported by Fertilizer Corporation during the last three years year-wise;

(b) the mode of distribution of imported fertilizer to the States; and

(c) the quantity supplied to Gujarat State during the last three years year-wise?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Fertilisers are not imported by the Fertiliser Corporation. These are im-

ported by the Government of India and are handled at the ports by the Food Corporation of India so far as non-potassic fertilisers are concerned and by the Indian Potash Ltd. so far as potassic fertilisers are concerned.

Based on berthing of vessels, the following quantities of fertilisers were imported during the years 1974-75 to 1976-77:

(Figures in tonnes)

Year	Total quantity in terms of material N	In terms of	
		P	K
1974-75	34,50,563	8,83,773	2,80,997	4,37,218
1975-76	32,52,199	9,50,394	3,36,805	2,67,143
1976-77	21,40,662	7,49,984	22,768	2,77,803

(b) After assessing the total net requirements of the States, Union Territories and Commodity Boards before the commencement of each manuring season, i.e., Kharif or Rabi, a consolidated Supply Plan for indigenous and imported fertiliser is prepared. In this Supply Plan, indigenous production is first allocated to different States. The gap between the total net requirements and the estimated indigenous production during the season, is met by imported fertilisers. The potassic fertilisers, i.e., Muriate of Potash and Sulphate of potash, are entirely imported from abroad and distributed by M/s. Indian Potash Limited. The non-potassic fertilisers, as per the Supply Plan, are allocated to the States, Union Territories and Commodity Boards, who in turn reallot the same to the institutional agencies and private parties. On the basis of the reallocations by the States/Union Territories Commodity Boards, despatch instructions are given and financial arrangements made by the reallotees and Food Corporation of India supply these fertilisers.

(c) The following quantities of fertilisers (in terms of nutrients) were supplied to Gujarat State by the Central Fertiliser Pool during the years 1974-75 to 1976-77:

(Figures in tonnes)

Year	In terms of		
	N	P	K
1974-75	28,685	14,924	74
1975-76	3,594	705	..
1976-77	13,275	915	9

The above quantum of K was present in the complex fertilisers supplied by the Pool. The balance of the following Potash consumption of the State during last three years was supplied by Indian Potash Limited directly and through complex manufacturers (in the form of complex) and mixing/granulation units:

(Figures in t nnes)

1974-75	12,590
1975-76	6,840
1976-77	13,270

Allocation of funds for urban development in Andhra Pradesh

3044. SHRI M. RAMGOPAL REDDY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Central Government have received any request from the Andhra Pradesh Government for allocation of funds for urban development in the State during the current financial year; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) The State Government had proposed an outlay of Rs. 246 lakhs for urban development in the State's Annual Plan proposal for 1977-78, and after discussions, the Planning Commission had approved an outlay of Rs. 230 lakhs, leaving the break-up to the discretion of the State Government. This outlay includes an armarked outlay of Rs. 74 lakhs for environmental improvement of slums which is part of the Minimum Needs Programme.

In addition, the State Government has sent proposals for assistance under the Integrated City Development Programme for Hyderabad and Visakhapatnam urban areas and for taking up projects for the Hyderabad Secunderabad city under the Six Point Formula Programme. Their request is for central assistance to support a total programme of Rs. 577.70 lakhs for Hyderabad-Secunderabad city and Rs. 207.84 lakhs for Visakhapatnam.

Assistance to the State Government is dependent on the appraisal of the progress of the on-going schemes.

Completion of projects undertaken during international women's year

3045. SHRIMATI RENUKA DEVI BARKATAKI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the projects undertaken during the International Women's Year for the welfare of women have been completed; and

(b) if so, what are the on-going projects and when Government propose to complete them?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). The programme for International Women's Year as drawn up by the National Committee on the International Women's Year

was focussed mainly on a national public awareness campaign to make the role and rights of women recognised and understood by all sections of people. Educating the people and changing attitudes is a complex and long term process and it is continuing.

2. However, a few projects did get started in International Women's Year as shown below:—

(i) Functional Literacy for Women in the age group of 15—45 years.

In the experimental scheme of the Integrated Child Development Services, it was decided to attempt to implement a scheme of functional literacy for women. The Scheme imparts training in health and nutrition, education, child care and programmes of supplementary income like kitchen gardening, poultry keeping, animal husbandry etc. and is now being implemented in 2628 centres in 31 project areas. 43168 women are reported to have been covered by the Scheme in 1976-77. An amount of Rs. 57.50 lakhs is provided for the Scheme in 1977-78, the amount spent in 1976-77 being Rs. 22.25 lakhs.

(ii) The Scheme for assisting voluntary organisations in the construction of Working Women's Hostels was liberalised in January 1975. The quantum of assistance for construction, given by the Central Government was raised from 60 per cent to 75 per cent from January 1975, and this pattern is continuing. The expenditure on the Working Women's Hostal Scheme rose from Rs. 52.40 lakhs in 1974-75 to Rs. 81.80 lakhs in 1975-76 and to Rs. 90.04 lakhs in 1976-77. An amount of Rs. 161.50 lakhs is provided for 1977-78.

(iii) A scheme of assistance to voluntary organisations for provision of creches for children of working and ailing mothers was finalised during the International Women's Year. In 1976-77, a sum of Rs. 25 lakhs was sanctioned as assistance covering 19050 beneficiaries (Children).

Ban on prostitution

3046. SHRI SAUGATA ROY: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to ban prostitution in the country; and

(b) if so, what are the plans for rehabilitating the prostitutes?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) There is no such proposal.
(b) Does not arise.

World Bank assistance for the Upper Krishna Projects

3047. SHRI RAJSHEKHAR KOLUR: SHRI TULSIDAS DASAPPA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether there has been any progress in negotiation in respect of World Bank assistance for the Upper Krishna Project in Karnataka between Government of India and the World Bank;

(b) whether the Government of India is giving substantial assistance for accelerating the Upper Krishna Project work; and

(c) if so, when and how much financial assistance was given?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) An Appraisal Mission of the World Bank is expected to visit the Upper Krishna Project in September, 1977.

(b) and (c). An advance plan assistance of Rupees two crores was provided to the Government of Karnataka during 1976-77 with a view to accelerate the tempo of works on the project.

"सुन्दरकली" नामक कम आयु के हाथी का रोगग्रस्त होना

3049. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालुम है कि 'सुन्दरकली' नामक कम आयु का एक हाथी अगली टांग की हड्डी टूट जाने से रोगग्रस्त है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसकी जिन्दगी बचाने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या हिसार से आये डाक्टर उसके जिन्दा रहने की आशा रखते हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही है ; और

(घ) क्या सरकार ने डाक्टर द्वारा अपेक्षित क्रेन भिजवाने के लिये रक्षा मंत्रालय से सम्पर्क किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) "सुन्दरकली" नामक हथनी एक प्राइवेट फर्म की थी । इस फर्म ने हथनी की जांच करने के लिये दिनांक 25-6-77 को दिल्ली चिडियाघर के निदेशक से अनुरोध किया था । चिड़ियाघर के अधिकारियों ने (जिनमें चिड़ियाघर के अवैतनिक पशु-चिकित्सा सलाहकार भी शामिल थे) हथनी की तत्काल जांच करके फर्म को सुझाव दिया कि ऐसे मामले में, जबकि एक टांग में विवत अस्थिभंग (कमपाउंड फ्रेकचर) हो गया हो और जिसका उस अवस्था में उपचार नहीं हो सकता हो, मानवीय ढंग से मार देना ही एक मात्र उपाय है । अब इस हथनी की मृत्यु हो चुकी है ।

(ग) सरकार के पास हिसार के डाक्टरों के मत के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं है ।

(घ) जी हां ।

दिल्ली की सी० एस० पी० कालोनियों में हाऊस टैक्स लगाना

3050. **श्री राम निरेश कुशवाहा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चारों काम्युनिटी सर्विस पर्सनल कालोनियों को दिल्ली नगर निगम को दिया गया है और निगम ने इन कालोनियों के निवासियों पर हाऊस टैक्स लगा दिया है ;

(ख) क्या इन कालोनियों के निवासी अब तक इन मकानों के मालिक नहीं हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण को मासिक किस्तों पर भुगतान कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा कालोनियों को अपने अधीन लेने के बारे में सही स्थिति का पता लगाया जा रहा है । यह सूचित किया गया है कि नगर निगम उनकी सम्पत्ति पर गृहकर लगा रहा है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन मकानों का आवंटन किराया आधार पर किया गया था । दिल्ली विकास प्राधिकरण विनियमों के अनुसार समस्त मासिक किस्तों की अदायगी करने के बाद हस्तान्तरण विलेख निष्पादित किया जाएगा ।

(ग) उपयुक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

Subernarekha Multi Purpose irrigation and flood control project

3051. SHRI S. KUNDU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the details of Subernarekha Multi purpose irrigation and flood control project;

(b) how much of flood water will be controlled at Jaleswar in Orissa and at further down stream of the Subarnarekha river;

(c) whether any construction work of a Dam at Chandil on this river has been started, if so, details thereof; and

(d) whether the scheme has been sanctioned and what is the financial implication on the three States of Bihar, Orissa and West Bengal?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The Subarnarekha Multipurpose Project of Bihar envisages the following works:

(i) A masonry dam on the Subarnarekha river near Chandil.

(ii) An earth dam near Icha on Kharkai, a tributary of Subarnarekha.

(iii) Two barrages—one on Subarnarekha near Galudih and the other on Kharkai near Bhua.

(iv) Canal system from the two dams and the two barrages. The scheme, estimated to cost about Rs. 129 crores, envisages annual irrigation to an area of 2.185 lakh hectares, regulated supply for meeting the industrial and drinking water requirements in Bihar areas and flood moderation benefiting West Bengal and Orissa areas.

(b) A flood storage of about 493 million cubic meter has been proposed in Chandil reservoir out of a gross storage of 2000 million cubic meter. No. flood storage has been provided in the reservoir on Kharkai. It is estimated that a peak flood of 0.20 lakh cumecs will be moderated at Jaleswar except in rare case of synchronisation of peak floods of Subarnarekha and Kharkai.

(c) The work on this project has not yet started.

(d) Clearance of the project will be considered after an overall agreement is reached between the concerned States, namely, Bihar, Orissa and West Bengal. An agreement has been reached between Bihar and Orissa. An understanding at officers' level between Bihar and West Bengal has also been reached on the use and development of some of the river basins common to the two States including Subarnarekha. This is being examined in consultation with the two States and the Damodar Valley Corporation as the agreement involves use and development of Damodar waters. The financial implications will be decided after the final agreement is reached.

Agricultural Scientists Recruitment Board

3052. SHRI R. L. KUREEL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Government have taken all necessary precautions/steps to ensure and uphold the independence of the Agricultural Scientists Recruitment Board; and

(b) if so, whether the Minister (President of I.C.A.R.) issued any directives in this behalf?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. Orders have been issued that the Agricultural Scientists Recruitment Board being an independent body appointed to assist the Indian Council of Agricultural Research, is to be treated in the same way as the Union Public Service Commission and that there should be no interference with its functioning.

Dealings of F.C.I. Officials with Farmer

3053. SHRI CHAND RAM: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the price of wheat has fallen below the support price announced by Government;

(b) whether the officials of Food Corporation of India in connivance with the traders are cheating the farmers by way of rejecting the wheat and allowing traders to buy at low price; and

(c) if so, the remedial steps taken to ensure fair dealings with farmers?

1421 LS—4.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The support price of Rs. 110/- per quintal announced by the Government is for fair average quality of wheat and the Government procuring agencies ensure that the price for fair average quality does not fall below this level.

(b) and (c). No, Sir. However, senior officers of the Food Corporation of India are keeping a constant watch on the procurement operations with a view to eliminating any chances of malpractices on the part of its staff.

ग्रौराई सहकारी चीनी मिल वाराणसी को ग्रौर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि

3054 **श्री नरसिंह यादव** : क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रौराई सहकारी चीनी मिल वाराणसी, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1976–77 ग्रौर 1977–78 में किसानों से कितना गन्ना खरीदा गया, किसानों को कितने गन्ने का मुल्य दिया गया है ग्रौर कितने किसानों को गन्ने का मुल्य नहीं दिया गया है ग्रौर ऐसी राशि कितनी है तथा यह किन कारणों से किसानों को नहीं दी गई है तथा यह राशि उन्हें कब तक दी जायेगी ;

(ख) क्या उक्त मिल मुनाफे में चल रही है ग्रथवा घाटे में, यदि मिल घाटे में चल रही है तो उसे प्रतिवर्ष कितना घाटा हो रहा है ; ग्रौर

(ग) इस मिल को मुनाफा हो, इसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मिल ने 1976–77 में 8.95 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा था;

1977–78 मौसम अभी शुरू होना है । 8.60 लाख क्विंटल के मुल्यों का भुगतान किया जा चुका है । 904 किसानों को गन्ने का मुल्य नहीं दिया गया है और उनको 4.2 लाख रुपयों का भुगतान किया जाना है । मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों में गिरावट आने के कारण पैसे की कमी होने से भुगतान नहीं किया जा सका; जैसे ही पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, मुल्यों का भुगतान कर दिया जाएगा ;

(ख) यह मिल हानि पर चल रही है । मिल वर्ष 1971–72 से कार्य कर रही है और उसे प्रत्येक वर्ष हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है ।

वर्ष	हानि लाख रुपयों में
1971–72 . .	35.64
1972–73 . .	53.61
1973–74 . .	61.27
1974–75 . .	47.63
1975–76 . .	43.86
	242.01 (अस्थाई । इसकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई)

उपर्युक्त आंकड़ों में मिल्स की स्थायी परिसम्पत्ति पर मूल्य ह्रास के लिए व्यवस्था भी शामिल है जोकि 112.21 लाख रुपये बैठती है ।

(ग) एक पंचवर्षीय सघन गन्ना विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें विशेष रूप से सिंचाई संसाधनों में वृद्धि करने, गैर मंजूरशुदा गन्ने की किस्मों की प्रतिस्थापना करने और फैक्ट्री के दरवाजे से 32 किलोमीटर की परिधि में अधिक मात्रा में उर्वरकों के इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है । इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि गन्ने की पिराई से संबंधित सामान्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

Centres/Schools in I.I.T. Delhi

3055. DR. RAMJI SINGH: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) what are the separat budget arrangements of the different Centres/Schools created by the Board of Governors in the I. I. T. Delhi;

(b) what is their output in terms of applied research for the nation;

(c) whether these Centres/Schools are mentioned for exchanging foreign visits; and

(d) if not, whether Government propose to place on the Table of the House the contributions made by the different Heads of the Departments in I. I. T.?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) A statement is attached.

(b) The work done in these Centres and Schools has been utilised in fields like electronic systems, microwave components, bio-chemical engineering, radar systems, instrumentation, and bio-medical engineering.

(c) The Centres/Schools are meant for carrying out inter-disciplinary research activities. For the development of two Centres, there are collaboration programmes with the Swiss and Norwegian Governments which include exchange of visits. In the case of other Centres/Schools the need

for exchange of visits is taken care of under other approved programmes.

(d) Heads of the Departments/ Centres/Schools are appointed for a specified period from among the Professors. The research papers, books published by the Heads of Departments and other faculty members of the I. I. T., Delhi during 1974-75, 1975-76 are mentioned in the Annual Reports of 1974-75 and 1975-76 of I. I. T., Delhi which were placed on the Table of the House on 12-1-1976 and 3-11-1976 respectively.

Statement

The Board of Governors of the I.I.T. Delhi allocates provision for the Centres and Schools and reappropriates funds from one Head to another as and when need arises. The provision allocated by the Board for 1976-77 and 1977-78 is as under:

(*Rs. in lakhs*)

Name of the Centre/School	Allocation 1976-77		Allocation 1977-78	
	Recurring	Non-recurring	Recurring	Non-recurring
1. Centre for Energy Studies	..	..	12·00	30·00
2. Industrial Tribology Machine Dynamics & Maintenance Engg. Centre	1·50	3·50	1·55	3·50
3. Bio-Chemical Engg. Research Centre	2·21	1·43	2·48	1·20
4. Bio-Medical Engg. Research Centre	2·00	0·80	2·39	0·50
5. Instruments Design Development Centre	7·47	2·50	7·49	2·00
6. Computer Centre	7·50	8·64	7·03	1·50
7. School of Material Science & Technology	1·80	2·50	2·07	1·50
8. School of Systems & Management Studies	1·00	0·30	1·12	..
9. School of Bio-Sciences	0·75	0·40	0·91	0·30
10. Centre for Applied Research in Electronics	..	..	2·05	..

(Funds are provided by Ministry of Defence & Ministry of Railways.)

Grants to Krishak Samaj

3056. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the total grants given to Krishak Samaj in various States during the period 1975—77 (Financial years);

(b) whether the amounts have been properly utilised;

(c) whether any report has been received by the Government against any Political Party for the misappropriation of this amount; and

(d) whether the accounts of the above grants are being audited regularly, if so, whether any irregularities have been found therein?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (d). Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha, as soon as it is received from the State Governments.

भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, नामकुम, रांची

3057. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अधीन नामकुम, रांची स्थित भारतीय लाख अनुसन्धान संस्थान के कर्मचारियों में वहां पर व्याप्त प्रशासनिक कुप्रबन्ध, पक्षपात और अनियमितताओं के कारण असन्तोष और घबराहट है जिसके परिणामस्वरूप अनुसन्धान कार्य अस्त-व्यस्त हो गया है ;

(ख) क्या उक्त संस्थान के कुछ आदिवासी कर्मचारियों को एक वर्ष पहले ही सेवानिवृत्ति कर दिया गया है और क्या ऐसा करना सरकारी सेवा नियमों के अनुकूल है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मृत कर्मचारी, श्री महादवउरांव, जिससे सेवा के दौरान उसकी मृत्यू के पश्चात्-सेवा-निवृत्ति से पहले की तारीख से ही सेवा-निवृत्त कर दिया गया और उसकी विधवा पत्नी को तीन वर्षों से अपने पति की भविष्य निधि लेखा आदी की राशि का भुगतान न करके भूखा मरने को विवश होना पड़ रहा है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि निदेशक नियमों के विपरीत अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करते हुये अपना वेतन ले रहा है और अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी संस्थान में बना हुआ है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर 'हाँ' है तो क्या सरकार वहां व्याप्त घोर प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु जांच करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) लाख अनुसंधान संस्थान रांची के मामलों से संबंधित शिकायतों की विस्तार से जांच की गई है । उस संस्थान में कोई कुप्रबन्ध नहीं है और न पक्षपात तथा अनियमितताओं के ही कोई उदाहरण सामने आये है । कर्मचारियों में भी किसी प्रकार का आतंक नहीं है कुछ कर्मचारी इस संस्थान से तबादले के कारण असन्तुष्ट है और वे झूठी अफवाहें फैला रहे है और संस्थान के निदेशक के विरुद्ध गलत आरोप लगा रहे है जिसके परिणामस्वरूप वहां के अनुसन्धान कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा मालूम पड़ता है ।

(ख) संस्थान का कोई आदिवासी अथवा अन्य कर्मचारी, सेवा निवृत्ति की नियत तिथि के पहले सेवा निवृत्त नहीं किया गया है और इस विषय पर नियमों के अनुसार ही सेवा निवृत्ति की गई है ।

(ग) इस संस्थान में सेवारत एक मजदूर, श्री महादेवउरांव को 20-1-1974 को सेवा निवृत्त होना था किन्तु कार्यालय की एक गलती के कारण वह 13-12-1974 तक कार्य करता रहा । सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद का उसका सेवाकाल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नियमित कर दिया गया । कुछ प्रशासनिक देरी के कारण उसकी भविष्य निधि का हिसाब अभी तक तय नहीं किया गया । इस कार्य के लिए उत्तरदायी अधिकारी से जवाब तलब किया जा रहा है और उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । निदेशक को आदेश जारी किये गये है कि उसकी भविष्य निधि और दूसरे हिसाब तत्काल तय कर दें ।

(घ) निदेशक को, कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा 1975 में चुना गया था और उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के अनुसार तत्कालीन कृषि तथा

सिंचाई मंत्री की स्वीकृति से उस पद पर नियुक्त किया गया था । उनका वेतन वित्त मंत्रालय के परामर्श से तय किया गया था और इस संबंध में किन्हीं भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है । संस्थान में उनका कार्यकाल (टर्म) अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) इस संबंध में पहले ही जांच की जा चुकी है । संस्थान में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं पाया गया ।

बिहार में तटबंध का निर्माण

3058. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा की बाढ़ से बचाव के लिए बिहार में बक्सर से कोयलवार तक 104 किलोमीटर लम्बे तटबन्ध का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) क्या तटबंध का निर्माण-कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ;

(ग) क्या न तो उक्त प्रयोजन के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए अब तक मुआवजा ही दिया गया है और न ही विस्थापितों को अपने मकानों के निर्माण के लिये भूमि आवंटित की गई है ;

(घ) क्या यदि बारिश शुरू होने से पहले तटबंध पूरा नहीं होता है तो न केवल तटबंध के लिए डाली गई मिट्टी ही बह जाएगी, बल्कि इसके परिणामस्वरूप आस पास के ग्रामों के निवासियों को भी भारी क्षति होगी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नदी में बाढ़ आने से पूर्व ही तटबंध का निर्माण पूरा करने और ग्रामवासियों को मकान बनाने के लिए स्थान देने और मुआवजा देने का है ;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ङ) बिहार सरकार ने 10.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बक्सर से कोइलवार तक एक तटबंध बनाने के लिए एक स्कीम तैयार की है । इस स्कीम में गंगा के दक्षिणी किनारे पर 96 किलोमीटर तक, सोन और गंगा के संगम से कोइलवार तक सोन के पश्चिमी किनारे के साथ 11 किलोमीटर तक, गंगा (पश्चिमी) के दोनों किनारों के साथ 20 किलोमीटर तक और गंगी (पूर्वी) के दोनों किनारों के साथ 38 किलोमीटर तक, तटबधों का निर्माण परिकल्पित है । इस स्कीम से 79,000 हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलने की आशा है । यह स्कीम योजना आयोग द्वारा मई, 1973 में मंजूर की गई थी और इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

श्रमिकों की मजदूरी में और सामग्री की लागतों में वृद्धि हो जाने के कारण बक्सर-कोइलवार तटबंध स्कीम की अब अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रुपए आंकी गई है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्कीम की लागत में इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और पटना बाढ़ सुरक्षा स्कीम के तात्कालिक कार्यों के निर्माण के कारण भी इन दोनों स्कीमों के बीच भी तटबधों की विभिन्न पहलुओं के निर्माण-कार्यों की प्राथमिकताएं दुबारा निर्धारित करना आवश्यक हो गया है । बक्सर-कोइलवार स्कीम का निर्माण 1973–74 में शुरू किया गया था और यह संभावना थी कि यदि धन उपलब्ध हो जाता है तो यह स्कीम पांच वर्ष में पूरी हो जाएगी । लेकिन धन की तंगी के कारण 1976–77 तक केवल 429 लाख रुपए ही खर्च किए जा सके । 1977–78 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 200 लाख रुपए है । अब इस स्कीम का 1980–81 में पूर्ण हो

जाने की संभावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो जाए । इस प्रकार के इतने बड़े तटबंधों के लिए यह जरूरी है कि इनका निर्माण चरणों में किया जाए और निर्माण के दौरान कार्यों को सुरक्षात्मक तरीकों से करने के लिए उपयुक्त सावधानियां और उपाय किए जाऐं ।

चूंकि बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का आयोजन और कार्यान्वयन राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, प्रभावित लोगों को अधिगृहण की गई भूमि का मुआवजा देना तथा घरों के लिए जमीन का आबंटन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । इस बारे में केन्द्र के पास कोई जानकारी नहीं है ।

मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना

3059. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सारे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए मातृ भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : ऐसी कोई योजना नहीं है । शिक्षा मुख्य रूप से राज्य का विषय है और इस मामले में कार्यवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को है ।

Import of Tractors

3060. SHRI P. M. SAYEED: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the present Government intend to import tractors to meet the demands for the same; and

(b) if so, from which country and their number?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Supply of electricity for domestic use

3061. SHRI R. K. AMIN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to supply electricity for domestic use to the resident of Sultanpuri Resettlement Colony;

(b) if so, the reasons for stoppage of work regarding laying of cables; and

(c) when Government propose to restart the work?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) The work has not started yet since financial arrangements have not been sorted out.

(c) Does not arise as the work has not started yet.

राजस्थान में चावल मिलरों द्वारा चावल के बारदाने की दर निर्धारित करना

3062. **श्री मीठा लाल पटेल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चावल मिलर लेवी चावल के मामले में बारदाने की दर प्रति क्विंटल की दर में निर्धारित करते हैं

जबकि सरकारी आदेशों के अनुसार एक बोरे में वास्तव में 95 किलो चावल भरा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बारदाने में कम की गई रकम का किसानों को भुगतान कराने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या लेवी वसूली वाले अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की नीति है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राजस्थान के चावल मिल मालिकों द्वारा जिन खाली बोरियों में लेवी चावल बेचा जाता है वे उनकी दरें निर्धारित नहीं करते है । मिल मालिकों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए सुपुर्द किए गए चावल की खाली बोरियों की प्रति क्विंटल दरें, बोरों में 95 किलोग्राम चावल भरने की क्षमता को ध्यान में रखकर, सरकार द्वारा त्रैमासिक आधार पर निर्धारित की जाती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यह प्रथा लेवी वसूली वाले अधिकांश राज्यों में भी अपनाई जाती है ।

Ceiling on Agricultural Land

3063. SHRI DHARAM VIR VASISHT: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the ceiling on agricultural land was fixed by the former Government on other considerations than the expert advice of leading agricultural experts including Punjab and Haryana Agricultural Universities;

(b) whether no marked rise in Agricultural production has taken place as a result of lowering of ceiling of agricultural land; and

(c) whether Government propose to review the results of the policy?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Fixing the ceiling on agricultural and holdings lies entirely with the State Governments. However, on the basis of the recommendations made by a conference of the Chief Ministers of the States held in 1972, the Central Government issued national guidelines on ceiling on agricultural land holdings suggesting among others the various levels of ceiling applicable to various categories of land. In framing the guidelines, all relevant factors including the social and economic were taken into consideration. Keeping in view the fact that the recommendations flowed from the consensus amongst Chief Ministers of the States, it was not considered necessary to invite and examine the expert advice of agricultural experts including Punjab and Haryana Agricultural Universities.

(b) and (c). As agricultural production is affected by a number of factors such as cultivated area, irrigation, inputs like fertilisers, improved seeds, adoption of improved technology, land reforms, price policy and weather, it is not possible to give a precise quantitative idea of the effect of a single factor such as lowering of ceiling of agricultural land on production. It may be, however, mentioned that since 1972-73, despite fluctuations from year to year, the agricultural production has registered a generally increasing trend as will be seen from the following figures:

Index number of agricultural production

(Base : Triennium ending 1961-62= 100)

1972-73	120·4
1973-74	133·3
1974-75	128·6
1975-76	148·6

(For 1976-77 firm estimates of production are not yet available. However, the total production is likely to fall compared to 1975-76, nevertheless it is likely to remain higher than in any of the other preceding years).

The fundamental justification of ceilings on agricultural holdings is more equitable distribution of land resources. A number of persons who had no land or very little land were to be allotted ceiling surplus lands and thereby enabled to improve their incomes. The ceiling law is basically an instrument of social justice and there is no proposal to review it.

Famine-like condition in Andaman and Nicobar Islands

3064. SHRI MANORANJAN BAKHTA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that due to heavy crop failure this year famine-like conditions prevail in the rural areas of Andaman and Nicobar Islands, and if so, the reliefs provided to the farmers;

(b) whether a Kilo of rice is sold at Bakultalah, Middle Andamans at the rate of Rs. 5/-, if so, action taken to bring down the prices; and

(c) whether pesticide supplied by Agriculture Department last year was of inferior quality and resulted in large scale uncontrollable pest attack and if so, the measures taken during this year?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). The information has been called for from the Union Territory Administration which is still awaited. It will be laid on the Table of the Sabha when received.

Forest Corporation for Andaman and Nicobar Islands

3065. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to implement the proposed Forest Corporation for Andaman and Nicobar Islands expeditiously and if so, main feature thereof;

(b) the programme to be undertaken for the year 1977-78; and

(c) whether proposed Plantation Corporation for Andaman and Nicobar Islands is likely to be set up?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Ltd. with an approved outlay of Rs. 1.70 crores in two years in the first phase had already been set up in January, 1977 under the Companies Act, 1956. It aims at harvesting of forest resources of the Islands to the maximum extent, marketing of timber and other forest products and re-stocking of harvested areas with valuable species with artificial and natural regeneration and promoting the setting up of wood based industries.

(b) During 1977-78 it is proposed to extract 15,000 Cum of timber.

(c) The Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation will handle both plantation and forest operations. Action is being taken to establish Red Oil Palm Plantation Corporation as a subsidiary of the said Andaman & Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation.

Central AID for Dairy Development in Orissa

3066. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the State Government of Orissa has approached the Central Government to seek financial assistance for the dairy development in the Orissa State; and

(b) if so, quantum of the help given by the Central Government as well as by the World Bank in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). No proposal for dairy development has been received from the State Govt. of Orissa by the Central Government. Provision is, however, available for dairy development in the State under a Central Sector Scheme.

Merit-cum-Means Scholarships

3067. SHRI SHANKER SINHJI VAGHELA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the number of merit-cum-means scholarships awarded by the Central Board of Secondary Education, New Delhi in 1976-77 to meritorious boys in the Higher Secondary Examination, 1976;

(b) the names of students whom this scholarships have been awarded;

(c) the particulars about the scholarships;

(d) the criteria of determining the eligibility for the award of this scholarship; and

(e) whether all those to whom the scholarships have been awarded since been paid the amount of scholarship?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) In 1976-77, 70 students have so far been selected by Central Board of Secondary Education for award of Merit-*cum*-Means Scholarships under the National Scholarships Scheme of the Ministry of Education administered through the State Government/UT Administrations. The Examining Bodies make the provisional selection of students on Merit-*cum*-Means basis and furnish the list to the State Governments/Union Territory Administrations.

(b) A list is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-663/77].

(c) The National Scholarships are awarded on Merit-*cum*-Means basis on the results of the Final School leaving Examinations and are tenable till the completion of 1st degree course;

(d) the main criteria of eligibility is:—

(i) Parents income should not exceed Rs. 500/- per month.

(ii) The candidates should not be in receipt of any other scholarship.

(iii) Candidates should be pursuing further studies in recognised colleges/institutions of India.

(e) Responsibility for payment of scholarship is that of the State Government or the Union Territory Administration from whose jurisdiction the student has passed the examination on the basis of which he has been awarded the scholarship. Information about actual payment is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Rules for Admission to Kendriya Vidyalayas

3068. SHRI SHANKER SINHJI VAGHELA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have changed rules for the admission to Kendriya Vidyalayas;

(b) if so, the particulars thereof;

(c) whether there is great rush for admission to Kendriya Vidyalayas; and

(d) whether there is any proposal to increase the number of these schools, and if so, to what extent?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Yes Sir. The rules for admission to Kendriya Vidyalayas have been revised from the current academic session.

(b) Subject to the candidate qualifying in the admission test, the criterion of admission shall be the number of times the parent has been transferred during the preceding seven years. Children of Civilians in defence Sector and defence personnel in civilian sector are all eligible for admission to these schools.

(c) Yes Sir, particularly in matropolitan cities.

(d) Every year the Sangathan starts 12 new Kendriya Vidyalas (8 in Defence Sector and 4 in Civil Sector). In addition, the Kendriya Vidyalayas are also opened in Campuses of Govt. of India Undertakings if they agree to bear the entire expenditure on them.

Gujranwala House Building Cooperative Society, Delhi

3069. SHRI RAM KANWAR BERWA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the total amount at the disposal of the Gujranwala House Building Cooperative Society, Delhi as on 31st March, every year since 1975, the amount spent by the Society every year and the purpose for which the amount was spent;

(b) the amount spent on development of land in Part I, Part II and likely to be spent on the development of additional land; and

(c) when the development of additional land is likely to be completed and allotted to the Members of the society?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHAT): (a) to (c). Information is being collected.

दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने अधिकार में लिए गए दिल्ली नगर निगम के स्कूल

3070. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नगर निगम के कितने स्कूल अपने अधिकार में लिए हैं;

(ख) इसके कारण कितने शिक्षकों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या इन सभी शिक्षकों को इस बीच स्थायी कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्दर चन्दर) : (क) 4131

(ख) 5613 अध्यापक ।

(ग) और (घ). 3563 अध्यापक पहले ही स्थायी हैं । 50 अध्यापकों के शेष मामले विचाराधीन हैं ।

Cotton Production

3071. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the targets fixed and actual production of cotton each year during the current five-year Plan;

(b) whether any time-bound national programme has been drawn up for increasing the per acre yield; and

(c) if so, facts thereof and how and where it is being implemented?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The information is given below:

Year	Target	Production
	(lakh balses of 170 Kgs. each)	
1974-75 . . .	72·00	71·55
1975-76 . . .	72·00	61·01
1976-77 . . .	75·00	Official estimates not yet available.

(b) and (c). In order to supplement the efforts of the State Government in increasing the per acre yield and also the total cotton production, so as to achieved the targeted production of 80 lakh bales at the end of the Fifth Plan, a Centrally Sponsored Scheme of Intensive Cotton District Programme is being implemented. During the Fifth Plan this scheme is in operation in the important cotton-growing States of Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesn, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Orissa and West Bengal. Under this Scheme, besides giving 100 per cent assistance for the appointment of staff, the Govment of India is giving subsidy for strengthening cotton seed multiplication programme, production of nucleus and foundation seed, hybrid seed production, plant protection equipments, *Kapas* grading centres, demonstration, etc. In addition, an Integrated Cotton Development Project with the assistance of the World Bank is also being implemented during the Fifth Plan in the States of Punjab, Haryana and Maharashtra. On the recommendations of the Special Group on Cotton, Edible Oilseeds and Pulses, Government of India are considering a scheme for suitably subsidising the operational charges for aerial spraying of pesticides, particularly for the benefit of small and marginal farmers, during the current season. Besides, the existing Intensive Cotton Distt. Programme is proposed to be further extended to 7 new rainfed districts, for producing mainly medium staple cotton.

Import of Foodgrain Under PL-480

3072. SHRI VAYALAR RAVI:
SHRI N. SREEKANTAN NAIR:
SHRI K. KUNHAMBU:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Government have decided to stop the import of foodgrain under PL-480;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the total quantity of foodgrain so far imported under PL-480?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). There is no proposal for the import of foodgrains from U.S.A. under PL-480 arrangement during the current year.

(c) The total quantity of foodgrain imported under PL-480 between 1956 and 1976 is of the order of about 59.4 million tonnes.

Poor People Living on Pavements in Big Cities

3073. SHRI VAYALAR RAVI:
SHRI N. SREEKANTAN NAIR:
SHRI K. KUNHAMBU:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether millions of poor people are still living on pavements in big cities of India;

(b) if so, the total estimated number of such poor people in cities (Corporations); and

(c) the steps proposed to be taken to provide housing facilities to them?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b). No up-to-date statistics of the number of people living on pavements in cities are available.

(c) The State Governments and local bodies are competent to formulate projects for providing accomodation to the shelterless people by constructing night-shelters as has been done by the Municipal Corporation of Delhi.

Alternative Plots to Plot Holders in Loni Residential Area

3074 SHRI KACHRULAL HEMRAJ JAIN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government are considering to give alternative plots to those plot holders who were allotted plots of land in Loni residential area and in whose case some dispute has arisen with the original owners of the land in Pitampura Residential Scheme where plots are available and where for allotment of plots of land, new applications have been invited; and

(b) if so, the particulars thereof and if not, the particular reasons when plots are available in Pitampura Residential Scheme and these poor low income group people have already paid full amount of the plot more than a year back and even the lease has also been executed?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). The matter is under consideration.

Representation by S.C./S.T. Employees for Promotion of National Seeds Corporation

3075. SHRI MAHI LAL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1002 on the 20th June, 1977 regarding percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in National Seeds Corporation and state:

(a) whether some employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in National Seeds Corporation made representations for promotion and they were being neglected in spite of availability of due opportunities for their promotion; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Two employees of the National Seeds

Corporation belonging to the category of Scheduled Castes have made representations for promotion. In one case an employee belonging to the Scheduled Castes on promotion was posted to Ahmedabad. He represented that he was unwilling to leave Delhi; as such the promotion could not materialise. It is not always administratively feasible to post persons to stations of their choice. A second representation from a Scheduled Caste employee of the Corporation was against his not having been selected for the post of Assistant Seeds Officer. Promotion to this category of posts from the next lower grade can be made irrespective of the employee's interest seniority, on the basis of merit subject to his meeting certain standards which have been prescribed. The employee did not meet up to these standards. He would be eligible for consideration on—

(i) attaining the minimum standards.

(ii) in the normal course on attaining adequate seniority.

(b) As the claims and representations of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees are given due consideration, the question does not arise.

विदेशों में बसे भारत मूलक छात्रों को सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां

3076. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में बसे भारत मूलक छात्रों को इस समय कितनी सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां दी हुई हैं और किस किस देश में कितनी कितनी; और

(ख) ऐसे कितने तथा कहां कहां के छात्रों को मैडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश प्राप्त है और उन्हें अन्य क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) और (ख). सामान्य सांस्कृतिक, राष्ट्रमंडल और पारस्परिक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेश मंत्रालय के परामर्श से कुछ विशिष्ट देशों के विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं । यद्यपि, अधिकांश छात्रवृत्तियां देशी मूल के विदेशी छात्रों को प्रदान की जाती हैं, तथापि कुछ छात्रवृत्तियां इन देशों में स्थायी रूप से बसे भारतीय मूल के छात्रों को प्रदान की जाती हैं । इस समय भारत में अध्ययन कर रहे उन छात्रों की संख्या जो भारतीय मूल के हैं तथा विदेश में बसे हुए हैं, के सम्बन्ध में सूचना नीचे गई है :

क्रमसं०	देश का नाम	विदेशों में बसे भारतीय मूल के छात्रों को इस समय दी गई सांस्कृतिक छात्रवृत्तियों की संख्या	ऐसे छात्रों की संख्या जिनको निम्नलिखित कालेजों में दाखिल किया गया है ।	
			इंजीनियरी कालेज	मेडिकल कालेज
1	2	3	4	5
1	बारब्राडोस	1	—	1
2.	कनाडा	1	—	—
3	श्री लंका	9	5	—

1	2	3	4	5
4.	फिजी	15	5	8
5	गुयाना	15	—	12
6	केनिया	4	—	4
7	मलेशिया	23	3	18
8	मारिशस	45	10	15
9	सिंगापुर	7	3	—
10	दक्षिण अफ्रीका	30	1	28
11	तंजानिया	4	—	3
12	थाईलैंड	8	2	6
13	त्रिनिडाड	1	—	1
14	यूगांडा	1	—	1
15	ब्रिटेन	1	—	1
	कुल	165	29	97

अवर स्नातक पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को प्रति माह 400 रुपये की दर से तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रति माह 500 रुपये की दर से अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है । इस के अतिरिक्त, छात्रों को वास्तविक शिक्षा शुल्क, अन्य अनिवार्य शुल्क, परीक्षा शुल्क, पुस्तक भत्ता, अध्ययन भ्रमण खर्च, ग्रीष्मावकाश के दौरान की गई यात्रा के लिए रेल गाड़ी भाड़े की प्रतिपूर्ति, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, ग्रीष्म शिविर तथा कुछ विनियम कार्यक्रमों के मामले में किफायती दर्जे से यात्रा व्यय (दोनों तरफ) जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है ।

Entry Tickets for seeing Historical Monuments

3077. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether in most of the cities there is a ticket to see the old Historical monuments which is beyond the approach of common man due to which a number of visitors are deprived of seeing the important Historical places; and

(b) if so, whether Government propose to exempt the people from this ticket system and make it free?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) In accordance with the Rules framed under Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, an entrance fee of fifty paise is charged from the visitors at 26 centrally protected monuments. On Fridays no such fee is charged. Persons upto the age of fifteen years are, however, exempted from the payment of the entrance fee.

(b) At present, there is no proposal to stop the levy of entrance fee at these monuments.

राजस्थान नहर परियोजना

3079. **श्री लालजी भाई** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर परियोजना के संबन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसकी शुरूआत से अब तक वर्षवार इस पर कितना धन व्यय किया जा चुका है ; और

(ग) भारत को इस धन में से कितना धन विदेशों अथवा विदेशी संस्थाओं से मिला है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राजस्थान नहर, जिसका उद्देश्य राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भाग में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करना है, हरि के बराज से निकलती है और इसे ब्यास नदी पर बने पोंग बांध द्वारा संचित जल से जल की सुनिश्चित सप्लाई प्राप्त होगी। हरि के बराज और पोंग बांध दोनों बन कर तैयार हो चुके हैं।

राजस्थान नहर का निर्माण, जिसकी अनुमानित लागत 396 करोड़ रुपए हैं, दो चरणों में किया जा रहा है। चरण-एक के अन्तर्गत अधिकांश निर्माण-कार्य पूरे हो चुके हैं, जिन में राजस्थान फीडर का 204 किलोमीटर लम्बा भाग, राजस्थान मुख्य नहर का 189 किलोमीटर भाग, लिफ्ट नहर का 152 किलोमीटर भाग और वितरण प्रणाली का 2900 किलोमीटर भाग शामिल है। अपर वितरण प्रणाली, पुंगल शाखा प्रणाली और और मुख्य नहर के 135 से 189 किलोमीटर तक के भाग की लाइनिंग करने का काम चल रहा है। पूरा विकास होने पर 5.94 लाख हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता का सृजन होगा। इस की तुलना में 4.43 लाख हैक्टेयर की शक्यता का सृजन किया जा चुका है और मार्च, 1977 तक वस्तुतः 2.78 लाख हैक्टेयर की सिंचाई की गई थी। चरण-एक की 176 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की तुलना में मार्च, 1977 तक लगभग 152 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। 1977-78 के लिए 16.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

चरण-दो के अन्तर्गत भी निर्माण-कार्य शुरू किया जा चुका है। इस में मुख्य नहर के 256 किलोमीटर भाग और वितरण प्रणाली के 4000 किलोमीटर लम्बे भाग का निर्माण शामिल है। मुख्य नहर के 10 किलोमीटर और 50 किलोमीटर भाग में क्रमशः लाइनिंग और मिट्टी का काम पूरा किया जा चुका है और अनुप्रवाह पहुंचों तथा वितरण प्रणाली में भी काम किया जा रहा है। चरण-दो की 220 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की तुलना में मार्च, 1977 तक 16.50 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका था। 1977-78 के वर्ष के लिए बजट में 12.00 करोड़ रुपया रखा गया है।

(ख) राजस्थान नहर के निर्माण पर उस के शुरू से लेकर किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	व्यय (लाख रुपए)
1955-56	2.64
1956-57	2.85
1957-58	25.76
1958-69	78.76
1959-60	577.81
1960-61	662.09
1961-62	785.78
1962-63	655.41
1963-64	494.19
1964-65	530.57
1965-66	454.11
1966-67	497.00
1967-68	299.01
1968-69	631.70
1969-70	799.12
1970-71	739.29
1971-72	939.06

1	2
1972–73	1101.30
1973–74	1196.60
1974–75	1643.94
1975–76	2236.45
1976–77	2462.00
कुल	16,815.95

(ग) राजस्थान नहर परियोजना के इंजीनियरी-कार्यों के निर्माण के लिए विदेशों विदेशी संगठनों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई डी ए) ने राजस्थान नहर कमान क्षेत्र के विकास के लिए 830 लाख डालर का एक ऋण दिया था, जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा 31–5–1977 तक 264 लाख डालर की प्रतिपूर्ति की गई थी।

प्राचीन कठपुतली संघ को वित्तीय सहायता

8080. **श्री लालजी भाई :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "प्राचीन कठपुतली संघ" शादीपुर डिपो के सैकड़ों राजस्थानी हस्तकला कलाकारों ने वित्तीय सहायता अथवा अनुदान के लिए सरकार को ज्ञापन दिए हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत की प्राचीन कठपुतली कला और और राजस्थानी कठपुतली हस्तकला कलाकारों को खत्म नहीं होने देने के लिए कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) जी, नहीं। तथापि जुलाई, 1976 में प्राचीन कठपुतली संघ, नई दिल्ली से कठपुतली कला में कठपुतली व प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। संघ का अनुरोध संगीत नाटक अकादमी के विचारार्थ भेज दिया गया था। अकादमी ने इस पर संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया तथा संघ को एक नई परियोजना प्रस्तुत करने की सलाह दी जो अभी संघ से प्राप्त होनी है।

(ख) और (ग).—संगीत नाटक अकादमी ने भारत में कठपुतली कला के संरक्षण तथा प्रोत्साहन के लिये विभिन्न कदम उठाए हैं। उन्होंने प्राचीन कठपुतली संघ नई दिल्ली को वित्तीय सहायता भी दी है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

I. भारत में कठपुतली कला के संरक्षण तथा प्रोत्साहन के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) अकादमी द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह प्रकट हुआ है कि देश के विभिन्न भागों में कठपुतली कला की विभिन्न किस्में विद्यमान हैं।

(ii) परम्परागत कठपुतली कला की लगभग सभी किस्मों का प्रलेखन हो चुका है। अकादमी के अभिलेखागार में परम्परागत कठपुतली कला की सभी किस्मों की फिल्में, रंगदार-स्लाइडें, फोटो तथा फीता-अभिलेखन पड़े हुए हैं। परम्परागत छाया कठपुतली कला की चार शैलियों पर दो रोल का एक विशेष, वृत्त चित्र तैयार किया गया है।

कठपुतली कला की सभी किस्मों की द्योतक कठपुतली प्रतिमाओं का एकत्रीकरण।

(iii) कठपुतली कला की प्रोन्नति में रत कई संस्थाओं तथा व्यक्तियों को विशेष प्रयोगों के लिए अनुदान दिए गए हैं।

(iv) परम्परागत प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण तथा प्रोत्साहन के लिए अकादमी की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत, कठपुतली कला की दो किस्मों केरल की "पवा कुठी" तथा उड़ीसा की "रावण छाया" को इस कला में प्रशिक्षण तथा कठपुतली नाटकों की रचना के लिए इस वर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता (क) नई कठपुतली प्रतिमाएं बनाने के लिए, (ख) इस कला में रुचि रखने वाले ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के लिए तथा (ग) आस-पास के गांवों में मुफ्त प्रदर्शन के लिए है। आगामी वर्षों में इस प्रचार की सहायता के लिए कठपुतली कला की अन्य किस्मों को भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

(v) अकादमी ने 1971 में दिल्ली में एक छाया थियेटर समारोह का आयोजन किया। उस समारोह में चार प्रकार की परम्परागत छाया कठपुतली कला का प्रदर्शन किया गया। अकादमी ने 1972 में कठपुतली थिएटर का प्रदर्शन किया जिसमें हत्थी डोरी और छड़ कठपुतली कला की प्रमुख किस्मों का प्रदर्शन किया गया।

(vi) 1972 में अकादमी ने अखिल भारतीय मुखौटों और कठपुतलियों की प्रदर्शनी में भाग लिया जिसमें परम्परागत सभी तरह की प्रतिनिधि कठपुतलियां प्रदर्शित की गई।

(vii) 1972 में आयोजित अखिल भारतीय मुखौटों और कठपुतलियों की प्रदर्शनी के अवसर पर अकादमी ने भारतीय कठपुतलीकला की विभिन्न किस्मों पर एक विवरणात्मक पुस्तिका प्रकाशित की। इस समय अकादमी द्वारा "रावण छाया" पर एक प्रबन्ध (मोनोग्राफ) प्रकाशनाधीन है।

(viii) अकादमी ने कठपुतली कला के बहुत से भारतीय और विदेशी छात्रों को अध्ययन और विषय पर सचित्र लेखन के लिए सूचना, टेप किया हुआ संगीत, फोटोग्राफ और स्लाइड भेज कर सहायता की।

II. (i) संगीत नाटक अकादमी 1969–70 से प्राचीन कठपुतली संघ, नई दिल्ली को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ब्यौरे नीचे दिये गये है :—

वर्ष	राशि (रुपये)	उद्देश्य
1969–70	3,000	अध्यापकों के वेतन के लिए।
1970–71	3,000	अध्यापकों के वेतन, वजीफे और सामग्री की लागत के लिए।
1971–72	5,000	अध्यापकों के वेतन के लिए और टेप रिकार्डर की लागत के लिए।
1972–73	2,000	कठपुतली वालों के वेतन और सामग्री खरीदने के लिए।
1975–76	2,500	संगीत वाद्य और कठपुतली सामग्री खरीदने के लिए।

1975–76 के दौरान संघ ने संगीत नाटक अकादमी से दिल्ली में "कठपुतली थियेटर व प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र" खोलने की योजना के बारे में सम्पर्क स्थापित किया, जिसमें 83,000/–रुपये का परिव्यय शामिल था। संघ के प्रतिनिधियों के साथ इस योजना पर विचार विमर्श किया गया और उनको दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए संघ को एक नई परियोजना प्रस्तुत करने के लिए सलाह दी गई। लेकिन संघ ने अकादमी को कोई नई परियोजना नहीं भेजी। तथापि, उन्होंने 1976–77 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए अकादमी को आवेदन किया। संघ से उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए अतिरिक्त सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया। संघ ने अकादमी के पत्र का कोई उत्तर नहीं भेजा।

(ii) 1974–75 के दौरान अकादमी ने दिल्ली में राजस्थान के कठपुतली वाले श्री बाबू लाल को सामग्री खरीदने और उनके प्रदर्शनों के पूर्वाभ्यास के सम्बन्ध में अन्य खर्चे के लिए विवेकाधिन अनुदान के रूप में 500/– रुपये की राशि मंजूर की।

C.B.I. Interim Enquiry Report against Ex-Chairman and Ex-Vice-Chairman and other Officers of D.D.A.

3081. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 17 on the 13th June, 1977 regarding C.B.I. inquiry against ex-Chairman and Ex-Vice-Chairman of D.D.A. and state:

(a) the details of allegations of corruption and mal-practices, in all the four matters mentioned in the answers of aforesaid question;

(b) when did C.B.I. receive the complaints against Chairman and Vice-Chairman and other officers;

(c) the names of officers and the charges against each of them;

(d) has C.B.I. given any interim report; and

(e) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon and reasons for delay in completing the inquiry?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). A statement is attached herewith.

(c) The allegations are mainly against ex-Vice-Chairman, Delhi Development Authority as mentioned in the statement attached.

(d) Yes, Sir.

(e) The details of the interim report are given in the statement attached herewith.

Statement

(a) and (c). The details of allegations of corruption and mal-practices in all the four matters mentioned in the answers of the Unstarred Question No. 17 replied to on the 13th June, 1977 regarding CBI inquiry against ex-Chairman and Ex-Vice-Chairman Delhi Development Authority.

(i) *Release of land known as Dilkush Bagh Kothi from acquisition:*

Shri Jagmohan, Vice-Chairman, DDA, illegally released requisitioned plot known as "Dilkush Bagh Kothi" measuring 2 acres on G.T. Road to one Shri Chadha of Messrs Chadha Industries of Subzi Mandi, Delhi. The release of plot was in contravention of the Land Acquisition Act, 1894.

(ii) *Non-maintenance of accounts in respect of Kichripur resettlement colonies:*

There is no account of Kichripur resettlement colonies. The Engineering Department of the Delhi Development Authority have pocketed a large amount..

(iii) *Collection of funds for the former ruling party through misuse of official position:*

Shri Jagmohan, ex-Vice-Chairman had been collecting funds for Congress Party through misuse of official position.

(iv) *Carving of additional plots in colony known as Vasant Vihar:*

Additional plots in Vasant Vihar were carved out with ulterior motives.

(b) *When did CBI receive the complaints against Chairman and Vice-Chairman and other Officers?*

The complaints mentioned above were received by the CBI in April-May, 1977.

(c) *The details of the interim report as given by the D.D.A.:*

The C.B.I. has stated that with regard to the allegations mentioned at (i) and (iv) above no meterial was forthcoming to substantiate the allegations. Hence the cases relating to these allegations have been closed.

As regards the remaining allegations, the position as stated by the C.B.I. is as follows:—

Allegation (ii): Non-maintenance of accounts in respect of Kichripur resettlement colonies:

The allegation was found to be vague and not specific enough for precise verification by the C.B.I.

Allegation (iii): Collection of funds for the former ruling party by the ex-Vice-Chairman, D.D.A.:

The allegation was found to be vague and not specific enough for precise verification by the C.B.I.

Market value of the Plot and the Building allotted to Board of Trustees of Jawahar Bhawan

3082. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 92 on the 13th June, 1977 regarding sale of Bungalow to Congress Party and state:

(a) whether Government recover the market value of the plots and the buildings allotted to the Board of Trustees of Jawahar Bhawan Trust of All India Congress Committee;

(b) if not, why not;

(c) whether Government propose to acquire them;

(d) who are the members of the trust; and

(e) who ordered to allot the aforesaid houses to the trust; was there any political pressure?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). According to existing policy, full market value is recovered from political parties for land. In respect of buildings, depreciated cost is recovered. Initially, land was allotted to Jawahar Bhawan Trust at the market rate of Rs. 598 per sq. metre (Rs. 500 per sq. yd.). Subsequently, the market rate was fixed at Rs. 149.50 per sq. metre (Rs. 125 per sq. yd.), for the reason that commercial use of the building on the site in the institutional area was not permissible.

(c) The course of action to be taken is under consideration.

(d) According to the information on record, the under-mentioned were the members of the Jawahar Bhawan Trust:

Shri D. K. Borooah

Smt. Indira Gandhi

Shri Uma Shanker Dikshit

Shri Syed Mir Qasim

Shri V. P. Naik

Shri Siddhartha Shankar Ray

Smt. M. Chandrasekhar.

(e) The allotment had the approval of the then Minister for Works and Housing.

Cultural Delegations sent Abroad

3083. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether any cultural delegations were sent abroad during the years 1975 and 1976;

(b) if so, full facts thereof;

(c) the actual and concrete benefits if any, which accrued to the country on account of the said visits; and

(d) the total cost in Indian and foreign currencies incurred in this regard?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-664/77.]

(c) The visits and performances of Indian artists and exhibitions of Indian Art and Culture abroad through our Cultural Exchange/Activities Programmes helped in presenting an image of India's cultural heritage abroad. Besides, these visits and performances are expected to have promoted mutual understanding and closer relations with foreign countries.

(d) Rs. 50,85,394.77 Indian currency. Rs. 2,38,748.00 in foreign currency.

English as Compulsory Language in Schools

3084. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to have a uniform policy regarding the teaching of English as a compulsory language in all the schools throughout the country; and

(b) if so, how and when?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). Under the 3-language formula which is in force the third language should be English. It can be introduced in Class VI or earlier or later depending on local conditions in each State.

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

3085. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष का वेतन केन्द्रीय सरकार के सचिव के वेतन के बराबर करने का है ;

(ख) क्या वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में कुछ सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है जिस से प्रत्येक विषय का हिन्दी में उच्च स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन शीघ्र हो सके ;

(ग) यदि हां, तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग को कब तक पुनर्गठित किया जाएगा तथा उस का पुनर्गठित स्वरूप क्या होगा ; और

(घ) क्या सरकार का यह भी विचार है कि, उक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपने कर्त्तव्यों के निर्वाह में संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के बराबर वेतन, भत्ता तथा स्वतंत्रता दी जाये ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) से (घ) अध्यक्ष तथा चार अंश कालिक सदस्यों की नियुक्ति करके 1975 में आयोग का पुनर्गठन किया गया था। अध्यक्ष 2500 रुपये के नियतन वेतन पर नियुक्त किए गए हैं तथा उनका पद विभागाध्यक्ष का है ।

आयोग में नियुक्त किए गए अंशकालिक सदस्यों में से तीन, चिकित्सा-शास्त्र, कृषि, तथा इंजीनियरी के विषयों में विशेषज्ञ हैं। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय इन विषयों में पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है । जब कभी भी और विशेषज्ञों तथा आयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी, सरकार निर्णय लेगी।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी और हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

3086. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान काशी नागरी प्रचारिणी संस्था वाराणसी और हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयोग को कितना अनुदान अथवा वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यह अनुदान किन-किन कार्यों के लिए दिया गया था और उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुदान के धन के उपयोग का ब्यौरा मंत्रालय को लेखापरीक्षक द्वारा प्राप्त होकर मिल गया है;

(घ) हिन्दी का कार्य करने वाली किन-किन संस्थाओं को अनुदान दिया गया था ; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की सस्थाओं को अनुदान देने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) से (ग). विवरण 1 में दिया गया है जो सभा पटल पर रखा गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया है । देखिये** संख्या एलटी–665/77] ।

(घ) शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय से अनुदान प्राप्त कर रही स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं की सूची विवरण II में दिया गया है जो सभा पटल पर रखा गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया है । देखिये** संख्या एलटी–665/77] ।

(ङ) इस मंत्रालय को "हिन्दी की उन्नति के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को सहायता" योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को अनुदान दिए जाते है । इस योजना के अन्तर्गत गैर हिन्दी भाषी लोगों के लिए निःशुल्क कक्षाएं चलाने, गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना करने, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशु लिपि की कक्षाएं चलाने, क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित करने तथा अन्य कार्यकलापों के लिए जो हिन्दी के विकास और प्रसार को और समृद्ध बनाने में सहायक हों, के लिए अनुदान स्वीकार्य है। स्वीकृत व्यय के 75 % के आधार पर

अदनुान दिए जाते हैं। निहायत विशेष मामलों में स्वीकृत व्यय के 60 प्रतिशत और अधिकतम 50,000/- रूपये के आधार पर स्वच्छिक संस्थाओं को भवन अनुदान भी स्वीकृत किए जाते है।

Memorandum from students of College of Science, Indian Veterinary Institute

3087. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the students of the Post graduate College of Animal Sciences, Indian Veterinary Institute, Izatnagar have recently submitted a memorandum urging the Government to give university status to the institute; and

(b) if so, decision taken thereon?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir. Government have received a memorandum from the students of the Post-Graduate College of Animal Sciences, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, requesting the Government to either confer Deemed University status on the Institute or affiliate it to the Rohilkhand University, Bareilly.

(b) The proposal for confering Deemed University, status to the Institute is under consideration of the University Grants Commission.

In the meanwhile, the Rohilkhand University, Bareilly, under whose territorial limits Post-Graduate College of Animal Sciences, IVRI, falls, has arranged to conduct the M.V.Sc. Examination in July, 1977.

Construction of underground Shopping Centre at Connaught Place New Delhi.

3088. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the New Delhi Municipal Committee's prestigious project for construction of an underground Shopping Centre at Connaught Place is being executed in violation of the Delhi Master Plan and without the approval of the Delhi Urban Art Commission; and

(b) if so, what action has been taken by Government in this respect?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) A report has been called for from the New Delhi Municipal Committee.

I.C.A.R. and Agricultural Scientists Recruitment Board

3089. SHRI DHARMA VIR VASIST: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether he received complaints against the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and Agricultural Scientists Recruitment Board from Indian Agricultural Research Institute, New Delhi;

(b) whether the name of the Director General, I.C.A.R. was also involved in the complaints;

(c) the action if any taken in the matter; and

(d) whether views of other institutes numbering twenty-seven were placed before and considered by Government before taking decision in (c) above?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) No complaints have been received from the Indian Agricultural Research Institute against the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) or Agricultural Scientists Recruitment Board. Representations have, however, been received from individual scientists as also from the Scientific and Technical Staff Association, I.A.R.I., New Delhi, on various matters relating to the service conditions of the scientists and technical personnel of the Institute. The major demands made in these representations are for (i) scrapping the interviews for five-yearly assessment of scientists under the Agricultural Research Service, (ii) upgradation of Grade 'S' Scientists (Rs. 550---900) to Grade S-1 Scientists (Rs. 700—1300) of the Agricultural Research Service, and (iii) revision of the scales of Heads of Divisions on the model of U.G.C. scales of pay.

(b) Yes, Sir.

(c) In so far as the representations regarding the scrapping of interviews are concerned, it has since been decided that while 'interview' will not be compulsory, opportunity should, at the same time, be provided to the scientist to appear before the Assessment Committee for a personal discussion if he so desires to enable him to project his work and achievements during the period under assessment. In other words, the scientist himself can decide whether or not he wishes to have an opportunity for discussion with the Board. As regards the upgradation of Grade 'S' Scientists and the revision of the scale of pay of Heads of Divisions, the demands are under consideration of the Council.

(d) The decision to make the interviews optional was taken in consultation with the Agricultural Scientists Recruitment Board as provided in the rules. Consultation with the ICAR Institutes was not necessary.

Committee on Development of Agriculture

3091. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Government announced publicly that development of Agriculture should be the key-note of its planning for national development:

(b) if so, whether the Government have set up any Expert Committee to study the problems and requirements related to structural and policy change in regard to development of Agriculture all over the country;

(c) whether the Government have thought over the issue of quantum of allocation of fund for the purpose; and

(d) if so, the principles related to the expected plan and programme of development of national agriculture?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir. The Government accords primacy to agricultural development.

(b) to (d). Keeping in view the key role of agriculture in the nation's life, the outlay on agriculture and allied services, including cooperation, fertilisers, irrigation, flood control and power for agriculture, has been enhanced from Rs. 2,312 crores in 1976-77 to Rs. 3,024 crores in 1977-78, or an increase of about 31 per cent. The Government have not set up any expert Committee as such to study the problems and requirements related to structural and policy changes in regard to the development of agriculture all over the country. However, the recently reconstituted Planning Commission is expected to undertake detailed exercise relating, *inter-alia* to structural and policy changes as also the resource allocation required for the development of agriculture within the framework of the national plan for overall economic development.

Multi Crop Agricultural Land

3093. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have made any study of development of one-crop agricultural lands into two-crops and three-crops agricultural lands during the last three years;

(b) if so, Statewise figures of such study;

(c) whether Government have drawn up plans for conversion of one-crop lands into two-crops and three-crops lands by extending facilities for irrigation; and

(d) if so, main features of such plans and Statewise break-up of such projects?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). No study as such of development of one-crop agricultural lands into two crops and three crops agricultural lands has been made. However, information on area sown more than once is available annually as part of land use satistics. The latest available data on area sown more than once for the years 1972-73 to 1974-75 are given in Statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-666/77.]

(c) and (d): A number of agricultural programmes included in the Plan, particularly those relating to the expansion of irrigation facilities, Command Area Development, extension of area under High Yielding varieties including short duration varieties and extension Programmes including National Demonstrations, contribute to the development of multiple cropping. The main features of the irrigation plan are: expansion of irrigation facilities through major, medium and minor irrigation schemes and conjunctive use of surface and ground water. The programmes are estimated to have resulted in the creation of irrigation potential of 7.0 million hectares during the last three years. State-wise break-up is given in statement II, laid on the Table of the House [*Placed in Library. See No.* LT—666/77.]

Identical Pay Scales of Employees of Universities

3094. SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR: Will the Minister of EDUCATION, SOCAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are considering to prescribe identical pay-scales for the employees of all the Universities; and

(b) if so, when and details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) (a) and (b). On the recommendations of the University Grants Commission, the Central Government has suggested revised pay scales for the following categories of employees for adoption by the Universities including Central Universities with effect from 1-1-1977.

Universities including Central Universities with effect from 1st January, 1973:

Teachers :

	Rs.
Lecturer	700—40—1100—50—1600
Reader	1200—50—1300—60—1900
Professor	1500—60—1800—100—2000—125/2—2500
Library Staff :	
Librarian	(i) 1500—60—1800—100—2000—125/2—2500
	(ii) 1500—60—1800—100—2000
Dy. Librarian	1100—50—1600
Asstt. Librarian	700—40—1100—50—1300
Documentation Officer	(i) 1100—50—1600
	(ii) 700—40—1100—50—1300
Director/Instructor of Physical Education	(i) 1100—50—1600
	(ii) 700—40—1100—50—1300
	(iii) 700—40—1100
	(iv) 550—25—750—EB—30—900
	(v) 425—15—500—EB—15—560—20—700

While communicating these revised scales for acceptance, the State Government were given an option to modify them after taking local conditions into consideration, and also to implement them with effect from a date later than 1st January, 1973.

The Central Government has no proposal under consideration to prescribe uniform scales of pay for other categories of employees in all the Universities in the country.

Trade Union Rights to Employees of Universities

3095. SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are considering to extend trade union rights to the employees of the Universities in accordance with the recommendations of the National Labour Commission; and

(b) if so, when?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) The National Commission on Labour and not recommended any amendment to the Trade Union Law as far as trade union rights of University employees are concerned.

(b) Does not arise.

समाज के आर्थिक दृष्टी से पिछड़े वर्गों का रिहायशी भूमि का आवंटन

3096. श्री मही लाल : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (एक) ग्राम सभा की भूमि में से (दो) अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि में से (तीन) अधिगृहीत भूमि में से, कितने परिवारों को केन्द्रीय सरकार की आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को रिहायशी भमि देने की नीति के अन्तर्गत भूमि दी गई है और प्रत्येक परिवार को कितनी भूमि दी गई है ;

(ख) क्या जिला नैनीताल की काशीपुर तहसील के अनेक गांवों में प्रत्येक भूमिहीन किसान को वन विभाग की भूमि में से या कालोनी बसाने की योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि में से केवल 20X25 फुट क्षेत्रफल का प्लाट देकर बसाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भूमिहीन किसानों के लिए इतनी कम भूमि पर्याप्त है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 12,12,014 पात्र परिवारों को आवास स्थल अलाट कर दिए हैं।

पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के परिवार को एक एकक माना गया है और जिन के पास 100 वर्जगज से कम भूमि प्रति एकक थी उन्हें 100—150 वर्गगज भूमि के आवंटन के लिए पात्र समझा गया। आवास स्थलों के आवंटन हेतु उपयोग की गई भूमि में गांव सभा सरकारी भूमि, जोतों पर अधिकतम सीमा लागू करने के परिणाम-स्वरूप फालतू घोषित भूमि और अर्जित भूमि शामिल है । जून, 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 1976 के अन्त तक 11,88,134 परिवारों को आवास स्थलों के आवंटन के लिए गांव सभा की 15,082.90 — हेक्टेयर भूमि तथा 567.30 हेक्टेयर अर्जित भूमि का उपयोग किया गया था।

शेष 23,880 परिवारों को आवंटित भूमि का ब्यौरा भेजने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है ।

(ख) और (ग) . उत्तर प्रदेश सरकार से आवश्यक ब्यौरा भेजने के लिए अनुरोध किया गया है और ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है ।

नगर निगम के शिक्षकों के वेतनमान

3097. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर निगम, दिल्ली का शिक्षा विभाग उन्हीं वेतनमानों को लागू करता है जो समय समय पर भारत सरकार द्वारा मंजूर किये जाते हैं;

(ख) क्या शिक्षकों के वेतनमान जिनकी तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी लागू कर दिये गये हैं परन्तु 20 प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्कूलों के निरीक्षकों, वरिष्ठ निरीक्षकों, सहायक शिक्षा अधिकारियों तथा उप शिक्षा अधिकारियों के वेतनमान 27 मई, 1970 तथा 1 जनवरी, 1973 से पूर्णतया लागू नहीं किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चुन्दर) : (क) जी, हां।

(ख) वेतनमान लागू कर दिये गये हैं तथा सेलेक्शन ग्रेड के 20 प्रतिशत कोटे को लागू करना आरम्भ कर दिया गया है।

(ग) यह मामला दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गेहूं की सुधरी किस्म के बारे में अनुसंधान

3098. **श्री जगदम्बी प्रासद यादव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के एक केन्द्र में उत्तरी भारत के कई राज्यों के लिए गेहूं की सुधरी किस्मों के बारे में अनुसंधान किया जाता है परन्तु वहां के केन्द्र में केवल एक ही सदस्य विज्ञानी है और उसकी सहायता हेतु क्लर्क नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या इस केन्द्र में प्रदर्शन कार्य के लिये न तो बीज उपलब्ध है और न ही उर्वरक; और

(घ) क्या सरकार का इस बारे में कोई उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक केन्द्र पूसा (बिहार) में है जो कि सामान्यत: दूसरे राज्यों के लिए और विशेषत: बिहार राज्य के लिए गेहूं की सुधरी किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कर रहा है। इस केन्द्र में, एक प्रजनक और एक रोगनिदान विज्ञानी के अलावा गेहूं अनुसंधान पर काम करने वाला एक सस्य विज्ञानी भी है। यद्यपि प्रत्येक विज्ञानी के साथ कोई क्लर्क कर्मचारी अलग तौर पर नहीं लगाया गया है फिर भी पूरे केन्द्र के लिए दफ्तर की सामान्य सुविधाएं हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूसा केन्द्र के अतिरिक्त, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, ढोली की बिहार में अनुसंधान करने की आरम्भिक जिम्मेदारी है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूरी सहायता देता है।

(ख) इस केन्द्र के गेहूं अनुसंधान कार्य के सभी सस्य संबन्धी पहलुओं की देखभाल के लिए एक सस्य विज्ञानी काफी है। फिर भी, जैसे जैसें काम का विस्तार होगा, केन्द्र को उपयुक्त सहायता दी जायेगी।

(ग) पूसा का गेहूं अनुसंधान केन्द्र प्रदर्शन कार्य करने के लिए नहीं है। फिर भी, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, ढोली दो जिलों में यानि सन्थाल परगना और मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन करता है। इन राष्ट्रीय प्रदर्शनों के अन्तर्गत बीज/उर्वरक/कीटनाशी दवाओं के रूप में सहायता देने का प्रावधान है।

(घ) इस केन्द्र में गेहू अनुसंधान करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों और पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् इस केन्द्र के अनुसंधान आधार को मजबूत करने के लिए जब कभी आवश्यकता होगी उपयुक्त कदम उठायेगी।

National Institute for Mentally Retarded

3099. DR. KARAN SINGH: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to set up a National Institute for the Mentally Retarded; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Yes, Sir.

(b) The main object of the Institute will be to sponsor or conduct research into all important aspects of the education and rehabilitation of the retarded and to train personnel. It may also have provision for producing instructional materials and teaching aids.

Periyar Sanctuary as a Tiger Sanctuary in Kerala

3100. DR. KARAN SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the suggestion of the Steering Committee, Project Tiger that the Periyar Sanctuary in Kerala should be included as the 10th tiger sanctuary has been accepted by Government; and

(b) if so, from what date the decision is likely to take effect?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The proposal is under active consideration of the Government.

(b) In view of (a), question does not arise.

National Park in Kashmir

3101. DR. KARAN SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposals for setting up a national park in Kashmir specially devoted to the rapidly vanishing Kashmir stag (Hangul); and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Extinction of the Bird Named Great Indian Bustard

3102. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the bird named as 'Great Indian Bustard' is badly threatened to extinction in India and the areas where it is located today;

(b) the causes of decay in its population and whether Government propose to protect it; and

(c) if so, the estimated population of this bird at present?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The Great Indian Bustard is endangered.

It is now found in a very scattered population in Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Gujarat.

(b) The causes of decrease in its population are due to the increasing human pressure on land for cultivation etc., which has reduced the habitat available for the bird and also their

large size makes them an easy target for the trapper and poacher.

Government have included this species in Schedule I of the Wildlife (Protection) Act, 1972 which affords legal protection to the bird. There is a sanctuary for the Great Indian Bustard in Karnataka and proposals for other sanctuaries are being actively pursued.

(c) As no census has been carried out so far, it is not possible to estimate its population.

Desert National Park

3103. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the proposal of Desert National Park is shelved and if so, reasons therefor;

(b) how many times Central agencies toured the proposed venues of the park in Rajasthan along with their name and gist of their recommendations; and

(c) when this scheme is likely to be finalised and its salient features?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) A proposal for the creation of a Desert National Park is under consideration of the Government.

(b) Central Government representatives visited Rajasthan on three occasions. Their names and gist of recommendations are given in the attached statement.

(c) The scheme can be finalised only after a scientific survey of the area, tentatively identified by the Inspector General of Forests, is carried out next winter.

The salient features of the scheme is the selection of a representative desert area having adequate remnant population of desert founa and flora.

Statement

1. Shri Ranjit Sinh, formerely Deputy Secretary, in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), visited Rajasthan in January, 1974 along with other officers of the Rajasthan Government. They proposed a rectangular area of land east of the Barmer-Jaisalmer road situated north and south to Devikot village which is 43 km. east of Jaisalmer on the above road as a suitable site for the Park.

2. Shri K. S. Sankhala, Director Project Tiger, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), visted Rajasthan in December 1975 and proposed the area to the west of a line connecting Sahgarh in the North and Danana in the South extending to the International border.

3. Shri S. K. Seth, Inspector General of Forest, visited Rajasthan in February, 1977 and identified a tentative area between Sam in the east and Shahgarh in the West which will require to be floristically and faunistically surveyed next winter before the proposed boundaries can be finalised.

दिल्ली दुग्ध योजना के घी का मूल्य

3104. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दिल्ली दुग्ध योजना से मिलने वाले घी का मूल्य कम करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : जी नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विनिर्मित घी के मूल्य में कमी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Subjects on Preservation of Wild Life in Schools/Colleges

3105. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government for introducing a subject on Preservation of Wild Life in Schools and Colleges; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) No, Sir, not as a subject, but this concept has been given emphasis in the teaching of biology at various stages in school education.

(b) Does not arise.

Selection Grade Posts in Primary School Teachers in Delhi

3106. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3156 on 3rd May, 1976 regarding Selection Grade posts for Primary School teachers in Delhi and State whether any step has so far been taken to remove the anomaly created with effect from September, 1971 on introducation of Selection Grades for Primary School Teachers and Head Masters of Delhi Schools?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): The matter is still under consideration with Delhi Administration.

Exploratory Fishing Project near Bombay

3107. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether there is an exploratory fishing project near Bombay;

(b) when was it started; and

(c) its results?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) It was started in October, 1946.

(c) The Project has surveyed the ground fish resources of about 3.2 lakh sq. km. of the sea around the Indian coast and published the results of surveys in the form of bulletins. These bulletins give information on the quality and distribution, in space and time, of the ground fish resources available and the type of fishing vessel and gear suitable for their exploitation, upto 50 metres depth around the coast. Selected surveys have also been carried out in farther areas and the results are published as bulletins from the Project.

The Project maintains an extension wing to advise the fishing industry on matters relating to off-shore and deep sea fishing and provides sea time qualifying service for marine fishing operatives.

Release of land to Dandakaranya Development Authority

3108. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Orissa Government agreed to release an area of 16,000 hectares of irrigable and cultivable land in the Potteru Irrigation Project area to Dandakaranya Development Authority;

(b) whether the Government are re-settling new migrants from former East Pakistan; and

(c) the cost of the barrage at Surlikonda across the river Potteru?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Rs. 167.76 lakhs.

Grant-in-aid to the Rajghat Samadhi and Gandhi Smriti Samithi

3109. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government are paying Grants-in-aid to the Rajghat Samadhi and the Gandhi Smriti Samithi; and

(b) if so, the amount given every year?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) Rajghat Samadhi Committe: Records are available from 1963-64 and information is furnished accordingly.

Year	Grant-in-aid given
	Rs.
1963-64	84,600
1964-65	152,700
1965-66	134,000
1966-67	212,500
1967-68	237,847
1968-69	269,862
1969-70	380,413
1970-71	532,379
1971-72	500,000
1972-73	532,300
1973-74	611,000
1974-75	700,000
1975-76	840,000
1976-77	902,000
Gandhi Samithi	
1972-73	115,000
1973-74	500,000
1974-75	Nil.
1975-76	160,000
1976-77	280,000

राजस्थान नहर के लिये भारत-ईरान के बीच वार्ता

3110. **श्री मीठालाल पटेल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में ईरान तथा भारत के बीच हुई वार्ता में राजस्थान नहर की सहायतार्थ ईरान द्वारा सहायता देने की पेशकश की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और राजस्थान नहर कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). इस विषय पर ईरान और भारत के बीच नई दिल्ली में हाल में कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन राजस्थान नहर परियोजना के इंजीनियरी निर्माणकार्यों को, धनराशि उपलब्ध हो जाने पर, 1983–84 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

Irrigation Scheme in Bihar

3111. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the number of major and minor irrigation schemes as approved by the Central Government for the year 1977-78 which have not been implemented by the State Government of Bihar; and

(b) the reasons for non-implementation of the schemes and where these schemes stand at present?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). Out of 11 major and medium irrigation schemes approved by the Planning Commission from April, 1976 to June, 1977, the Bihar Government made provisions for 9 schemes but have not made any provision for implementation of two schemes viz. Pandarwa Reservoir and Orni Reservoir in their annual plan for 1977-78.

The clearance of minor irrigation schemes does not come under the purview of the Central Government.

Special Registration Scheme for allotment of D.D.A. flats

3112. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the total number of applications registered with D.D.A. during special registration schemes meant for allotment of D.D.A. flats for M.I.G. and L.I.G. which are still pending for allotment of flats; and

(b) the time by which they are likely to be covered?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) In the Special Registration Scheme of 1973 meant for persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the number of registered persons awaiting allotment are:

M.I.G.	58
L.I.G.	386

(b) In about a year.

Auction of D.DA. Plots

3113. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government are considering to give up the present Policy of auction of D.D.A. Plots meant for M.I.G. and L.I.G.; and

(b) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The residential plots meant for Low Income Group and Middle Income Group are allotted only by draw of lots and not by auction.

(b) Does not arise.

गुजरात में केन्द्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र

3114. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मूंगफली की पैदावार बढ़ाने के लिए गुजरात में कोई अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो कहां पर और उसके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है;

(ख) देश में मूंगफली की कितनी किस्मों का उत्पादन होता है ; और

(ग) क्या गत तीन वर्षों में मूंगफली की कोई नई किस्म पैदा की गई है, यदि हां, तो वह कौन सी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मूंगफली के सुधार हेतु, अखिल भारतीय तिलहनी सुधार प्रयोजना के अधीन गुजरात के जूनागढ़ नामक स्थान पर एक अनुसन्धान केन्द्र पहले से ही स्थित है । यह केन्द्र 1967 से कार्यरत है ।

(ख) देश में विकसित की गयी किस्मों की एक सूची साथ संलग्न है ।

(ग) निम्नलिखित किस्में जारी की चुकी हैं :—

1. एम—13

2. टी एम वी—10

देश में विकसित की गयी मूंगफलियों की किस्में

1. कादिरी । (ए० एच० 288) 2. अर्ली रनर 3. जूनागढ़—11 4. ए० के० 10 5. ए० के० 12—24 6. के० जी० 61—240 7. कोपरगांव 1 8. कोपरगांव 3 9. इम्प्रूव्ड स्पेनिश 10. इम्प्रूव्ड स्माल जापान 11. फैजपुर 1—5 12. करद 4—11 13. एन० जी० 868 14. ट्रोम्बे ग्राउंडनट 1 से 18 15. एच० जी० 7 16. एच० जी० 8 17. एच० जी० 9 18. एच० जी० 10 19. एस० 206 20. एस० 230 21. टी० एम० वी० 1 22. टी० एम० वी० 2 23. टी० एम० वी० 3 24. टी० एम० वी० 4 25. टी० एम० वी० 5 26. टी० एम० वी० 6 27. टी० एम० वी० 7 28. टी० एम० वी० 8 29. टी० एम० वी० 9 30. टी० एम० वी० 10 31. पोलाची—1 32. पोलाची—2 33. पंजाब ग्राउंडनट सं० 1 34. मूंगफली 145 35. सी 501 36. सी 148 37. टाइप 28 38. टाइप 32 39. टाइप 64 40. टाइप 9

Central aid for minor Irrigation in West Bengal

3115. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the total amount earmarked by the Central Government for providing irrigation facilities in West Bengal during 1971—77;

(b) the yearly amount ear-marked for minor irrigation projects in that State; and

(c) the results achieved?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Irrigation is a State subject and funds for irrigation schemes are provided in the State Plan. The outlay provided for irrigation schemes in the State Plan of West Bengal for the period 1971-72 to 1976-77 comes to about Rs. 86 crores. In addition central assistance over and above State Plan ceiling, released during this period, is as below:—

Year	Amount (Rs. in Crores)	Purpose
1973-74	7·20	For Minor Irrigation Schemes under advance action for 5th Plan.
1975-76	1·00	For Kangsbati Irrigation project.
1976-77	0·50	

(b) The yearly amount provided for minor irrigation in the State Plan of West Bengal during the period 1971-72 to 1976-77 is as below:

Year	Approved outlay (Rs. in crores)
1971-72	4·50
1972-73	5·88
1973-74	5·15
1974-75	6·40
1975-76	6·50
1976-77	13·50

(c) An additional irrigation potential of about 6 lakh hectares is estimated to have been created from irrigation schemes taken up during this period.

Expenditure incurred on the construction of Parliament House Annexe

3116. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred on the construction of Parliament House Annexe;

(b) the progressive expenditure year-wise since the commencement of the construction of the building; and

(c) the break up of the expenditure incurred in furnishing, air-conditioning, electrifying and in providing lawns, etc. together with progressive yearly expenditure on each of these items?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The booked expenditure upto end of March, 1977 is Rs. 3,73,29,506 (including departmental charges). Some bills are still outstanding. The total expenditure on the work is expected to be Rs. 3,75,99,000 (including departmental charges).

(b) As per Statement I.

(c) As per Statement II.

STATEMENT-I

Progressive expenditure year-wise since the commencement of the construction of the building

Year	Civil	Electrical	Horticulture
	Rs.	Rs.	Rs.
1968-69	36,443	..	..
1969-70	14,68,631	..	..
1970-71	45,70,219	..	..
1971-72	85,37,451	3,33,071	..
1972-73	1,08,62,715	22,12,354	..
1973-74	1,68,31,785	62,40,902	8,238
1974-75	1,93,85,280	87,20,964	1,22,742
1975-76	2,48,99,475	1,09,38,399	2,60,619
1976-77	2,57,98,070	1,12,60,292	2,71,144

Statement II

Break-up of the expenditure incurred in furnishing air conditioning, electrifying and in providing lawns, etc., together with progressive yearly expenditure on each of these items

Year	Furnishing	Air-conditioning	Electrification	Horticulture
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1971-72	..	..	3,33,071	..
1972-73	..	16,07,214	6,05,140	..
1973-74	..	30,13,609	32,27,923	8,238
1974-75	..	40,97,359	46,23,605	1,22,742
1975-76	..	45,38,945	63,99,454	2,60, 619
1976-77	23,29,846*	45,98,153	66,62,139	2,71,144

*The total expenditure on furnishing since 1973-74 is Rs. 23,29,846/—The expenditure on civil works is worked combined for building and furnishing. Hence separate figures for building work and furnishing cannot be furnished year-wise.

Air-conditioning of Parliament House Annexe

3117. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Central air-conditioning of the entire building of Parliament House Annexe was planned initially;

(b) if so what steps were taken to implement the said plan for air-conditioning the building;

(c) the reasons for not air-conditioning the upper floors of this building; and

(d) whether Government propose to provide central air-conditioning to these floors also?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

(c) the scope of air-conditioning work sanctioned initially was limited to the basement, ground floor and the first floor only and those have already been centrally air-conditioned.

(d) A proposal with an estimate for Rs. 39.71 lakhs for air-conditioning the balance portion of the building has been submitted by the Chief Engineer (Electrical), CPWD to Government for sanction. This is under examination.

Factories Manufacturing Sugar through Vacuum Pan Process

3118. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the number of factories manufacturing sugar through vacuum pan process opened since 1971;

(b) the number of such factories, State-wise in the private sector; the public sector and in cooperative sector; and

(c) the optimum manufacturing capacity of each such factory and the actual annual production thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Fifty nine.

(b) Of the fifty nine factories forty seven are in the cooperative sector, six in public and six are joint stock factories.

The State-wise break up is set out in Statement I. Laid on the Table of the House [*Placed in Library. See* No. LT-667/77].

(c) The information is furnished in Statement II. Laid on the Table of the House [*Placed in Library. See* No. LT-667/77].

White Revolution

3119. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether there is any time bound programme with the Government to bring 'White Revolution in the country'; and

(b) if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) From the base level of 23.2 million tonnes in 1973-74 milk production is planned to rise to 28.6 million tonnes by the end of 5th Plan.

Guidelines to State Governments for Sanctioning Building Plans

3120. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Central Government have issued any guidelines to the State Governments for sanctioning building plans on vacant lands in excess of the ceiling prescribed under the law; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). Yes, Sir, a copy of the guidelines issued with the Ministry of Works and Housing's Circular letter No. 1|50|76-UCU dated the 31st December 1976 is laid on the Table of the House [*Placed in Library. See* No. LT-668/77].

Allotment of Plot to Kulachi Hansraj Model School, Ashok Vihar, New Delhi

3121. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the D.A.V. College Managing Committee, New Delhi has urged upon the Delhi Development Authority for the allotment of adjoining plot of Kulachi Hansraj Model School, Ashok Vihar, New Delhi;

(b) if so, the main demand made by the Committee;

(c) number of students in the school and the area of land of the school building; and

(d) whether Government have decided to allot the adjoining plot to the school; if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Yes; Sir.

(b) The main demand of the Committee is for allotment of additional land measuring about 3 acres.

(c) The number of students is reportedly 2215 and area of the land of the school building is 1.46 acres.

(d) No; Sir.

Progress of Narmada Irrigation Projects

3122. SHRI AHMED M. PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) broad details of the various minor and major irrigation projects cleared in relation to Narmada Waters;

(b) whether the work on these projects has been started; and

(c) if so, what is the progress?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Pending a decision of the Narmada Water Disputes Tribunal on the Narmada water dispute, and without prejudice to the claims of the party States before the Tribunal, the party States of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan agreed in March, 1975 that Gujarat may go ahead with Karjan, Sukhi, Heran and Rami irrigation projects and Madhya Pradesh with Kolar, Bichia, Sukta and Bichhua-Latia projects subject to the usual scrutiny and approval by the Government of India. The table below gives the broad details of the projects of Gujarat and

Madhya Pradesh so far cleared by the Planning Commission:

Name of Project	Sanctioned Estimated Cost (Rs. lakhs)	Benefit ('000' ha.)
GUJARAT		
Rami . . .	61·00	1·323
Sukhi . . .	2311·00	21·25
Karjan . . .	3720·00	61·97
MADHYA PRADESH		
Bichia . . .	124·00	2·00
Sukta . . .	493·00	19·00

In addition the following two major projects of Madhya Pradesh in the Narmada basin were approved by the Planning Commission prior to the setting up of the Narmada Water Disputes Tribunal:

Name of Project	Estimated Cost (Rs. lakhs.)	Benefits. ('000' ha.)
Tawa . . .	7928·00	332·00
Barna . . .	1297·00	63·20

(b) and (c). While construction work has not started on Sukhi and Karjan projects of Gujarat, work on the construction of an earthen dam for the Rami irrigation project is in progress. Rami project is expected to be completed by the end of the 5th Plan. Works on the Bichhua and Sukta projects has recently been started.

TAWA: The work on the dam is complete upto the crest and spill-way gates are expected to be erected by next year. The works on the canal system are in an advanced stage.

BARNA: The work is in an advanced stage. Erection of gates and 4 spans of spill-way bridge is expected to be completed by the end of July, 1977 and the entire project by 1977-78.

Import of Foodgrains

3123. SHRI M. RAM GOPAL REDDY:
SHRI C. K. CHANDRAPPAN:
SHRI S. R. DAMANI:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased state:

(a) whether Government propose to import foodgrains during the current year;

(b) if so, the quantity of foodgrains proposed to be imported and the countries with which negotiation are being held in this regard; and

(c) the reasons for import?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). In the context of the comfortable stock position, Government do not intend to import foodgrains during the current year. However, about 1.8 lakh tonnes of aid wheat from EEC and Belgium against their 1975-76 Food Aid Programme, which could not be supplied last year, is expected to be shipped and received during the current year.

Registered Persons with DDA

3124. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of persons registered with the DDA for the allotment of flats and plots of land under

various categories i.e. low, middle and high income-groups;

(b) since when the first person in various categories is registered with the DDA and the reasons for not allotting him flat or plot of land.

(c) the price of a flat at the time when the registration was made and the price of a flat of various categories now and the particular reasons for which the prices were fixed so high; and

(d) the particular steps proposed to be taken to wipe out the list of the registered persons by allotting them suitable flat or plot of land at an early date?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) There is no registration scheme for the allotment of plots.

The number of persons registered with D.D.A. under various categories for allotment of flats are, however, as under:—

M.I.G.	23868
L.I.G.	20866
Janta	19273
	64007

(b) First scheme for allotment of built up flats was opened in the year 1969-70.

The reasons for non-allotment of flats to the old registered persons are *inter-alia* as follows:—

(i) The registered persons have not been lucky in the draw of lots for allotment of flats;

(ii) In some cases, the allotment is not availed of because the locality offered is not preferred by the registered person; and

(iii) In some cases, surrenders of allotments have taken place because of the floors being not of their choice.

(d) The price of flats of LIG and MIG categories at the time of first registration was announced as likely to be as follows:—

(i) LIG—Rs. 12500-Rs. 22000.

(ii) MIG—Between Rs. 25000 and Rs. 30000.

The present price in respect of LIG and MIG flats is as follows:—

(i) LIG—between Rs. 44300 and Rs. 50400.

(ii) MIG—between Rs. 61700 and Rs. 79500.

The price has registered upward trend due to increases in cost of labour, cost of building materials and enhancement in the cost of land.

(d) Delhi Development Authority has decided that priority and preferential treatment will be given to those persons who have got themselves registered in the first and second registration schemes. Thus it is expected that the backlog will be cleared within a period of one year or so.

Irrigation Projects in States under construction

3125. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether number of irrigation projects in the States are under construction for the last 25 years;

(b) if so, the names of these projects and at what stage of construction they are;

(c) whether Government have taken any decision to complete these projects within a schedule; and

(d) which new irrigation projects are to be taken up in Kerala for 1977 and which are to be completed by 1980?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). The works under the following projects taken up in the pre-Plan or Ist Plan period are in progress:

1. Kosi Barrage and Eastern Kosi Canal (Bihar).
2. Mahi Stage-I (Gujarat).
3. Kakrapar (Gujarat).
4. Bhadra (Karnataka).
5. Chambal Stage-II (Madhya Pradesh and Rajasthan).

The position in respect of these projects is given below:

Kosi Projects: The Barrage has been completed. Irrigation potential of about 3.0 lakh hectares has been created against the ultimate potential of 4.34 lakhs ha. Works on the Canal system are in progress.

Mahi and Kakrapar: The Projects are substantially completed. With the construction of Kadana Dam on Mahi and Ukai Dam on Tapi, additional works required in the canal systems are being carried out.

Bhadra: The Project is substanially completed. Some additional works involving construction of storages in the command area have since been incorporated in the scope of the Project and are in progress.

Chambal: The project is substancompleted. Some improvement works required due to problems of water logging and weed growth are, however, being carried out.

It is proposed to complete these projects by the end of the Fifth Plan.

(d) In addition to the seven on going major irrigation schemes, the following 3 new major and 3 new medium irrigation schemes in Kerala will be under implementation during the current financial year:

MAJOR:

1. Muvathupuzha.
2. Chimani.
3. Idamalayar.

MEDIUM:

4. Karapuzha.
5. Attappadi.
6. Meenachil.

As per the present indications the following on-going projects are likely to be completed by 1980:

1. Chitturpuzha.
2. Kuttiadi.

None of the above 6 new schemes is likely to be completed by 1980.

Drop out at School Stage

3126. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURI be pleased to state:

(a) how many school going students boys and girls belonging to age group of 5—16 years, have completed middle school in last three years;

(b) the drop out of boys and girls in the same age groups from the schools in last three years;

(c) how many boys have opted for technical training in last three years; and

(d) how many had completed it?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE

(DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER):

(a) This Ministry collects enrolment figures of School going children. According to the available information, about 650.73; 663.55 and 684.79 lakh children were studying in classes I—V (6—11 age group) during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 respectively. The enrolment in classes VI—VIII (11—14 age group) was 155.63; 161.95 and 172.12 lakhs respectively during this period.

(b) The requisite information for the last three years is not available. However, according to studies made sometimes back, only about 40 per cent students enrolled in class I reach class V and 25 per cent reach class VIII.

(c) According to the available information, as many as 47,291; 48,769 and 50,270 students were admitted in diploma courses of technical institutions during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 respectively. The enrolment in Technical and Industrial courses was 1,03,958; 1,37,742 and 1,35,388 respectively for 1970-71, 1971-72 and 1972-73.

(d) As many as 16,887; 20,141 and 25,145 students completed technical diploma courses during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 respectively. The number of passes from ITI's and other Technical Institutions of school standard was 27,346; 34,437 and 33,750 respectively for 1970-71, 1971-72 and 1972-73.

Master Plan for East Pak Refugees

3127. SHRI SAUGATA ROY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Government propose to fully implement the Master Plan for East Bengal refugees prepared by the previous West Bengal Government and submitted to the Centre in 1973; and

(b) if so, details thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). The Hon'ble Member's attention is invited to the reply given to a Lok Sabha Unstarred Question No. 2544 by Shri Priya Ranjan Das Munsi on 6-3-1975. As indicated in the reply, a Working Group was set up on 2-7-1975 under the chairmanship of Secretary, Department of Rehabilitation, to go into the details of residuary problems of rehabilitation in West Bengal. The report of this Working Group was submitted on 10-3-1976 and its recommendations, by and large, have been accepted by the Government as detailed below:—

(1) The on-going rehabilitation schemes already included in the 5th Plan should be continued. There are five schemes involving an approximate expenditure of Rs. 6 crores.

(2) Additional resources to the extent of Rs. 6 crores (in addition to the amount indicated in (1) to cover about 3 lakh agriculturist families in 9 districts under the Small Farmers Development Agency/Marginal Farmers and Agricultural Labour schemes should be provided in the 5th Plan.

(3) Required funds will be provided for the development of 1,008 colonies of displaced persons mentioned in the Report.

(4) Specified colonies of migrant squatters which came into being after the 31st December, 1950 uptil the 25th March, 1971 may also be accepted for regularisation and right and title to land conferred on such squatters (15 thousand families in 175 colonies will benefit from this measure).

(5) The scheme of remission of 'type' loans i.e. loans given for land purchase, non-contributory house building, agriculture and small trade may be further liberalised to ensure complete removal of the burden on account of these loans. This would mean remission of approximately Rs. 6.38 crores and about 2 lakh families will benefit from it.

(6) An outlay of Rs. 1.52 crores should be provided for medical facilities for new migrants to cover expenditure on 337 Non-T.B. beds, 103 T.B. beds and 2 Chest Clinics.

Rehabilitation Programme in Andaman and Nicobar Islands

3128. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government have any rehabilitation programme in Andaman and Nicobar Islands; if so, the main proposals;

(b) the total expenditure to resettle one ex-Service man family at campbell Bay; and

(c) the total expenditure to resettle one East Bengal migrant family in Andamans?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir. During V Plan, it was estimated that 2200 families from former East Pakistan migrants and repatriates from Sri Lanka (in equal proportion) would be settled in Little Andaman, and 400 families of ex-servicemen would be resettled in Great Nicobar. The work of reclamation, however, was suspended for about 2 years as the then Prime Minister wanted ecological aspects to be examined by an International expert before undertaking any further deforestation in Andaman and Nicobar Islands.

In the current financial year, 415 acres of land have been released for reclamation in Little Andman for settlement of about 60 migrant/repatriate families and 525 acres in Great Nicobar for settlement of 50 ex-servicemen families.

(b) and (c). As the expenditure is still being incurred on their resettlement and for providing various infrastructure facilities, it may not be possible to indicate the expenditure per family of migrant/repatriate and ex-serviceman.

Selection Grade to Teachers in Andaman and Nicobar Islands

3129. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have fully implemented the Kothari Commission recommendation which provided Selection Grade to teachers in Andaman and Nicobar Islands; if so, how many P.G.T. G.T.T., and Senior Teachers were given selection grade in Andaman and Nicobar Islands, category wise; and

(b) whether still some P.G.T., G.T.T. and Senior Teachers are not given Selection Grade though eligible, their numbers category-wise and the reasons therefor?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

News report re. Anomalies in Scientist Inductions into Ars

3130. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government has been drawn to the news report appearing in "The Times of India" dated the 14th June, 1977 under the caption, "Anomalies in scientist inductions into ARS"; and

(b) if so, the reaction of the Government to the various observations made therein and the action taken/proposed in the matter?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) Under the procedure laid down by the Indian Council of Agricultural Research, the existing scientists employed in various Institutes were required to furnish their bio-data and other particulars in the form prescribed by the Agricultural Scientists Recruitment Board for induction into the Agricultural Research Service. Since most of the information required by A.S.R.B. had already been obtained by the then Director, IARI, in a somewhat different form, from the scientists of his Institute, the A.S.R.B. initially agreed to undertake induction of IARI scientists on the basis of information available with the Institute. Subsequently, however, it was found that in some cases, it was not possible for the Board to induct scientists on the basis of information obtained by the Director, I.A.R.I. It was, therefore, decided in December, 1976 that the scientists who were not inducted in the initial phase should submit their bio-data afresh in the form prescribed by A.S.R.B. Most of the scientists complying with this requirement have since been inducted into the Service with effect from 1-10-1975, the date of initial constitution of the Service. The induction of scientists who have not yet submitted their bio-data in the prescribed from will be undertaken as soon as they make available complete information required by the A.S.R.B.

The A.S.R.B. functions on the pattern of the U.P.S.C. and does not intimate to the I.C.A.R. the basis of its recommendations. All their recommendations in regard to induction of ICAR scientists into the Agricultural Research Service have been accepted by the Minister (Agriculture and Irrigation) who in his capacity as the President of the Council is the Controlling Authority for the Service.

Government Accommodation for Central Government Employees in Delhi

3131. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the total number of Central Government employees in Delhi and the number out of them allotted Government accommodation;

(b) the number of Government servants who are having their own houses and have got Government accommodation in pursuance to recent and earlier orders; and

(c) whether Government would formulate some plan in the near future by which Government servants in Delhi rendering 10 years service become entitled to Government accommodation, and if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The number of Central Government employees in Delhi/New Delhi eligible for general pool accommodation is 1,00,587. Out of these, 41,522 have been allotted accommodation.

(b) 1553 house-owning employees are now in occupation of Government accommodation.

(c) It is the intention of Government to provide accommodation to 80 per cent of the eligible employees in Delhi/New Delhi during the course of next 20 years. To achieve this, a perspective plan has been taken up to construct 1,700 houses in Delhi every year subject to the availablility of funds. As on 31st March, 1977, 3,713 quarters are under construction and during 1977-78, it is proposed to take up construction of 3,098 quarters.

Parliament House Annexe

3132. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the total cost at which the Parliament House Annexe was got constructed and the authority by which this decision was taken;

(b) when this building was completed and handed over to C.P.W.D. and what is its annual maintenance cost;

(c) whether Government received complaints of embezzlement in the construction of this building and if so, whether the same were got investigated and found true;

(d) whether it is also a fact that basement to first floor of the building is air conditioned and the rest on which the staff is accommodated is not air conditioned; and

(e) by what time the whole building is proposed to be made air conditioned and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The booked expenditure upto end of March, 1977 is Rs. 3,73,29,506 including Department Charges). However, some bills are still outstanding. The total expenditure on the work is expected to be Rs. 3,75,00,000. Sanction for the amount was accorded by Lok Sabha Secretariat *vide* their letter No. 9/1/68-WG dated 19-8-1974.

(b) The building was completed on 15th December, 1975. Annual expenditure on maintenance is:—

Civil	..	Rs. 1,38,800
Horticulture	...	Rs. 70,303
Electrical	..	Rs. 1,82,706

(c) No, Sir.

(d) Yes, Sir.

(e) An additional estimate for Rs. 39.71 lakhs for air conditioning of the upper portions of the building has been submitted by Chief Engineer (Electrical), C.P.W.D. to Government for sanction. This is under examination.

स्लम प्रगृहों की किराया खरीद कीमत

3133. **श्री महीपाल** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह स्लम प्रगृहों की कीमत के बारे में 23 अगस्त, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1189 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण विंग ने स्लम प्रगृहों के किराया खरीद मूल्य के बारे में इस बीच कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो कालोनी-वार, विशेष रूप से रणजीत नगर कालोनी के लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया है, और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं, जब कि किराया खरीद आधार पर इन प्रगृहों को आवंटित करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां । कुछ मामलों में ।

(ख) रणजीत नगर कालोनी के लिए मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है उन कालोनियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है जहां मूल्य निर्धारित कर दिये गये हैं ।

(ग) मूल्य का निर्धारण कई कारणों पर निर्भर करता है तथा अन्य कालोनियों के लिए मूल्य निर्धारित किया जा रहा है ।

Production of Food Grade Oil From Rice Bran

3134. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of Food Corporation of India for a plan to promote production of food grade oil in India from rice bran;

(b) whether it is also a fact that the Central Food Technological Research Institute (CFTRI) at Mysore has developed a process to prevent rice bran from becoming rancid; and

(c) if so, whether Government are satisfied with its programme and if so, further steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) By installing Rice Bran Stabilisers, FCI have succeeded in producing Bran oil with low Free Fatty Acid content in their Sembanarkoil Solvent Plant. This oil was sold to the Vanaspati Industry at a premium price compared to the price of Industrial grade oil. Further research, development and extension work is being planned in order to promote this technique.

डी० डी० ए० के हस्तांतरिक फ्लैटों के आबंटन के बारे में नई रीति

3135. **श्री रामनरेश कुशवाहा** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० फ्लैटों का आबंटन होने के पश्चात् परिस्थितियों से बाध्य होकर आबंटी व्यक्ति वे फ्लैट अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित करके दिल्ली से बाहर चले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी परिस्थितियों में नई नीति निर्धारित करके हस्तांतरित फ्लैटों को इस समय वहां रहने वाले व्यक्तियों के नाम आवंटित करने की कोई व्यवस्था कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण नियमों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण के बने बनाये फ्लैटों का अन्तरण मूल आवन्टी के परिवार के सदस्यों को करने की अनुमति है तथा यदि आवंटी का अपना कोई परिवार न हो तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी को जिसकी परिभाषा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 में दी गई है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐसे अन्तरण की अनुमति दे दी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मौजूदा नीति से हट जाना सरकार आवश्यक नहीं समझती ।

Rajasthan Canal Project

3136. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) when is the Rajasthan Canal Project expected to be completed and what will be its estimated total cost:

(b) why is its progress slow;

(c) whether the French or Iran Governments come forward to finance

the project; if so the outcome of the proposals; and

(d) whether Government are aware of gross misuse of funds in the project by engineers and contractors; and do Government propose to inquire into the same?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The Engineering works on Rajasthan Canal Project are scheduled to be completed by 1983-84 subject to availability of funds. The estimated cost of the Project is Rs. 396 crores at the 1975 price level.

(b) In the earlier stages, the progress on the project had been slow due to constraint of resources. This is no longer the case. Against an average annual expenditure of about Rs. 4.6 crores during the five-year period preceding the Fourth Five-Year Plan, and an expenditure of about Rs. 9.5 crores during the Fourth Plan, the annual expenditure during the first three years of the Fifth Plan has been about Rs. 21 crores and the outlay for the current year is Rs. 28 crores.

(c) There has been no proposal from the French Government to finance the project. However, Iran has shown interest in assisting the Stage-II of the Rajasthan Canal Project, and the proposal is under discussion between India and Iran.

(d) The Government of Rajasthan have reported that they are not aware of any gross misuse of funds on the Project by Engineers or contractors.

Diversion of Rajasthan Canal Water

3137. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) do Government know of a move to divert the waters of Rajasthan Canal Project and not let it reach the targeted end of canal upto Ramgarh in Jaisalmer district;

(b) what is the merit of taking up Lift-Irrigation Scheme out of the waters of Rajasthan Canal; how many such schemes are in hand and what is their progress; and

(c) are Government's experts convinced over viability of diversion of such waters; will it not create duplicity of efforts delaying the original plan of irrigation in desert?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). In 1974, the National Commission on Agriculture, in their Interim Report on Desert Development, had suggested recasting of Stage-II of Rajasthan Canal Project to cater to 3.1 lakh hectares of comparatively thickly populated (about 10—40 persons per square Km.) and developed flat lands by lift irrigation to protect maximum number of people against the ravages of recurring drought and excluding unsuitable and sparsely populated (about 3 persons per square Km.) area of 2.10 lakh hectares from the command of Stage-II served by gravity flow. To consider this suggestion, the Government of Rajasthan constituted a committee of experts and got prepared a detailed approach report for the Project. Messers Water and Power Development Consultancy Services (India) Limited who were entrusted with the work of survey and preparation of the Project Report under the overall guidance of the above committee, submitted their report at the end of 1976, recommending the inclusion of 5 lift schemes in Stage-II of the project.

The Government of Rajasthan after taking into consideration this report and various economic and other aspects including the maximum opportunities for employment and in consultation with the Government of India, decided that under Stage-II of the Project 5 lakh hectares be covered by flow and 2.6 lakh hectares by 5 Lift Schemes with maximum lift upto 60 metres as against only 6 lakh hectares under flow proposed in the original Project. The

Rajasthan Main Canal will, however, be constructed upto Ramgarh in Jaisalmer district as originally planned. The Project Report of Stage-II of Rajasthan Canal Project as recast is under examination of the Government of India and the survey work of these 5 lift schemes is in progress.

The Rajasthan Canal is now scheduled to be completed by 1983-84 subject to the availability of funds. The development of irrigation as now proposed is not expected to create any duplicacy of efforts and the original plan of irrigation in the desert is not likely to be delayed on this account.

डी० ए० पी० और कीटनाशी औषधियां

3138. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि डी० एमोनियम फासफेट जो किसानों को सप्लाई की जाती है, आयातित है [और उसका पांच साल पहले आयात किया गया था और अब वह प्रभावहीन हो गई है और यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या छोटे किसानों की ठीक समय पर उर्वरकों और कीटनाशी औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं और यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) डाई अमोनियम फास्फेट देश में तैयार किया जाता है तथा इसका आयात भी होता है । वह एक लोकप्रिय और तेजी से ढुलाई किया जाने वाला उर्वरक है तथा कृषकों को आयातित और देश में बना दोनों कस्म का डाई अमोनियम फास्फेट सप्लाई कया जाता है । आयातित डाई अमोनियम फास्फेट राज्य सरकारों को अलाट किया जाता है, जो इसे संस्थागत एजेंसियों को फिर अलाट करती हैं । ये ऐजेंसियां भारतीय खाद्य निगम, और / या केन्द्रीय अथवा / और राज्य भांडागार निगमों से सप्लाई प्राप्त करती हैं, जिन्हें 1970 में ही हिदायत दे दी गई थी कि ये नया स्टाक जारी करने से पहले पुराना स्टाक बेच दें । इसके अलावा, जनवरी, 1975 के अन्त में न तो भारतीय खाद्य निगम के पास और न ही भांडागार निगमों के पास पूल के आयातित उर्वरकों का कोई स्टाक मौजूद था । अत: सरकार द्वारा वितरण एजेंसियों को (जिन्हें राज्यों द्वारा उर्वरकों का पुन: आवंटन किया जाता है) आयातित डाई अमोनियम फास्फेट का 5 वर्ष पुराना स्टाक सप्लाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ख) किसानों को (जिसमें छोटे किसान भी शामिल हैं) समय पर उर्वरक उपलब्ध करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) प्रत्येक मौसम और विशेषकर खरीफ और रबी से काफी पहले उर्वरक की आवश्यकताओं के अनुमान लगाये जाते हैं तथा सप्लाई योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाता है ।

(2) संकट-कालीन मांग पूरी करने के लिए देश के 600 से अधिक केन्द्रों में उर्वरकों का बफर स्टाक रखा जा रहा है ।

(3) लगभग एक लाख खुदरा दुकानें किसानों को उर्वरक बेचती हैं । इसके अलावा, देहाती इलाकों में खुदरा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

(4) रेल द्वारा उर्वरकों की ढुलाई प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है ।

(5) उर्वरकों तथा अन्य कृषि आदानों की खरीद के लिए किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की जा रही है ।

जहां तक कीटनाशी औषधियों का संबंध है, राज्य सरकारों तथा संस्थागत एजेंसियों ने अनेक डिपो खोले हैं और उनके पास देश में लगभग 52,000 वितरण केन्द्रों का एक विस्तृत जाल है । भारत सरकार भी एक योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसके अन्तर्गत उत्पादन तथा कुछ महत्वपूर्ण कीटनाशी औषधियों (विशुद्ध सामग्री) के आयात का 50 प्रतिशत सीधे राज्य सरकारों को विनिर्माण एवं किसानों को सप्लाई करने के प्रयोजन के लिए अलाट किया जाता है । कुछ महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों के मामले में कीटनाशी औषधियों के सतही/हवाई छिड़काव के लिए राज-सहायता दी जा रही है ।

Books of 20 Point and 5 Point Programme Prescribed as Text Books

3139. SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the number and names of books on 20 point programme of the former Prime Minister Indira Gandhi and 5 point programme of Sanjay Gandhi prescribed as text or reference books in various schools and colleges of the country; and

(b) the facts thereabout and the reaction of Government in this respect?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) According to information available with the Ministry of Education and SW, a book on 20 Point Economic Programme and the 5 Point Programme entitled "Pragati Ke Path Par" was published and prescribed by the Delhi Administration in December 1976 as a supplementary text book for Classes 9 and 10 for schools in Delhi.

(b) Originally, instructions were issued by the Delhi Administration that question(s) carrying 5 marks should be set from this book. But the instructions were subsequently withdrawn by the Delhi Administration on 24th March, 1977.

Complaint against the Gujranwala House Building Cooperative Society, Delhi

3140. SHRI RAM KANWAR BERWA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether any complaint has been received by the Registrar of Cooperative Societies, Delhi that the Gujranwala House Building Cooperative Society, Delhi is making alterations and additions in the List of names of the left out members of the Society who are yet to be allotted plots and for whom additional land has been allotted to the Society by Government; and

(b) if so, the nature of the complaint and measures being taken or proposed to be taken to safeguard the interest of the left out members who are waiting for allotment of plots for the last 18 years and so?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) The Delhi Administration has made an enquiry. Appropriate action will be taken according to law.

भारतीय वन्य जीव परिषद्

3141. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन्य जीव परिषद् का पुनर्गठन किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस परिषद् को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव है; जिससे वन्य जीवों के उचित संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) देश में भारतीय वन्य जीव परिषद् जैसी कोई संस्था नहीं है । देश में भारतीय वन्य प्राणी मण्डल नाम की संस्था अवश्य है जिसका 4 वर्ष की अवधि के लिए 4 जुलाई, 1974 को पुनर्गठन हुआ था । अत: इसका 4 जुलाई, 1978 को पुन: पुनर्गठन होना है ।

(ख) भारतीय वन्य प्राणी मण्डल एक सलाहकार निकाय है । इसके विषय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

Persons Sent to U.K. for Training by I.I.T., Delhi

3142. DR. RAMJI SINGH: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether two persons from I.I.T., Delhi were sent to U.K. for training; if so, the nature of training; and

(b) whether it is the policy of Indian Institute of Technology to get persons from I.I.T. trained in foreign countries?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). The Government of India have collaborative arrangements with the Government of U.K. for the development of the IIT Delhi. Initially, the scheme of collaboration was established for a period of three years *viz.*, 1968—70 and was subsequently renewed for a further three year period from April 1971 to March 1974. In April 1974 the agreement was extended for a further two year period ending March 1976. The present agreement of collaboration commences on 31st April, 1976 and is valid for a period of five years.

The purpose of collaboration is to assist the I.I.T. to serve the needs of Indian Industry, as defined in the Government of India's plans, through projects of research and development. The collaboration is also meant to assist the I.I.T. in developing its educational role.

From 1-4-1976 upto date, seven persons were sent to U.K. utilising the provision of visits under this agreement, for training in University Administration, and operation of N.C. Machines, and for discussion with the British authorities.

Final Decision regarding Abolition of Lease of D.D.A. Flats

3143. CHOWDHRY BALBIR SINGH: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 89 on the 13th June, 1977 regarding abolishing of lease of D.D.A. flats and state:

(a) the time by which final decision to abolish lease of D.D.A. flats and to make them free hold will be taken; and

(b) whether the pricing policy of these flats will be applicable only to the flats sold by D.D.A. in December 1976 and January 1977 or also to the flats sold in the earlier years?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) No decision has been made in this regard and it is not possible to indicate any time limit.

(b) No decision has been taken yet.

डी० डी० ए० फ्लैटों की वसूल की गई कीमत का ब्यौरा

3144. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1976 और जनवरी, 1977 में विभिन्न कालोनियों जैसे राजौरी गार्डन एक्सटेंशन (मायापुरी), प्रसाद नगर, वजीरपुर और कटवारिया सराय में बेचे गए मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों और निम्न आय वर्ग तथा जनता फ्लैटों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितनी कीमत वसूल की थी;

(ख) इसकी लागत अर्थात् भूमि की कीमत, विकास शुल्क, ठेकेदारों को दी गई धनराशि, निरीक्षण शुल्क आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फ्लैटों की लागत में फ्लैटों के रख-रखाव के लिए भी कोई धनराशि शामिल है, यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए फ्लैटों का रख-रखाव दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और इस रख-रखाव के अन्तर्गत कौन-कौन सी मदें शामिल होंगी; और

(घ) क्या आवास बोर्ड बम्बई द्वारा बेचे जाने वाले फ्लैटों की कीमत की अपेक्षा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बेचे जाने वाले मध्य आय वर्ग के फ्लैटों की कीमत लगभग दुगनी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है ।

जानवरों की खालों की बिक्री पर रोक

3145. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानवरों को मार कर उसकी खालें नेपाल में हजारों रुपये में विदेशियों को बेची जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है और यदि नही की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) इस प्रकार का कोई दृष्टान्त सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

विदेशों में भेजे गये पक्षी

3146. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पक्षी पकड़ने वाले व्यक्तियों द्वारा अनेक पक्षी कलकत्ता की एक फर्म द्वारा विदेशों में भेजे जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप ऐसे अनेक पक्षी गायब होते जा रहे हैं, जो फसलों आदि के लिए बहुत लाभप्रद हैं; और

(ख) उन पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) पता चला है कि 4 बड़े निर्यातकर्ताओं द्वारा कलकत्ता से प्रति वर्ष सभी प्रकार के लगभग 8 लाख पक्षी निर्यात किये गए हैं। समस्या का जायजा लेने के लिये जनवरी, 1977 से निर्यात के आंकड़ों का विस्तृत ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। इस प्रकार के निर्यातों को नियन्त्रण में लाने के लिये वन्य जीव (परिरक्षण) अधिनियम की अनुसूचियों में शीघ्र ही संशोधन करने का प्रस्ताव है।

12.25 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Detailed Demands for Grants of Ministry of Shipping & Transport for 1977-78

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Shipping and Transport for 1977-78. [*Placed in Library. See* No. LT—648/77].

Food Corporations (2nd Amdt.) Rules, 1977

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): I beg to lay on the Table a copy of the Food Corporations (Second Amendment) Rules, 1977 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 413(E) in Gazette of India dated the 25th June, 1977, under sub-section (3) of section 44 of the Food Corporations Act, 1964. [*Placed in Library. See* No. LT—649/77].

Notifications under Customs Act, 1962

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:—

(1) G.S.R. 427(E) published in Gazette of India dated the 1st July, 1977, together with an explanatory memorandum.

(2) G.S.R. 428(E) published in Gazette of India dated the 1st July, 1977, together with an explanatory memorandum.

[*Placed in Library. See* No. LT—650/77].

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I am on a point of order. Under Direction 2, sub para 2, unless the Speaker otherwise directs on any particular occasion, the relative precedence of the classes of business before the House specified shall be in the following order:—

(i) Oath of affirmation

(ii) President's Address to be laid on the Table.

(iii) Obituary references.

(iv) Questions including short notice questions.

(v) Leave to move motions for adjournment of the business of the House.

(vi) Questions involving a breach of privilege.

(vii) Papers to be laid on the Table.

I have given notice of a breach of privilege under rules 222 and 223. So, I should be allowed to raise it before the papers are to be laid.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, you have yourself answered it 'unless the Speaker otherwise directs'. So,

I direct that papers should be laid on the Table.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Then you have to tell today that you are going to supersede your earlier direction number two.

MR. DEPUTY-SPEAKER: When I called for the papers to be laid, you did not stand up. After it was called, you stood up. So, I think the order will be that after the papers are laid, you can raise the point.

DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICERS (FEES) AMDT. RULES, 1976 AND NOTIFICATION UNDER DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICERS (FEES) AMDT. RULES, 1976

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Amendment Rules, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 817(E) in Gazette of India dated the 15th October, 1976, issued under section 8of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948. [*Placed in Library. See* No. LT—651/77].

(2) A copy of Notification No. G.S.R. 922(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 16th December, 1976, issued under the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Amendment Rules, 1976. [*Placed in Library. See* No. LT—652/77].

12.27 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRI KISHORE J. TANNA OF JAMNA DASS MADHAVJI AND COMPANY, BOMBAY

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Under rules 222/223, I hereby seek your consent to raise a question involving a breach of privilege of the House. I wish to raise this today at the appropriate time (*vide* directions) after the question hour. The facts of the case are as follows:

Shri Kishore K. Tanna of Jamna Dass Madhavji and Company Bombay, one of the firms against whom serious charges of economic offences and malpractices have been correctly levelled has written a letter to the Editor of the Times of India and got it published in the issue today. The relevant portion which is related to my privilege motion reads as follows:

> "While we do not mind any enquiry against us we feel that the official action in publicising the names of the firms without any proved charge against them is unfair. It seems to be a politically motivated cheap gimmic."

This refers to the reply the Commerce Minister, Shri Mohan Dharia, gave in response to my compelling insistance on the floor of the House during the debate on the Demands of the Ministry. He did not do it *suo motto*. I also gave a notice to the Lok Sabha and also wrote to the Minister insisting to get fullest details about the criminal misappropriation of our precious foreign exchange of about 600 crores of rupees by 13 firms dealing in oils. In the list of names this firm's name should also be seen.

The unwarranted criticism and insinuations made in the letter under reference clearly amounts to a breach of privilege of the House where it is the right of the House to get fullest details on matters of public importance and therefore, this action is motivated and deliberate. The writer of this letter has shown contempt of the House and for this serious misdeed, he should be brought to book immediately and that could be done by referring the matter to the Pri-

vileges Committee unless of course, they tender unconditional apology and get it published for three consecutive days within a fortnight from the date of this letter.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am seized of the matter. I have just received the papers and I am considering them. It will be brought to the House tomorrow.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have given notice of.... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Giving notice does not mean that you just get up.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The persons connected with the International Society for Krishna Consciousness Ashram are CIA agents. Some of the persons were ordered to leave the country but they are still here. A shooting incident took place in the Ashram in which 24 persons were injured. Since the External Affairs Minister is here, he can say something on this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are getting information on this.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Many of the Members have given calling attention notices and short notice questions regarding handing over Bangladesh refugees by the BSF. Please admit it as calling attention.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have discussed this matter several times in this House.

12.30 hrs.

*DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78—*contd.*

MINISTRY OF INDUSTRY—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall resume discussion on the Demands for Grants in respect of Ministry of Industry. Shri George Fernandes.

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am glad that my introductory remarks have found approval from all sections of the House. The support extended to the basic thrust of our industrial policy by all the hon. Member who participated in the debate has given me considerable encouragement. Certain points have been raised which do not pertain to my Ministry. I shall refer them to the concerned Ministries, particularly, the Commerce Ministry and the Energy Ministry.

Some hon. Members of the Congress Party have joined issue with me for my saying that there has been a kind of degeneration, of three decades of devastation of our economy. Their case is that the country has progressed in the thirty years during which the Congress Party has ruled. Nobody denies that there has been progress in this country. But it is all a matter of how one looks at it. The British ruled this country for 150 years and during those 150 years, they built almost a thousand kilometres railway lines every year. In the thirty years during which the Congress Party ruled, it was only about a hundred kilometres per year. I wonder whether you would say that the country progressed much sooner under the British rule than under the Congress rule.... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY SPEAKER: Order, please; don't interrupt.

SHRI GEORGE FERNANDES: The British built ports and the docks, the telephone and telegraph installations and they even built this Parliament House. I wonder whether one would like to say that that was the progress because, while they were building these things, making progress in certain spheres, they were

*Moved with the recommendation of the Vice-President acting as President.

[Shri George Fernandes]

also devastating the country in certain other areas. During the last 30 years, this is precisely what has happened. I do not wish to go into all those statistics today which we have been debating in this House for years on end and, particularly, in the last three months.... (*Interruptions*). I know it hurts people.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): We have our sympathy for your ignorance.

SHRI GEORGE FERNANDES: When the country got Independence, there were 35 crores of people in this country.... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please don't interrupt. All of you please sit down.

SHRI GEORGE FERNANDES: I knew that it would hurt. But I did not know that it will hurt so much. (*Interruptions*).

I think they should make up their mind whether they would like anyone on this side to be responsible or whether they would like to say that there has been progress. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: If Mr. Ravi, Dr. Henry Austin and others stand up and talk like this, then I will ask everything that you say to go out of record. (*Interruptions*)

SHRI VAYALAR RAVI *rose*—(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Unless the Minister yields, you cannot interrupt.

SHRI GEORGE FERNANDES: It is a question of standard; it is a question as to how one looks at it. If by increasing unemployed every year by 2.8 millions is progress, then there has been phenomenal growth. That is a question of standard. You admit that you increased employment at the rate of 2.5 millions. Then you say that every developing country has to go through this. This is your standard. I am sorry, I do not accept that as progress. That is precisely the point that I am trying to make. (*Interruptions*). In the last ten years, for instance, the consumption of pulses, which is the only thing that provides protein to the poor in this country has gone down *per capita* from about 60 ounces per head to 35 ounces per head. If you believe this is the progress and phenomenal progress, our standard of progress is different.

In the last ten years, the *per capita* consumption of cloth has come down from 50 metres per head to 31 1/2 metres per head. If you believe that is the progress, then that is not our concept of progress. So standards differ, and it is in every sphere of our national life.

The number of people living below the poverty line has been going up. If you believe that this is the progress, good luck to you. The number of illiterates in this country has gone up. If you believe that this is the progress of the country, then that is your standard. So, when I talk of progress, I speak both in an absolute term and in terms of comparing our progress with those of other countries. Mr. Venkataraman took an exception to a point that I made where I cited statistics to say that progress has been 4 per cent in the industrial sphere. I suppose industrial growth which is about half of what the progress of the developing countries has been is much lower than the standard you set for yourself. He said, this is not true and that India's progress has been more than that of any other industrially developing country on earth that has attained independence since 1947. M. Venkataraman is very wise and very able administrator. He was Minister of Industry in Tamil Nadu, I think, for ten years. He was also a Member of the Planning Commission for five years. I do not know what authority he generally relies upon

for his information, for his statistics.

I have here a Report of the World Bank (1976). Between 1965—1975, the industrial production in all the developing countries of the world was about 9 per cent. It is on page 96. It is admitted that it is 4 per cent in this country. If you have any other authority, Mr. Venkataraman, I would certainly like to be enlightened on this.

SHRI VAYALAR RAVI: If you look to the World Bank's Report.....

SHRI R. VENKATARAMAN (Madras South): What I said was that no country which became independent after 1947, after the Second World War, had built this kind of industrial base, forging, casting, steel-producing capacity as India had done. I was not comparing the rate of development between one country and another, because, these percentages are all very illusory. It has happened in another case also: there was an occasion where it was said that the number of nurses had increased from one to two, and the report said that it had increased by a hundred per cent. Therefore, when you say 9 per cent or 8 per cent, it is from the base. If the base is small, the mere fact that you had a few things, say four or five, may be even 50 per cent or a hundred per cent. Even now I say this on the authority which you can check that there is no country, which has become independent after the Second World War, which has anything like our HEC, anything like our MAMC, anything like our steel plants. Do not compare with Japan and others.

SHRI GEORGE FERNANDES: May I quote this from Mr. Venkataraman's speech? This is what he had said:

> "If you compare with any country which has become independent after the Second World War, you will find, no country in the world has achieved a rate of industrial progress and industrial development as India has been."

While the debate did throw up a number of new ideas and Suggestions on how to achieve our goals of industrial development, it also helped me to gain an insight into the minds of the Members of the Opposition. It was quite amusing to see them find out the contradictions that existed in the Janata Party and in the Janata Government. And more amusing was their attempt to draw a distinction between the Minister of Industries on the one hand and the Prime Minister, the Home Minister and the Finance Minister on the other. These are old habits which keep lingering. There was a time when Pandit Jawaharlal Nehru was very good but Mr. Morarji Desai was very bad, Shrimati Indira Gandhi was very good but some one around her was very bad. These are old habits. I was thinking that, with the passage of time or with people moving from one side of the House to the other, some of the habits at least would die, but they do not seem to.

Sir, there are differing views in our Party. Ours is a democratic party. We are running a democratic government. For instance, there are differences among us on how the erstwhile dictator should be dealt with—very sharp differences. There are differences among us whether there should be a communication satellite in the orbit or not—very sharp differences. But this is what makes us really strong. This is the essence of democracy. This is what makes us strong—these differing views, where there is an interaction of opinions and ideas. I hope, they will learn that 'Indira is India', that kind of thinking where one person knows the best, one person knows everything, there is only one leader and the rest are just to be excepted, is what ultimately goes to weaken a political movement and a government.

So, if there are differences among us, those differences do not come in the formulation of a policy. What I have spoken before this House in so far as our industrial policy is con-

[Shri George Fernandes]

cerned, are not my personal views; they are the views of the Government; I spoke here for the Government; I did not speak here as an individual.

Sir, the opposition has cautioned me about the various dangers that are lurking around as we go ahead with our industrial policy. They have particularly warned me about the big business houses and the multi-nationals. I do not want to underestimate the power and the reach of both the big-business houses and the multi-nationals. But I would like to say, without being immodest, that they do not worry me at all. We, on this side of the House are made of much better stuff than that. These big business houses and these multi-nationals will not worry us. I know the big business has a way of operating: they believe that everyone is available for sale. But, Sir, none on this side is available for sale—and I think they know it too. And if there are people who are incorrigible and who still believe that they will be able to manipulate things the way they had manipulated them in the last thirty years, I am afraid they are in for a very bad experience.

As far as the multi-nationals are concerned, I know how powerful they are. In fact, they tried to gain control of the Government right here in Delhi. My friend Mr. Vijay Kumar Malhotra prevented one of them coming in. It was a Coca Cola man. (I think someone that side is particularly concerned about Coca Cola). There were two pictures when I was being driven from the jail to the court. In those days, there were two pictures, both with folded hands. The person whom Mr. Vijay Kumar Malhotra prevented from coming in was there on the streets of Delhi with folded hands, along with another picture, also with folded hands, asking the people to vote the multi-nationals into this House. But the multi-nationals have been defeated, right here in Delhi, in Amethi and even in Rae Bareli. Therefore, in so far as their effort to influence this Government is concerned, I think the people themselves resolved this question in March this year. I am however aware and I am getting to know of a number of deals which have been struck with the multi-nationals. I am trying to go into them and, as and when something very interesting shows up, I will come before this House and let the House know what the multi-nationals have been up to in this country during the last several years.

But there is however one class of parasites, and these are the 'con' men or the 'fixers' who operate even to this day. You see these men operate in the corridors of the Parliament House and of the Ministries. These are the men who blackmail the officials; these are the men who try to bully them or try to brow-beat them and get things done. They cater to the human weakness of those in authority: they now how to get things one. I am aware of the activities of some of them and I am trying to unearth the activities of some more of them. I only want to say at this juncture that we shall take care of them. We do not want to allow them to operate in the corridors of power in this Capital.

Now, my hon. friend Shri Unnikrishnan spoke about p. 56 of the Report. He was very particular about mentioning p. 56 of the Report on the working of this Ministry till March this year. He referred to the enquiry against the Birlas and he said that how I deal with this question will be a touch-stone. Sir, this enquiry commission—the Sarkar Commission—was set up in 1970, and this is the eighth year of its functioning. Each year, Rs. 2 lakhs were budgeted for this enquiry against the Birlas, and we have already spent a crore and a half: but the enquiry is still on! why is this so? It is because the terms of reference were so framed

that one can satisfy public opinion on the one hand and Birlas on the other. I am now told that this will be a touch-stone! In other words, what I am supposed to do about this Sarkar Commission has to be within the terms of reference, so wide and so varied that they will go on and on!

You throw back on me now and say that this will be my touch-stone. What do you want me to do? The Commission has done a lot of work; it has gone through 9,000 files out of 11,000 files produced before it, or which they have been able to collect. I hope, it would only be a matter of time. Despite all the problems faced by this Commission, we shall be able to do something worthwhile and be able to expose the misdeeds of big business in this country through the findings of this Commission.

SHRI O. V. ALAGESAN (Arkonam): Do you propose to alter the terms of reference?

SHRI GEORGE FERNANDES: It is very difficult to do that and start the whole thing afresh. The Commisson has been in existance for 8 years and altering the terms of reference would not be an exercise that would give us any result. But I want to assure the House that we shall do all that is possible and see that no one gets away with crime.

We want the industry to grow; we want it to expand and produce more and we shall give all the encouragement that is necessary to see that industry grows, expands and produces more. But, if there is any transgression of law, the reaction from the Government will also be equally sharp. We do not want industry also to commit crime. Earlier, during the Question Hour, there was a discussion about the economic offences. If a man picks somebody's pocket of a hundred rupees, it is a criminal offence, but if one cheats the share-holders, loots the exchequer and if he denies the workers their jobs, that is a very respectable act which is called an economic offence. We would like to change the standards, we would like to change these values and it is necessary to change the standards and values. If a poor man picks someone's pocket of Rs. one hundred, it is a criminal offence, but if someone else robs the share-holders of crores of rupees by mismanagement of a company and diverting the funds to the various other companies and loots the exchequer of all the public funds that have been put into the industry, it is necessary to re-examine whether this is to be called an economic offence, or this is also a crime of the same variety, or magnitude as when a pick-pocket or someone else robs someone on the street, or in fact of a much bigger magnitude.

Here, I will give you a very typical case. Shri Madhu Limaye, in his speech referred to Jaipur Udyog. Jaipur Udyog is quite a big cement producing unit, with almost half a million tonnes or a little more. Now, this is a sick unit and the Government is running it. The main reasons for its sickness, as detailed by the State Bank of India and which was quoted by Shri Madhu Limaye are:

> (i) "Continued fall in production arising out of neglect of essential, preventive and maintenance repairs of the plant over a number of years.
>
> (ii) Paucity of funds arising out of large scale diversion of funds through their sole selling agents, BOPL.
>
> (iii) Managerial misdemeanours in the areas of sales, purchases and expenditure. The management pursued policies and practices inconsistent with the interests of the company."

This is the State Bank of India's report. Since this report was made and since the government got itself involved with the affairs of Jaipur Udyog, certain other matters pertaining to the transactions of Bharat Overseas Ltd. have also come to light and they are very serious. We will examine this

[Shri George Fernandes]

whole question of Jaipur Udyog and take certain far-reaching decisions...

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): 6000 workers are in distress.

SHRI GEORGE FERNANDES: Just now the plant is working and it is now working to its full capacity.

But, as I said, a lot of other things have come to light and we shall take certain decisions.

Shri Madhu Limaye also referred to National Rayons. This matter is very serious—the National Rayon's affair... (*Interruptions*) I will examine the various issues that have been raised in regard to this company on the floor of the House and at the level of the government, appropriate decisions will be taken. But that is one more illustration how big business operates and how influential big business are, because the man who is managing this company or rather mismanaging this company is Sudhir Kapadia, a Director of Maruti Ltd. I can now understand how serious the Congress Members were when they were warning of the reach of the big business.

So, the Modi's have also been referred to in the course of the debate and some of their own actions earlier in so far as Modi Rubber is concerned and since then their dealings with National Rayons have been referred to. Sir, I am examining this entire case and will inform the House of the findings at the earliest... (*Interruptions*).

Then, about Coca-cola. In fact, even now Congress Members are agitated about Coca-Cola....

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Which drink does the hon. Minister prefer?

SHRI GEORGE FERNANDES: Neither.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): *Neemou pani.*

SHRI GEORGE FERNANDES: The Coca-cola problem is not just a problem which is a problem of multinationals. It is also a much wider problem of priorities and planning, of the concepts of progress and of the standards of progress which the predecessor government had.

Coca-cola has reached almost all the villages of the country. But there are two and a half lakhs villages in this country which still do not have drinking water. That was planning, that was progress.

Just two and a half lakhs villages, Mr. Ravi.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Many members on this side including Ministers did not approve of Coca-Cola. They opposed Coca-Cola. You can go through the record.

SHRI GEORGE FERNANDES: But they are very powerful.

SHRI VAYALAR RAVI: Agreed. They are powerful.

SHRI GEORGE FERNANDES: Ultimately they managed to get a ticket right here in the capital.

Two points have been made with regard to Coca-Cola. One is that a licence has been given and the other is that some money has passed under the table. I can assure the House that no licence has been given and if there is any evidence or any material which can give any clue to the transfer of money. I shall be happy to have it investigated provided I get some clues. At the moment, excepting the statement made here, I do not have any other information in my possession.

13.00 hrs.

Mr. Venkataraman talked about cement production. I had referred to

cement as one of the major constraints while I was discussing the various problems which confronted us when we discussed our industrial policy. He said that cement production will fall short of the targets set by the Planning Commission. I am afraid this is not so. The Planning Commission set a target of 23.50 million tonnes, with actual production of 20.8 million onnes in 1978-79, *i.e.*, at the end of the Fifth Five Year Plan. This target, will materialise. My grievance is that the target itself was inadequate. During the current year there will be a shortage of 2 million tonnes of cement because of this haphazard planning. In the Draft Fifth Five Year Plan the targeted capacity in 1978-79 was fixed at 29 million tonnes. But when the Plan was finalised I am sure Shri Venkataraman is aware of that, these projections were reduced and they were brought down from 29 million tonnes to 23.50 million tonnes, with actual production of 20.8 million tonnes. The earlier projections were realistic, the subsequent ones were not. It is because of these unrealistic projections and subsequent modifications that were made, the country will have to face shortage of cement. The present Government would seriously consider ways and means how this mistake can be rectified and how we solve the cement problem.

Shri Unnikrishnan was deeply perturbed about Government's attitude to the Public Sector. I have in my introductory remarks set at rest all fears, imaginary or otherwise that people had entertained aobout our approach and attitude to the public sector I can only reiterate that in our scheme of things the public sector has a very important role to play in the economic and industrial development of this country. There are deficiencies, as I have said, and there are inefficiencies also so far as the public sector is concerned. It shall be our endeavour to see that whatever those deficiencies and inefficiencies are, they are removed and the public sector does play its rightful role in the economic development of this country. And here I would like to make a special appeal to the workers and to the management of public sector enterprises. While, I shall work out in consultation with them the plan that has to associate workers with the management of these industries, I would also like them to have a total innovative approach to see that production targets are fulfilled. We are having problems in some of the units at the moment and I would like to take this opportunity to appeal to them to see that the targets are fulfilled even while resolving all the disputes and even while we work out new plans and programmes to associate them to the management of these sectors.

We propose to enlarge the Management Development Institute of Heavy Electricals Limited. It was an Institute that was concerned with Training, Management and Workers in this one big public sector enterprise. But now we propose to convert this centre for continued education to cover the entire public sector. This centre would catch not only the executive of the public sector enterprises under the Ministry of Industry but would also provide periodical courses for the workers representatives on their respective rolls.

Shri G. Narsimha Reddv had observed that out of 5 cement projects prepared by the Cement Corporation of India, only three had been cleared. I am happy to announce that the Government have now cleared the remaining two projects. These would be set up at Tandur and Adilabad and orders for certain materials and equipments for these two projects could be placed in September and October of this year.

A point was raised as to why Government should import wrist watches. Somebody suggested that we were now concerned with importing some kind of luxury items. In the current year we have given permission to HMT to import one million watches

[Shri George Fernandes]

in completely knocked down condition. These watches will be imported from the collaborators of the HMT in Japan, the Citizen Watch Company. They will be marketed under the brand name of the HMT watches, HMT Citizen; and they will be assembled in various units of the HMT particularly in Darjeeling in West Bengal, where we are setting up units for assembly of HMT watches.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: What is the difference in cost? What is the difference in the price of the two, your own watch here and this one which you bring in a dismantled condition?

SHRI GEORGE FERNANDES: There should not be any difference in the price.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Then what is the use.

SHRI GEORGE FERNANDES: There is a deficit of watches for the country's present-day needs.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: My point is this. If there is no difference in the price of these two, what is the use of importing the watches in a dismantled condition?

SHRI GEORGE FERNANDES: I will explain it. We need 5 million to 6 million watches a year. This year's requirement is 5.6 million watches. Production is not adequate to meet our needs. Our production this year, 1976, would be 1.25 million watches both in the private and public sectors.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : कब तक हम घड़ियों के मामले में आत्म निर्भर हो जाएंगे और हम को विदेशों से घड़ियां मंगानी नहीं पड़ेंगी, विदेशों पर घड़ियों के मामले में निर्भर नहीं रहना पड़ेगा ?

SHRI GEORGE FERNANDES: यह भी बता दूंगा ।

So far our watch requirements were largely met partly from indigenous production and partly by permitting smuggling. Nothing was done over the years to see that the capacity of the watch industry was expanded. HMT had technical know-how, expertise and manpower. The private sector also had expertise and manpower. But nothing was done over a period of years to see that India is selfsufficient so far as watches are concerned. On the contrary those who were smuggling watches into India were considered very respected men, who even worked as campaign managers of certain persons of a certain political party. We now propose to increase the capacity in our own HMT unit. In the meanwhile this year we are importing one million watches in completely knocked-down condition and assembling them here. We are in fact setting up a number of assembling units.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI (Anantnag): The point is whether it is worthwhile to import watches in a dismantled condition or to have it imported as a whole. Mr. Venkataraman was speaking about providing more employment and at the same time not increasing the cost of production. If you assemble them here your cost will be more. If you compare the price of the two your watches will not be able to sell. Smuggled watches will have a ready market in the country as the price of smuggled watches seized by Customs and then released for sale would be less.

SHRI GEORGE FERNANDES: I shall have that matter examined.

SHRI D. D. DESAI (Kaira): For the initial training, it is necessary to pick up tempo of larger production. That is why CKD watches are being imported.

SHRI GEORGE FERNANDES: We are just now importing it in order to meet the immediate requirements. We are setting up eleven watch as-

sembly units in this country. We are setting them up in Sikkim, in Goa, in U.P., M.P., Meghalaya, Maharashtra Tamilnadu, Punjab, Kerala, Orissa and Andhra Pradesh.

The above units are a part of the expansion programme of H.M.T. to increase their watch-manufacture, from one million handworn watches to three million per annum, in 1980-81.

In the meanwhile, I would like to work out a crash programme so that, within the next three years, India is made self-sufficient in so far as our domestic watch requirements are concerned.

SHRI R. VENKATARAMAN (Madras-South): If that is so, why did the Finance Minister put the watches in the negative list?

SHRI GEORGE FERNANDES: We will examine that. I shall find that out. On the other hand, let us first meet our domestic requirements of watches and then let us talk about export. We have been exporting too many things to meet our own requirements. I think, we should stop this practice. A question was raised about the H.M.T. project in Gujarat. A project is being set up by the Gujarat Industrial Development Corporation, a Government of Gujarat undertaking in collaboration with the Hindustan Machine Tools Ltd.

The H.M.T. will have 25 per cent of the equity in the Gujarate State Machine Tools Corporation. The cost of this project will be about Rs. 11 crores. Possession of land for this project has been given to the company by the Government of Gujarat only a few days back. The construction will commence in August 1977 and we expect the production to commence in January 1979. This is a further proof, to those who are concerned about the government not being keen particularly about the public sector, of expanding the public sector to which this Government is committed.

SHRI VINODBHAI B. SHETH (Jamnagar): Small scale industry has died due to excise.

SHRI GEORGE FERNANDES: That is a different question.

Another question was asked as to why the WIMCO, a foreign majority company was dominating the field of the small scale industries. WIMCO has been operating in this country for several years. They have five factories with a capacity of 5,000 million boxes per annum. But, Sir, the production of matches has now been reserved for the small-scale sectors since 1970 and, as at the moment, while WIMCO has thirty per cent of production in this country, the remaining seventy per cent of production is taken care of in the small-scale sector.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): The question is not only of reservation of the production in the small-scale sector but the question is: while large companies are able to buy soft-wood at a concessional price of Rs. 5/- per ton, this concession is not extended to small-scale sector. They buy this wood at Rs. 20 per ton. The concession has been allowed only for protecting the big manufacturing industries. Therefore, I want to know whether this aspect will be gone into by him or not.

SHRI GEORGE FERNANDES: We will go into this aspect to find out under which circumstances, the WIMCO was given this special concession. In the meanwhile, in the current budget, the small scale match units have been given further concessions in excise duty of 55 paise per gross of boxes. There is now the problem which the small scale units face. That relates to the paraffin wax which they need. The Ministry of Petroleum and Chemicals is concerned with this. There have been certain problems.

[Shri George Fernandes]

The Health Ministry has raised certain objections against the production of inferior quality paraffin wax on the ground that it would find its way as wrappers used in food industry, etc., which would be injurious to health. To relieve the temporary shortage of good quality paraffin wax the government will consider imports by the small scale sector if such requests should come from them.

A point was made that while in the course of my observations I had laid tremendous emphasis on the growth of village and small scale sector, in fact statistics and figures in the budget documents show something else; certain figures were quoted. So far as allocations to small, rural and cottage industries are concerned, there has been an increase of 40 per cent in the proposed outlay for 1977-78 over the revised estimates for 1976-77; from Rs. 41.2 crores in 1976-77 the outlay has been increased to Rs. 55.9 crores in 1977-78. In addition for handicrafts, handlooms and sericulture looked after by the Ministry of Commerce, the allocations have been increased to Rs. 27 crores in 1977-78 from about Rs. 13 crores in 1976-77. It is more than a 100 per cent increase. On the other hand the total investment in the planned schemes for large, medium industries including heavy industries under the Ministry of Industry during 1976-77 was Rs. 127.99 crores and it was raised to Rs. 180.35 crores for 1977-78 in the interim budget presented to Parliament. This has since been reduced by Rs. 12.45 crores and funds have been allocated to small scale and the rural sector. In addition, in order to improve the infra-structure in the rural areas an allocation of Rs. 20 crores had been made to accelerate the programme of approach roads; a further allocation of Rs. 40 crores had been made to provide drinking water in the rural areas. I do not know how the critics of this policy got the idea that while the thrust was for rural development, and for small scale industries development, in fact the figures were to the contrary. That does not seem to be so if one were to go through the budget proposals carefully.

In so far as small scale industries are concerned, I had said that we shall examine certain sectors which we shall completely reserve for the small scale industry. There has been some criticism that small scale industries were corrupt and sell in black market some of the raw materials that are given to them. There may be blacksheep in the small scale industry as there are blacksheep in various other sectors also. But our commitment is to see that this sector grows, that this sector is encouraged. We shall take positive steps to see that certain additional areas are reserved for the small scale sector during the current year.

SHRI R. VENKATARAMAN: In the 1976 Finance Bill there was an investment allowance of 25 per cent given to small scale industries but in the present Finance Bill all the small scale industries do not get this investment allowance; only those which are not governed by the negative list will get. Therefore the investment allowance which was given to small scale industries has been reduced. That is why we said that emphasis has not been laid on small scale industries.

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, in addition to these, whatever are the constructive suggestions that come from the other side each one of them will be examined and whereever it is appropriate, it will be acted upon.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: May I then make a constructive suggestion? When he is talking about small scale industries there is excise duty that has been levied on the hosiery industry which is mainly a small scale industry and on which thousands of workers are dependent

and which are mainly in the smaller district towns in the country where they do not have any protection. This excise duty is not levied on those who are producing ready-made cloth. Therefore this being a constructive suggestion, will the hon. Minister use his good offices to persuade the Finance Minister to withdraw that excise duty when the Finance Bill comes up for discussion and also the duty on the Beedi Industry to which my colleague and leader Shri M. N. Govindan Nair has referred.

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi): May I draw the attention of the hon. Minister to the matter of a small scale industry? After the Budget was presented, the excise duty on copper scrap was increased from 45 per cent to 120 per cent. This scrap is needed for chemical industry for insecticides and things that are necessary for our agriculture in the country. The result of these duties are that the scrap will be 20 per cent costlier than pure copper and about 30 to 40 small scale industries in Pune and other places will be wiped out as a result of the excessive financial burden. Will the hon. Minister see to it that the excise duty is withdrawn?

SHRI GEORGE FERNANDES: I think the hon. Members will use their persuasive powers not only with me but also with the Finance Minister. (*Interruptions*).

All that I am saying is that there is a time to take up every issue. I am not admitting anything else. There are issues which pertain to Commerce Ministry relating to handloom and hosiery sectors and they should be raised during the discussion on the demands of that Ministry.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: We did raise.

SHRI GEORGE FERNANDES: My point is that Shrimati Parvathi Krishnan should use her persuasive powers at the appropriate time when the demands of the concerned Ministry are taken up. A reference has been made to a number of sick units. Mr. Halder referred to a large number of units in Bengal. There have also been references to the BIC and the TAFCO. Members from all sides have made references to the sick units in Bombay, Bihar, U.P. and Tamil Nadu and in every State. I can only assure the House that shall apply my mind to each of these cases and take immediate steps to resolve the problems faced by the workmen of these units in particular and by the industry in general. Here I may be permitted to do some loud thinking. I am wondering whether the workers employed in these sick units could be persuaded to take over the management of these units. We shall give them all the assistance that they would get otherwise. We shall give them all the financial assistance. Let the workers have a committee of Management. We shall give them any expert advice that they need.

We can have a representative of the government on the committee of management. I think the stage has come when the workers should come forward to take this responsibility. I am not making this suggestion because the units are sick and someone has to run them. Where because of mismanagement a unit becomes sick, I do visualise a situation where the workers by taking over the management may be able to show to the industry and to the country that they are in a position to manage better than so-called industrial houses.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon): The Cashew Development Corporation of Kerala has on its board of management only representatives of workers and it is working very fine.

SHRI GEORGE FERNANDES: Mr. Nair is only substantiating my point. Therefore, I would like the trade unions in these so-called sick units to come forward with any suggestions they may have in so far as

[Shri George Fernandes]

their own running these units is concerned.

SHRI AMRIT NAHATA (Pali): The working class of this country has always thrown a challenge that most of the sickness of the mills is due to mismanagement and if an opportunity is given to the workers they would show it by managing them properly. Suppose in a particular sick mill, the workers come forward and take up the management and run it successfully, would the minister think of handing over healthy mills' management also to the workers?

SHRI GEORGE FERNANDES: If this is a suggestion, I have no hesitation in accepting it. In fact, I would like to see the growth of the workers' sector in the country where workers do run the industries and show they can do it far more efficiently than what the big business has been doing over a period of time.

PROF. R. K. AMIN (Surrendranagar): Regarding the sick mills, the State Governments have followed different policies for different industries. Is this not the time to evolve a comprehensive policy so that the State Governments and the Central Government may follow the same policy in regard to all industries?

SHRI GEORGE FERNANDES: I do not think any uniformity in this matter is possible. As I said, I am only indulging in some loud thinking and I am making a suggestion to the workers. At the moment we have about a hundred sick units queued up wanting to be taken over here and now. It is a question of resources. Where there are such problems both of money and management, I am making a suggestion that if the workers are prepared to run the industries, the government would provide them with all the necessary expertise and inputs to see that they run those industries.

A point was made about import of capital goods. Some members expressed concern that we were going to import capital goods and machinery when indigenous industry is starved of orders. Mention was made particularly of the textile machinery. The Department of Heavy Industry provides most of the capital goods required for various industries. I want to assure the House that imports will be allowed only if our own industry is not in a position to provide the requisite machinery. In no other case we shall allow the import of machinery. But where our industry unable to provide machinery at the right time and at a cost which is, shall I say, reasonable in such a situation i.e., where we are concerned with the growth of industry, it will be necessary for us to permit such imports. But nothing will be done to hurt our indigenous industry, if the industry is able to meet the requirements of the industry, at the appropriate time. Suppose we need a cement plant—this is by way of illustration; I know it would not be necessary for us to import cement machinery—and we need machinery to do it, and our industry is unable to provide a plant for the next two years. I am sure no one, no matter what his convictions are, would say that one has to wait for two years to be able to put up a cement plant. This is the size of the problem. But we will not, if our cement plant producing unit is in a position to provide the machinery tomorrow, say that this industry will be starved and that we are going to import machines. That will not be the policy of the government.

श्री लखन लाल कपूर (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवासी भारतीयों के लिए इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक नीति बनी थी कि जो प्रवासी भारतीयों के पास फारेन एक्सचेंज है वे कैपिटल गुड्स को यहां लाकर, अपने पैसे से मशीनरी खरीद कर यहां इंडस्ट्रीज स्थापित

करना चाहते हैं उनको सरकार की ओर से सुविधायें दी जायेंगी परन्तु जो प्रवासी भारतीय यहां पर उद्योग लगाना चाहते थे उनको सुविधायें नहीं दी गई और उनको वापिस जाना पड़ा । तो क्या ऐसे प्रवासी भारतीयों के लिए जो भारत में उद्योग लगाना चाहते हैं सरकार उनके लिए उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री जार्ज फर्नांनडिस : यदि ऐसी कोई स्थिति है कि जो लोग ऐसा करना चाहते थे उनको ऐसा नहीं करने दिया गया तो उसकी जांच कर ली जायेगी और इसके बारे में क्या नीति रही, क्या नीती आगे रहेगी उस पर भी विचार करके निर्णय ले लिया जायेगा ।

Many other specific questions have also been raised; but I do not think it will be possible to answer all of them here. Members have referred to under-utilization in the tractor industry and the power-tiller industry as also to the working of the Mining and Allied Machinery Corporation and of the Lagan Jute Machinery Co. I have noted all these points; and where necessary, action will be taken and I shall also inform the Members who have raised these points, of the decision taken in regard to these questions.

Lastly, I will refer to the problem of backward areas and their development. Mr. Purna Singh suggested that we should treat the entire North Eastern region as one backward region for purposes of development.

Other Members who participated in the debate have also spoken of their respective States, regions and even of districts or constituencies. Yesterday I was in Patna and I heard legislators of the Bihar Assembly discussing the question of industrializing their State and their own respective constituencies, and speaking about the problem of backwardness in their respective areas. In terms of investment by the Central Government, it may come as a surprise to my colleagues from Bihar when I say that the largest investment by the Government of India is in Bihar. As on 31st March 1976, it was Rs. 1882 crores; and yet Bihar is the most backward State in the country. Madhya Pradesh has a Central Government investment of Rs. 1366 crores; and yet it is also one of the most backward States. And Orissa which vies with Bihar for being in the list of States that are backward, has the third largest investment by the Government of India, *viz.*, Rs. 619 crores as on 31st March 1976. I am giving these figures to point out that declaration of an area as backward and pumping in of money into the big industry, is not going to find the answer to the problem of unemployment or of development of these areas.

So, the whole investment pattern has to be changed, and that is the thurst that is contained in my introductory remarks. While heavy industry is required, and heavy industry would be sustained, yet in the coming years our emphasis will have to be in the rural sector, small-scale sector and the village sector.

Any investment of a lakh of rupees in the big sector provides employment to four persons only, and there also there are always complaints that people from other States come to their States and take away these jobs, because some of these jobs are skilled jobs. The larger the investment, the more sophisticated the plant and you need skilled people who may not be locally available. They come from other parts of the country and there is local complaint that the employment generated has been taken away by the skilled people from outside. So, an investment of a lakh of rupees provides employment to four persons in big units and in small units the same investment provides employment to 20 to 25 persons, whereas in the rural and villages sector we are able to provide employment to 60 to 70 persons with the same investment; sometimes more but never less. Therefore, when we discuss back-

[Shri George Frenandes]

wardness and when we refer to the fact that the Centre should have a policy, that we should declare a particular area backward and put in more money, that money, instead of going into large scale and big industry, must go into small-scale, rural and cottage industries.

One of our problems in the industrialisation of the country is that of planning Industrial planning so far has taken particular care of a small segment of our people. We produce may be for 50 million to 60 million people. Those were the consumers in mind when one discussed the industrial policy, generally speaking, as to what are the needs of this particular segment of our population, which is about 10 per cent or may be even less than 10 per cent of the people. The rest of the people have not existed, so far as planning was concerned, so far as industrial development was concerned. They have no purchasing power, they do not figure in any of the schemes, in any of the programmes or plans that have been outlined for the past several years. So, we would like now to pursue a policy where the purchasing power is no more concentrated in the hands of a few, where the whole economic development and industrial policy does not act in a manner in which every year 10 lakhs or 15 lakhs of people are raised from certain standards of proverty and brought to standards of, may be, affluence or may be a certain standard of living. This is how things have been every year we have attended to 15 lakhs to 20 lakhs of people, and the rest of the people, may be a crore of people each year, are condemned to a life of destitution. They have no purchasing power and you do nothing to increase their purchasing power. In your industrial policy, there is no scope for additional employment, no scope for further expansion of employment for the huge market of 600 million people, which is expanding at the rate of 12 millions a year. It would be possible only if the purchasing power is taken into account, is diffused, so that it goes into the hands of a larger number of hands, and this would be possible when industries in the rural, village and small-scale sector are encouraged, and this will be our effort in the coming years.

When one discusses backwardness, I do not want to suggest that there are a few States in this country which alone are backward. Take Maharashtra, where Bombay has perhaps half the wealth of India. But, just across the creek, Konkan is just as backward and poor as the poorest backward districts of Bihar. This is a fact.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): Do not forget me.

SHRI GEORGE FERNANDES: Orissa is generally categorised as a backward State. When one discusses backwardness, Orissa invariably comes to one's mind, even though, of course, you do not look backward. Therefore, it is not only a question of certain areas or certain States but it is a question of the entire country. So, what I have stated in my introductory speech about this new thrust in the rural areas and in the small scale sector, that will guide us.

I am grateful to the hon. Members for the many suggestions that they have made in the course of the debate. I want to assure the House that in the coming days we shall implement a policy which makes it possible for us to remove that backwardness, that poverty which has been the bane of our country. I hope, Members will cooperate with the Government in fulfilling the various tasks that we have set before ourselves in so far as our industrial policy is concerned.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I put all the cut motions together.

All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to *complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1978, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 62 to 64 relating to the Ministry of Industry."

The motion was adopted.

Demands for Grants, 1977-78 in respect of the Ministry of Industry voted by Lok Sabha.

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 30-3-1977		Amount of Demand for Grant voted by the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
	MINISTRY OF INDUSTRY				
62.	Ministry of Industry .	1,05,87,000	..	2,11,74,000	..
63.	Industries . . .	7,98,69,000	80,04,89,000	15,87,37,000	147,74,79,000
64.	Village and Small Industries.	12,81,28,000	10,82,78,000	26,42,56,000	25,85,55,000

MINISTRY OF LABOUR

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demands Nos. 68 and 69 relating to the Ministry of Labour for which 6 hours have been allotted.

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to *complete* the sums necessary to defray the charge that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1978, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 68 and 69 relating to the Ministry of Labour."

Demands for Grants, 1977-78 in respect of the Ministry of Labour submitted to the vote of Lok Sabha.

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 30-3-1977		Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
	MINISTRY OF LABOUR				
68.	Ministry of Labour . .	28,33,000	..	56,67,000	..
69.	Labour and Employment .	22,46,00,000	3,15,000	44,76,00,000	6,31,000

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move thei. cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.

Now, the discussion will go on till about 6.30 and the Minister will reply tomorrow. I think that is the best arrangement that we can have. Shri Sathe.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Let me begin by, first, welcoming to this portfolio a young, dynamic and balanced person as Labour Minister. I believe that this is a vital and important portfolio particularly in view of the fact that one of the major planks of the Janata Government is employment and that is immediately connected with Labour portfolio. Therefore, I am hopeful that the hon. Minister would be able to pursue a clear-cut policy with the infrastructure that he has in his Ministry, with the various reports that are there, with the Bhagwati Committee's Report having been completed.

So, we have in this Ministry today a fair enough picture of the problem of unemployment and also of the ways and means, of tackling it provided the hon. Minister is able to implement the programmes and policies which they themselves have announced.

I would like to take this question of employment and particularly related to various machinery that they have, such as, the employment exchanges and the working of the various institutions. It appears from the Report, Part II Volume, connected with this subject that there is a wide range of training programme and that covers training of crafts, technicians under the network of the institutes, like, about 356 Industrial Training Institutes with the seating capacity of 1.54 lakhs, the Advanced Training Institute, Madras, for training high-skilled workers with the UNDP assistance, the Foremen Training Institute, the Central Staff Training and Research Institute at Calcutta, the Central Training Institute for Instructors, the Advanced Training Institute for Electronic and Process Instrumentation and Similar other institutes that have been set up.

Now, if we see to the problem of employment that has been tackled, we will find that the employment in the organised sector increased from 196.71 lakhs as on 31st March, 1975 to 202.07 lakhs at the end of March, 1976. The number of people employed in the public sector are 128.68 lakhs and 68.4 lakhs in the private sector. As far as the people who are today on the employment register, the Report says that a total number of work seekers on the live register of employment exchanges showed a rise of 5.2 per cent from 93.26 lakhs in December, 1975 to 98.13 lakhs in December, 1976. The total number of placements effected during 1976 were only 4.91 lakhs. This will show that as far as the educated unemployed are concerned, that is, those who are of matriculation standard and above, their number was 49.34 lakhs at the end of June, 1976 as against 43.42 lakhs in June, 1975. No break-up has been given of placements found for the educated unemployed.

13.50 hrs.

[SHRI SONU SINGH PATIL *in the Chair*]

As far as Scheduled Castes are concerned, out of about 13.3 lakh persons, only 38508 have found placement. This shows that we have not touched even the fringe of the problem of finding employment. If we find employment only for the additional job seekers, which has been done, that is, about 5 lakh persons, then you still have on your hand a backlog of over 93 lakh persons. You can understand the magnitude of the problem of unemployment in this country.

If this problem is to be really tackled, then it is obvious that we will have to find employment not in the organised sector, which has reached more or less a saturation point, but in the rural sector. The Minister of Industry himself is a great trade unionist. It is heartening to hear from him that he is planning the increase of employment in the rural sector, in the small scale industries. If this is coordinated with the Ministry of Labour and both the Ministries work together along with other Ministries concerned, particularly the Ministry of Finance, I have no doubt that this is not an impossible task.

The man-power and the labour force that we have in this country is so great, as you know, that the real wealth is always our goods. In basic economic term, wealth is what labour creates by its work on land and the land means all the resources. When I say labour, it includes everything like artisans, artistes, skilled and unskilled. Therefore, if this wealth is to be created, it has to be in terms of creating more goods, and when we talk of goods, let us think in terms of essential consumer goods. If we comproduce in the rural areas basic consumer goods, it is good. We have the resources. It is not that there is any dearth of resources in this country. In the rural areas, you can produce agricultural commodities. Agro-industries can be brought up. Essential things like poultry, food stock, vegetable, handicrafts for necessity of life like furniture, other things, like other goods, can be produced there. There is no dearth of raw-material.

The only question today is, as I said once here, that you always think in terms of economic market. In the urban areas, as far as market is concerned, the purchasing power is hardly restricted to two crores of population; the remaining 60 crores is not the market in economic term, and therefore, they have no purchasing power. and you do not have any goods to produce for them, even these goods that may be produced in the small scale sector. We find that they depend on the urban market and if they cannot sell their goods in the urban market in competition with the capital intensive advertisement based industries, large scale industries, then their goods would not be sold. That is the real problem. The crux of the matter is the marketing of these goods.

I have something to do with the small scale industries and I can tell the hon. Minister that the main problem of these industries, of the self-employed people in the rural areas or small towns is: (a) raw-material assurance and (b) marketing of the goods.

These are the two major constraints. If you can control the total national market of essential commodities, if you can regulate it and stop this competition with the Lever Brothers, with the multinationals, with even the monopolists in the country, it will be good. The other day some hon. Member was asking: 'Why do you need competition in the area of soap or tooth-powder or tooth-paste or some such small things which can be produced by any matriculate knowing a little bit of chemistry and technology? ' Don't you know that, in your public sector, in your government departments, you do not purchase a bucket or a shovel or a pick-axe produced by a small-scale manufacturer? Why? They say that it must have he stamp of Tayyabji or Tatas or some much thing. Your own officers do not encourage the small-scale producers. Government is one of the biggest buyers in the country. You should encourage the small-scale people. Your Ministry, while formulating the entire national plan, will have to think in terms of this basic thing, how you are going to market the produce. There should be no fear of that. If they produce, then they get the purchasing power in the rural area.

[Shri Vasant Sathe]

Immediately there is a market there also.

My friend was talking about khadi. I have my reservation there. Let that not be a fad. When you think of khadi, let us think of handloom, that is, what can be produced on a larger scale; and a good cloth can be produced if your spinning mills can give yarn to the handloom weavers. But you have to protect them from competition with the large scale sector. Here lies the whole total panorama of the employment problem. It is no use merely paying a lip sympathy; Ministries after Ministries, Government after Government, have been doing it, but they have not been able to tackle the problem because they leave it to the people to market their goods which the poor people, in competition with the large houses, cannot do. Therefore, marketing is the essence of providing employment on a large scale and relief to the producers of essential consumer goods.

Then I would also like to submit that, if you really want to give employment, then you must reserve areas relating to consumer goods to the small scale and village industries. Today what is happening in our country? Whereas in the public sector you produce the infra-structure base, the raw materials required like the steel, coal, cement, fertilisers power and all other things, producing the entire profit-making goods, consumer goods, is in the hands of the private sector. That private sector, basically, is the large scale sector. Who, as I said, produce only for that class where there is purchasing power and make all the profits, and those profits are accumulated in the hands of a few in the private sector who get richer. The gap between the rich and the poor is, thereby growing; the number of the people living below the poverty-line has grown; they are about 60 per cent in the country today. How are we going to fill this gap? Unless you deliberately make a plan .. ...

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may address the Chair.

SHRI VASANT SATHE: I am addressing them through you, Sir. You can always take this for granted. If I do not look at you always, please forgive me, Sir.

14.00 hrs.

I would like to submit that the main thing is to regulate the productive activity in the country, particularly the production of essential commodities.

Who is going to produce these essential commodities? Unless you determine this, you will not be able to solve the problem of unemployment in this country. Imagine what tremendous resources we have—60 crores of population of whom at least 30 crores are work-worthy. If their 60 crore hands can just produce goods, we can flood the world market and not only fulfil the necessities within our own country, especially with the cheap labour that we have. See what Japan does. A country with only 4 crore people, it brings iron-ore and other raw materials from other countries of the world and produces 110 million tons of steel and steel goods and sells them to different countries of the world. While that country can do this, we, with so much iron ore in the country, produce hardly 8 million tons saleable steel—and then we start perspiring and ask what we are going to do with the surplus stocks—surplus stocks of steal surplus stocks of coal, surplus stocks of cement, etc. How can we have a surplus of these things with so many people needing these goods in the country? This is only because, as I have said, to begin with your whole economy is the economy of a mini-India with 2 crore people and not of a 60 crore India. If you want to solve the problem of unemployment, you will

have to think in terms of a 60 crore India, the total India. Then alone will you be able to mobilise and utilise the resources properly.

Talking of employment, you have the National Service Act. I was surprised to see from this Report that National Service is defined to mean only that service which has something to do with defence of the country. I do not understand why there is such a restriction on the definition of National Service. Any developmental activity of a nation building character should be a National Service. We can employ lakhs and lakhs of persons in nation building projects like, for instance, the completion of the Rajasthan Canal or any other big river-valley project. Irrigation is such an important thing and if we can cut across our party barriers we can make a worthwhile effort. You, with such tremendous popularity, can mobilise the motivation of the people of this country and we, on our side, will cooperate with you in any such effort—because this is not a Party matter but a national matter. Under the National Service programme, let us enthuse our youth and involve them in such projects of nation-building character as the river-valley projects—the completion of the Rajasthan Canal, which I mentioned earlier, the Chambal Valley scheme or any other such programme. You will be able to employ lakhs and lakhs of young men there by rotation and, when the programmes are completed, you can give employment to these people there.

You have the Apprenticeship schemes; but see the tragedy of these schemes. You have trained so many young men. They come to us and they must be coming to other Hon. Members also with the complaint that they have been trained but there is no employment for them after completion of the training. In the Employment Exchange registers there are lakhs and lakhs of people. Ninety-three lakh people are on the live registers, but this does not give a true picture of how many people are actually unemployed as this covers only those industries which employ more than ten persons, while self-employed people and agricultural labour etc. are excluded from its purview. The picture is therefore incomplete. And yet, even for these 9 lakh people we cannot provide employment. Why is this so? It is because there is no co-relationship between the availability of Jobs and the persons for whom placements are to be found.

I would beg of you to consider in this context the increasing age of those who are on your live registers. As long as they remain on your live registers, the age limit should be calculated taking into account the years they have been on your live registers. After one has attained 25 years of age, it is said that he is not fit or considered not fit for any job in Government, semi-Government or other offices. This is one suggestion that I would like to make.

While talking of these employees categories, I find from your Report that out of 13 lakh women job seekers, hardly 58,000 women were able to find placement. We know that our capacity to find placement for them and other in this country is very limited, but you will have to open very wide range of self-employment jobs in the rural and also urban areas to accommodate specially women, weaker sections of our society, scheduled castes and scheduled tribes etc.

My second point is regarding the labour laws of our country. This is another subject which concerns this Ministry. I have had to do something with labour legislation as a person who has worked in the trade union field for more than twenty-five years and as one who has been fighting labour cases from labour courts right upto the Supreme Court. I can

[Shri Vasant Sathe]

tell you from my personal experience that it is high time that we have one comprehensive labour code. This has been talked of and thought of, but nothing has been done so far. There is such a plethora of labour laws overlapping each other like Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Industrial Disputes Act, so many other laws for the welfare of the workers; every State has its own Industrial Relations Act; the Provident Fund Act, Maternity Act etc. and so many other laws meant for the benefit of the employees. But what happens now? A large section of the employees are out of the purview of the Industrial Act, because the courts have declared that they do not come within the definition of workmen. For example, medical salesmen were not considered as workmen; hospital employees were not considered as workmen. One Supreme Court judgement said that they were workmen, later another decision of the Supreme Court said, they were not workmen. Therefore, I say, that there must be a comprehensive code concerning the labour and the benefits which should be given to them. If you prepare a comprehensive code, you will be able to solve many problems. The employer-employee relationship should also be covered by that code. I find that in the Industries Development Regulations Act, many of these industries are out of the purview. Even if they go sick or are mismanaged there is no method of taking them over and on this point, I would like to ask: why do you think in terms of allowing amalgamation etc? We talk of labour participation in management. Has the time not come to allow the workers to become share-holders and run the industry which has become sick? I know of an instance of Model Mills, which was the first to be taken over at my instance under the Industries Development and Regulation Act at Nagpur. The mill was closed and within six months the employees ate away Rs. sixty lakhs of their provident fund. Why don't you allow them to utilise their provident fund as share capital and run that unit as an industrial unit of the workers. And, wherever the workers have participated, whether in the public sector like Steel industry, or private sector like Geep Flash Light Industries, or other units in Maharashtra, they have created wonders.

Therefore, let us not distrust our workers that they do not have the capacity. Once they feel, 'Now it is our job, it is our stake,'. then they will give the results and they will work for their own interests. Therefore, instead of allowing amalgamation, when public funds are involved, the private industries get money from you, from your public financial institutions—80 per cent of their money is from the public financial institutions—why not the workers get it? Why should you not penalise and put a cess on those industries who made these units sick, siphoned of all the money from there and put it in some other profit-making units? Why not you levy some cess and take the funds and make it available to the sick units? If there is a will, there is a way.

Workers of this country to-day must get a feeling of belonging and that feeling of belonging can be given by participation at all levels. Here, I would only like to say, as a trade unionist, that a stage has come when we should end this trade union rivalry. If you make workers in every industry as partners and shareholders, then why should there be any trade union rivalry? Let the workers elect their own representatives from among themselves on the Board of Management. Let that not be a show only. We must have their real participation. At least one-third of the Board of Management must be the elected representatives of the workers. One-third should be from the financing institutions. You give 80 per cent of the money to these private industries. Why should you not tell them that they must take at least one-third on the Board of Management from you, directly from the Government who are the representatives of the people, one-third from the workers and one-third

will be from the private management. Thus, you will be able to regulate and control the productive activity and the mischief that is done to-day in the industries of hiding the real profits. Then, they will not be able to hide the profits and, then, when the workers are partners, you can corelate their interests, their wages, their bonus with productivity. That is the real way of doing it.

As a trade-unionist, I beg to submit that I am not in favour of saying, although it may sound unpopular, that...

MR. CHAIRMAN: The hon. Member's time is over. You have already taken 30 minutes. Please conclude.

SHRI VASANT SATHE: I am concluding.

You may consider this. Bonus unrelated to productivity or production is not a happy phenomenon. It is all right to say that it is considered a deferred wage and, therefore, we must now give 8.33 per cent as bonus, whether it is loss or profit. But some day, you will have to corelate it. But that cannot be done as long as employees are only employees and they have no voice in production or management. But once you give that voice by real participation, then you will be able to corelate the production to wages.

One last sentence. Your Bureau of Employment Statistics, index preparing and all that is in Simla. It has been so long there because they have been saying that they do not find any place either in Delhi or anywhere in the whole country. They are on the sylvan heights of Simla. Is it not high time that you think of bringing them down to earth? If you do not have any place, then come to Nagpur, a centrally situated place or Hyderabad...

SHRI VAYALAR RAVI: Or Akola.

SHRI VASANT SATHE: Yes, for that matter, Akola.

Therefore, I would submit that this thing also should be considered.

Thus, in totality I will end by saying your Labour Ministry is a very important Ministry. There is a study group, a Sub-committee and the infrastructure is there. Let us get down to the task of mass employment in producivity. That must be the slogan, maximum number of people in this country, a work force getting productive work in their houses, in their homes, in their cottages. If this is the slogan and control marketing, don't leave it, the entire marketing activity in this country must come under the regulation, under the umbrella of some National Marketing Corporation or whatever you may call it, and bring even the private traders into the discipline. Without this, we will not be able to solve the problem of unemployment in this country.

Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak.

PROF. SHIBBAN LAL SAKSENA (Maharajganj): I bg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Failure to implement the assurance of the former Minister late Shri Kumaramangalam that the Gorakhpur Labour Depot will continue to provide labour to coal mines and other undertakings (1).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Failure to review the proposal to give away two hospital wards of the Gorakhpur Labour Depot to U.P. Government when the labour depot badly needs them for serious patients (2).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Prof. Shibban Lal Saksena]

[Failure to bear 50 per cent of the expenditure on running the six medical centres for welfare of ex-coal miners and their families in Gorakhpur Depot (3).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to reinstate one thousand dismissed labourers of Mahabir Jute Mills Sahjanwa, District Gorakhpur (5).]

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): I beg to move:

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Failure in enforcing labour laws (14).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Failure to prevent the Management of Indian Express in Delhi from closing its concern (15).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Long delays occuring in settling industrial disputes (16).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to implement the minimum wages for agricultural labour in rural areas (17).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to prevent accidents in mines (18).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to modernise the mines rescue services (19).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to spend more money for labour welfare (20).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to appoint labour officers in industrial institutions as per the provisions of the Act (21).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to implement the Employees Provident Fund Act correctly (22).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to spend Central Coal Mines Rescue Station Funds profitably (23).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to register artisans and skilled workers like masons in Employment Exchanges (24).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to provide houses to all factory labourers (25).]

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Failure to clear all dues of workers of the money deducted from them under the CDS (26).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Delay in setting up the Committee to go into the question of a new industrial relations law for the country (27).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Failure to ensure payment of minimum bonus at 8.33 per cent (28).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Failure to extend the right of bonus to all employees of the public sector undertakings and the railways (29).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to revamp the ESIS and to check the malpractices of the administration and the medical personnel (30).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to associate labour at all stages of the discussion of the Sixth Plan (31).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to end the delays in clearance of provident fund dues (32).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to undertake measures to clear lobour disputes by toning up the conciliation and industrial relations machinery at all levels (33).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to evolve a method of recognition of unions by means of secret ballot (34).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced to Re. 1."

[Failure to take steps to reopen the units which have been under closure ,look-out or partial closure and ensure protection of employment to the workers (36).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced to Re. 1."

[Failure to take penal action against all employers who have closed down or locked out their concerns thereby affecting employment and production (37).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to check widespread malpractices in the Labour Exchanges throughout the country (42).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Delay in evoloving a national wage policy and ensuring a national need based minimum wage (94).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Failure to ensure minimum 8.33 per cent bonus in both private and public sectors (95).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Shri K. A. Rajan]

[Failure to honour the agreement signed between management and employees of the LIC (96).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Failure to evlove a scheme to provide employment to the bonded labour who have been released (97).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to speed up implementation of the Bonded Labour System (Abolition) Act (98).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to settle the issues facing the employees of Jaipur Ddyog Limited (99).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to resolve the problems facing the employees of Punjab National Bank regarding the promotion policy settlement of clerks and Special Assistants (100).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to establish and set up fair price shops for essential commodities at lower prices in all industrial enterprises for the welfare of workers (101).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to take more stringent action against employees who default in payment of E.S.I. and E.P.F. dues (102).]

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to settle demands of the workers of the Glaxo Limited, Bombay and to order reinstatement of the victimised workers (35).]

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon): I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Discrimination against the employees of the public sector in referring industrial disputes for adjudication (92).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Giving full veto power to the employing Ministries and Departments to refer industrial disputes which the Labour Ministry considers just and fair (93).]

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Discrimination against the employees of the public sector in referring industrial disputes for adjudication (103).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Giving full power to the concerned Ministries of the public sector undertakings to veto any decision to refer the industrial disputes for adjudication as and when the Labour Ministry feel it right (104).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to declare 8 1|3 per cent Bonus to all workers (105).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to declare Bonus as a deferred wage (106).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to make ESI scheme acceptable to workers (107).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to give better medical benefits as compared to ESI scheme (108).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Functioning of ESI Scheme and its failure to provide better medical facilities to workers (109).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to accept the demand of workers of Instrumentation Ltd., Palghat for exemption from ESI Scheme (110).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to check the growing unrest among workers (111).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to enact comprehensive legislation on labour disputes (112).]

श्री रामधारी शास्त्री (पदरौना) : मान्यवर, मैं माननीय श्रम मन्त्री जी द्वारा प्रस्तावित श्रम की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस के साथ ही मैं अपने वरिष्ठ साथी माठे साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं।

मान्यवर, जनता पार्टी के शासन से पहले लगभग 19-20 महीनों तक सारे देश में एक विशेष शासन व्यवस्था रही और उस काल में यदि सब से ज्यादा किसी के साथ ज्यादती हुई तो वह इस देश का मजदूर वर्ग है। यहीं नहीं कि उन को उसी स्थान पर रखा गया, बल्कि यह भी हुआ कि पिछली सरकार के बनाये हुए कानून के मुताबिक जो उन को बोनस 8.33 परसेंट मिलता था, उस को भी घटा कर 4 परसेंट कर दिया गया। इतना ही नहीं यह चार परसेंट भी कारखानेदारों की मर्जी पर छोड़ दिया गया, यदि उन को कारखाने में मुनाफा होता है, तब उन्हें वह बोनस मिलेगा, और मुनाफा नहीं होता है तो बोनस नहीं मिलेगा। यही नहीं—हमारी तरफ बहुत सी चीनी मिलें हैं, उन मिलवालों ने न केवल उन का बोनस रोका, बल्कि उन की तनख्वाहें भी प्राइस इण्डक्स के आधार पर 40 रुपये से 45 रुपये महीने तक कम कर दीं। इस एमर्जेन्सी के दौरान यदि किसी को सब से ज्यादा कष्ट हुआ है तो वह कारखानों का मजदूर है।

मैं आज माननीय मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं—उन के ऊपर आज एक बड़ा भारी बोझ आ पड़ा है। सारे देश में जो एक बड़ा भारी असंतोष था, जनता पार्टी की सरकार के निर्माण के बाद लोगों को एक आशा बन्धी है। मैं नहीं जानता कि उन की आशाओं को किस

[श्री रामधारी शास्त्री]

सीमा तक पूरा करने में आप सफल होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि श्रम मंत्री जी अपनी डाइनमिक पर्सेनलिटी से इस तरह के नियम बनायेंगे, इस तरह की व्यवस्था करेंगे जिस से मजदूर वर्ग में जो असन्तोष व्याप्त है, वह समाप्त हो। आप की सरकार धीरे धीरे उन की समस्याओं का समाधान करेगी। मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अब जनता ज्यादा इन्तजार करने वाली नहीं है—इस लिए बहुत तेजी से आप को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए।

जब आपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया था—तो अंग्रेजी के चुनाव घोषणा पत्र के पृष्ठ 17 पर जहां आप ने दूसरी बातों का उल्लेख किया, वह यह प्रतिज्ञा भी आप ने की थी कि :—

Janata Party's economic programme envisages deletion of property as a Fundamental Right.

2. Affirmation of the right to work and full employment strategy.

यह बड़ी भारी प्रतिज्ञा है, कोई छोटा काम नहीं है कि सरकार जनता के फन्डामेंटल राइट्स में यह बात जोड़ दे कि प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार है और उन को काम देने की जिम्मेदारी सरकार की है, सब को पूरा-पूरा काम मिलेगा। यह एक गुरुतर भार है जो इस सरकार को अपने ऊपर उठाना है।

साठे साहब ने कुछ फिगर्स कोट कर के यह साबित करने की कोशिश की कि इस देश में बेकारों की बहुत बड़ी तादाद है। रोजगार दफ्तरों की फिगर्स से यह स्वयं सिद्ध बात है। लेकिन साठे साहब पूरी फिगर्स नहीं दे सके। आज देहातों और शहरों में जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वे रोजगार दफ्तरों में अपना नाम लिखाने नहीं जाते—यदि सब को इस में शामिल किया जाये तो यह संख्या बहुत ज्यादा है। मैं इसके बारे में कुछ सुझाव आप के सामने रखना चाहता हूं। साठे साहब ने ठीक ही कहा है कि काटेज उद्योग फैलाऐ जाए, छोटे-छोटे उद्योग फैलाए जाऐ, ग्रामीण उद्योगों को कायम किया जाय; लेकिन मेरा सबमिशन है कि क्या हम इनके लिये प्रतीक्षा करते रहेंगे? मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं—क्या हम कई साल तक इन बातों की प्रतीक्षा करेंगे—कि अगले दो-तीन सालों में जब काटेज उद्योग कायम हो जायेंगे तब बेकारी की समस्या का समाधान हो जाएगा? लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार पहले की सरकार ने दूसरी, तीसरी, और चौथी योजना में इस समस्या को भूला दिया कहीं ऐसा न हो कि यह समस्या आपके बूते से भी बाहर हो जाए। मैं संकेत करना चाहता हूं कि यह बेकारी की समस्या किस हिसाब से बढ़ रही है। मेरे पास रोजगार दफ्तरों के आंकड़े हैं इनसे यह सिद्ध होगा कि यह समस्या कहां तक पहुंच गई है।

सन् 1950 में केवल 3 लाख 33 हजार लोगों ने रोजगार दफ्तरों में अपने नाम दर्ज कराए थे। 1955 में यह संख्या बढ़ कर 6 लाख 92 हाजर, 1960 में 16 लाख, 1965 में 25 लाख, 1969 में 34 लाख से कुछ ज्यादा, 1973 में 82 लाख, 1974 में 84 लाख, 1975 में 93 लाख से कुछ ज्यादा और 1976 में 97.7 लाख हो गई। बेकारी बेरोज़गारी जिस तेजी से बढ़ रही है, उसको देखते हुए अगर हम यह सोचें कि काटेज इंडस्ट्रीज खोल कर इस समस्या का समाधान कर लेंगे और तब तक हम उसके लिए प्रतीक्षा करते रहें तो इससे काम चलने वाला नहीं है जब तक यह सब कुछ होगा तब तक बेकारी की समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि जिस प्रकार से इस समस्या पर पिछली सरकार नियंत्रण

नहीं पा सकी, उसी प्रकार से इस सरकार के लिए भी इस समस्या पर काबू पा सकना असम्भव हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि अब क्या करें।

मान्यवर हमारे देश में जितने कारखाने हैं उनमें जो आदमी काम पर लगे हुए हैं, जिन के बारे में माननीय साठे साहब ने भी फिगर्स दी हैं जो कि ठीक ही हैं, उनके बारे में जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे इस प्रकार हैं -- सरकारी क्षेत्र के कारखानों में एक करोड़ 34 लाख 20 हजार और गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में 67 लाख 19 हजार लोग काम पर लगे हुए हैं। इन दोनों क्षेत्रों में जो आरगेनाइज्ड लेबर है वह सब मिलाकर दो करोड़ से कुछ ज्यादा है। पिछले दिनों उद्योग मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि हमारे यहां बेकारों की संख्या चार करोड़ से कम नहीं है, चार करोड़ से ज्यादा ही होगी। मान्यवर बेकारों के बढ़ने की जो गति है उसमें इस समस्या के समाधान के लिए क्या इन्तजार किया जा सकता है।

मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोरे नारे लगाने से काम चलने वाला नहीं है। ये जो बड़े-बड़े कल-कारखाने है, जो बड़े बड़े मुनाफे कमाते है, उनके ऊपर भी आपको हाथ लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही आप छोटे-छोटे उद्योगों को विकसित करें। लेकिन इन सबके करने के बावजूद भी आपको एक काम मजबूती के साथ करना पड़ेगा वह यह है कि कारखानों में काम के घण्टों में कमी। इसके सिवाय इस देश की बेकारी की समस्या का और कोई सोल्यूशन नहीं है।

हिन्दुस्तान में आठ घंटे जो वर्किंग डे हैं, उसको घटाकर आपको 6 घंटे का वर्किंग डे करना पड़ेगा। तभी जाकर इस समस्या का समाधान हो सकेगा। इस पर बहस हो सकती है, अर्थशास्त्री इस पर कुछ विवाद उठा सकते हैं कि इससे कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हो सकता है कि एकाध पैसा कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ जाए लेकिन बढ़ती हुई बेकारी के लिए यह ज्यादा नहीं होगा। मैं मंत्री जी के ध्यान में इन काम के घंटों का इतिहास लाना चाहता हूं। सबसे पहले 1908 में जब फैक्ट्री लेबर कमीशन बैठा तो अंग्रेजों को इस बात की जानकारी हुई कि उस जमाने में एक श्रमिक 13 से 15 घंटे काम पर लगता हैं। उस जमाने में कमीशन ने यह शिफारिश की कि 12 घंटे का काटन मिलों में प्रयोग किया जाये। 1911 में यह प्रयोग सफल रहा। काम की दृष्टि से उत्पादन की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से वह प्रयोग सफल रहा। उसके बाद 1922 में फिर सुधार हुआ। 1922 में साठ घंटे प्रति सप्ताह काम के किए गए। उससे भी उत्पादन में में वृद्धि हुई कोई घाटा नहीं हुआ। यह भारत के कारखानों का रिकार्ड सो करता है। 1929 में एक कमीशन बैठा जिसने अपनी रिपोर्ट 1931 में दी। मोटे तौर पर उसको व्हिटले कमीशन की संज्ञा दी जा सकती है। अपने अनुभव के आधार पर उसने यह सिफारिश की :—

"But there can be little doubt that following the change on the average, the efficiency of the operation has risen substantially."

उसके बाद उसने और सिफारिश की:—

"The existing weekly and daily limits be reduced to 48 and 8 respectively and that provision be made for adequate rest period etc...."

उसके बाद अपनी राय जाहिर की :

"They believe that, within a reasonable period of time, it would result in increased efficiency and would be a sound economic proposition."

[श्री रामधारी शास्त्री]

रायल कमीशन आन लेबर की भी रिपोर्ट है। वह 1931 में बैठा था। उसकी राय पर अमल करते हुए सबसे पहले 1934 में हिन्दुस्तान में फैक्ट्री ऐक्ट बना। उसके बाद 1948 में माडिफिकशन करके फैक्ट्री एक्ट बना। 1936 में सबसे पहले हिन्दुस्तान के कारखानों में आठ घंटे काम के निर्धारित हुए। इसके बाद मजदूर यूनियनों के माध्यम से यह चीज चलती रही। 1966 में नेशनल कमीशन आन लेबर बैठा। उसने अपनी रिपोर्ट 28 अगस्त, 1969 को भारत सरकार को सबमिट की। आई एल ओ की सिफारिशों के आधार पर उसने यह राय दी थी काम के घंटे कम किए जाएं। उसकी रिकमेंडेशन में यह सिफारिश की गई :

"In the first stage, the working hours should be brought down to 45 a week and, in the second, 40 a week."

अपनी रिपोर्ट के पेज 104 में उसने अपनी यह राय जाहिर की है। दुनिया के दूसरे देशों को भी लें। आस्ट्रिया में 35.8 घंटे प्रति सप्ताह है इसी तरह डेनमार्क में 33.4 घंटे प्रति सप्ताह है। नार्वे में 35.5 घंटे प्रति सप्ताह है। पुरुषों के लिए और 30.6 घंटे प्रति सप्ताह महिलाओं के लिए है। ये छोटे-छोटे देश है। दुनिया के वे देश जो दुनिया को नई दिशा देते है वहां भी तीस और पैंतीस घंटे प्रति सप्ताह काम के निश्चित किए गए है। भारत में बेकारी विकराल रूप में विद्यमान है। यहां लोग दाने-दाने के लिए तरसते है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां काम के घंटे कम करना जनता पार्टी की सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए। बेरोजगारी को दूर करने का इसके अलावा और कोई साधन नहीं हो सकता है। उद्योगपति इसका विरोध कर सकते है। लेकिन आपको मजबूती के साथ इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और दृढ़ता दिखानी चाहिए। आप काम के घंटे ज्यादा नहीं तो आठ से छः करें। इससे सारे देश में एक करोड़ लोगों को काम तुरन्त मिल जाएगा। ज्यादा को भी मिलेगा। जो आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज है वहां मिल जाएगा।

पार्लियामेंट में एक बहस हुई थी 1957 में। तब एक कमीशन बैठा था जिस का नाम पटेल कमीशन था। उसने सबसे गरीब जो तीन जिले है गाजीपुर, आजमगढ़ और देवरिया उनके बारे में 1962 में एक रिपोर्ट सबमिट की। उसने सिफारिश की कि वहां की बेरोजगारी को दूर करने के लिए नए-नए कल कारखाने, नए नए छोटे उद्योग धंधे वहां लगाए जाएं। पटेल कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई लेकिन उसको अलमारियों में बन्द करके रख दिया गया। उसको किसी ने शायद पढ़ा तक नहीं, उस पर अमल करने की कोशिश तक नहीं की। अब भी देवरिया जिले में चौदह चीनी मिलें है जिन में से तीन मिलों के मजदूर जिन की संख्या तीन हजार से ज्यादा है आज भी बेकार है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। कोई कदम उसने इसके बारे में नहीं उठाया छितौनी शूगर फैक्ट्री है जहां के 1100 मजदूरों को पिछले तेरह महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। और वह फैक्टरी ले ली। इस तरह का उदाहरण कम मिलेगा कि 13 महीने से जिस चीनी मिल के मजदूरों को तनख्वाह न मिली हो वह कैसे रहते होंगे। और यही स्थिति गोरखपुर जिले की सिसवा और घूघली शूगर फ़ैक्टरी की है जिसको सरकार ने अभी लिया है, और मजदूरों की तनख्वाह 6 महीने की बाकी है, और यह फ़ैक्ट्री श्री दीपक प्रदीप की है जो कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरार है, लेकिन उन्होंने जान बूझ कर फ़ैक्ट्री का दिवाला निकाल दिया। इसलिए बेकारी की समस्या का अगर समाधान करना है तो मंत्री जी को मजबूती के साथ आई० एल० ओ० की सिफारिश के अनुसार मजदूरों के हित में काम के घंटे कम करके 6 घंटे प्रति दिन करने चाहियें, तब जाकर समस्या का समाधान होगा अन्यथा नहीं।

बोनस का भी एक झगड़ा है। सरकार ने तो अपने कारखानों पर लगा रखा है कि वहां बोनस नहीं मिलेगा, चाहे वह कारखाना हो या दफ्तर हो। जो सरकारी कारखाने है उनमें आप ऐक्स-ग्रेशिया करके चाहें जो दे दें, मगर मजदूर अधिकार के तौर पर उसको नहीं मांग सकता है। सबसे पहली बात यह है कि यह बोनस क्यों मेहरबानी पर है। सरकार ने कानून बनाकर छोड़ दिया कि मर्जी पर है अगर मुनाफ़ा हो तो दें। और मुनाफ़ा सभी को होता है क्योंकि अगर मुनाफ़ा किसी मिल मालिक को न हो तो वह पैसा नहीं देगा, मिल भी बन्द हो जाएगी।

बोनस के सम्बन्ध में यह कहना है कि बोनस का काम सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में चालू हुआ जब बढ़े हुए प्रोडक्शन की जरूरत हुई तो उन्होंने वार बोनस करके मजदूरों को दिया ताकि ज्यादा उत्पादन कर सकें। द्वितीय विश्व युद्ध में मान लिया गया कि मुनाफ़े का कुछ हिस्सा मजदूरों को देना चाहिए। और जब अपनी सरकार बनी तो 1961 में बोनस कमीशन बैठाया और 1964 में उसकी रिपोर्ट आई। उन्होंने स्वीकार किया कि 4 परसेंट बोनस दिया जाय या 40 रु० दिये जायें। मगर उसके बाद जब गरीबी हटाओ सरकार आयी तो उन्होंने 8.38 परसेंट की बात कही, या 80 रु०। लेकिन जब इमरजेंसी आयी और प्रोडक्शन बढ़ाने की बात आयी तो पता नहीं किन वजूहात से उन्होंने इसे रोक दिया। 8.33 परसेंट से घटा कर 4 परसेंट कर दिया और वह भी उनकी मेहरबानी पर छोड़ दिया। इस हिसाब किताब में जब तक निजी व्यापारी हैं तब तक मजदूरों के बस का नहीं कि वह नफ़ा नुकसान जान सकें। इसलिये मैं चाहता हूं कि बोनस को प्रोडक्शन के साथ जोड़ा जाना चाहिये। हमारे यहां चीनी मिलें बराबर चलती हैं, किसी में बोनस मिलता है और किसी में नहीं मिलता। जिनके यहां रकवरी अच्छी आती है वह बोनस देती हैं और दूसरी मिलें नहीं देती हैं। इसलिये बोनस को भी प्रोडक्शन के साथ जोड़ा जाना चाहिये तब जाकर के मजदूर के साथ अन्याय नहीं होगा, हिसाब किताब का मामला खत्म होगा और प्रोडक्शन के साथ उनको मिलता जायगा।

इसी तरह हमारे यहां फ़िरोजाबाद चूड़ी के कारखानों का सबसे बड़ा केन्द्र है। लेकिन वहां का मजदूर बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे भिखमंगे रहते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये जहां काम के घंटे का कम करने की जरूरत है वहां यह भी आवश्यक है कि काम की स्थिति ठीक हो, उनके रहने के लिये मकान की व्यवस्था हो, उनके बच्चों के पढ़ने के लिये स्कूल हों, उनके लिये पार्क हों। फैक्ट्री एक्ट में इसका प्रावधान है लेकिन कोई फ़ैक्ट्री मालिक इसे नहीं मानता है, और किसी भी फ़ैक्ट्री मालिक को आज तक जेल जाते नहीं देखा। इसलिये आप इस तरह की व्यवस्था बनायें। साठे साहब से मैं सहमत हूं कि तमाम सूबो में जो अलग अलग तरह के श्रम कानून हैं उनका कोडिफ़िकेशन होना चाहिये, लेबर लाज़ को एक जगह इकटठा करके एक तरह की व्यवस्था होनी चाहिये।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में भी और अधिकांश सूबों में यह है कि अगर कोई फैक्ट्री एम्पलाई अपने काम से डिसमिस हो जाये, तो डिपार्टमेंट उसको आदेश देता है कि अपील करो या न करो। उसको राइट आफ अपील नहीं है। मैं समझता हूं कि किसी मजदूर के लिये नौकरी का खात्मा हो जाना सजाएं मौत के समान है। जिस तरह से सजाएं मौत के खिलाफ किसी भी स्टेट में अपील हो सकती है, मर्सी एप्लीकेशन पड़ सकती है, उसी तरह से श्रम कानून में भी संशोधन होना चाहिये कि किसी भी मजदूर को एज ए राइट यह अधिकार होना चाहिये कि वह डिस्मिसल के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सके जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके।

[श्री रामधारी शास्त्री]

मजदूरों के रहने की स्थिति बड़ी खराब है । हमारे यहां चीनी मिल हैं । आधे से अधिक मजदूर सड़क पर सोते हैं । कानपुर में आप देख लें । दिल्ली में हमारी सरकार की नाक के नीचे भी यही होता है । मैं आपको 3, 4 नाम बताता हूं—श्री ब्रजमोहन रोहतगी, श्री अनिल रोहतगी, सुनील रोहतगी, कपिल रोहतगी । ये सब भाई हैं और इनकी कई फर्में हैं—के० पी० आर० सैल्स, पी० ए० आर० सैल्स, पी० ए० आर० इण्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, बी० आर० पिस्टन रिंग्स । इस तरह से इन्होंने कई कारखाने बना रखे हैं । 40, 50 मजदूर रखते हैं । कुछ दिन उनसे एक फर्म में काम करा लिया, फिर उस फर्म का साइन-बोर्ड हटाया, दूसरा साइन-बोर्ड लगा लिया और कुछ दिन काम करा लिया और फिर तीसरा साइन-बोर्ड लगा दिया और काम करा लिया । इस तरह से वह मजदूरों का शोषण करते है । राजधानी में इस तरह की कम-से-कम 200, 300 फर्में होंगी, जो फर्जी काम करती है । जब चाहा, ये मजदूरों को निकाल देते हैं । उनको 5, 6 रुपये रोज देते हैं । मैं समझता हूं कि दिल्ली शहर का लेबर डिपार्टमेंट की ओर से एक सर्वे होना चाहिये । यहां के श्रम विभाग के अफसर इन मालिकों से मिले हुए हैं, इस तरह की आम शिकायत मजदूरों की है । इसलिये मेरा निवदन है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें ।

अब मैं समान वेतन, समान काम की बात कहना चाहता हूं । यह एक बड़ा भारी सिद्धान्त है, सभी को मंजूर है लेकिन यह आज तक हिन्दुस्तान में हुआ नहीं है । जनता पार्टी की सरकार को अविलम्ब इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

यही नहीं काटन मिलें हैं, शुगर फैक्टरीज हैं, स्टील फैक्टरीज हैं, सब जगह अलग-अलग मिनिमम वेज है । मेरा कहना यह है कि सारे देश में एक पैमाने पर सभी फैक्टरीज में मिनिमम वेज एक समान होना चाहिये । इसी तरह से बैंकिंग इण्डस्ट्रीज में है । अलग-अलग बैंकों ने अलग-अलग तरीके से मिनिमम वेज बनाये हुए हैं । यह भी समाप्त होना चाहिये ।

इसी तरह सरकारी नौकरियों में भी नेशनल पे-स्केल होना चाहिये । कोई वजह नहीं है कि सूबों में काम करने वाले कर्मचारियों को, उसी योग्यता, उसी तरह के पद और उसी नेचर के काम करने वालों को कम तनख्वाह मिले और केन्द्रीय सरकार में ज्यादा तनख्वाह दी जाये और सुविधाएं भी दी जायें । इस ओर भी मन्त्री जी का ध्यान तुरन्त जाना चाहिये ताकि इसमें सुधार हो ।

लेबर मशीनरी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी मजदूर ने हड़ताल कर दी तो उसके लिये सरकारी मशीनरी है । हमको एक लेबर का केस याद पड़ता है । शुगर मिल पडरौना में 11 बरस पहले एक डाक्टर को निकाल दिया, लेकिन आज तक उसके केस में कुछ नहीं हुआ है । स्टेट की मशीनरी क्या है यह मैं बताता हूं—जैसा मार्क्स ने कहा था—

"The State is a machinery in the hands of richer to oppress the poorer."

ऐसा ही लगता है कि वह बात जैसे की तैसी आज भी सही है । स्टेट की लेबर कोर्ट की मशीनरी मजदूरों को तबाह करने के लिये है । आपकी किताब कहती है, मैं एक वाक्य पढ़ देता हूं—

"From 54 per cent in January 1976, the percentage of time-loss relating to lockouts increased to a staggering figure of 90 per cent in May, 1976. During January-December 1976, lockouts accounetd for 79 per cent as compared to only 17

per cent and 24 per cent during the calendar years of 1974 and 1975 respectively."

तो इससे आप देखेंगे कि 1975–76 में जब एमरजेंसी पीक पर थी, तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मिल मालिकों ने तोड़ा है, लौक-आउट किया है । सबसे ज्यादा उनका कसूर है । 90 प्वाइन्ट तक यह पहुंच गया, लेकिन किसी मिल मालिक को सजा नहीं हुई । अगर मजदूर हड़ताल करे तो उसके लिये सरकारी कानून बने हुए हैं, चाहे वह किसी अफसर की ज्यादती के कारण ही हो ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार को देखना चाहिये कि हमारे कानुनों का रुख श्रमिकों की तरफ हो, मालिकों की ओर न हो । अब तक जो कांग्रेस की सत्ता थी, वह मिल मालिकों की तरफदारी करते थे, पूंजीपरस्तों की इज्जत हो रही थी । उनको छोड़ कर अब जो यहां श्रमिक नीति हो वह श्रम उन्मुख होनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं श्रम मन्त्री की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

कब्ल इसके कि मैं इस मंत्रालय के विभिन्न विभागों और सरकार द्वारा वितरित रिपोर्ट में दी गई सामग्री के विषय में कुछ कहूं, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लेबर विभाग की पुस्तिकाओं और रिपोर्टों में पहले की तरह "भक्षिका स्थाने भक्षिका" के अनुसार केवल स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े दे देने से काम नहीं चलने वाला है । मैंने देखा कि जो साहित्य हमें दिया गया है, उसमें बेसिक रीडर के से पाठ लिखे हुए हैं । उदाहरण के लिए, एम्पलायमेंट के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े तो दिये गये हैं, लेकिन इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या कब से खड़ी हुई है, उसके हल के लिए सरकार की ओर से अब तक क्या उपाय किये गये हैं और उसके समाधान के लिए भविष्य में सरकार किस नीति का पालन करेगी । जो साहित्य हमें दिया जाता है, अगर सरकार चाहती है कि उस पर अपने विचार प्रकट कर सकें, तो मंत्री महोदय को यह कोशिश करनी चाहिए कि अगले बजट के अवसर पर हमारे सामने जो साहित्य रखा जाये, उस में देश के करोड़ों मजदूरों से सम्बन्धित वास्तविक समस्याओं का समुचित रूप से विवेचन किया जाये ।

माननीय सदस्य, श्री साठे, और श्री शास्त्री ने कहा है कि वर्तमान श्रम कानूनों में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत सी विषमतायें विद्यमान हैं । मुझे लगता है कि जो साहित्य पिछले तीस वर्ष में वितरित किया जाता रहा है, वही विषमतायें उस में भी मौजूद हैं । मंत्री महोदय को इन विषमताओं को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिये ।

मुझे भी कम से कम तीस वर्ष से ज्यादा तक मजदूरों में काम करने का अवसर मिला है । मैं कालेज में पढ़ता था । जेल से छूटने पर मुझे यू० पी० से एक्सटर्न कर दिया गया और मैं 1 अगस्त, 1945 को बम्बई चला गया । मैंने लेनिन की किताबों को पढ़ा था कि सब से ज्यादा क्रान्तिकारी मजदूर टैक्सटाइल का मजदूर होता है । इसीलिए मैं काटन टैक्सटाइल मजदूरों के बीच में काम करने लगा । उस बात को बहुत दिन गुजर गये हैं । मैं पांच दस वर्ष से बम्बई नहीं गया हूं, लेकिन मैं उन लोगों की हालत को जानता हूं । 1945 से 1949 तक वेतन आदि विभिन्न मांगों को लेकर कपड़ा मजदूरों की हड़तालें होती थीं और उनके जलूस निकलते थे । लेकिन तथ्य यह हैं कि उस समय

[श्री उग्रसेन]

उन लोगों की जो क्रय शक्ति थी, आज वह उससे कम हो गई है । इसका क्या कारण है ?

इसका एक कारण यह है कि सरकार के इरादे ठीक नहीं थे और सरकार की नीति पूंजीपतियों की पोषक थी, वह पूंजीपतियों की पोषक रही है । टाटा, बिरला, सिंहानिया सूरजमल नागर मल बजाज, खेतान, रूंगटा, चूंगटा की चेरी रही है और मजदूरों को खत्म करती रही है । इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले कोई माननीय सदस्य बता सकते हैं कि कोई ऐसी मिल हैं जहां से सांचे उखाड़े नहीं जा रहे हैं ? चले जाइये यहीं दिल्ली में ठीक नाक के नीचे जहां यह आदरणीय सदन है जिस पर कि दुनिया की निगाह लगी हुई, यहीं पर एक दिल्ली क्लाथ मिल है, भरत राम चरत राम जिसके मालिक हैं । मेरे पास वहां के मजदूर आए थे, बता रहे थे कि वहां के सांचे उखाड़े जा रहे हैं । 1939–40 में इस मिल में 12 हजार मजदूर काम करते थे । आज तीन हजार मजदूर काम कर रहे हैं क्यों ? क्योंकि इसके मालिकों ने डासना में, मिल लगा ली । वहां पर मिनिमम वेज ढाई सौ, सवा दो सौ, दो सौ रुपय देते हैं जब कि यहां पर साढ़े तीन सौ, चार सौ रुपए देने पड़ते हैं । इसलिए रोज सांचे उखाड़ उखाड़ कर रात में लेकर भागे चले जा रहे हैं । सरकार की आंख के नीचे यह सब हो रहा है, सरकार देख नहीं रही है । उनका यहां फायदा नहीं रहा इसलिए सांचे उखाड़े जा रहे हैं । मजदूर निकाले जा रहे हैं । गलत मेडिकल सर्टिफिकेट देकर उनको हटाया जा रहा है । कहा जा रहा है कि अब ये इस काम में लायक नहीं रहे हैं इनका स्वास्थ्य काम करने लायक नहीं है । यह सब क्यों हो रहा हैं ? कांग्रेस के तमाम घोषणा-पत्रों में, मंत्रियों के भाषणों में, लेबर कान्फरेंसेज के निर्णयों में, आइ एल ओ के डेसीशंस में. इंडियन लेबर कान्फ्रेंसेज के निर्णयों में हमेशा यह कहा जाता रहा है कि हम मजदूरों की नौकरी की गारंटी करेंगे, जो हैं उन्हें गलत तरीके से निकालने नहीं देंगे । उनकी नौकरी की सेफ्टी के लिए तमाम कानून भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने बनाए । 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस ऐक्ट बना था । अभी सन् 76 में उसमें थोड़ी सी तरमीमें हुई हैं । हर एक राज्य की सरकार ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसमें तरमीमें की हैं । मगर उन कानूनों से मजदूरों की सुरक्षा नहीं हुई है, कपड़ा मिलों के मालिकों की सुरक्षा हुई है जिसके अन्दर आज भी भरत राम चरत राम अपने सांचे उखाड़ कर ले जा रहे हैं ।

कहा जाता है कि ये मिलें सिक हैं । किसने इन्हें सिक बनाया ? यह देश सिक है । पिछले 30 वर्षों में सरकार का दिमाग ही रुग्ण शैया पर पड़ा था । हमारे नेता और मंत्री लोग तथा बड़े बड़े हुक्मरा रुग्ण शैया पर पड़े थे । इसलिए उन को यही दिखता था । आज देश में 120 सिक मिलें हैं, कपड़े की, चीनी की, ये मिलें रुग्ण शैया पर पड़ी हैं । हम ने 1952 में कहा था कि जितने बड़े-बड़े उद्योग धन्धे हैं उन का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय और आज मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन मिलों का राष्ट्रीयकरण हो उन के मालिकों को मुआवजे का एक पैसा भी नहीं देना चाहिए । हमारे पूर्वांचल में 40 चीनी मिलें हैं । ये मिलें 1925–26 के बाद की बनी हुई है । उस समय इस के जो मालिकान थे । उन्होंने किताबों में देखा कि चीनी मिलों में मुनाफा है तो उन्होंने मिलें लगा लीं । 40 लाख, 50 लाख में मिल उन्होंने लगायी, हद् से हद् 1 करोड़ 20 लाख रुपये में लगायी इससे कई गुना ज्यादा मुनाफा उन्होंने इन मिलों से कमा लिया । आज इन में से प्रत्येक चिल्लाता हैं कि मेरा पोषता यही है, मेरे

प्रास पैसे नहीं हैं, मुनाफा नहीं है जब कि एक करोड़, दो करोड़, पचास लाख, साठ लाख रुपया प्रति वर्ष मुनाफे का ये कमाते हैं। जो पैसा इन्होंने लगाया था वह कभी का इन्हों ने कमा लिया। अब तो ये केवल मुनाफे में ही चले जा रहे हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम इन्होंने कमाए और यह कौन कमा रहे हैं —थापर कमा रहे हैं, बिरला कमा रहे हैं, सिंहानिया कमा रहे हैं, डी आई सी के लोग कमा रहे हैं। इन को मुआवजा क्यों दिया जाये ?

यही नहीं, मेरे एक लायक दोस्त थे बाबू गेंदा सिंह। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की एक कमेटी बनी। वे उस के चेयरमैन बनाए गए और उन्होंने कोशिश की कि लिखें कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाये लेकिन नहीं हो सका। जब माननीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार हार गई तो उन्होंने कागज भेजा कि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये, हमें कोई एतराज नहीं है। इस बीच मिल मालिकान ने क्या किया कि इन के नट बोल्ट और बाकी दूसरे पुर्जे उखाड़ उखाड़ कर कलकत्ते और बम्बई के बाजारों में बेच दिया और उस से लाखों रुपये कमाए। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ये जितने बड़े बड़े उद्योग धन्धे हैं इन का राष्ट्रीयकरण किया जाये और सरकार इस बात को देख ले, जितना रुपया इन्होंने लगाया था उतना अगर कमा लिया है तो इन को एक पैसा मुआवजे में देने की जरूरत नहीं है।

सरकार की पिछले 30 सालों की नीति श्रम-विरोधी नीति रही है, मजदूरों से दुश्मनी करने वाली नीति रही है, उन के हक हकूक की रक्षा करने की नीति नहीं रही है। मजदूरों को क्या चाहिए ? उन को भत्ता चाहिए, उन को मुनाफे का हिस्सा चाहिए, बोनस चाहिए, रिहायश के लिए मकान चाहिए। क्या मिला तीस साल में ? उनके रोजगार के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए क्या सुविधायें दी गई ? बंधक मजदूर 1976 में 91,642 थे उन सभी को आजाद कर दिया गया। जब 1976 में हम लोग जेलों में थे तो इस बात को सुनते थे। लेकिन इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 25 फीसदी बंधुवा मजदूरों को इन्होंने आबाद किया है। उनको आजाद करके इन्होंने सड़क पर छोड़ दिया कि "विश्वनाथ और तिरुपति मंदिर के सामने जाकर भीख मांगो"। इससे अच्छा था कि आप उनको गुलाम ही रहने देते। आपने क्यों उनको भूखों मरने के लिए छोड़ दिया ?

श्रीमन्, जनतंत्र कई तरह का होता है लेकिन आज दुनिया में जिस जनतंत्र की चर्चा है वह कम से कम दो तरह का है ही —एक तो सर्वहारा वर्ग का जनतंत्र और दूसरा बुर्जुआ पूंजीपतियों का जनतंत्र। इस बुर्जुआ जनतंत्र में परीक्षण हो जायेंगे, सेमिनार हो जायेंगे और डेलिगेशंन का आदान प्रदान हो जायेगा लेकिन मजदूरों के हक के बारे में होगा कुछ भी नहीं। इन्होंने मिनिमम वेजेज ऐक्ट का कानून बना दिया, वह सभी जगह लागू किया गया लेकिन इस देश में जो करोड़ों कृषि मजदूर हैं, कृषि कामों के मजदूर हैं उन पर वह लागू नहीं है। उस कानून को भी यह रोज बदलते जाते हैं। बहुत से कारखाने हैं जहां पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत जीविकोपार्जन के लिए जो मजदूरी जरूरी है वह लागू नहीं की गई है। मैं मांग करता हूं कि इसको वहां पर लागू किया जाये।

सभापति महोदय, मैं अब बताना चाहता हूं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में कितने मैन-डेज नष्ट हुए उसको आप मुलाहजा फर्मायें। इन्होंने इस किताब में लिखा है कि 1976 में 11.48 मिलियन मैन-डेज नष्ट हुए। केन्द्रीय सरकार के कारखानों में 37 लाख मैन-डेज नष्ट हुए और निजी क्षेत्र में 11 मिलियन मैन-डेज नष्ट हुए। इन्होंने कहा कि हमने बड़ी पैदावार की, बड़ा तीर

[श्री उग्रसेन]

मारा और बड़ी उन्नति की लेकिन स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा तालाबन्दी 1976 में ही हुई । 79 फीसदी तालाबन्दी सरकारी कारखानों में 1976 में हुई जबकि 1974 में यह संख्या केवल 17 फीसदी थी । जब इमर्जेन्सी का कानून लागू नहीं था तब तो 17 फीसदी तालाबन्दी हुई थी लेकिन जब इमरजेन्सी लागू कर दी गई तो तालाबन्दी 79 फीसदी हुई ?

इसी तरह से इन्होंने बोनस ऐक्ट पास किया । बोनस किसी तरह की बखशीस नहीं है,-वह तो मजदूरों का हक है । 1965 में इन्होंने कानून बनाया और 8.33 परसेंट का मिनिमम बोनस लागू किया लेकिन 1976 में उसको बदल दिया और कह दिया कि बैलेंस-शीट देखकर 100 रुपये दे दिए जायेंगे । हमने अखबारों में पढ़ा है कि सरकार बोनस के सवाल को रिव्यू करने जा रही है । हम चाहेंगे कि पब्लिक सेक्टर के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में भी इसको लाजमी किया जाये कि बोनस दिया जायेगा ।

बेरोजगारी की जो समस्या है उसके सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता । मैं चाहूंगा काम के घंटों को कम किया जाये । 8 घंटों की जगह पर 6 घंटे रखे जायें । यूरोप के कुछ देशों में इस पर एक्सपेरिमेन्ट होने जा रहा हैं । हमारे पूर्वांचल में 40 चीनी मिलों में अगर 8 घंटे की जगह पर 6 घंटे कर दिया जायें तो उन 40 मिलों में कम से कम 25-30 हजार मजदूर और लग जायेंगे-यह हिसाब मैंने लगाकर देखा है ।

जहां तक मजदूरों के रोजगार की सुरक्षा की बात है आपने उनके लिए क्या किया है ? आज बेचारे वे फटेहाली में मरे जा रहे हैं नीरज ने उन की भावनाओं को इन लाइनों में व्यक्त किया है —

तन की हविस मन को गुनहगार बना देती है,
बाग के बाग को बीमार बना देती है ।
सूखी अंतड़ियों को सन्देश - सुनाने वाला,
भूख इन्सान को गद्दार बना देती है ।

अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का कायाकल्प हो, अगर आप हिन्दुस्तान को गांधी, डा० लोहिया और जयप्रकाश नारायण का देश बनाना चाहते हैं, तो मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूं—आप को इस देश में भुखमरी को समाप्त करना पड़ेगा । आज चार करोड़ लोग बेकार है । 1952 में 38 प्रतिशत लोग पावर्टी लाइन के नीचे थे और आज 78 फीसदी लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं । कहा जाता रहा कि हमारी तरक्की हो रही है—यह तरक्की तो जरूर हुई है—1947-48 में जब मैं यहां आता था, मैं उस समय बच्चा था, पढ़ता था, उस समय यहां दो-मन्जिले मकान होते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है—बहु-मन्जिले मकान बन रहे हैं—यह तरक्की हो रही है ।

आज देश के श्रमिकों में असन्तोष बढ़ रहा है—उत्पादन घट रहा है । खान मजदूरों के लिये आप कानून बनाते है—एक उदाहरण देता हूं । दो खदानें है—सोन्डा कोलियरी और सुदामाडीह कोलियरी—1976 की दुर्घटना में वहां जो मरे, उन के लिये कहा गया है कि उन को केवल 250 रुपये मुआवजे के रूप में दिये जायेंगे—"दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है" । जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उन के एम्पलायमेन्ट का कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है । आज ऐसे प्रशिक्षित बेकारों की एक बड़ी फौज बेकार बैठी है । उन को कोई काम नहीं मिल रहा है ।

आप की तरफ से रिसर्च की जाती है, बहुत सी रिसर्च लैबोरेट्रीज खोली हुई हैं—जैसे सी० एस० आई० आर०, सी० डी० आर० आई०, सैम्पों, ए० सी० आर० आई०

डिफेन्स लेबोरेट्रीज । लेकिन इन में हो क्या रहा है —10 वैज्ञानिक आत्म हत्या कर के मर गये। ये विदेश से यहां आते हैं, यह सोच कर कि हमें यहां काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लेकिन मिलता कुछ नहीं ।

मेरे कुछ सुझाव हैं—समय बहुत कम है—पढ़ देता हूं—

1. मालिक मजदूरों के सम्बन्ध ठीक होने चाहिएं, उन में कटुता समाप्त करें ।

2. एक उद्योग में एक यूनियन के सिद्धान्त को मानते हुए उन में एक यूनियम बने ।

3. बड़े उद्योगों का तत्काल राष्ट्रीयकरण करें । उन को मुआवजा न दें ।

4. प्रबन्ध में मजदूरों की सक्रिय साझेदारी हो ।

5. पुराने कायदे–कानूनों में क्रान्तिकारी संशोधन किये जायें ।

6. निम्नतम मजदूरी कानून को सख्ती से लागू किया जाये ।

7. इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 तथा संशोधित एक्ट, 1976 में मजदूरों के हित में संशोधन किया जाये ।

8. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर श्रम समितियां गठित की जायें ।

मैं उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नेन्डीज साहब के उस सुझाव का स्वागत करता हूं कि सिक यूनिट को मजदूरों की यूनियन को या उन की फैडेरेशन को चलाने के लिये दिया जाये । आज पब्लिक सैक्टर और निजी सैक्टर दोनों में ऐसे मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या है, जो 20–20 साल से कैजुअल पड़े हुए हैं । रेलवे, पोस्ट-आफिस, रोड-वेज सब जगह यही हालत है । उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की यह हालत है कि उस में 16 करोड़ रुपये का घाटा है । वहां के एस० पी० सिंह—मंत्री खा गये, चेयरमैन खा गये, डिप्टी जनरल मैनेजर खा गये, सब लूट-पाट कर चले गये । 40 हजार मजदूर आज भूखा सड़क पर पड़ा है । जब उनका नाम करता है और मैं उन की मदद करता हूं तो लोग कहते हैं कि उग्रसैन युद्धगामी है । 30 वर्षों से जो पूंजीपरस्त नीति चल रही थी, उस में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाइये, जो सर्वहारा के भले के लिये हो । आज हमें इस देश में ऐसा जनतन्त्र बनाना है जिस में लोक-भोजन मिले, लोक-भवन मिले, लोक भूषा और लोक भाषा हो । हमारी जबान फले-फूले, तमिल, तेलगू, कन्नड फले-फूले, ताकि हमारी जबान में वे हमारे दुख-दर्द को समझ सकें और उन की जुबान में हम उन के दुख-दर्द को समझ सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय हमारे जजबातों पर थोड़ा ध्यान देते हुए कुछ कार्यवाही करेंगे ।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, शुरू में सबसे पहले मैं अपने लेबर मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने इधर कुछ अच्छे कदम उठाये हैं । एकता जो आप के मन्त्रालय की एपेक्स बाडी थी, कन्सलटेटिव कमेटी, उसमें जिन यूनियनों ने एमर्जेंसी में कांग्रेस सरकार का साथ दिया था, उन्हीं यूनियनों के प्रतिनिधि थे, लेकिन आपनें अब उस एपेक्स बाडी को बदल दिया है और नई कमेटी में सब यूनियनों को लिया गया है—यह एक बहुत अच्छी बात है ।

15.00 hrs.

[SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

[श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर]

दूसरे—मीसा के अन्दर जो लोग बन्द थे, उनको काम पर लेना चाहिये, ऐसा सरकुलर आपने निकाला है—यह भी एक अच्छा काम है। तीसरे जो आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन्स के बारे में कमेटी बिठायी, यह एक अच्छी चीज है। इससे इस देश की मजदूर जनता खुश है। लेकिन मैं एक इशारा करना चाहती हूं कि अगर आपने चंद दिनों में बोनस के बारे में एलान नहीं किया तो हमारे देश के मजदूरों में असंतोष होगा और इसको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। मुझे आशा है कि मन्त्री जी जो अपना भाषण करेंगे उसमें बोनस का एलान जरूर किया जाएगा। आपके चुनाव मेनिफेस्टो में भी यह है और आपने वायदा किया है कि बोनस को आप डेफर्ड वेजिज मानते हैं। बोनस को आप वह वेज मानते हैं जो कि मजदूर को वास्तव में मिलना चाहिए और जो मिलता है, उसमें जो फर्क है, वह फर्क को आप बोनस मानते हैं। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि आप बोनस के बारे में एलान करेंगे। कल ही बम्बई में एक बड़ा भारी मोर्चा लगा है जिसमें सब ट्रेड यूनियनों के लोग शामिल हैं और वह यह मांग कर रहे हैं कि हमारा जो बोनस का हक वह हमें मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वह हक आप उनको देंगे।

इसी तरह मैं सी० डी० एस० के बारे में कहना चाहती हूं। इकोनोमिस्ट्स एक झूठी रिपोर्ट आपके सामने रख देते हैं जिसको मान कर आप चलने लगते हैं। अभी पिछले सालों में 15 सौ करोड़ रुपया गरीब जनता का सरकार ने अपने पास रख लिया लेकिन फिर भी कीमतें कम नहीं हुई, इन्फलेशन कम नहीं हुआ। आप कहते हैं कि अगर आप सी० डी० एस० का पैसा देंगे तो इन्फलेशन बढ़ जाएगा। यह गलत है। अगर आपको इन्फलेशन को रोकना है तो जो काले पैसे की पेरेलल इकोनोमी चल रही है, उसको रोकना चाहिए। इस रोकने की पिछली सरकार ने कोशिश नहीं की। आपको यह कोशिश करनी चाहिए। मजदूरों की पगार में कटौती करके कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कहूंगी कि सी० डी० एस० का पैसा मजदूरों को दिया जाए।

मुझे मन्त्री महोदय की यह रिपोर्ट पढ़ कर दुःख होता है। ऐसा लगता है कि यह रिपोर्ट पिछली सरकार की है, आपकी नहीं है। साढ़े तीन महीने में भी आपका डिपार्टमेंट इसमें कोई तबदीली नहीं ला सका। इसमें बीस सूत्री कार्यक्रम की स्तुति गाइ गयी है जिसे देख कर बहुत दुःख होता है। मैं इसे झूठा नहीं बता सकती क्योंकि झूठ कहना अनपार्लियामेंटरी हो जाएगा। बहुत सी असत्य बातें इसमें लिखी हुई हैं। एमरजेंसी के दौरान अगर किसी ने फायदा उठाया है तो वह मिल-मालिकों ने उठाया है। इसमें जो आंकड़े दिये गये हैं वे सब मिल-मालिकों के लिए ही दिये गये हैं, मजदूरों ने जो देश के लिए किया, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। श्री उग्रसेन जी ने भी अभी कहा, मैं भी कहती हूं कि इस अनुशासन पर्व में मेन डेज का लास अगर किसी ने किया है तो वह मालिकों ने किया है। ये जो बड़े मालिक हैं इन्होंने किया। 1973 में टोटल मेन डेज का लास 54 परसेंट था जो मई, 1976 में 90 परसेंट हो गया। यह किस ने किया ? यह मजदूरों ने नहीं किया। मजदूरों को तो आपने तंग कर दिया, जिन्होंने आन्दोलन किया उनको जेल भेज दिया, उनके लीडर्स को मिसा के अन्दर बन्द कर दिया। इन बड़े बड़े मिल-मालिकों ने मेन डेज का लास 90 परसेंट तक कर दिया। पिछले दिसम्बर तक, 11 महीनों में लोक

आऊट से 79 परसेंट मेनडेज का लास हुआ और आज मजदूरों पर प्रोडक्शन कम करने का इल्जाम लगाया जाता हैं । इस एमरजेंसी का फायदा मालिकों ने, सरमायेदारों ने उठाया । 79 परसेंट मैनडेज लास्ट हुए लाक आउट्स की वजह से । बीस सूत्री कार्यक्रम के बहुत ढोल पीटे गए । लेकिन उस दौरान में एक भी मिल मालिक को जेल में नहीं डाला गया । मजदूरों ने जिन्होंने उनके खिलाफ थोड़ी सी भी आवाज उठाई उनको पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया ।

आप भी बीस सूत्री कार्यक्रम से शुरू करते हैं इसको मैं समझ नहीं पाई हूं । इसमें यह भी नहीं दिया गया है कि जो कुछ भी उस दौरान हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं । साढ़े तीन महीने आपको बैठे हो गए हैं । आप एक सप्लीमेंटरी रिपोर्ट इसके साथ दे सकते थे । आपने यह भी नहीं किया है । इसको मैं समझ नहीं पाई हूं ।

मार्च 1976 में इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट में तबदीली की गई थी । यह कहा गया था कि तीन सौ मजदूरों से अधिक जहां मजदूर काम करते हैं अगर वे लाक आऊट करना चाहते हैं तो उनको सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह गैर कानूनी होगा । जो बीस सूत्री कार्यक्रम का ढोल पीटते हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि मालिकों ने एमरजेंसी के दौरान लाक आऊट किए, कानून के खिलाफ किए, क्या उनमें से भी किसी को जेल भेजा गया, उनके खिलाफ भी कोई ऐक्शन लिया गया ? मुझे खेद है कि अभी भी वही रास्ता हम अपना रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं । इंडियन एक्सप्रैस के लाक आऊट को आप लें । क्यों नहीं आपने उस केस में कानूनी कार्रवाई की । जो मालिक कानून को तोड़ कर लाक आऊट करते हैं, परमिशन नहीं लेते हैं, उनके खिलाफ अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो यही कहा जाएगा कि आप भी पुराने रास्ते पर चल रहे हैं और अगर आपने वही रास्ता अपनाए रखा तो हमारे देश के मजदूरों को न्याय नहीं मिल सकेगा । आपको अभी से सचेत रहना चाहिये । अभी भी आपको जांच करनी चाहिये कि कितने लाक आऊट चल रहे हैं । आपकी रिपोर्ट में यही बताया गया है कि पांच लाक आऊट चल रहे हैं । अगर और भी लाक आऊट चल रहे हैं तो इन सभी को खत्म करवाने के लिए आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिये । अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यही कहा जाएगा कि आप भी उसी पुराने रास्ते पर चल रहे हैं ।

इंडस्ट्रियल रिलेशंज को सुधारने की जो पुरानी मशीनरी थी, पुराना रास्ता था उस पर आप आज भी चल रहे हैं । मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहती हूं पुराने रास्ते के बारे में । राऊरकेला में पांच सात मजदूरों की छंटनी कर दी गई । छः साल हो गये हैं आज तक उनको लेबर कोर्ट में न्याय नहीं मिला है, उनके केसिस का फैसला नहीं हुआ है । उनका केस उस कोर्ट में लगता नहीं है । ऐसा भी होता है कि लेबर कोर्ट में अगर मजदूरों के पक्ष में फैसला हो जाता है तो मालिक लोग उस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक में ले जाते हैं और सालों तक मजदूर बेकार फिरता रहता है । उसकी फैमिली तबाह और बरबाद हो जाती है । उसको कहीं न्याय नहीं मिलता है । लेबर कोर्ट को आप लेबर कोर्ट क्यों कहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है । लेबर कोर्ट और लेबर आफिस को आपको मालिक कोर्ट और मालिक आफिस कहना चाहिये । ये मालिकों की मदद करती हैं । लेबर आफिसर्स ने कभी भी नहीं देखा गया है कि मजदूरों की कभी भी मदद की हो । यह मशीनरी मजदूरों के खिलाफ काम

[श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर]

करती है । इसमें अगर सरकार सुधार नहीं करेगी तो इंडस्ट्रियल रिलेशंज किसी भी हालत में सुधर नहीं सकेंगे । मजदूरों में असन्तोष व्याप्त रहेगा और इसका फायदा मालिक लोग उठायेंगे । यह आपके ध्यान में रहना चाहिये । इसलिए कानून में तब्दीली करनी चाहिये ।

बंधुआ मजदूरों के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कुल 91,642 बंधुआ मजदूर थे । मैं समझती हूं कि इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है । उनकी संख्या कहीं अधिक है । आज भी महाराष्ट्र में थाना जिले में, धूलिया में बंधुआ मजदूर हैं । लेकिन यहां बताया गया है कि 91,642 में से 90,704 को मुक्त करा दिया गया है । इस पर कौन विश्वास करेगा ? फिर आप देखें कि कितने दिनों में कराया गया है । कितने एफिशेंट हमारे चीफ मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर हो गये थे । फरवरी, 1977 में कानून पास हुआ और मार्च में चीफ मिनिस्टर्ज की मीटिंग हुई । तब तक रिव्यू भी हो गया, मुक्त भी करा दिया गया । एक महीने के अन्दर अगर हमारे चीफ मिनिस्टर इतने एफिसेंट हो सकते थे तो मैं समझती हूं कि हमारे पूरे देश का भाग्य बदल सकता था । इन सबको एक ही महीने में मुक्त करवा दिया गया । वाराणसी के एक रिसर्च प्रोफेसर हैं डाक्टर कृपा शंकर । उन्होंने वाराणसी में जाकर के, यू० पी० में जा करके बंधुआ मजदूरों से बातचीत की और रिसर्च किया, मालूमात की तो उन मजदूरों ने कहा कि हमारी परिस्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं आया है । हमारी वही परिस्थितियां हैं हमें उसी तरह बंधकर काम करना पड़ता है, सारे वही बन्धन है, हम दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं । और रिपोर्ट में कहते हैं कि बंधुआ मजदूर देश में नहीं रहे । इस तरह से ऐग्जेजरेटेड रिपोर्ट अगर पार्लियामेंट के सामने आयेंगी तो जनता कैसे विश्वास करेगी । इसलिए मंत्री जी को ठीक तरह से जांच करके मालूमात हासिल करनी चाहिये । सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर कर्नाटक में थे 58,918 । इन में से 58,571 मुक्त कर दिये गये । चार दिन में इतने मजदूरों को मुक्त करना कितना बड़ा भारी काम है । इन गलत रिपोर्टों के बारे में मंत्री जी को जांच करनी चाहिये ।

आपने एग्रीकल्चर वर्कर्स को मिनिमम वेज देने की बात कही है । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी—दादरा नगर-हवेली —में से सबसे कम एग्रीकल्चर वर्कर को मिलता है— 2.34 पैसा प्रति दिन मिलता है । जब केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में सबसे कम मजदूरी मिलती है तो कौन ऐसे कानून को अमल में लायेगा ? अनस्किल्ड वर्कर्स को 4.50 पैसा मिलना चाहिये, मगर इतना कहीं भी नहीं मिलता है । हम जब जेल में थ तो रेडियो पर सुनते थे, हम टी० वी० देख नहीं सकते थे लेकिन बहुतों ने टी० वी० में भी देखा कि एक अनस्किल्ड वर्कर्स को इतनी वेज कम से कम मिलती है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं । जिस मजदूर के लिए कानून बनाया उसके घर में अगर वहीं अंधेरा है तो उसका कुछ लाभ नहीं है । इमरजेंसी में जितने कानून बने उनमें से किसी कानून का इमप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है । कानून का इमप्लीमेंटेशन होना चाहिये । ऐग्रीकल्चर वर्कर्स के बारे में अभी तक कानून का इमप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है । ऐग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज बहुत कम है । अनस्किल्ड वर्कर्स को अगर 4.50 पैसा मिलता है और 25 दिन महीने में उसको काम मिला तो वह एक महीने में 100 रु० ही कमायेगा ।

इस देश की 80 फी सदी जनता देहात में रहती है । अगर महीने में मजदूर 100 रु० ही कमायेगा तो कैसे उसका परिवार चलेगा ? हम कहते हैं कि शिक्षा बढ़नी चाहिये । लेकिन जब तक मजदूर की आमदनी नहीं बढ़ती है, दो वक्त उसको भोजन नहीं मिलता है, तो कैसे शिक्षा में प्रगति होगी ? इसलिए ऐग्रीकल्चर वर्कर की वेज बढ़नी चाहिये । खेती में काम करने वाले मजदूर की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी वेज भी बढ़नी चाहिये, और जिनको काम नहीं मिलता है उसको कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिये ।

सोशल सिक्योरिटी के बारे में आपने बहुत कानून बनाये हैं । हमारे जो मिल मालिक हैं वह मजदूरों से तो प्रोवीडेंट फंड का पैसा काट लेते हैं, लेकिन खुद अपना कंट्रीब्यूशन नहीं जमा कराते हैं । 15 करोड़ का प्रोवीडेंड फंड का कंट्रीब्यूशन मिल मालिकों, एम्प्लाईयस की तरफ जमा कराने के लिए बाकी है । लेकिन अभी तक गवर्नमैंट ने कुछ इस बारे में नहीं किया है । मजदूरों का पैसा तो पगार में से काट लिया जाता है लेकिन मालिक अपने कंट्रीब्यूशन की परवाह नहीं करते । मजदूरों को इस तरह से पैसा मिलता नहीं है । यह मजदूरों के साथ लूट होती है । मिल मालिक जो इसका इम्पलीमैंटेशन नहीं करते हैं, उनको सजा देनी चाहिये । इस बारे में मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये ।

मैं सेफ्टी के बारे में भी कहना चाहती हूं । चासनाला खान की रिपोर्ट अभी आई है उसकी जो दुर्घटना हुई थी, उसमें 4 अफसरों की नैगलीजेंसी से यह हुआ, ऐसा कमीशन ने बताया है । उस कमीशन की मदद करने के लिए हमारे जियालोजिकल डिपार्टमैंट के अधिकारी साथ में थे । मजदूरों के नुमाइंदे भी थे । उन्होंने 4 अफसरों की गलती इसमें बताई है । लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, बल्कि कोई दूसरी चालबाजी चल रही है । उन अफसरों को बचाने की कोशिश हो रही है । उस दुर्घटना में 350 से ज्यादा आदमी मारे गये हैं, अगर अब उसके बारे में ऐसा किया जायेगा तो यह ठीक नहीं होगा ।

कांट्रेक्ट लेबर के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है । मेरा ख्याल है कि इसी की वजह से राजहैरा में फायरिंग हुई है । कांट्रेक्टर अभी 9 रुपए पगार लेते हैं और मजदूर को 5 रुपए देते हैं, बाकी वह सब खा जाते हैं । हमारा शासन भी पैसा कांट्रेक्टर को देता है, लेकिन बीच वाले कांट्रेक्टर सब खा जाते हैं । कहा जाता है कि इसको रद्द करने के लिए कानून बनाने वाले हैं, तो यह जल्दी ही बनाना चाहिये ।

मेरा यह सुझाव है कि यूनियनों की रिक्गनीशन सीक्रेट बैलट से होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो पार्टी पावर में थी, उन्हीं की यूनियनों को मान्यता मिलती थी । इंटक की यूनियनें है बहुत जगह मान्यता प्राप्त यूनियनें थीं । हमने टैक्सटाइल मिलों को देखा है कि सुपरवाइजर चन्दा इक्ट्ठा करता था और देता था । उसकी ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए । वैरीफिकेशन के नाम से गलत व्यवहार होता है ।

डिस्क्रीमिनेशन अगेन्स्ट वूमैन बहुत होता है जो महिलायें मजदूर हैं, उनके खिलाफ हर जगह बहुत डिस्क्रिमीनेशन होता है । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं । आपके डिपार्टमेंट में 1976 में एक महिला सैल फार्म किया गया है, यह आपकी रिपोर्ट में है । लेकिन उसने अभी तक क्या काम किया है, यह मालूम नहीं है वह सैल कायम हुआ है और आगे काम करेगा ऐसी मुझे उम्मीद है ।

आपने बीड़ी वर्कर्स को इक्वल पे फार इक्वल वर्क देने की बात की है । मध्य प्रदेश में हजार बीड़ी पर 25 पैसे मजदूरी बढ़ा दी

[श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर]

गई, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक सरकुलर निकालकर कहा कि यह कानून औरतों के लिए लागू नहीं है । हमारी यूनियन ने आपके डिपार्टमेंट के पास उस सरकुलर की कापी भेजी है । साठे साहब यहां है नहीं, मालूम नहीं वह इसके बारे में क्या कहेंगे ।

प्लानटेशन के बारे में क्या हो रहा है । जब से यह कानून लागू हुआ है प्लानटेशन के मालिकों ने एक चालबाजी की है । एक ही काम के लिए दो ग्रेड बनाए है---ग्रेड-1 और ग्रेड-II । महिलाओं के लिए ग्रेड II लाग किया है । एक ही काम है लेकिन महिलाओं के लिए जानबूझकर ग्रेड-II रखा, जिससे हमारी महिलाओं का तन पुराने जैसा कम है। वह न इसे ज्यादा देना चाहते है और न करना ाहते हैं इसलिए वूमैन वर्कर की संख्या कम हो रही है। चूंकि महिला मजदूरों को मैटर्निटी बेनिफ़िट देना पड़ता है और उनके बच्चों के लिए क्रीश की व्यवस्था करनी पड़ती है इसलिए कानून से बचने के लिए महिलाओं को नौकरी में नहीं रखा जाता है । इस देश में जब एक स्त्री का शासन था, तब भी ये सब बातें हुई । अब इस स्थिति को बदल देना चाहिए । एक माता का जो हक है, उसकी रक्षा करनी चाहिए ।

अनएम्पलायमेंट के बढ़ने का एक कारण यह है कि हमारी फ़ैक्टरीज और आफ़िसिज में आटोमेशन हो रहा है । एल० आई० सी० में आटोमेशन किया गया है । जहा तक टैक्सटाइल मिलों का सम्बन्ध है, जहां पहले 4 से 8 सांचे थे, अब वहां 32 से 32 सांचे काम कर रहेहै । यू० एन० ओ० की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश में सबसे कम मजदूरी मिलती है---एक फिटर को अमरीका में 15 रुपए, हालैंड में 11 रुपए और जापान में 4 रुपए मिलते है, लेकिन उसी काम के लिए हिन्दुस्तान में केवल 85 पैसे दिए जाते है । इसीलिए बड़ी बड़ी कम्पनियां हिन्दुस्तान में अपने उद्योग खोलना चाहती हैं । इस तरीके से हमारे मजदूरों का इतना बड़ा एक्सप्लायटेशन हो रहा है । जहां मैनपावर प्रचुर मात्रा में है, वहां आटोमेशन को कम करना चाहिए और मैनपावर का इस्तेमाल करना चाहिए ।

इमर्जेंसी के दौरान मजदूरों पर जुल्म करने वाले जो सर्कुलर जारी किए गए, उन्हें वापस लेना चाहिए । रिजर्व बैंक में इस प्रकार का एक सर्कुलर वापस ले लिया गया है, लेकिन एल० आई० सी० में ऐसा नहीं किया गया है । एल० आई० सी० में जो बोनस एग्रीमेंट किया गया था, उसे रद्द कर दिया गया है । वो वापस अमल में लाना चाहिए ।

SHRI G. NARSIMHA REDDY (Adilabad): Mr. Chairman, Sir, we know that for any developing country like ours, the most important thing would be the relationship between the labour and the management of an industry. Unfortunately, for some reason or the other, in this country, the relationship between the labour and the management has not always been in a proper way. That is the only reason here why the labourers go on a strike with the result that the production in the country falls.

So, the main aim of any government would be to maintain the best relationship between the labour and the management. Have we achieved that? With the present policy of the Government, I am very much doubtful whether we can achieve it. For example, it is all right in the private industry where the owner of a factory is not prepared to give the due share to the labourers and they go on strikes. But in the public sector where the proprietorship falls in the hands of Government, even there the labourers go on a strike for demanding their due share. It is a miserable thing and it is shameful, because even there we are not in a position to give the due share to the labourers.

Therefore, there is basically something wrong with our labour policy. That is what I feel. And when we go down to the agricultural sector, this is the sector which is not organised. Unfortunately, in our country, any labour union which is well organised, if they go on a strike with a proper notice or any othr type of notice, they only get their due share; and the unions who have no power or who have no capacity to organise themselves for demanding their due shares, are not talked about; they are left away. As far as agricultural labour is concerned, who are engaged in agricultural operation, they are not organised properly. It is one of the biggest labour forces. But, unfortunately, God forbids, if that union is organised and if they go on a strike, then what would be the fate of this nation.

I would request the hon. Minister to see that this country does not face such a situation. Once the agricultural labourer says that he will not hold the plough in his hands, say, in this season, then what will be the fate of our country? Unfortunately in this country, as I said earlier, whoever puts up a demand, whoever gives a notice of strike, whoever says that unless he is given such and such a thing, he will not work, it is they who get their share.

In my own constituency there is one paper mill, the Sirpur Paper Mill. There are three or four mills of this type, one in my own State and one in Maharashtra. I shall quote the minimum wages fixed there: in the case of Sirpur Mill in Kakaznagar, an unskilled labourer gets a minimum of Rs. 193 and a maximum of Rs. 238; in the same type of industry, in our own State, at Rajahmundry, the minimum is Rs. 302 and the maximum is Rs. 342; the same unskilled worker working in the same industry, in Ballarpur Paper Mills in Maharashtra, gets a minimum of Rs. 407 and a maximum of Rs. 460. This is just an example that I have quoted. In the same industry, in the different paper mills, the minimum wages vary so much. What do you expect from these labourers who are getting the lowest wages? I would request the Minister to see that the same wages are fixed, so that the labourers working in the same type of industry do not feel that, because they are not in a position to organize themselves, they are getting lesser wages.

Taking the example of anotner industry, the bidi industry, this is a very peculiar type of industry; it is an industry which, today, has given work to 20 lakh families in the country. As an hon. Member said, this is an industry where the maximum number of ladies work. This is an industry which does not require any machinery, which does not require any import or collaboration. This is also an industry which is giving you an income of Rs. 150 crores by way of excise duty. And what are you giving them? In your budget you have provided for only Rs. 7 lakhs for an industry which is supposed to be a cottage industry and which is giving a revenue of Rs. 150 crores to this Government. And you have provided just Rs. 7 lakhs for your own administration; that is all. Recently, a labour cess has also been levied. That alone is giving an income of about Rs. 5 crores. So, I would like to submit humbly to the hon. Minister through the Chairman that this is an industry which does not have a factory area. For them, there has been no question of giving housing facilities. These people are today, in all the big cities and in all the villages, sitting on the footpath or in their small huts and are manufacturing bidis. I would request that, with the amount which is going to be collected by way of cess, that is, about Rs. 5 crores, Government should also contribute another Rs. 5 crores and create a revolving fund so that with this revolving fund, like any other housing colonies which are coming up, housing colonies for the bidi manufacturers in their area can be provid-

[Shri G. Narasimha Reddy]

ed; on a hire-purchase system, houses could be given to them. This is the only way by which we can help the bidi manufacturers. Similarly, medical facilities, education and other facilities may also be given to them.

Lastly, I would like to submit this. There are big coalmines, as the Members know. Btu unfortunately in some of the coalmines the cess which is collected for the welfare of the labourers—I would like to draw the attention of the hon. Minister to this—is used for constructing very big school buildings. But whom are they admitting? It is only the officers' children that are admitted into these schools. I will give you an example from my own district where big colonies are there. Thousands of crores have been collected by way of cess and big school-buildings have been constructed where the ordinary labourers' children are not being admitted. The only reason given is that they will be admitted on the basis of merit, but what is the meaning of this 'merit'? It is only fluency in English. You cannot expect a small labourer's child, well acquainted with the English language, to appear for the interview. I would therefore request that in all such places where civil population does not exist and where only colonies are there, education given through these funds should be given to the labourers' children also and not only to the officers' children.

Lastly, I would like to make another suggestion. If you want industries and other things to be developed in our country without any labour problem, then, in my humble opinion, wherever you fix the minimum wages category-wise, you should also fix the prices of essential commodities. We see that whenever there is drought, the prices of essential commodities go up and, when these prices go up, it is but natural that the labourers should want more wages and they go on strike. Therefore, you should fix the prices of essential commodities which are usually required by the labourers and once these are fixed, if by any chance, due to some natural calamity in the country the prices of essential commodities go up, it would be the duty of the Government or the duty of the concerned factory to supply these essential commodities at the rates fixed, so that good-relations between the Management and Labour can be maintained and peace can be maintained and our development programmes can be continued without interruption.

श्रीमती चन्द्रावती (भिवानी) : जनाब चैयरमैन साहब, हमारे सामने जो लेबर की डिमाण्ड्स है उनके समर्थन में मैं खड़ी हुई हूं। जैसे हम मजदूरों का नाम लेते हैं तो कारखाने की शक्ल आटोमेटीकली हमारे सामने आ जाती है। जिस देश में 75 फीसदी या उससे भी ज्यादा आदमी हाथ से काम करते हों, चाहे वे खेत में काम करते हों या कोई फिजिकल लेबर करते हों किसी कारखाने में वहां हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोगों के हाथों में दौलत का रह जाना स्वाभाविक है। एक आदमी के पास मान लीजिए दस कमरों का मकान होता है तो दूसरे के पास एक कमरे का मकान होगा या फिर वह भी नहीं होगा। इस तरह से पूंजी जितने ही कम लोगों के हाथों में रहेगी गरीबी उतने ही ज्यादा लोगों के हिस्से में जाएगी। आज कोई मजदूर चाहे कारखाने में काम करता है, सड़क पर काम करता है या मकान बनाने का काम करता है करीब करीब उन सभी मजदूरों की हालत एक जैसी ही है। जो मजदूर बेचारे मकानों का काम करते हैं या सड़क पर काम करते हैं उनकी तो मजदूरी भी स्थाई नहीं होती और न ही उनकी अपनी कोई खास यूनियन होती है जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें और ज्यादा हो जाती हैं। इस तरह के जो मजदूर हैं या जो भट्ठों के मजदूर होते हैं वे आज एक जगह पर है तो कल दूसरी

जगह पर हो जाते हैं। वे एक खानाबदोश की जिन्दगी बिताते हैं। न तो उनके बच्चों की शिक्षा का कोई सवाल होता है और न उनके खद के स्वास्थ्य का कोई प्रबन्ध होता है। अगर उनमें कोई बीमार हो जाता है तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर की बात तो मैं नहीं करती लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई भी मजदूर आपको नहीं मिलेगा। वहां कुछ न कुछ ऐसे हालात पैदा करते हैं जिस से उनको नौकरी से हटाया जा सके। मान लीजिए वह छुट्टी लेकर घर जाता है, उस को कानून मालूम नहीं है, जब छुट्टी से वापस आता है तो उस से कहा जाता है कि तुम को नए सिरे से लेंगे और इस तरह से उस की पिछली नौकरी खत्म कर दी जाती है। आप को ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में 45 साल से ज्यादा उम्र के आदमी काम करते नहीं मिलेंगे। एक बड़ा विशस-सर्किल उन के अन्दर बना हुआ है, जो उन को वहां रहने नहीं देता।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहती हूं—जिस पर मुझसे पहले बोलने वाले अनेक वक्ताओं ने भी प्रकाश डाला है—कारखानों में जो लोग मशीनों पर काम करते हैं, अगर उनके हाथ-पांव कट जाते हैं या आंख चली जाती है तो वे बेकार हो जाते हैं। ऐसे लोग जो रिस्क का काम करते हैं, अगर उनके साथ कोई इस तरह का हादसा वाका हो जाय तो उनको नौकरी से हटा दिया जाता है, कोई दूसरा काम उनको नहीं दिया जाता है। कल ही मुझे एक आदमी मिला, जो किसी प्राइवेट फर्म में था। उसकी दायें हाथ की अंगुली कट गई, अब वह कहीं भी काम करने लायक नहीं है और उस कारखाने में उसको काम नहीं दिया जा रहा है—बतलाइये, वह बेचारा क्या करे, कहां जाय। इसके बारे में हमें सोचना चाहिये।

जहां तक लेबर कोर्टस का ताल्लुक है—वहां भी ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जो मैनेजमेंट का फेवर करते हैं। मेरा सुझाव है कि लेबर-कोर्टस में ऐसे लोगों को बैठाया जाना चाहिये जो इम्पार्शल हों। यह बात ठीक है कि लेबर यूनीयन्स होती हैं, लेकिन लेबर यूनियनों में भी हमने देखा है कि उनके लीडर मोटे होते चले जाते हैं और मजदूर वैसे का वैसा ही रहता है। जब तक हम अपने देश में आमदनी का, तनख्वाह का अनुपात तय नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा। इस समय हमारे देश में 1 और 100 का अनुपात है, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा ही होगा। इसके लिये आपको तय करना होगा कि यह अनुपात 1 और 4 से ज्यादा न हो और न सिर्फ तनख्वाहों में बल्कि रहन-सहन, मकान और दूसरी तमाम चीजों में इस अनुपात को कायम करना होगा, तभी हम अपने समाज को न्याय दे सकेंगे। हम तय कर सकते हैं कि किसी आदमी के पास एक हजार गज से ज्यादा का मकान नहीं होगा, उस पर मल्टी-स्टोरी फ्लैटस बनाये जायेंगे उस को रहने के लिए एक फ्लैट मिलेगा, जिससे सब को रहने के लिये जगह मिल सके। जब तक हम इसके बारे में कोई सोशल कानून नहीं लायेंगे, तब तक चाहे जो कहते रहें, हम उनके साथ न्याय नहीं कर सकते हैं।

मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहती हूं —आज हमारे बोलने में भी छोटे और बड़े का फर्क लगा हुआ है। जब तक हमारी भाषा में आप, तुम और तू शब्द लगा हुआ है—तब तक यह फर्क कायम रहेगा। हमारे यहां कहा जाता है—माया तेरे तीन नाम, परसू, परसा, परसराम। जब तक यह फर्क हमारे समाज में कायम है, तब तक हमें सामाजिक न्याय मिलेगा, यह मुश्किल है। कारखाने में काम करने वाले सब मजदूर हैं—लेकिन मैनेजर तू कर कर बोलता है, उस को क्या हक है कि वह तू कह कर बोले। चूंकि हमारे मजदूरों में शिक्षा की कमी है, उनको बचपन से ही इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि उनको सहन करना है, क्योंकि

[श्रीमती चन्द्रावती]

उनकी किस्मत में ही ऐसा लिखा है । मेरा बस चले तो जो किस्मत और कर्म लिखने वालों का साहित्य है, उस को खत्म कर दूं, ऐसा साहित्य लिखा ही नहीं जाना चाहिये, बल्कि उन लोगों पर जुर्माना होना चाहिये जो किस्मत और भाग्य की बात करते हैं । हमें उनके अन्दर इस भावना को निकालना है कि वे सिर्फ मजदूरी के लिये ही पैदा हुए हैं । चेअरमैन साहब, आपके नोटिस में मैं यही लाना चाहती हूं कि उनके रहन-सहन के, उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाने के, उनकी तरक्की के इन्तजाम ठीक से किये जाएं ।

हमारे यहां चीजें बनती हैं—कार हो, साइकिल हो, ट्रांजिस्टर हो, ये सब चीजें और भी अच्छी बन सकती हैं अगर हम मजदूर को अच्छी सुविधाएं दें । आज वह बेचारा गन्दगी में रहता है, गन्दा खाना खाता है, गन्दा पानी पीता है । इसलिए हम अच्छी चीजें अपने देश में अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें मजदूरों की हालत को अच्छा करना होगा । जिस प्रकार मालिक चाहता है कि प्रोडक्शन बढ़े उसी तरह मजदूर भी चाहता है कि प्रोडक्शन बढ़े । यह प्रोडक्शन तभी बढ़ सकता है जब हम मजदूर का भी ख्याल करेंगे । हमें यह देखना होगा कि वह अच्छे वातावरण में पैदा हो, वह इस तरह के वातावरण में पैदा न हो, जिस तरह के वातावरण में वह पैदा हुआ है । जब तक मजदूर का स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं होता तब तक प्रोडक्शन भी एफीशियेन्ट और अच्छा नहीं हो सकता । मजदूर का सारा जीवन गन्दगी में बीतता है । उसे अच्छा वातावरण मिलना चाहिए ।

इसके साथ साथ मैं आर्टिजंस की बात भी कहे बिना नहीं रह सकती । इन आर्टिजंस का भी एक्प्लोइटेशन होता है । सभी आर्टिजंस का शोषण होता है । चाहे बनारस में जरी का काम करने वाला हो, चाहे काश्मीर में शाल का काम करने वाला हो, चाहे छोटे जूते बनाने वाला हो, सभी का एक्प्लोइटेशन होता है । यह एक्सप्लोइटेशन इसलिए होता है कि इन्हें मार्किट के लिए कारखाने वालों पर निर्भर करना पड़ता है । आप छोटे छोटे कारखाने खोलने जा रहे हैं । लेकिन जब तक आप उनकी प्रोड्यूस के लिए उन्हें मार्किट नहीं देंगे तब तक बड़े बड़े कारखाने वाले उनका एक्सप्लोइटेशन करते रहेंगे । लुधियाना और पानीपत में छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज हैं । हेण्डलूम का, रंगाई का वहां काम होता है । छोटे छोटे लोग वहां प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उनके पास मार्किट नहीं है और उन्हें अपना माल कारखानेदारों को देना पड़ता है । उनकी प्रोड्यूस का उन्हें जितना मुनाफा मिलना चाहिए उतना उन्हें नहीं मिलता है । यह सारा मुनाफा बड़े कारखानेदारों को चला जाता है । इसलिए मैं चाहूंगी कि जहां भी आप इन इण्डस्ट्रीज को खोलें वहां उनकी मार्केटिंग का पूरा इन्तजाम करें ।

आज उद्योग मन्त्री जी कह रहे थे कि बिहार में सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और वहां सबसे ज्यादा गरीबी है । इसलिए हम इसके पक्ष में नहीं रहे कि हरियाणा में बड़े उद्योग लगें । जब हम छोटे उद्योग खोलने जा रहे हैं तो हमें मजदूरों की भलाई के लिए भी कदम उठाने होंगे । जो हमारा स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है उसकी तनख्वाह के अनुपात में हमें उसके लिए सुविधाएं जुटानी पड़ेंगी । मैंने कहीं पढ़ा था, हो सकता है कि यह गलत हो, हम जितना प्रोडक्शन करते हैं उसके हिसाब से ज्यादा मजदूरी उसको देते हैं । हमें इसलिए उसको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, हमें उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा जिससे वह ज्यादा मजदूरी कर सके और प्रोडक्शन करने में उसकी सहानुभूति हो । कोई कारखाना आजकल ऐसी जगह नहीं है जिस के पास दारू की दुकान खड़ी न कर

दी गई हो । जहां स्कूल होना चाहिए वहां दारू की दुकान है । गुड़गांव में मैंने एक पोल्ट्री फीड की फैक्ट्री देखी । वहां 15–20 वर्कर्ज से मैं मिली । उनमें से पांच सात पढ़े लिखे थे, बाकी अनपढ़ थे । उन अनपढ़ों में भी कुछ स्किल्ड थे । उसके पास ही दारू की दुकान थी । मैनेजमेंट की तरफ से अगर वहां स्कूल खोल दिया गया होता जहां वे एक दो घंटे जाकर पढ़ लेते तो कितना ही अच्छा होता । अब उनका पैसा वहीं का वहीं दारू की दुकान में दारू पीने में खर्च हो जाता है । मैं चाहती हूं कि आपको वहां स्कूल उनके वास्ते खोलने चाहिये बजाये इसके कि दारू की दूकानें खोलने की आप इजाजत दें । इससे समाज को भी और उनको भी फायदा होगा ।

कुछ कारखाने हैं जहां काम करने पर मजदूरों का स्वास्थ्य बहुत जल्दी खराब हो जाता है जैसे रूई का कारखाना है, सीमेंट का है । वहां पर सावधानी के तौर पर ताकि मजदूरों की सेहत खराब न हो कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । वे बहुत जल्दी टी० बी० के पेशेंट हो जाते हैं । एक बार उन्होंने छुट्टी ली तो हमेशा के लिए उनकी छुट्टी कर दी जाती है । मैं चाहती हूं कि आप अपने तौर पर करें या प्रान्तीय सरकारों के जरिये करें आपको यह पता लगाना चाहिये कि सीमेंट के या रूई के कारखानों में या दूसरे कारखानों में कितने अर्से में लेबर को और कितनी प्रतिशत लेबर को टी० बी० आदि बीमारियां हो जाती हैं वे रोगग्रस्त हो जाते हैं । उसके बाद आपको चाहिये कि वहां पर आप इस बात का इन्तजाम कराएं जिससे मजदूर रोगग्रस्त इतनी जल्दी न हो सकें और कारखानेदारों को कहें कि वे मजदूरों को कांफिडेंस में लें, उनका सहयोग ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें ताकि उनका प्रोडक्शन भी बढ़े और सामग्री भी अच्छी पैदा हो ।

इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहती थी ।

SHRI P. THIAGARAJAN (Sivaganga): So far as this subject of labour is concerned there are so many categories of labourers—agricultural, mill workers, etc.

So far as agricultural workers are concerned, there are two special Acts. But the workers are not properly paid. Even the bond system is still existing in various parts of Tamilnadu. The agricultural labourers are not given protection by the Government. They are not employed throughout the year. They are employed only for three or four months a year. The remaining eight months are wasted and they remain unemployed.

In Tamilnadu there are two Acts—Cultivating Tenants Protection Act and Tanjore Pannyal Protection Act. No doubt these are meant to protect the labourers and farm workers but they do not get proper protection.

The agricultural labourers do not get protection at all. They are paid only Rs. four or five per day. They cannot maintain their family which comprises of six or seven children. They cannot educate their children. They cannot meet their necessities of life.

When we take into account the conditions of labourers, they must be given protection. There must be an office to look into the welfare of the labourers.

As far as the agricultural labourers in our parts of the area are concerned, there are so many persons who have been repatriated from Burma and Ceylon. They are settled in Tamilnadu in various parts of the districts and they are unemployed throughout the year; they are hard-working and capable persons. Unfortunately they are not absorbed in either agricultural operations or in the mills. They are wasting their time. The country is not utilising the labour of these persons who have done so much for Burma and Ceylon and who have now

[Shri P. Thiagarjan]

come to India. Their services are not properly utilised by Government.

The workers employed in spinning mills and weaving mills are not given proper protection; as far as medical facilities are concerned, there are no such medical facilities and employers are not bothered about it. As far as management is concerned they want to squeeze the workers. They are not given residential quarters; they are not given medical facilities; they are not even paid their minimum wages. Even the badli workers are thrown out of employment by the management without any proper notice or proper legal action. Most of the workers in our part are compelled to work more than the prescribed time. They are not even paid the proper amount for the additional work. Absolutely there is no facility for their residential accommodation. They will have to come from far off places to attend to the mill work. So far as these workers employed in the textile mills are concerned, no encouragement is being given either by the labour Officer or by the Management. If they meet with any difficulties from the management, they will have to seek remedy from the Labour Officers who are supposed to be agents of the management. The Labour Officers themselves consider themselves as agents of the management. The welfare of the workers is not at all considered by the Labour Officer. Industrial disputes which are to be considered and reconciled by the Labour Officers are not settled smoothly and quickly.

Sir, when a worker is thrown out of employment naturally he has to seek remedy from the Labour Officer who is the proper person to look into the matter. The poor worker has to wait for a number of months. He is not given the remedy quickly.

So, he has to incur so much of expenses. He is not getting employment. And ultimately he has to seek the remedy in the court of law. Even in the Labour Tribunals they have got a number of cases of labour disputes which they are not able to dispose of quickly.

In order to dispose of the labour disputes quickly, I suggest that the Government may appoint special category of judges to deal with only the industrial dispute cases. For this purpose, the district level officers may be appointed. Apart from that, the labour dispute cases may be dealt with by the high court or by some other appellate courts.

As far as various acts which protect the welfare of the labourers are concerned, I say that no act will help the labourers. Take even the Industrial Disputes Act, Workmen's Compensation Act, the Minimum Wages Act and other acts. They are not helpful to the labourers. On the contrary, these acts are helpful to the management. If you take into account various recommendations, like the Wage Board Recommendations, they are not binding upon the management. If we simply say that the Wage Board recommendations should be implemented, the management may refuse to implement those recommendations. In that event, the labourers have no other alternative except to resort to strikes. There is no remedy and they are not bound to abide by the wage board's recommendations. For example, a Committee was formed under the chairmanship of Shri Ramanujam by the previous Lok Sabha which was mainly constituted to go into and evaluate the impact of the scheme of workers, trade unions and the employers and to suggest some modifications. But, these have no effect and these recommendations have not been implemented.

When we take all these factors into account, I feel that the Labour Ministry of the Government of India should give protection. The hon. Labour Minister must be able to enact a law so as to bring all categories of labourers under the Union Act to deal with this.

श्री वाई० पी० शास्त्री (रीवा) : माननीय सभापति महोदय, श्रम मन्त्रालय की मांगों का मैं इस आशा और विश्वास के साथ समर्थन कर रहा हूं कि मजदूरों के प्रति वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है । पिछली सरकार का दृष्टिकोण केवल मजदूरों के प्रति मौखिक सहानुभूति व्यक्त करना था, वास्तव में उनकी नीति तो मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण करने का अवसर प्रदान करने की थी ।

पिछले दिनों जो कुछ होता रहा है, उससे बिल्कुल हट कर मजदूरों के प्रति एक नया दृष्टिकोण जनता पार्टी की सरकार ने अपनाया है । मजदूरों ने समूचे देश में सरकार की वर्तमान नीति का समर्थन किया है और उनके हृदय में बहुत बड़ा उत्साह है और सरकार से बड़ी-बड़ी आशाएं उनको हैं ।

पिछली सरकार ने कहने के लिये कानून तो बहुत बनाये थे, मजदूरों के नाम पर, चाहे वह पेमेंट आफ मिनिमम वेजेज एक्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट हो या इडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो, लेकिन ये सारे कानून केवल कागजों तक ही सीमित रहे । मजदूरों को इनसे न्याय नहीं मिल सका । ऐसे कानून बनाये जिससे कभी भी मजदूर अपने हितों का संरक्षण नहीं कर सका, उसके साथ न्याय नहीं हो सका ।

मैं चाहता हूं कि हमारे प्रगतिशील श्रम मन्त्री नवयुवक हैं, वे इन सारे सवालों को नये परिप्रेक्ष्य में देखें और एक क्रान्तिकारी परिवर्तन उन सब में लायें । इन कानूनों को बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है । मैं थोड़े से समय में कुछ मोटी-मोटी बातें सदन के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं ।

आज मजदूरों की न्यायोचित मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए कोई प्रभावकारी व्यवस्था नहीं है । उन की मांगों की सुनवाई नहीं होती है । हमारा सरकारी तंत्र बड़ा हास्यास्पद और विचित्र है । अगर मजदूर हड़ताल का नोटिस देते हैं, तो श्रम विभाग के अधिकारी मालिक और मजदूरों के प्रतिनिधियों को बुलायेंगे । अगर मालिक न आये, तो वे उसे आने के लिए मजबर नहीं कर सकते । उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे मजदूरों की न्यायोचित मांगों को मालिक से मनवा सकें । 15, 20 दिन या एक महीने तक कनसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं । अक्सर मालिक समय मांग लेंगे कि हम एक महीने के बाद जवाब देंगे, और उसके बाद कह देंगे कि हम इन मांगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं । तब अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिवाए यह रिपोर्ट देने के कि कनसिलिएशन प्रोसीडिंग्स फेल हो गई हैं ।

चीफ लेबर कमिश्नर भी इस विषय में कुछ नहीं कर सकते । वह मजदूरों की बात को सुने बिना उनकी कुछ मांगों को—सब मांगों को नहीं —एडजुडिकेशन के लिए भेज देंगे । इसके बाद सालों तक चलने वाली बहुत लम्बी प्रक्रिया शुरू हो जाती है । मामला ट्रिब्यूनल में जायेगा और फिर हाई कोर्ट में जायेगा । मालिक के पास बहुत पैसा होता है; वह सुप्रीम कोर्ट तक जायेगा । इस तरह कारखाने या खदान में काम करने वाले मजदूरों को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता है । उनके पास न पैसा है, न समय है, न धीरज है कि वे बड़े बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से लड़ सकें । मैं श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इन कानूनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन करें ।

सबसे पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि कम्पलसरी आरबिट्रेशन की

[श्री वाई० पी० शास्त्री]

व्यवस्था की जाये । अगर मालिक मजदूरों की मांग को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट करता है, तो अनिवार्य रूप से उसका आरबिट्रेशन होना चाहिये, और उसका निर्णय मालिक और मजदूरों दोनों के लिए बंधनकारी और मान्य हो । तभी मजदूरों को न्याय मिल सकता है । अभी तक जो प्रणाली है, वह मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली प्रणाली नहीं, बल्कि शोषकों, उद्योगपतियों के हितों का संवर्द्धन करने वाली प्रणाली है । इसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये । मैं उम्मीद करता हूं कि जनता पार्टी की सरकार इस बारे में तत्काल निर्णय लेगी और मंत्री महोदय उत्तर देते समय स्पष्ट रूप से घोषणा करेंगे कि कनसिलिएशन प्रोसीडिंग्स की विलम्ब करने वाली प्रणाली समाप्त कर दी जायेगी, ताकि मजदूरों की न्यायोचित मांगों के सम्बन्ध जल्दी से जल्दी निर्णय हो सके और उन्हें न्याय मिल सके, और मजदूर समझ सकें कि सचमुच आज उनकी सरकार है—ऐसी सरकार है, जिसे उसके हितों की चिन्ता है ।

पिछली सरकार ने मजदूरों के साथ जो बहुत बड़ा अन्याय किया था, उसका निराकरण तत्काल होना चाहिए । आपातकाल की, घोषणा का सबसे अधिक प्रभाव इस देश के श्रमिक वर्ग पर पड़ा था । उनका 8.33 प्रतिशत बोनस, जो उन्होंने बहुत बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त किया था, छीन लिया गया । अचानक कह दिया गया कि अब तो केवल 4 प्रतिशत बोनस रहेगा और केवल वही कारखाने, वही संस्थान देंगे जो मुनाफा कमाते हैं । अब मुनाफा कमाने का तो मामला इतना पेचीदा है कि इसकी कोई जांच हो ही नहीं सकती । कोई भी बड़ा उद्योगपति कभी यह नहीं कहता कि हमें मुनाफा हुआ है । वह तो हमेशा घाटा ही बताता है, नहीं तो उसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और वेल्थ टैक्स देना पड़ेगा । इसलिए वह कभी भी सही मुनाफा बता नहीं सकता और मजदूरों को बोनस मिल नहीं सकता । जो उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा है वह उनको नहीं मिल सकता । यह सिद्धांत मान लिया गया था कि यह बोनस उनकी मजदूरी है, डेफर्ड वेजेज है । यह वह मजदूरी है जो सही माने में मजदूर को दी नहीं गई थी इसलिए 12 महीने काम करने के बाद एक महीने का वेतन 8.33 प्रतिशत के रूप में उन्हें दिया जाय । आपात स्थिति में यह समाप्त कर दिया गया । लेकिन मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज का मजदूर उसके लिये अब और अधिक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है । उनको बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हमारी जनता सरकार से हैं । इसलिए मंत्री जी आज या कल जब मंत्रालय की मांगों का जवाब दें तो इसकी भी घोषणा वे करें कि यह 8.33 प्रतिशत बोनस अनिवार्यतः सभी मजदूरों को मिलेगा ।

इसमें आप इसकी परवाह न करें कि कोई यह कहेगा कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी । यह बात मैं बहुत सुनता हूं और मुझे बहुत दुख होता है कि इससे कि जो लोग समझते नहीं कि मुद्रा-स्फीति कैसे बढ़ती है वे लोग इसका नारा लगाते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और उससे महंगाई और बढ़ जायेगी । यह एक कहने का तरीका हो गया है । कोई इसकी गहराई में नहीं जाता चाहात कि मुद्रा-स्फीति बढ़ती कैसे है उसके परिणाम में महंगाई कब बढ़ती है । मुद्रा-स्फीति बढ़ने का मामला तो तब होता है जब रुपया इकटठा करके संग्रह के रूप में रखा जाय या उसका उपयोग अधिक से अधिक चीजों की खरीद करने में किया जाय । उत्पादन कम हो और उस पैसे का उपयोग अधिक से अधिक चीजों को इकटठा करके रखने में किया जाय तब मुद्रा-स्फीति बढ़ती है और उसके परिणामस्वरूप महंगाई बढ़ती है । लेकिन

मजदूरों के मामले में तो रुपया संग्रह करके रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता । वह तो हैड टू माउथ रहता है । काम कर लाता है, खा जाता है । उसको पैसा देने से मुद्रा-स्फीति का खतरा कहां आता है ? वह तो उसका पैसा है जो उसको मिलना चाहिये, उसकी मजदूरी है वह । वह उसका संग्रह नहीं कर सकता । वह उससे आवश्यक वस्तुयें खरीद कर उनका संग्रह करके उससे मुनाफाखोरी भी नहीं कर सकता । वह पैसे तो केवल उसके खाने के लिए और जो उसकी न्यूनतम आवश्यकतायें है उनकी पूर्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है । वह बोनस जो आप देंगे वह उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा । तो उससे मुद्रा-स्फीति नहीं होने वाली है ।

दूसरी ओर यह बोनस जिसको मिलेगा, उसकी वास्तविक मजदूरी उसको मिलेगी तो उसका उत्साह बढ़ेगा और उससे वह और अधिक उत्पादन करेगा । जब उत्पादन बढ़ेगा तो उससे मुद्रा-स्फीति रुकेगी । मुद्रा स्फीति रोकनें का इससे कारगर तरीका दूसरा कोई नहीं हो सकता । उसका यही उपाय है । और यह तो देखा जा चुका है, अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि अगर मजदूर के साथ न्याय किया जाय, उसको सही मजदूरी दी जाय, उसका बोनस उसको दिया जाय, उसके अधिकार दिए जायें, तो उससे उत्पादन बढ़ता है । अभी पिछले दिनों हमारे रेल मंत्री ने इसी सदन में बताया था कि चूंकि हमने रेल मजदूरों के साथ न्याय किया, पिछली हड़ताल के समय जिनको निकाला गया था उन सबको काम पर वापस ले लिया , तो उसका नतीजा यह हुआ कि पिछले साल जो डेढ़ करोड़ का उत्पादन हुआ था उसकी जगह इस साल छः करोड़ का उत्पादन हुआ है । जो उत्पादन के केन्द्र हैं चाहे वह डीजल इंजन का कारखाना हो, चाहे वैगन बनाने का कारखाना हो, उन सबमें मिला कर 6 करोड़ का उत्पादन हुआ है । इससे साबित हो गया है कि मजदूरों को दबा कर रखने से, उनको भूखा रखने से आप उत्पादन नहीं बढ़ा सकते, बल्कि उनके साथ न्याय करके, उनके उचित हकों को उन्हें देकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है । यही सबसे बड़ा तरीका है । इन्फ्लेशन रोकने का भी यही सबसे कारगर फारमूला है । इसलिए यह बोनस उनको देने की घोषणा तत्काल श्रम मंत्री जी करें ।

इसी तरह से जो यह कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम की रकम जुलाई में देय डिपाजिट स्कीम को रकम जुलाई में देय थी और उसे प्राविडेंट फंड में डाल दिया गया, पिछली बार जब यह प्रकरण आया था तब भी मैंने उसके लिए कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि यह उनके साथ अन्याय है । यह पैसा उनको वापस किया जाना चाहिये । बहुत बड़ी उम्मीद मजदूरों ने की थी कि जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमको अवश्य ही यह पैसा वापस मिल जाएगा । लेकिन यह उनके प्राविडेंट फंड में डाल देने का जो निर्णय लिया गया है यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है । एक तो महंगाई भत्ता उन्हें यों ही पूरा नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है । जितनी महंगाई है उसमें मात्रा में महंगाई भत्ता उसको मिलता नहीं है क्योंकि प्राइस इंडेक्स जिस तरह से आंकलित किया जाता है और जिस तरह से उसके आंकड़े तैयार किये जाते हैं वह बहुत ही गलत है । उन गलत आंकड़ों के आधार पर पूरी की पूरी महंगाई को न्यूट्रलाइज करने के लिए महंगाई भत्ता उन्हें नहीं दिया जाता । केवल कुछ जगहों में बैरिएबल डीयरनेस इलायेंस उनको मिलता है । जब सब जगह वह नहीं मिलता और जहां मिलता भी है वहां सूचकांक बढ़ने के अनुपात में पूरी महंगाई

[श्री वाई० पी० शास्त्री]

भत्ता उन्हें नहीं मिलता । जो महंगाई होती है उसको देखते हुये उसको न्यूट्रलाइज करते हुये नहीं मिलता है, उसका आधा ही मिलता है । लेकिन उस महंगाई भत्ते का भी आपने उससे छीन लिया । पहले की सरकार ने तो उसके साथ सारे का सारा अन्याय किया ही था । उसको जबर्दस्ती उनके कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम में जमाकर दिया गया जब कि उन्हें इसकी आवश्यकता तत्काल थी, अपना अनाज खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, अपने बच्चों को दवा देने के लिए । उस पैसे को पिछली सरकार ने अनिवार्य जमा योजना में जमा कर दिया था, उसका भुगतान होना चाहिये था और जब वह पैसा उनके हाथ में आने वाला था तो आपने अचानक निर्णय कर दिया कि उसका उनके प्रोविडेंट फंड में जमा करवा दिया जायेगा । उस दिन माननीय वित्त मंत्री ने जो घोषणा की उसका हमें स्वागत करना चाहिये कि प्रोविडेंट फंड में भी ब्याज की दर वही रहेगी जो कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम में थी, उसमें कमी नहीं होगी लेकिन ब्याज पर रुपया जमा कराने की हैसियत उन गरीब मजदूरों की नहीं है । यह बात तो मैंने संगठित क्षेत्र के मजदूरों के सम्बन्ध में कही ।

अब मैं आपके माध्यम से उस वर्ग के मजदूरों की स्थिति भी सरकार के सामने रखना चाहता हूं जो कि संगठित है जिनकी ओर कभी किसी ने देखा ही नहीं । इन असंगठित मजदूरों में खेतिहर मजदूर है, बीड़ी बनाने वाले मजदूर है, लोक निर्माण विभाग के मजदूर है, आरा मशीन और दाल मिलों में काम करने वाले मजदूर है तथा छोटे छोटे होटलों में काम करने वाले मजदूर है जिनका अपना कोई संगठन नहीं है । वे अपनी आवाज बुलन्द नहीं कर सकते है । पिछली सरकार ने तो उनके लिए कुछ किया नहीं लेकिन आज इस सरकार से हम उम्मीद करते है कि उनके लिए कुछ करेगी । उनकी मजदूरी की बात आप सुनेंगे तो हैरान रह जायेंगे । अगर उनकी सही सही मजदूरी बता दी जाये तो दुनियां उसको सुनकर हंसेगी । हमारे मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में एक मजदूर की प्रति दिन की मजदूरी 2 रुपए 40 पैसे है । जो वर्कजार्ज के मजदूर है उनको 1947 में जो 30 रुपया महीना मिलता था वही आज भी मिल रहा है । सरकार ही उनकी मालिक और नियोजक है । कोई पूंजीपति उनका नियोजक नहीं है । या 30 रुपया महीने की मजदूरी दुनियां में किसी ने सुनी होगी ? जो मजदूर सड़क और पुल बनाने का काम करते है उनको 2 रुपया 40 पैसा प्रति दिन मिलता है। पिछली सरकार ने बड़ जोरों से ढिंढोरा पीटा था कि खेतिहार मजदूर की न्यूनतम मजदूरी तय कर रहे हैं। कहीं तीन रुपया, कहीं साढ़े तीन और कहीं पर चार रुपया मजदूरी तय की गई। इस पर लोगों ने कहा कि आप किसानों से कहते हैं कि खतिहार मजदूरों को कम से कम इतना दो लेकिन जो स्वयं तुम्हारे मजदूर हैं, जिनसे सरकार स्वयं काम लेती है और जिनके काम के घण्टे भी 8 नहीं बल्कि 12-14 घण्टे होते हैं, जो पी०डब्लू०डी० में काम करते हैं उनको केवल 2 रुपया 40 पैसा प्रति दिन क्यों दिया जाता है ? इस असंगति कोई इस अन्याय को और इस शोषण को सरकार समाप्त करेगी या नहीं ? जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि अपने देश में अधिक से अधिक और कम से कम आमदनी का अन्तर एक और बीस से ज्यादा नहीं रहने दिया जायेगा और धीरे धीरे इसको एक और दस के अन्तर पर लाया जायेगा। आप इस बात को सोचें कि एक तरफ 30 रुपए महीने की मजदूरी है और दूसरी तरफ बड़े बड़े उद्योगपतियों की आमदनी है और

हमारे शासकीय क्षेत्र में राष्ट्रपति महोदय की 10 हजार रुपए महीने की तनख्वाह तो है ही ऐसी हालत में अगर एक और बीस का अन्तर रखना है तो कम से कम जो आमदनी हो वह 500 रु० मासिक से कम नहीं होनी चाहिये। अभी कुछ वर्ष पूर्व देश में बड़ा संघर्ष हुआ, रेल मजदूरों ने, खदान मजदूरों ने और कारखाना मजदूरों ने संघर्ष किया कि नीड बेंस्ड मिनिमम वेंज होनी चाहिए। श्री गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में थर्ड पे कमीशन ने 1974 में एक हिसाब लगाकर रिपोर्ट में लिखा है। न्यूनतम मजदूरी यदि जरूरत के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर आंकी जाये, तो उस समय 1974 में 314 रुपये से कम नहीं होगी। उस के बाद महंगाई काफी बढ़ी है, इस लिये अब तो और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 314 रुपए से कम तो किसी मजदूर को मिलना ही नहीं चाहिए—ऐसा उस समय गजेन्द्र गडकर कमीशन ने लिखा था। लेकिन उस सरकार ने कमीशन की उस सिफारिश को नहीं माना। मैं जानना चाहता हूं कि अब हमारी सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है। मैं चाहता हूं कि जनता सरकार सब से पहले उच्च-प्राथमिकता इस सवाल को दे, क्योंकि यह देश का सचमुच में सबसे निचला तबका है।

अन्तोदय की बात हमारे प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तावित कृतज्ञता प्रस्ताव के उत्तर में कही थी। हम को अन्तोदय का आदर्श अपने सामने रखना है, अन्तवाला कौन है, अन्तिम स्थिति में नीचे के स्तर पर कौन लोग हैं? हमारे देश के खेतिहर मजदूर, पी० डब्ल्यू० डी०, मजदूर, सर्वहारा समाज, जिन के पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिन के पास सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है—यह समाज है जिस की तरफ़ हमारा ध्यान जाना चाहिए। भादों के महीनों में, जब वर्षा की झड़ी लगी होती है—उस समय अगर कोई खेतिहर मजदूर एक दिन खेत में काम करने नहीं गया, तो वह बड़ा किसान उस को उसके झोपड़ से निकाल कर बाहर कर देता है। अपने बाल-बच्चों, पत्नी को लेकर उस भादों की अंधेरी रात में पेड़ के नीचे जा कर बैठता है—यह हालत है उस सर्वहारा समाज की। इन्होंने पिछले दिनों बहुत ढिंढोरा पीटा कि बन्धक मजदूरों को मुक्त कर दिया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन को कहीं भी मुक्त नहीं किया गया। मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जानता हूं, जहां तक बन्धक मजदूरों की प्रथा है। जहां भू-स्वामी लोग कुछ थोड़ा सा कर्जा दे देते हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी परिवार-भर के लोगों को बन्धक-मजदूर बना कर रखते हैं। अगर वह काम करने न जाये, कम से कम मजदूरी पर काम करने से इन्कार करे तो उनको उनके घरों से निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। आज तक इतनी सुरक्षा भी उन को प्रदान नहीं की गई है कि जिस जमीन पर उन का घर बना हुआ है, उस से उन को नहीं निकाला जाएगा—यह हालत है आज इस देश के करोड़ों लोगों की।

कहा गया है कि 98 लाख लोग बेकार हैं—ये आंकड़े एम्पलायमेंट एक्सचेंज में दर्ज नामों के आधार पर दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि ये आंकड़े गलत हैं, एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में नाम दर्ज कराने वाले बहुत कम लोग हैं। यदि गांव-गांव का सर्वेक्षण किया जाये तो आप को मालूम होगा कि यह संख्या सात करोड़ से कम नहीं है। जो लोग एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराते हैं, जब उन को नौकरी नहीं मिलती, चार-चार, पांच-पांच साल बीत जाते हैं उनको इन्टर्व्यु तक के लिए काल-लैटर नहीं मिलता तो फिर अपने कार्ड को रिन्यू कराने नहीं जाते। यह हालत हमारे एम्पलायमेंट एक्सचेंज की है। इसको छोड़िए—बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जिन को एम्पलायमेंट एक्सचेंज के बारे में ज्ञान नहीं है। हमारे बस्तर का क्षेत्र है—वहां जा कर पूछिये, उन को पता ही नहीं

[श्री वाई० पी० शास्त्री]

है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज भी कोई चीज है जहां नौकरी के लिए नाम दर्ज कराना होता हैं।

हमारे देश में बरोजगारी की स्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है। इस का तत्काल निदान न किया गया तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा इस के लिए बहुत दिनों तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। मैं अपनी सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं--हमारे चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदा किया गया है कि हम रोजगार का अधिकार, काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में इस देश के नौजवानों को प्रदान करेंगे--उसके पालन करने का समय अब आ गया है। अब हम यह नहीं कह सकते हैं कि संविधान में यदि काम के अधिकार का फण्डामेंटल राइट्स में जोड़ेंगे तो यह राज्य विधान सभाओं में पास नहीं होगा, क्योंकि फण्डामेंटल राईट्स में यदि कुछ जोड़ना है तो इस तरह का संशोधन केवल लोक सभा में पास करना ही पर्याप्त नही होगा, यह आधे से अधिक विधान सभाओं में भी पास होना चाहिये। आज देश की जनता ने यह अवसर प्रदान कर दिया है कि अब हम इस को विधा नसभाओं में भी पारित करा सकते हैं। इस काम में अब विलम्ब नहीं करना चाहिये। इस देश के करोड़ों नवयुवकों को यह आशा की किरण देनी चाहिये। यह एतिहासिक लाभ होगा और इस काम के लिये आगे आनेवाली पीढ़ियां सदा के लिये जनता सरकार को याद रखेंगी। इसका लाभ केवल आज नहीं होगा, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसको प्राप्त कर सकेंगे और उनके जीवन से निराशा दूर होगी। इस देश का नागरिक यह नहीं समझेगा कि उसकी सन्तान भूखों मरेगी। उनको इतना विश्वास होगा कि जो कोई इस देश में पैदा होगा, उसको 18 वर्ष की उम्र के बाद अपनी आजीविका प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। अगर काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा ताकि वे भूखा न मर सके। वह इन सुविधाओं से वंचित न रहे, इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि हम तुरन्त संविधान में संशोधन करें। हमारे ऊपर जनता ने जिम्मेदारी डाली है। हमें तुरन्त सदन के समक्ष यह संशोधन लाना चाहिए। इस संशोधन को पारित कर हमें अपने वचन को पूरा करना चाहिए।

इसके साथ ही मैं अपनी सरकार से कहना चाहूंगा कि श्रमिक क्षेत्र में हमें समन्वित रूप से एक नीति लाना चाहिए। पिछले दिनों जो सरकार की नीति रही, चाहे वह श्रमिक क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो, उन सभी में यह रही कि अपने पिछलग्गुओं का एक गिरोह तैयार किया जाए जो हमारे विरोध में या कांग्रेस के विरोध में बोलने वाला न हो और जो बोले उसका मुंह दबाने वाला हो। देश के सारे कारखानों में, उत्पादन के केन्द्रों में इस तरह के संगठन खड़े किये गये। जो इस संगठन में लोग थे उनका मजदूरों पर कोई प्रभाव नहीं था। वे मालिकों से मिले रहते थे। जिस मांग के लिए सरकार की तरफ़ से इशारा होता था कि मांग मान लो, उस मांग को मालिक लोग उनके माध्यम से स्वीकार कर लेते थे। जो मजदूरों के बीच में सही काम करने वाले लोग थे, जो उनके लिए लड़ने वाले थे उनको दबाया जाता था। सरकार का संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त था। उन्हीं लोगों के संगठनों, इन्टक को, मान्यता दी जाती थी। इन्टक के लोग चुनाव में हारते थे, मजदूरों का उनको विश्वास प्राप्त नही था। लेकिन इन्टक के लोग ही मजदूरों के भाग्य विधाता थे। मजदूरों के लिए समझौता करने का अधिकार उन्हीं को मिला हुआ था, चाहे उनका कोई प्रभाव मजदूरों में हो या न हो। विवश होकर मजदूर उनके पास जाते थे। लेकिन अब यह चीज नहीं चलने दी जाएगी, इस तरह की गिरोह-

बाजी को, इस तरह की आतंकवादी हरकतों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । सही मायनों में जो संस्थाएं मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हीं को मान्यता मिलनी चाहिए । जो लोग सचमुच मजदूरों में प्रभाव रखते हैं, मजदूरों में काम करते हैं, उन्हीं को मान्यता दी जानी चाहिए ।

आपात्कालीन स्थिति के दौरान एक नाटक रचा गया कि संयुक्त समितियां सब जगह बनाई जाएंगी । शाप फ्लोर और प्लांट स्तर पर मजदूरों की भागीदारी के लिए ये समितियां बनाई जायेंगी । यह कहा गया कि मजदूरों को प्रबन्ध में भागीदारी देने के लिए ये समितियां बनाई जा रही हैं । वे ही लोग इन समितियों में लिये गये जो तानाशाही के पिछलग्गू थे । उनके सामने कारखानों में कोई लेखा-जोखा या हिसाब नहीं रखा जाता था । अब यह बिल्कुल नहीं होना चाहिये । इस तरह की जो समितियां हैं उनमें मजदूरों के सही प्रतिनिधि होने चाहिएं । अब समय आ गया है कि सही मायनों में जो मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते ह वे ही इन समितियों में जाएं । तभी वास्तव में मजदूरों की भागीदारी मानी जाएगी । भागीदारी का अर्थ यह है कि मजदूरों के सही प्रतिनिधि उनमें भागीदार हों । मजदूरों के सही प्रतिनिधियों के लिए आप चुनाव करायें । माननीया अहिल्याबाई जी ने कहा कि मजदूरों के सही प्रतिनिधि तय करने के लिए गुप्त मतदान की प्रणाली से चुनाव हों और आप यह जानें कि कौनसी संस्था सही मायनों में मजदूरों का सही प्रतिनिधित्व करती है। अगर प्रतिनिधित्व देना है तो सही मायने में प्रतिनिधित्व वाली जो यूनियनें हैं उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । सचमुच में मजदूरों का जो विश्वास पात्र संगठन है, जो संस्था है, जिस पर उनका विश्वास है उसके प्रतिनिधि होने चाहियें । संयुक्त समितियां हों, या कोई भी समिति हो उसमें नाटक या आडंबर नहीं रचा जाना चाहिये और मजदूरों का कारखाने में मुनाफे में भी हिस्सा होना चाहिये, तभी वह सही भागीदारी होगी । जो कुछ भी कारखाने में मुनाफा होता है उसमें उसका हिस्सा होना चाहिये । कारखाने का सही हिसाब किताब मजदूरों को मालूम होना चाहिये । जो एकाउण्ट्स हैं उन तक उनकी पहुंच होनी चाहिये । फिर जो कुछ भी मुनाफा हो उसमें उनका हिस्सा होना चाहिये, वही सही भागीदारी होगी । इसके बिना भागीदारी का कोई मतलब नहीं है ।

आज ही सुबह सिक मिल्ज की चर्चा हो रही थी । सिक मिल्ज कैसे बनती है? जान बूझ कर इनको बीमार मिलें बनाया जाता है । सारा मुनाफा खा जाते हैं मालिक लोग, सब कुछ बेच डालते हैं और उसके बाद मुआवजा लेने के लिये सिक मिल उसको बना देते हैं । सिक मिल्ज को चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी जाती है । चाहे सिक मिल्ज हों या दूसरी तरह की हों मजदूरों का शोषण ज्यों का त्यों जारी है । बजाये इसके कि सरकारी अफसर जाकर किसी मिल को चलाएं उस मिल में जो उत्पादन करता है, जिन के ऊपर देश का उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर देश की आवश्यक वस्तुए मुहैया करने की जिम्मेदारी उनके हाथों में उस मिल को दे देना चाहिये । जो पसीना बहाते हैं, उनका स्वामित्व उस मिल पर होना चाहिये । वे ही उसको चलायें । यह आवश्यक है और देश की श्रमिक जनता सरकार से इसी बात की उपेक्षा करती है ।

इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्रालय की मांगों का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): First of all, I would like to congratulate my old friend and colleague, Mr. Ravindra Varma, who is shouldering the responsibility for one of the vital Ministries of government.

[Shri Vayalar Ravi]

I was patiently hearing Mrs. Rangnekar, the Marxist Member. She was taking objection to some points in the 20-Point Programme. I do not know why she is objecting to these points which deal with bonded labour, minimum wages for agricultural workers and workers' participation in management.

I can understand her agony and anger. Her party had occasion to rule twice in two States, viz., West Bengal and Kerala. Unfortunately during its regime, her party had failed to look into any of the points—neither the bonded labour problem, nor the question of minimum wages for agricultural workers. My State, Kerala, can take credit for introducing minimum wages for agricultural workers for the first time in this country. Naturally, the Marxist Party will be angry, because we introduced these reforms and it was not done by any one of the governments run by her party.

In regard to workers' participation in management, Mr. Jyoti Bosu's government in West Bengal did not give any right of participation to workers in management in their own State government industries. Under the 20-point programme, 99,000 persons i.e., bonded labourers were set free. Unfortunately, the lady Member has objected to this. I am sorry about her remarks I wish she apcreciates these points. I can understand the anger of her party-men in regard to the Emergency; But she should not get angry with the economic programme.

16.28 hrs.

[MISS ABHA MAITI *in the chair*]

Now about the role of the workers in the country to-day. (*Interruptions*). The Janata party is in the government. The Janata party Members should place before the country what the facts are. The question is whether the governments in Kerala and West Bengal when they were run by Namboodiripad and Jyoti Bosu respectively, made any study, with any sincerity, to ascertain whether there was bonded labour in their States. Have they done anything? They have done nothing. My only request to them is to please rule West Bengal properly as they got another chance.

The workers in this country are the most-blackmailed. They are more responsible than others in this country. The working class in this country behaved in a responsible way during the emergency. They played an important role in the economic life of the country. Yet, unfortunately, they are blackmailed by the monopoly press and the employers. If we look at the whole class—I am not defending everything that has happened even in 1976—the workers have not resorted to strike, in spite of the fact that there are elements in the trade unions who used to say that they would rather see the nations starve to die and not allow the steel mills to function. The workers have played an very important role. But, I am sorry to say that the industrialists and employers behaved in a very irresponsible way and even he previous Government could not control them.

According to this Report the mandays lost is 21.9 million. The mandays lost due to lock-out ranged from 54 per cent to 90 per cent. During the last one year of emergency the employers made it a point to create hardship for the workers. Even though the workers behaved very well and in a responsible way, the employers and the monopolists always blackmailed them through the mass media.

To take one example there is one Mr. Dalmia who has two factories in Kerala. Something happened to the works and they protested to the management. The entire press, including the *Indian Express*, came out with four-column headlines that an industrialist was man-handled. What was the result? He closed down the paper

mill and another factory. He declared lock-out and went away. There is no law in the country either to prosecute him or to make him open the factory. Yet, the entire newspapers supported this industrialist. They are not looking at the plight of the poor workers who are starving today. Even though the schools are opened, the workers could not send their children to schools because they have no money to pay the school fee. When this is the condition of the workers, the newspapers are supporting the industrialists. So, I would say that the Minister should have a fresh look at the Industrial Disputes Act, which needs comprehensive change.

There is a provision in that Act for domestic enquiry, which means the workers lose their job. The employers appoint their own lawyers, have an enquiry and then dismiss the workers. Another locuna in the Act is that is not mandatory for the employers to go in for conciliation. I would say that conciliation must be made mandatory.

In 1976 we amended the Industrial Disputes Act to the effect that if there are more than 300 workers in a factory, the management cannot resort to lockout or lay off without the permission of the Government. At the same time it was provided that if they give 90 days' notice, it can be done. So, there is no meaning for this provision. Government have to come forward with a law which will prevent the employers from resorting to lockout or lay off, retrenchment or other hardship to the workers.

Another bad feature is police intervention in strikes. Shri Jyoti Bosu said that he will use the police against the workers.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Did he say so?

SHRI VAYALAR RAVI: Yes, he said it. He said that illegal strike would be prevented and there will be police intervention against it. The police will come into the picture on the pretext of law and order. There is a past history behind every labour agitation. The police cannot simply say that it is a law and order problem and intervene. There should be some report before them to that effect. I am saying this because Shri Charan Singh wants to enforce discipline. Take, for instance, the strike in Modern Bakeries, Ernakulam. I am also President of one of the unions. The police intervened. I asked why. They said they had instructions from Delhi that the public sector must be protected. Instead of being an exemplary employer, the public sector, unfortunately, has become a privileged employer today, and the Labour Minister is helpless because he has no power to refer to adjudication any dispute in a public sector undertaking. He has to wait for the permission of the Under Secretary from the Ministry concerned who can veto it. What I am saying is past history. Definitely I share part of the responsibility, I am not escaping, but I am only appealing to the hon. Minister to reconsider it. This privilege given to the public sector enterprises is a very important point. You have to assert your rights. You should not wait for the Under Secretary of the concerned Ministry to give permission. You should guide the public sector management to be an example to all, including Jyoti Bosu's Government.

The Prime Minister said that they are not going to reduce the strength of Government servants by 10 per cent, but only they are not going to fill up the vacancies up to 10 per cent. It means practically they are reducing the strength by 10 per cent. What is the philosophy behind it? It is the same as that of the Congress Government.

The CDS was introduced by the Congress Government because of eco-

[Shri Vayalar Ravi]

nomic and financial constraints, to cut the money supply in the organised sector. Now, the Finance Minister, Shri H. M. Patel, has said the same thing and the scheme is being extended. Practically it has been made permanent. Why? Because they do not want the money to go to the workers. Under the law the scheme continues only up to June and in July they have to return one-fifth of the deposits with interest, but Government say thay are not paying. The reason is the same philosophy of financiall constraint, moncy supply having to be cut. So, what difference does it make between the Congress and the Janata Governments when there is a 10 per cent reduction in the staff, the CDS money is not returned and there is no bonus?

I am not blaming them about bonus. I know he will say that it was our law, but I will remind him that he is sitting there because he has made a promise that the Bonus Act will be amended. He has assured the workers that he will repeal it. Both of us come from the same State. He knows that in Kerala bonus has been customary from the time of Sir, C. P. Ramaswamy Aiyar's regime. I am proud that the Coalition Government of Kerala during the emergency forced every management to pay a minimum bonus of 4 per cent during Onam, but today the Kerala Government seems to be helpless, they cannot compel the industries to give bonus. So, we are going to face serious agitations in industries, including the public sector. So, I appeal to the hon. Minister to introduce a Bill to repeal the Bonus Act and see that bonus of 8 1/3 per cent is given to all workers.

Regarding workers' participation in management, I know he is very eager to introduce it and may expedite it.

The ESI scheme now covers 5.2 million workers, but now it applies only to factories employing more than 20 employees. Statictics show that the total number of workers is 19.6 million. Out of 19.6 million workers, you are covering only 5 million. A majority of the workers who are in the establishments which employ less than 20 workers, are not covered under this shceme. I know for a fact that the organised workers do not want this scheme at all, because they can get better medical facilities through the agreements with the employers. If the workers do not want it, please do not impose this scheme on them. If they can get better medical facilities through agreements, let them have it. I know, the ITI workers, Palghat represented to the Government that they should be given exemption from this ESI scheme. Moreover, the hospital facilities are not good. I know a hospital where cattles are in Ernakulam. Then ESI gives Rs. 100/- for funeral. ESI is not for funeral or killing people but to keep them medically fit. Many of the Unions which I represent, have requested the Minister to exempt them from this scheme. I request the Minister to extend this scheme to those establishments which employ less than 20 persons because. there, the workers do not get any medical facility from the employers and do not impose the scheme on those organised workers who do not want it.

About EPF scheme, I know the employees are very responsible and they are trying to clear the arrears of accounts. During the last two or three years, the EPF arrears have come down from Rs. 20 crores to Rs. 18 crores. Still, it is a huge amount. The Government has also launched prosecutions. But I feel the Government is not providing enough staff to the PF Commissioner and Regional offices. On the floor of this House, on many a occasion, I demanded that the Provident Fund Office should be made an autonomous body. If you

make it an autonomous body, they will get more powers and more authority. Now the EPF officers go up and down for getting a small thing done from the Ministry. So, I would appeal to the Minister to consider converting this into an autonomous body and give them more powers and staff.

There are 11 million unemployed youth in this country, but you have no provision to give them employment. May I request you to start an unemployed insurance scheme for these youth? There is lot of corruption in the employment exchanges and I would request the Minister to take some effective steps to eradicate corruption in the employment exchanges.

There is heavy indebtedness among the industrial workers. The moneylenders are exploiting these persons. There has been some attempt by the previous Government to eradicate rural indebtedness. I would request the Minister to take some steps to eradicate indebtedness among industrial workers.

The Port employees have threatened to go on strike. I appeal to the hon. Minister to see that this strike is averted so that our economy does not suffer in any way.

In conclusion, I have only one request to make to the hon. Minister. He has given great hopes to the workers that their grievances will be looked into and their lot will be improved. But the workers are always exploited by the ruling class. I have no doubt that the exploitation may continue because the ruling class is always on the winning side. They will try to exploit the workers. The entire machinery, the entire mass media, is controlled by the ruling class. That does not mean that you alone are a part of the ruling class. They are omnipotent and omnipresent. They always try to exploit the workers. An hon. Member on the other side was talking about the INTUC affairs because of his ignorance of the working of the INTUC. I say with great pride that I am a worker of the INTUC in my State and I can say that it stands for the cause of workers. It champions the cause of the workers. But we are being blamed by the Chairman of the Janata Party in Kerala who said in Kerala that the INTUC workers and the leaders are exploiting the workers creating agitations to tarnish the image of the Janata Government. He issued a statement last week. The strike is going on in some factories with unity of all trade Unions including CITU. We are being blamed that the strike is being organised to black-mail the Janata Party. I can assure you that we have no intention to make the labour as a political war weapon to fight with as many members of the Janata Party may think. We will see that the INTUC and the Congress Party will do their best to safeguard the interests of the workers.

With these words, I can assure the hon. Minister that we will support him when he brings forward a legislation for the betterment of the workers. Once again, I congratulate him.

प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना (महाराजगंज): सभापति महोदया, मैं श्रम मंत्री जी को उन के साढ़े तीन महीने के कार्यकाल पर बधाई देता हूं। मुझे मजदूर यूनियनों में काम करते हुए 58 साल हो गए। सन् 1920 में स्वर्गीय श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नेतृत्व में मैं ने यह काम शुरू किया था। उस समय वहां कानपुर में मजदूर सभा कायम हुई थी जिस के वे सेक्रेटरी थे और मैं उस का असिस्टेंट सेक्रेटरी था। मैं ने सभी मजदूरों में चाहे वे कपड़ा मिलों के मजदूर हों चाहे चीनी के कारखानों के मजदूर हों या बन्दरगाहों के मजदूर हों, सभी में काम किया है और अपने इस लम्बे अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यह साढ़े तीन महीने का जो कार्यकाल उन का गुजरा है वह बहुत ही

[प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना]

शानदार गुजरा है । अभी हाल ही में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का जो डिस्प्यूट सैटिल किया है उस के लिए मैं उन को बधाई देता हूँ । यह इंडियन एक्सप्रेस अखबार गोयनका जी का है । पिछली सरकार के लिए गोयनका रेड रैग टु दि बुल के समान थे । उन को खत्म करने के लिए पिछली सरकार ने क्या नहीं किया। उन के अखबारों पर जुल्म किया, उन की प्राइवेट प्रापर्टी पर जुल्म किया, उन की कलकत्ते की जूट मिल को कान्फिस्केट किया और हर तरह से उन को बरबाद करने की कोशिश की । वे शायद उन को मार ही डालना चाहते थे । इसलिए इंडियन एक्सप्रेस में जब हड़ताल हुई तो उन के जो पहले के दुश्मन थे वे बड़े खुश हुए कि चलो, अच्छा हुआ हड़ताल हो गई । लेकिन जिस शान के साथ श्रम मंत्री जी ने इस डिस्प्यूट को सैटिल किया और जिस तरह से गोयनका जी ने उन की बातों को माना उससे हम बहुत प्रसन्न हैं । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह काम उन्होंने इतनी खूबी से किया ।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान अपने उस तार की ओर दिलाना चाहता हूं जो मैं ने उन्हें लेबर डपो, गोरखपुर के सम्बन्ध में भेजा था । गोरखपुर में एक लेबर डिपो सन् 1940 की वार में शुरू हुआ था और सन् 1973 तक वह बहुत जोर से चला । पिछले 34 सालों में हर साल इस लेबर डिपो से लगभग 30 हजार मजदूर सबसे कठिन काम करने के लिए कोयला खदानों में और दूसरी जगहों पर जाते रहे । जिस काम को दूसरे मजदूर नहीं कर सकते थे । वह काम ये मजदूर करते थे । वहां पर तरीका यह था कि एक साल के लिए मजदूर खदान में काम करने के लिये जाते थे और साल भर के बाद घर लौट आते थे और फिर एक दो साल घर पर रहने के बाद फिर जाते थे । इस तरह से उनकी तंदुरस्ती खराब नही होती थी । रिकार्ड्स यह बताते हैं कि जितना कोयला वे मजदूर निकालते थे वह दूसरे मजदूरों की तुलना में दूना होता था । यह सिस्टम बहुत ही अच्छा था लेकिन 1973 में जब कोल माइन्स नेशनलाइज़ कर ली गई तो श्री कुमारमंगलम चोकि उसके अगुवा थे उनसे मैंने कहा कि इस चीज को आप चलने दीजिए, यह बहुत फायदेमन्द है और एक साल का एग्रीमेन्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें उनकी तंदुरुस्ती खराब नहीं होती हैं लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है कि कोल माइन्स के मजदूरों को परमानेंट किया जाय । लेकिन उन्होंने फिर वादा किया था कि इस लेबर डिपो को कायम रखेंगे और कोल माइन्स को इस डिपो से लेबर जाते रहेंगे लेकिन दुर्भाग्य की बात हैं कि वह डिपो तो कायम है लेकिन कोल माइन्स को वहां से लेबर की सप्लाई बन्द है । यह कोल माइन्स के मालिकों और सरकार की लापरवाही है । कोल माइन्स में मरने व रिटायर होने से वैकैन्सीज़ होती रहती हैं अगर उन जगहों पर ही इस लेबर डिपो के मजदूरों की भर्ती की जाये तो काफी लेबर इस डिपो से हर साल कोयला खदानों में रखे जा सकते हैं । पिछले तीस सालों में गोरखपुर लेबर डिपो से साढ़े दस लाख मजदूर कोयला खदानों में गए हैं । गोरखपुर, देवरिया और बस्ती का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 10–12 फेमिलीज का एक न एक आदमी खदानों में न गया हो ।

लेबर वेलफेयर फंड में मजदूरों का जो अनक्लेम्ड पैसा बच जाता था वह जमा होता था । उससे हमने पूर्वी यू० पी० के जिलों में 6 बड़े हेल्थ सेन्टर्स कायम किए हैं । एक दिन में एक सेंटर में एक हजार मजदूर डाक्टर को दिखा कर दवा लेने आते हैं जिनको सात दिन की दवाई बांटी जाती है । जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको गोरखपूर के सिविल अस्पताल में हमारे दो वार्डों में भेज देता हैं जहां हमारा

डाक्टर उनकी दवा करता है। इधर दो तीन साल से लेबर सप्लाई बन्द हो जाने से काम कुछ हलका हो गया है और हमारे उन दोनों वार्डों को यू० पी० सरकार को देने की बात चल रही है। ये दोनों वार्ड लगभग पांच लाख रुपये में बने थे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और उनको रखना चाहिए ताकि वहां पर डाक्टर संगीन बीमारों की देख भाल कर सकें। मैं आशा करता हूं कि इनको कायम रखा जायेगा और यू० पी० सरकार को उन्हें नहीं दिया जायेगा। हमारे पास लेबर वेलफेयर फंड में दस लाख रुपए थे, पांच लाख हम खर्च कर चुके हैं और पांच लाख बाकी है, मैं चाहूंगा कि भारत सरकार की जो कोल माइनस वेलफेयर फंड है उस फंड से हमारे खर्चे को आधा खर्चा मीट किया जाये और आधा हम लगाये। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस फंड से सरकार आधा खर्चा मीट करे ताकि इस काम को सदैव के लिये कंटीन्यू रखा जा सके और कोल माइन और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाया जा सके।

मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब हमारे गोरखपुर लेबर डीपो पर एक बार पधारें और देखें कि हमने क्या काम किया है और क्या कर रहे हैं, उसको देख कर आपको खुशी होगी।

आपने रेलवे स्ट्राइक में जितने मजदूर निकाले थे, उनको बहाल करके काम पर ले लिया। लेकिन ऐसे ही कुछ दूसरे कारखाने हैं जहां हड़ताल करने पर मास डिस्मिसल हुआ था। जैसे महावीर जूट मिल्स, सहजनवां है, जहां एक हजार मजदूर निकाल दिये गये थे, वहां पर लाक आउट कर दिया गया था। जब मामला एडजूडिकेशन के लिये भेजा गया तो कांग्रेस सरकार ने उसको तथ्यहीन कह कर डिपोजिट कर दिया। मैं चाहता हूं कि ऐसे जितने डिस्मिसल्स हुए हैं, उन मजदूरों को फिर से बहाल किया जाय। और आइन्दा से हर लेबर डिस्प्यूट का ऐडजूडिकेशन कम्पलसरी कर दिया जाय। ऐसा ही मामला देवबन्द शूगर मिल का है, वहां 300 मजदूरों को निकाला गया था, वहां मजदूरों को मारा गया, उनकी हड्डियां तोड़ दी गईं, उन पर गोली चली। मिल मालिक का चूंकि सरकार पर दबाव था, उसने मजदूरों को बरबाद करने में कुछ उठा नहीं रखा। उनके नेता ठाकुर मुकुन्द सिंह को जो मजदूरों के क्रान्तिकारी लीडर थे, उनको पकड़ लिया गया। मैं चाहूंगा कि जितने लोग देवबन्द, वाल्टरगंज, नवाबगंज, हरदोई, सहजनवां, मसूरपुर और पिपराइच की शूगर और जूट मिलों से निकाले गये हैं उनको बहाल किया जाय। एडजूडिकेशन में सालों लग जाते हैं, फिर भी कोई न्याय नहीं हो पाता है। आप इस पर गौर करें और तुरन्त कार्यवाही करें। आपकी कार्यवाही एक शानदार कदम होगी और मजदूरों को सन्तोष होगा कि आपने उनको न्याय दिलाया है।

कुछ शब्द मैं शुगर इण्डस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं—1930 में मैंने एक यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन बनाई थी, मैं उसका प्रजिडेन्ट तब से लगातार रहा हूं और उसमें आल इण्डिया की शुगर मिलों की यूनियनें हैं। बाद में उसका नाम आल इण्डिया शुगर वर्कर्स फड्रेशन पड़ा। 15-3-1950 को सारी चीनी मिलों के 82 हजार मजदूरों की मतगणना हुई थी जिसमें हमारी फेडरेशन को 79 परसेंट वोट मिले और आई०एन०टी०यू०सी की राइवल फेडरेशन को 21 परसेन्ट वोट मिले थे। उस जमाने में एक मजदूर का न्यूनतम वेतन 5 रुपये मासिक था। हमने लड़ लड़ कर उनका न्यूनतम वेतन 300 रुपये कराया लेकिन आज क्या हालत है—आप जरा उसको देखिये—

[श्री० शिवन लाल सक्सेना]

कोयला खदानों में 430 रुपये मिनिमम वेज है, लोहा, सीमेंट और टेक्सटाइल इत्यादि उद्योगों में भी लगभग इतना ही चार सौ रुपये न्यूनतम वेतन है, लेकिन शूगर फैक्ट्रीज में अब न्यूनतम वेतन 260 रुपये है, यह कितने शर्म की बात है । शूगर फैक्ट्रीज साल में पांच महीने चलती हैं । 260 रुपये में पांच महीने काम करके 12 महीने तक एक मजदूर कैसे निर्वाह कर सकता है ? शूगर इण्डस्ट्री एक फारन-एक्सचेंज अर्निंग इण्डस्ट्री है, देश के लिये यह बहुत आवश्यक वस्तु पैदा करती है—मैं चाहता हू कि इस इण्डस्ट्री के मजदूरों के साथ भी न्याय किया जाय और उनकी मिनिमम वेज को भी बढ़ा कर चार सौ रुपये मासिक किया जाय ।

पिछली रेलवे स्ट्राइक में फर्नान्डीज जी ने एक मांग रखी थी कि तमाम रेलवे कर्मचारियों को वही तनख्वाह मिले जो कोल इण्डस्ट्री या दूसरी इण्डस्ट्री में दी जाती है । एक यनिफार्म वेज सबका होना चाहिये, लेकिन सरकार ने उस मांग को तब नहीं माना । अब मैं चाहूगा कि इस सम्बन्ध में एक नेशनल वेज पालिसी बनाई जाय, जिसमें सब इण्डस्ट्रीज का वेज एक सा हो और सब इण्डस्ट्रीज का सन्तुलित विकास हो, जो जितना काम करे, जितना स्किल्ड हो, उस के हिसाब से उसको तनख्वाह मिले । यह आवश्यक है, और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको करेंगे ।

17.00 hrs.

धनबाद में डायरेक्टर जनरल आफ सेफ्टी इन माइन्स की पोस्ट तीन साल से खाली पड़ी है, वह अभी तक भरी नहीं गई है । इसको फौरन भरा जाना चाहिए जिससे मजदूरों की सेफ्टी को जो खतरा रहता है वह दूर हो ।

शूगर इण्डस्ट्री में मजदूरों को सात महीने की बन्दी के दिनों में कुछ नहीं मिलता है, वे खाली रहते हैं । मजदूरों की यह पुरानी डिमाण्डड रही है कि उन्हें आफ सीजन में 50 परसेंट वेज मिलना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि मजदूरों की इस डिमाण्ड को पूरा किया जाएगा और उनको आफ सीजन में 50 परसेंट वेज दिया जाएगा ।

इसी तरह से बोनस की मांग के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बोनस जो कम किया गया है । उसे फौरन बढ़ा कर 8⅓ प्रतिशत किया जाय । यह एमर्जेन्सी के दौरान कम किया गया है । इसे फौरन बहाल किया जाना चाहिए ।

सी०डी०एस० फण्ड्स में मजदूरों का जो जमा है वह भी मजदूरों को वापस मिलना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और मजदूरों को उनका जमा लौटा देंगे ।

शूगर इंडस्ट्री के नेशनलाइजेशन की मांग बहुत दिनों से हो रही है । लेकिन अभी तक इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ । पिछले 10 सालों में शूगर मिल-मालिकों ने अपनी मिलों से बहुत कुछ कीमती सामान निकाल कर बेच दिया । मिलों की रिपेअर करनी बहुत मामूली कर दी । इसलिए मैं चाहूंगा कि इन शूगर मिलों का नेशनलाइजेशन फौरन किया जाए और बिना मुआवजे के किया जाए । हमें नई चीनी की फैक्टरियां लगाने के बजाय वर्तमान चीनी मिलों की हर यूनिटों को कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए । एक यूनिट जो 800 टन का होता है अगर उसको दो हजार टन का कर दिया जाए तो इससे ओवर हैड खर्च बहुत कम होगा और फैक्ट्री का मुनाफा भी बहुत बढ़ जाएगा । इसलिए मैं चाहता हूं शूगर फैक्ट्रीज का नेशनलाइजेशन अविलम्ब किया जाय और उनकी कपेसिटी कम से कम दो हजार टन की जाय । यह काम फौरन होना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं लेबर मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स को रपोर्ट करता हूँ ।

श्री अहसान जाफरी (अहमदाबाद) : सबसे पहले मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे श्रम मंत्री जी एक नौजवान आदमी हैं और उन्होंने जो भी कुछ किया है उससे देश के मजदूरों को आशा बंधती है कि उनकी पालिसियों की वजह से मजदूरों को काफी फायदा होगा ।

हमेशा इस मुल्क के अन्दर उत्पादन बढ़ाने के लिए बातें कही जाती हैं । मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि आज भी मजदूरों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ बरताव अच्छा नहीं हो रहा है । जो देश के लिए धन दौलत पैदा करते हैं, जो देश का एक अहम हिस्सा हैं, उनकी हालत आज भी हम देखते हैं कि देश में बहुत ही गिरी हुई है । हम चाहते हैं कि मजदूर हमारे उत्पादन को बढ़ाएं लेकिन जिस तरह की दर्दनाक उनकी हालत है, जिन बाधाओं के अन्दर रह कर उनको काम करना पड़ता है, देहातों में और शहरों में उन में वे देश के उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते हैं । आपने शहरों में उनको भीख मांगते हुए देखा होगा । गांवो में भी मजदूरों को आपने उन लोगों के दरवाजों पर जाकर भीख मांगते हुए देखा होगा जिन्होंने कभी अपने हाथ से हल नहीं चलाया । मजदूर खेत में दिन रात मजदूरी और मेहनत करता रहा है । जब कभी कहत पड़ जाता है तो उसके बाल बच्चे, उसकी बीवी उन लोगों के दरवाजे पर भिखारियों की तरह पहुंच जाते हैं जिन्होंने कभी हल नहीं पकड़ा, कभी खेत की सूरत नहीं देखी । वे वहां जा कर अनाज की भीख मांगते हैं ।

यही हाल मयमारों का है । वे खुद तो झुग्गी झोंपडियों में रहते हैं, उन में अपनी जिन्दगी बिताते हैं लेकिन दूसरों के लिए वे महल खड़े कर देते हैं । जो दूसरों के लिए जूते बनाते हैं उनके बच्चे जूतों से महरूम रहते हैं । जो दूसरों के लिए मजदूर कपड़ा बनाते हैं उन के बच्चों को तथा उनको कपड़ा पहनने को नसीब नहीं होता है । ऐसी हालत में उन से कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे देश को ज्यादा पैदावार कर के दें । यह बात नहीं है । उनकी हालत को आपको सुधारने चाहिये ।

हमने देखा है कि हमारे यहां हमेशा आर्गीनाइज्ड सैक्टर की तरफ ही ध्यान दिया गया है । इस सैक्टर के मजदूरों ने हमेशा अपनी मांगें मनवा ली हैं । बाकी जो करोड़ों की तादाद में इंसान हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है । नैशनल मिनिमम वेज के बारे में हमने आज तक कोई अपनी पालिसी अखत्यार नहीं की है । ऐसा हमने किया होता तो मजदूर समझ सकते थे और कह सकते थे कि सरकार भी उनकी भलाई के काम कर रही है और तब वे मेहनत भी ज्यादा कर सकते थे । देश की सरकार पूरी तरह से जागृत है और उनके हितों की हिफाजत कर रही है ऐसा नहीं कहा जा सकता है । रेलें आदि जो आर्गेनाइज्ड सैक्टर है या बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज हैं, मिलें हैं वहां पर तो मजदूरों को कुछ तनख्वाह मिल भी जाती है लेकिन जो छोटी छोटी फक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, जो अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए मिनिमम वेज तय नहीं की गई है । ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा एक्सप्लायटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा शोषन उनका हो रहा है । उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये । तमाम जितने मेहनतकश लोग हैं चाहे वे कहीं भी काम करते हों उनके लिए एक नेशनल मिनिमम वेज आपको तय कर देनी चाहिये और वह वेज उनको मिले इसकी व्यवस्था आप को कर देनी चाहिये ।

रिपोर्ट में खेत मजदूरों की बात कही गई है । खेत मजदूरों को क्या मजदूरी मिले

[श्री अहसान जाफरी]

यह तो आप ने तय कर दिया है । लेकिन अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज भी पूरे हिन्दुस्तान में खेत मजदूरों के साथ जुल्म हो रहे हैं । जहां पर मिनिमम वेज उनके लिए तय कर दी गई है उसको मांगने के लिए जब वह जाता है तो उसको निकाल बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह पर बाहर से आदमी को ले आया जाता है और उस से काम करवा लिया जाता हैं । इसकी जानकारी श्रम मंत्री को अगर है तो वह इस सिलसिले में क्या करना चाहते हैं यह मैं उन से जानना चाहता हूं । वे लोग इन मजदूरों की मजदूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं । ऐसे जमींदारों के खिलाफ वह क्या कार्रवाई करेंगे, इसका वह हमें बताएं ।

उन करोड़ों मजदूरों के लिए जो खेत मजदूर कहलाते हैं और जिन को हिन्दुस्तान के मिनिमम वेज नहीं मिलती है उसके लिए वह क्या करने जा रहे हैं यह भी वह बताएं ।

रिपोर्ट में एक अजीब बात कही गई है जो मेरी समझ में नहीं आई । इस पर मंत्री महोदय रोशनी डालें । पेज 20 पर आपने बांडिड लेबर का जिक्र किया है । आपने कहा है कि हिन्दुस्तान के 19 राज्यों में से दस राज्यों में है । आपने आंध्रे प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मिजोरम का नाम लिया है । उसके बाद आप यह कहते हैं:

"Remaining States and Union Territories have reported non-existence of bonded labour system."

इस सदन के तमाम माननीय सदस्य यह जानते हैं कि भारत के और हिस्सों में भी जहां जमींदार हैं वहां पर बांडिड लेबर पाई जाती है । इसके अन्दर उन राज्यों का नाम नहीं लिया गया है । किस बुनियाद के ऊपर आप कहते हैं कि दस राज्यों के अलावा बाकी राज्यों में हिन्दुस्तान में बांडिड लेबर मौजूद नहीं है ।

मैं गुजरात की बात बताता हूं । वहां मेहषाणा और बनासकांठा में आज भी साथी नाम से जाने जाने वाले बंधुआ मजदूर हैं । आप गुजरात में सूरत, जहां से हमारे प्रधान मंत्री आते है, साबरकांठा, बनासकांठा में जाइये वहां की हाली प्रथा आज भी जारी है । आज भी खेत मजदूर गुलाम की हालत में रहते हैं । उन्होंने किसी जमाने में 200, 400 रु० ज़मींदार से लिये हुए हैं, मेरे पास ऐसे लोगों के नाम मौजूद हैं जहां पर उन मजदूरों ने कहा है कि किसी जमाने में हमने शादी विवाह के लिये रुपया लिया, उसको 15, 20 साल गुजर गये हैं लेकिन आज तक उसके एवज में हमें डेढ़, दो रु० रोज़ की मजदूरी करनी पड़ती है, उसके बच्चों को गाय भेड़ चरानी पड़ती है और उसकी बीवी को ज़मींदार के घर में काम करना पड़ता है । यह प्रथा आज सूरत के अन्दर मौजूद है जहां से प्रधान मंत्री जी आते हैं । लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि बौंडेड लेबर खत्म हो गया है ।

इसी तरह से रिपोर्ट में ई० एस० आई० स्कीम की बात कही गई है कि कितने अच्छे ढंग से यह मजदूरों की सेवा कर रही है । मैं आपका ध्यान गुजरात की तरफ़ दिलाना चाहता हूं । गुजरात में ई० एस० आई० में मजदूर जो पैसा देते हैं वह 11 लाख के करीब है, जब कि खर्चा 7 लाख के करीब होता है । इसके बावजूद सुरेन्द्रनगर, भड़ोच अहमदाबाद शहर से लगा हुआ एक इलाका है जहां सैंकड़ों मजदूर काम करते हैं लेकिन वहां आज भी ई० एस० आई० स्कीम लागू नहीं की गई है । गुजरात में 14 केन्द्रों में से 9 केन्द्रों पर सिर्फ मजदूर और उसके खानदान का इलाज किया जाता है और बाकी के जो

केन्द्र हैं, जैसे भावनगर, बड़ौदा, सूरत, क्लोल और राजकोट में मजदूर का ही इलाज होता है, उसकी फ़ेमिली का इलाज नहीं होता है । गुजरात में 4 लाख 90 हजार मजदूर ई० एस० आई० स्कीम से फायदा उठाते हैं । कुल गुजरात में 11 एम्बुलैंस गाड़ियां हैं ई० एस० आई० के पास । बड़ोदा, भावनगर, सूरत, अहमदाबाद को 11 एम्बुलैंस दे दी गई हैं, बाकी के इलाकों में कोई एम्बुलैंस न होने से मजदूरों को काफ़ी तकलीफ़ होती है ।

इसी तरह से जो लेबर कोर्टस हैं उनमें जो काम होता है वह भी काबिले तारीफ़ नहीं है । इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कितने दिनों में किस तरह से लेबर डिसप्यूट के फ़ैसले आते हैं । रिपोर्ट के पेज 31 पर आपने धनबाद में बताया है कि एक फैसले के आने में कम से कम 3, 4 साल लगते हैं । मजदूर के एक झगड़े का फैसला 4 साल में होता है । जब मजदूर को कारखाने से निकाल दिया जाता है और उसको खाने के लाले पड़ जाते हैं ऐसी हालत में अगर 3, 4 साल के अन्दर मजदूर के झगड़े का फ़ैसला होता हो तो उसकी क्या हालत होती होगी इसका अंदाज आसानी से लगाया जा सकता है । इस हालत को बदलने के लिये हमें लेबर पोलिसी के अन्दर और जिस ढंग से लेबर कोर्टस चलते हैं उनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा । अगर ऐसा नहीं किया तो मजदूर की हालत खराब होगी और एक नये रास्ते पर वह चल पड़ेगा जिससे औद्योगिक शांति खत्म हो जायेगी । इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मिल मालिक जब चाहता है, मजदूर को काम से निकाल देता है । इसके बाद मजदूर बेआसरा हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसके कुटुम्ब के सहारे के लिये उसके पास कोई चीज नहीं रहती हैं । ऐसे निकाले हुए मजदूरों में कम से कम 50 फीसदी ऐसे होते हैं जो कोर्ट का सहारा नहीं लेते, चुपचाप किसी और धन्धे को ढूंढ लेते हैं । बाकी के 25 प्रतिशत मजदूर ही ऐसे होते हैं जो अपने मामले को लड़ते रहते हैं और शेष 25 प्रतिशत इस बात को छोड़ देते हैं और अपने किसी ऐसे काम में लग जाते हैं । मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि लेबर लाज में इस बात की आवश्यकता है कि ऐसा प्रावधान उसमें होना चाहिये कि कोई भी मिल मालिक, चाहे वह पब्लिक सैक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, अगर किसी मजदूर को निकालता है तो जब तक कोर्ट से उसका फैसला न हो जाये उसे मिल से बराबर वेतन मिलता रहे और वेतन लेने के साथ साथ वह कोर्ट में अपनी लड़ाई जारी रखे । अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह जंगल के कानून के अलावा और कुछ नहीं । अब मिल मालिक मजदूरों को निकाल देता है और 3, 4 बरस तक वह केस लड़ता रहता है । अगर वह हार जाता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती और अगर जीत भी जाता है तो उसके 3,4 सुनहरे बरस बेकार चले जाते हैं । उसका पुराने, हाल कोई नहीं होगा । इस गवर्नमेंट के जमाने में अब ऐसी बात नहीं, होगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं ।

हम मजदूरों से हमेशा कहते आये हैं कि वह ज्यादा एफीशियेंसी से काम करें, लेकिन उसको क्या-क्या सुविधायें चाहिये, यह कभी नहीं देखा । हिन्दुस्तान के शहरों में जहां बड़े-बड़े कारखाने बने हुए हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई है, वह इमारतें जितनी ऊंची होती गई हैं, उतनी ही गन्दी बस्तियां बसती चली गई हैं । वह ऐसे स्थान हैं जहां इनसान क्या जानवर भी नहीं रह सकते हैं । हमारे अहमदाबाद में ऐसी बस्तियां मिलेंगी, जो जहन्नुम से भी बदत्तर हैं । अगर भगवान भी जमीन पर आकर देखे तो वह भी शर्मिन्दा

[श्री अहसान जाफरी]

हो कि मैंने जो नर्क बनाया है वह भी इससे ज्यादा अच्छा नहीं है । वहां पर आदमी के मर जाने के बाद उन गंदी बस्तियों में मजदूरों को विचार करना पड़ता है कि किसी लाश को झोपड़ी से बाहर कैसे ले जाया जाये । अहमदाबाद में 18 लाख की आबादी में से 5 लाख इनसान आज गन्दी बस्ती में बसते हैं । न उनके लिये पाखाने की व्यवस्था है, न नल की न गटर की । यहां बरसात में पानी भर जाता है । रात भर मजदूर बैठे रहते हैं । सवेरे 7 बजे मिल की सीटी बजती है और उसे फिर काम पर जाना पड़ता है । ऐसी हालत में आप उससे आशा करते कि वह ज्यादा काम करेगा, ज्यादा पैदावार करेगा ?

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वह इन जहन्नुमों को दूर करने के लिये कोई योजना रखें । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक जगह पर कोई योजना बताई है और उसमें कहने की कोशिश की है कि हमने इतने मकान बनाये हैं । हिन्दुस्तान में जहां 4 करोड़ बेकार रहते हैं, गलियों में फिरते हैं, वहां आपकी योजना में 1-1-76 से 31-12-76 तक आपने 66 हजार मकान बनाये और 13 हजार और बनाने वाले हैं । यदि इसी रफ्तार से चलते रहे तो क्या हम हिन्दुस्तान के इन शहरों में गंदी बस्तियों में रहने वालों को, जो जहन्नुम में सड़ते हुए मजदूर हैं, उनको कोई काम दे सकते हैं, उनको रोजगारी दे सकते हैं उन्हें रहने के लिये मकान दे सकते हैं ।

हमने देहात के खेती मजदूरों के लिये योजना बनाई । सूरत में आज भी वहां के खेती मजदूर कलैक्टर के आफिस के सामने बैठे हुए हैं कि मई महीने में वहां की पंचायत ने जो मकान दिये थे वे तोड़ दिये गये हैं । ये मकान पंचायत के अफसरान के सामने बनाये गये थे । वे मकान मई में तोड़ डाले गये हैं । अगर इन झोंपड़ियों में रहने वालों को अच्छे मकान नहीं दे सकते हैं, अगर वे अपने मकान में रहते हैं तो भी वह तोड़ दिये जाते हैं तो ये लोग गन्दे मकान में रह कर कैसे हिन्दुस्तान की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं । मजदूर को इस तरह से झोंपड़ी में रहना भी नसीब नहीं होता है । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार कोई ऐसा इन्तजाम करेगी कि हिन्दुस्तान में मजदूरों के साथ आइन्दा इस तरह की हरकतें न हो सकें ।

मैं मन्त्री महोदय से विनती करना चाहता हूं कि मजदूरों को राइट टु वर्क, काम करने का हक, दिया जाये । आज हिन्दुस्तान की अलग अलग रियासतों में अलग अलग लेबर कानून बने हुए हैं । उनकी जगह पर सारे मुल्क के लिए एक कोडिफ़ाइड लेबर कानून बनाना जाये । हिन्दुस्तान के बेकारों को भत्ता दिया जाये । देश की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार जो भी कदम उठायेगी, उसमें हिन्दुस्तान के मजदूर यकीनन उसका साथ देंगे, और बहुत हिम्मत के साथ हिन्दुस्तान की दौलत को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे ।

मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय मजदूरों की गिरी हुई हालत को सुधारने के लिए नई योजनायें बनायेंगे और एक नेशनल मिनिमम वेज पालिसी तैयार करेंगे । मैं तवक्कु रखता हूं कि हिन्दुस्तान के मजदूरों ने मन्त्री महोदय के साथ जो उम्मीदें वास्बास्ता की हैं, वे पूरी होंगी ।

श्री मनोहर लाल (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं श्रम मन्त्रालय के अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

ऐसा लगता है कि देश में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने इस बात से कोई सबक नहीं सीखा हैं कि अनेक अंकुशों और प्रतिबन्धों के बावजूद हिन्दुस्तान की जनता से अपराजय लगने वाली इन्दिरा सरकार और संजय-

गिरोह को मलबे के नीचे दफ़न कर दिया, कांग्रेस सरकार का सफ़ाया कर दिया और जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया । मैं श्रम मन्त्री से कहना चाहता हूं कि वह श्रम विभाग के उन अधिकारियों की तरफ़ कुछ ध्यान दें, जिन के बारे में हिन्दुस्तान के श्रमिकों की यह आम धारणा हैं कि वे कभी भी मजदूरों के पक्षपाती नहीं रहे हैं, बल्कि हमेशा मालिकों के पक्षपाती रहे हैं, और रहेंगे । वे अधिकारी यह समझते हैं कि हिन्दुस्तान के जिन श्रमिकों ने अपनी बौद्धिक प्रौढ़ता और साहस का परिचय देते हुए इन्दिरा गांधी की कांग्रेस का सफ़ाया कर दिया और जनता पार्टी की सरकार बनाई, वे निस्सहाय, नाबालिग और नासमझ हैं । उन अधिकारियों को यह समझ लेना चाहिए कि हिन्दुस्तान की जनता, और हिन्दुस्तान के श्रमिक, असहाय, नासमझ और नाबालिग नहीं हैं । वे समझ गये हैं कि उनके वोट की कीमत क्या है । अगर संविधान में दिये गये उन के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई, तो वे उन अधिकारों को छीन कर ले लेंगे । मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय केन्द्र और प्रदेशों के श्रम विभागों के उन अधिकारियों की तरफ़ ध्यान देंगे ।

किसी ने कहा है कि **इंडिया इज़ पेइंग दि प्राइस फ़ार इट्स रिटर्न टू डेमोक्रेसी इन दि फ़ार्म आफ़ लेबर अनरेस्ट** । यह बिल्कुल सही है कि उन्नीस महीनों की इमरजेंसी के दौरान श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात किया गया और उके अधिकारों का हनन किया गया । उदाहरण के लिए, उनके सामने बोनस के अधिकार को छीन लिया गया, कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम लागू की गई, 1974 में एल० आई० सी० और वहां की यूनियन के बीच हुए एग्रीमेंट को तोड़ा गया, आदि । यही कारण है कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मई महीने के मध्य तक दो लाख मजदूरों ने हड़ताल की । यह कारण है लेबर अनरेस्ट का जिसके कारण हमारे 2 लाख मजदूर जनता पार्टी की सरकार बनते ही हड़ताल पर चले गए । इसके ऊपर हमें खास तौर से ध्यान देना होगा ।

साठे साहब इस समय हैं नहीं, अभी वह उनके लिए घड़ियाल के आंसू बहा रहे थे । वह हिन्दुस्तान के 60 करोड़ इंसानों की बात कर रहे थे । यहां के 60 करोड़ मजदूरों की तरफ से वह वकालत कर रहे थे और उनकी तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहे थे । कह रहे थे कि हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाले 60 करोड़ इंसानों की तरफ और मजदूरों की तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिए । वे कह रहे थे कि आजकल की जनता पार्टी की सरकार की जो नीति है वह केवल 2 करोड़ मजदूरों को रोज़गार देने की है । केवल उन दो करोड़ को रोजगार देने की बात को ध्यान में रख कर वे पालिसी बना रहे हैं । लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? हमारी जनता पार्टी की सरकार है या हमारे वर्तमान श्रम मन्त्री हैं या इससे पहले की सरकार और उसके मन्त्री तथा वे अधिकारी हैं जिन्होंने 30 साल तक उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया । उसके लिए जिम्मेदार तानाशाही की तरफ जाने वाली पिछली सरकार है । जनता पार्टी की सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है । वे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने देश में बेरोज़गारी बढ़ाई है ।

जहां तक बरोजगारी का सवाल है उसके ऊपर बहुत से लोगों ने कहा है । मैं उस में इस समय अधिक न जाकर केवल 1976 का उदाहरण सामने रखना चाहता हूं । सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यद्यपि ये आंकड़े सब गलत हैं लेकिन फिर भी उन्हीं को ले कर मैं कहता हूं, जनुवरी से दिसम्बर 1976 तक 56 लाख 15 हजार लोगों ने रोजगार दफ्तरों में अपने अपने नाम लिखाए और

[श्री मनोहर लाल]

नौकरी कितने लोगों को मिली? नौकरी सिर्फ 4 लाख 90 हजार लोगों को मिली। यानी साढ़े आठ परसेंत लोगों को नौकरी मिली। यह हालत सन् 1976 की है जब कि एमर्जेंसी लागू हो चुकी थी और सब लोग समझते में थे कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। बेरोजगारी का तो आलम यह है कि हर साल 7 करोड़ लोग हिन्दुस्तान के अन्दर लाइन लगाकर खड़े हो जाते है जो रोजगार पाने के इच्छुक होते हैं। मैं इस समय उस के अन्दर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं हालां कि उस का सम्बन्ध श्रम मन्त्रालय से भी है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे नौजवान दोस्तों को नजरन्दाज किया है पिछली सरकार ने उसी तरह से जनता पार्टी की सरकार भी करेगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनता इस को भी माफ करने वाली नहीं है। जिस तरह से जनता ने अपनी चैतन्यता का परिचय दिया है और पिछले चुनावों में कांग्रेस की सरकार को निकाल बाहर किया है उसी तरह से अगर जनता पार्टी की सरकार ने भी उन की तरफ ध्यान नहीं दिया, अभी तक जो स्थिति चली आ रही थी उस में सुधार नहीं किया तो जनता पार्टी को भी जनता माफ नहीं करेगी।

जहां तक लेबर अनरेस्ट की बात है उस की तरफ मैं बाद में ध्यान आकृष्ट करूंगा। सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रम पूंजी और उत्पादन तीनों चीज देश की तरक्की के लिए जरूरी होती है। इन तीनों के जरिए ही देश की तरक्की हो सकती है। अगर श्रमिकों के सम्बन्ध अच्छे हैं, श्रम की मात्रा अच्छी है और उत्पादन अच्छा होता है और उस के साथ साथ पूंजी अगर समानान्तर नहीं है, पूंजी का बटवारा ठीक ढंग से होता है तो देश तरक्की कर सकता है। हिन्दुस्तान के अन्दर सौभाग्य या दुर्भाग्य से जनशक्ति की कमी नहीं है। यहां हमेशा से जनशक्ति काफी रही है और आज भी काफी है। उस जनशक्ति का सदुपयोग कर के हम चाहें तो देश की तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि पिछले तीस सालों के अन्दर उस जन-शक्ति की तरफ, उस जनशक्ति की कार्य-क्षमता की तरफ, जो उन के अन्दर काम करने के गट्स हैं उन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और उस के कारण हमारा देश तरक्की नहीं कर सका। दुनिया के और देशों से हम बहुत पीछे रह गए। आज अमेरिका और जापान हम से बहुत आगे है। हमारे हिन्दुस्तान में जब से यह औद्योगिक क्रान्ति शरू हुई तब से यहां के मजदूरों ने यह नारा लगाना शरू किया कि नया जमाना आएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय ने भी लेबर की मीटिंगों में इस नारे को दोहराया होगा और आज हमें यह कहने में संकोच नहीं है कि आज नया जमाना आ चुका है। कांग्रेस की सरकार को बदलने के बाद और उस की जगह जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद वह नया जमाना आ गया है। कम से कम अब जो देश में लूटने वाले है उनको जाना चाहिए और जो कमाने वाले है उनको खाने के लिए मिलना चाहिए। इस देश में जो कमाने वाले हैं उनको रोजी रोटी और मकान मिलेगा—ऐसी उम्मीद इस देश की जनता करती है। अगर कमाने वाले भाइयों को रोजी रोटी और मकान नहीं मिलता है तो फिर हम समझते है यह जो नारा है—नया जमाना आयेगा, कमाने वाला खायेगा और लूटने वाला जायेगा—वह थोथा नारा है और उसमें कोई तत्व नहीं है। फिर इस नारे को बदल देना चाहिए। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि यह नारा कभी झूठा नहीं होगा अगर इसपर उचित रूप से ध्यान दिया जाये। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी इस नारे की तरफ ध्यान देते हुए उन गिनती के पूंजीपतियों पर, जिहोंने इस देश की पूंजी अपने पास इकट्ठा कर रखी है अंकुश लगायेंगे

और मजदूरों को वचन देंगे कि मजदूरों के काम के घण्टे कम किये जायेंगे और समान काम के लिए समान वेतन दिया जायेगा ताकि मजदूर भली प्रकार से अपना जीविकोपार्जन कर सकें।

मजदूरों में कोई धर्म नहीं होता है, मजदूर न हिन्दू होता है न मुसलमान होता है, न सिख होता है और न ईसाई होता है। उसका एक ही धर्म है–मेहनत करना। ऐसी स्थिति में हमारी मांग है कि जब मजदूरों का एक धर्म है तो फिर उनको समान काम के लिए समान वेतन क्यों नहीं मिलता है। आज इस देश में मजदूरों के वेतन में जो असमानता है उसी के कारण लेबर अनरेस्ट है। इस लेबर अनरेस्ट के चार पांच मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है लांग स्टैंडिंग वेज डिस्प्यूट्स। दूसरा कारण है राइजिंग प्राइसेज। तीसरा कारण है बोनस इश्यू। चौथा कारण है विक्टिमाइजेशन आफ वर्कर्स। पांचवां कारण है ओल्ड लेबर लाज। इन पांच कारणों की वजह से आज देश में औद्योगिक अशान्ति है। यदि सरकार इन बातों में सुधार कर देगी तो मुझे उम्मीद है कि आज जो देश में लेबर अनरेस्ट फैली हुई है वह समाप्त हो जायेगी। श्रमिक अशांति समाप्त होने पर देश में उत्पादन भी बढ़ेगा और उसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति भी कम होगी। मेरा निवेदन है कि सरकार इन पांच बातों की ओर विशेष ध्यान दे। इन बातों में सबसे मुख्य चीज लांग स्टैंडिंग वेज डिस्प्यूट्स है जिसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए।

जहां तक राइजिंग प्राइसेज की बात है, कहा जाता है कि कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम की तहत जो पैसा मजदूरों को मिलता है अगर वह दे दिया जायेगा तो देश में मुद्रास्फीति बढ़ेगी। कीमतों में और मुद्रास्फीति में यह किस तरह की दौड़ है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह जो कीमतें बढ़ रही है उनको रोकने के लिए जरूरी है कि उत्पादन को बढ़ाया जाये। अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे हों। अगर मजदूर और मालिकों के औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे नहीं है तो कभी भी उत्पादन ठीक नहीं होगा। इसीलिए मांग की गई कि जो आज एपेक्स कमेटीज है, वर्कर्स कमेटीज हैं, जो यूनियन्स है वे मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने में सफल नहीं हो पाती है इसलिए मजदूरों को प्रबन्ध में हिस्सा दिया जाये, उनको भी भागीदार बनाया जाये ताकि वे समझें कि फैक्ट्री में उनका भी हिस्सा है। इसी प्रकार से देश में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

तीसरा बोनस वाला इश्यू भी बहुत इम्पार्टेंट है। पहले 8.33 परसेन्ट बोनस रखा गया था जो फिर 4 परसेंट कर दिया गया और इमर्जेन्सी में वह भी छीन लिया गया। मैं चाहता हूं कि बोनस के इश्यू को मन्त्री जी जल्दी से जल्दी तय कर दें।

अभी पिछले दिनों हमारे मन्त्री महोदय ने कुछ बयान दिये थे—सब से पहला बयान उन्होंने 20 अप्रैल को दिया था जो अखबारों में छाया हुआ था। उस में उन्होंने कहा था—

"सरकार श्रमिकों के हक वापस कर देगी,
पर हिंसा बरदास्त नहीं करेगी।"

दूसरा बयान उन्होंने 24 अप्रैल को मद्रास में दिया था— जिस में उन्होंने कहा था—

'केन्द्रीय श्रम नीति में तुरन्त मूल परिवर्तन किये जायेंगे।" तीसरा बयान उन्होंने 6 मई को दिया था।– उस में उन्होंने कहा था–"एमर्जेंसी के दौरान जिन मजदूर भाइयों को निकाला गया था, उन सब को तत्काल वापस लेने के

[श्री मनहोर लाल]

लिये राज्य सरकारों को आदेश दे दिये गये हैं।"

सभापति महोदया, इस आदेश के बावजूद अभी भी राज्य सरकारों ने उन मजदूरों को काम पर वापस नहीं लिया है जिन को एमर्जेंसी में निकाला गया था। मिसाल के तौर पर कानपुर में जिन श्रमिकों को डी०आई०आर० और मीसा में बन्द किया गया था उन को वापस नहीं लिया गया है।

आप की जो लेबर कोर्टस बनी हुई है, उन में फैसले नहीं हो रहे है। 1975 में 63 हजार मामले लेबर कोर्ट के पास भेजे गये थे, लेकिन 16 हजार केसेज के फैसले हुए। कहने का मतलब यह है कि इन लेबर कोट्स को इसलिये बनाया गया है कि लेबर को न्याय मिले, लेकिन फैसले ही नहीं होते तो न्याय कहां से मिलेगा। मिल-मालिकों के पास पैसा है, वे मुकदमे को दस साल तक लड़ सकते है, लेकिन मजदूर के पास तो रोटी का भी इन्तजाम नहीं है, वह कहां तक मुकदमा लड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था में सुधार किया जाये और ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि मुकदमों के तत्काल फैसले हों।

मैं अपने मन्त्री महोदय से, जो समाजवादी विचारधारा के है, कहना चाहता हूं—यदि हिन्दुस्तान की तरक्की करनी है तो श्रमिकों की समस्याओं पर सब से पहले ध्यान देना होगा, उन की रोजी-रोटी की तरफ ध्यान देना होगा। उन की मकानों की समस्याओं, उन की दूसरी दिक्कतों की दृष्टि में रखते हुए जिस आशा और विश्वास के साथ श्रमिकों ने जनता पार्टी की सरकार की स्थापना की है, उस आशा और विश्वास को मन्त्री महोदय को पूरा करना होगा।

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): Respected Madam, I shall be precise to the point and short because the time at my disposal is very short. We are dealing with a concerning the subject Labour Ministry which is very sensitive in its area, which is very strategic and is very vital to the economy. Before going into the performance and the working of your Ministry, I would like to bring to the notice of the hon. Minister one relelevant point. This Ministry cannot think in terms of dealing any labour policy without looking into the state of the economy of the country, and the share of the workers in the value of wealth. It is a relevant point which has got a bearing on the overall policy. Even if you think in terms of a national industrial policy or even if you think in terms of an integrated income and wage price policy or in terms of national minimum wage policy, it has got a bearing on the overall economic activity and the workers' share in the overall economy The hon. Minister has shown his mettle in the past few months in understanding the various problems. So, here would like to draw the attention of the hon. Minister to the Reserve Bank of India Bulletin of September 1975. In that Bulletin, Sir, you will find that the rate of growth per annum of 1650 companies in the Corporate private sector. A survey was made by the Reserve Bank of India in 1975. According to the survey, the value of production in 1972-73 was 9.00; for the period 1973-74, it was 11.00. The Gross profit in 1972-73 was 5.4; in 1973-74, it was 19.9. Operating profits in 1972-73 was 5.3; in 1973-74, it was 27.0. Profit before tax in 1972-73 was 6-3; in 1973-74, it was 25.2. Profit after tax in 1972-73 was 5.1; in 1973-74, it was 25.0. The hon. Minister may kindly see how the corporate sector has taken advantage of inflation while the growth rate of net sales has slowed down, the profits have surged forward. Here I need not narrate the whole statistics because sometimes statistics become inconvenient.

Within the limited time at my disposal, I shall give you another amazing picture depicting the fate of the workers who contributed their sweated blood and labour, and what share they got. This is what the report says:

It is a table which is very valuable to understand the machanics of the economic activities of capitalism in relation to production, the value added by labour and how much share the workers get out of the surplus created by their activity in the form of wages, Salaries and bonus. If we look at the share of workers in the form of wages, D.A and Bonus in the value added by their labour, the share of salaries, wages and bonus in value added (per cent) at the time of the first Plan (1952) stood at 63.6. In 1970-71 it came down to 38.0 per cent. Then it went up to 59.3 per cent in 1971-72. And again came down to 38.1 per cent in 1972-73 and 38.2 per cent in 1973-74. So the workers share in the wealth created by them has been going down. The sudden spurt to 59.3 per cent in 1971-72 the political crise year not due to any big increase in wages or D.A. It was due to the manupulation by the big capitalists acting in collusion with the landlords and big traders to raise the prices and value of raw materials consumed. This value is suddenly shown to have risen from Rs. 4361.60 crores in 1970-71 to 5920.91 crores. And then it fell to 5280.67 crores in 1972-73 and again rose to Rs. 5820.55 crores in 1973-74. But for the manipulated rise in prices of raw materials, the workers share in value added remained more or less the same. And in spite of this share of the workers not showing any rise but rather a fall, the workers were blamed for the rise in prices and crisis of production. And when their real wages began to suffer due to the rise in prices, they had to go into action to protect the falling real value of their earnings. I want to impress upon the Minister the direction to which the economy has taken and the share that the workers got in the wealth that they produce. If you are thinking of evolving a policy, on an integrated wage income price policy, or a policy on national minimum wage, you have to take into consideration the share of the workers which they contribute by their sweated labour for production, whether it is public sector or private sector. I am glad that the hon. Minister has resurrected the Indian Labour Conference and he is thinking of constituting a committee to go into the anomalies of price index. I also appreciate the magnanimous job you have done in bringing down Goenka from Express Towers and reaching an agreement on working journalists. You are dealing with a very sensitive area of the economy, the wages question, the bonus question, the question of prices while doing so, the performance of the workers, the share of the workers contribution should be taken into consideration in evolving the policy.

Regarding the wage policy mechanism on an All India basis, I may say that there had been so many wage boards, commissions, committees and other tripartite machineries. No more of wage boards or tripartite machineries or arbitration or commissions for wage negotiations. It should be settled industrywise, through bipartite negotiations, around a table between the management and the employees and they should settle the matter taking into consideration the nature of the industry, and the capacity of the particular industry. On the question of wages your party is committed. You have stated that you would aim at a fair wage. I do not know what is meant by that. Fair wage is the aspiration of the worker in this country. But we cannot achieve even the national minimum wage according to the 1957 Indian labour conference norms. I request at least the national minimum wage need based minimum wage according 1957 ILC norms in the organised sector, be implemented. In the unorganised sector we can be satisfied with Rs. 300 as minimum wage for the time being.

Then coming to the problem of workers participation in management, you had the twenty point economic programme which stated:

[Shri K. A. Rajan]

workers participation in industry. Workers' participation in industry and participation in management has been found to be different in practice. There participation was to increased production and productivity. For real participation in management the whole structure has to be changed; the machinery has to be restructured; workers should not participate only to increase production. They should also participate in management right from floor level to the board of directors level. For instance, in six companies in Kerala, government owned companies workers representatives are elected by secret ballot and they have shown that they can do the job; they have shown by convincing arguments the right policy to be adopted, whether it is at the shop level or the director level. Workers should have an access to the inventories, price policy, sales policy, purchase policy and should have the right to look into the deals of contract They should not be mere onlookers and watchers. They should have a voice in running the whole show.

I come to the other point regarding the Industrial Relations Policy which you are going to evolve. So much is said in the papers that you are going to bring up a comprehensive Industrial Relations policy. We welcome it. But the only point I should like to mention to the hon. Minister is that a sound Industrial relations machinery could stand only on three edifices, viz., right for organisation, right for collective bargaining and the right for strike. Unfortunately these rights were denied to the workers when the nagtive aspects of the Emergency emerged. The working class was the first victim of the Emergency. The first shot was fired against the working class by the caucus-oriented and the caucus-driven then Government. At that time itself we gave the warning that it is going to be the doom. So Industrial Relation Machinery should be built up on these edifices because these are vital. The right to strike is a right which the workers fought for and got. We can see that this right to strike exists even in the capitalistic countries. And then on the multiplicity of unions and so much of inter-union rivalry. It affects the workers class as well as the industry. But in that aspect I just urge upon you that while giving recognition, you should take a stand, without any vascilation, that it will be by secret ballot system and that the recognised union should come up as the sole bargaining agency of that industry.

You know Sir, that there is now unrest among he working class. If you travel all over the country in every State capital, you see demonstrations, satygrahas, strikes, lock-outs, closures and victimisation. In our State the Modern Bakery workers are on strike, HMT workers are on strike. Punalur Papers or Dalmias have closed down. There are so many things going on like this. Bilateral agreements are violated. An agreement on promotion is being violated by Punjab National Bank. It was also reported in the Press that Pfizer is going to be closed down. This unrest, suppressed feeling, suppressed discontentment and the suppressed protest on the workers should be tackled. You should not attribute any political motive behind it. The dynamic Labour Minister has shown his mettle already by settling disputes of all-India nature. He is a good and capable conciliator at the same time a hard bargainer. I hope he will not allow these things to continue and will not allow the workers to be exploited by these monopolists, big industrialists, and the greedy few who take institutional finances as and when they like, who plunder the people's money and who make fraud of the contributions to the Provident Fund. Our economy should not go to shambles at the will and pleasure of the capitalists and the big monopolists.

So, I humbly request you, Sir, to evolve a sound Industrial Relations Policy and evolve need based National Minimum Wage Policy on the lines of the I. L. C. norms of 1957 and restructure the workers participating machinery, and also see that the workers are

given their due share. It is the working class, Sir, that has stood behind the nation at the time of national crisis. At the time of test, this class has never faultered. This class has never betrayed. But the other class, the capitalist class which seeks protection even from this Government, are those who have never proved their matter at the time of any national crisis. So, I request you, Sir, to think in terms of a broad policy in evolving a sound Industrial Relations Policy, National Wage Policy and Bonus Policy which you have already agreed to in principle, and of deferred wage protecting the provisions for bilateral negotiations for coming to a settlement by opting out of the Act and also to have the right to go into the Audits.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Madam, I rise to support the demands for Grants under the control of the Ministry of Labour. While I extend my support to the demands for grants, I would request the hon. Minister to kindly take note of the serious developments in the labour scene of our country today.

You would agree that the labour, particularly organised labour of our country bore the rigours of the emergency during the last 20 months. During the emergency, the entire industrial relations were designed in such a way that the objective of the emergency could be fulfilled. The objective of the emergency in industrial relations was to maximise production and productivity. There is no reason to say that the working class does not want increased production and productivity, but the question is whether they will be entitled to their rightful share of the fruits of increased production and productivity. Here I accuse those who are now sitting on the opposition that they had denied the just and rightful share of the working class, although the working class contributed the most for increased reproduction and productivity. I want to urge on the hon. Minister that even today that sense of denial is pervading among the working class. They are still smarting under the sense of denial of their rightful share of the increased production and productivity. So, when the Labour Minister announces his new labour relations policy, I would request him to remember this quintessence of the labour situation, because this sense of denial today occupies the focus of the labour situation.

The previous government had no labour policy as such. If they had any labour policy, it was merely the policy of wage freeze. This concept of wage freeze has been borrowed from the western developed capitalist countries. The predecessor of the hon. Minister in the previous government pursued a policy of wages which was for all practical purposes a policy of wage freeze. You would agree that in those developed western capitalist countries, while they pursue a policy of wage freeze, they also follow a policy of price freeze. But here when there is wage freeze, prices are not frozen. That has been the continuous policy of the erstwhile government. This wage freeze policy was built up on an erroneous theory, *viz.*, in order to fight inflation, it is the wage which is to be frozen. That was the most preposterous and sinister policy that was foisted upon the working class of this country. I have no time to explain the wage freeze policy in detail, but I would quote one or two expert opinions about this.

A study of the Research Bureau of the *Economic Times* of July 8, 1974 states:

> "Looking at the trends in the industrial raw materials and manufactures, one finds that it is mainly the prices of raw materials and costs of capital equipment, and machinery which have gone up. Thus it is a 'material push' or 'capital push' inflation, but not 'wage-push' as is commonly understood."

[Shri Chitta Basu]

The entire concept of wage freeze was based on the so-called erroneous theory of wage-goods-inflation. That has been completely repudiated and that has been completely rebutted. On the basis of that false theory, the entire working class of our country have been victims of the preposterous position taking by the predecessor Government.

Again, I may mention that the share of the wages has steadily declined. I only want to mention the latest figure given by the Reserve Bank of India Bulletin. And I quote:

> "The share of the remuneration to employees declined marginally from 15.5 per cent in 1973-74 to 14.8 per cent in the current year, *i.e.* 1975-76."

That is the latest figure available. Madam, you will agree with me that the inflation that we have got today is based on the wage-goods-inflation theory. It is the Government which has to fight this inflation from another angle. But it is the workers who have been made victims of this erroneous theory of wage-goods-inflation.

Madam, during all these years the workers have suffered a lot. The real wage has fallen down. I have got some figures to show that in 1972 the real income index or the index of money earnings was 199. It has come down to 103. Therefore, there has been a fall in real wages, there has been wage freeze and the result is very much alarming. Who was responsible for this wage freeze policy? It was the employer, it was the capitalist, it was the monopolist and it was the multinational who had made huge profits. Madam, you will see that the share of operating profits in the total value of production moved up from 5.7 per cent in 1973-74 to 6.2 per cent in 1974-75. Again, I qoute from 'Finances of Medium and Large Public Limited Companies': Study Report of 1650 Companies—RBI bulletin, July 1976:

> "Profits before tax crossed Rs. 1,000 crores mark in 1974-75 recording a phenomenal 36.8 per cent increase over the previous year which was also a year of good performances with a 23.7 per cent growth in profits before tax."

Therefore, it is quite clear that the working class of the country has suffered and is deprived of their legitimate rights. While I want to draw the attention of the hon. Minister to this, I want to humbly ask him: Is he in a position to reverse the entire process of wage freeze policy? I hope that the Government will start the process of reversing. If they are interested in the process of reversing, then the question of scrapping the CDS comes, the enactment of a new Bonus Act comes and also the question of neutralising cent per cent increase in dearness allowace comes and only by that method the wrong, preposterous anti-working class policy pursued by the erstwhile Government can be corrected. And I hope the hon. Minister will initiate the process of a new labour policy which will include among other things, the following: (1) Immediate scrapping of the CDS and return of all accumulated money to the workers in a single instalment; (2) Repeal of the amended Bonus Act and the passing of a bill to ensure the payment of the statutory bonus of 8.33 per cent—to workers including those in the public sector undertakings and (3) Progressive introduction of need-based minimum wages, in a phased manner. If the government is really interested in initiating a new labour policy, this is the 3-point programme which it should take up immediately and initiate a new process.

18.00 hrs.

The hon. Minister was eloquent about re-structuring of industrial re-

lations. I have got no time to discuss all the points involved in it. I would merely tell him that he should really take proper care to see that the Government of India takes a full and final decision on these basic problems facing the country and the working classes today, *viz.*, (a) Fair compensation for labour for increased production and productivity; (b) right to collective bargaining; (c) limitations on the regulatory role of the State and (d) determination and recognition of the bargaining agent on the side of the workers. These are the 4 major and fundamental problems, on the basis of which you can really re-structure industrial relationship.

I have listened to him and I have read his speeches also. Here he harbours an idea of industrial truce. We on the side of the working classes are for truce; we are for cooperation; and we are ready to extend cooperation. But unless the major issues I have mentioned are solved, unless a new labour policy is there and, unless you reverse the dark process, there is no question of truce. Let me be very frank and fair. If you want this truce in the prevailing circumstances, it is merely a surrender on the part of the working classes; it means capitulation to the monopolists. Therefore, if you really mean an industrial truce, if you really mean industrial stability, if you really mean to have a new working class with new ideas which will continue to do its mite for the growth of the country, you will have to revise your decision, you will have to revise and reorient your entire outlook; and then only can you ensure cooperation and industrial truce.

Look at the state of things in the industrial sphere. Workers know how to get their demands realized. They will be on the roads and will seize the opportunity to wrest their just rights and demands from the employers and the unwilling government which supports the multi-nationals and big houses.

MR. CHAIRMAN: We will sit up to 6.40 P.M.

SHRI RAVINDRA VARMA: On Saturady, it was agreed by the House —when the time for the debate on the Ministry of Industry was extended— that if necessary, we will sit for a few more minutes or hours after 6 O'clock on Monday, to dispose of the debate on Labour; and that the Labour Minister will reply the next day, i.e., tomorrow. It is only a question of 40 minutes. I would request the Members on the opposite side to cooperate.

श्री राम अवधेश सिंह (विक्रमगंज) : सभापति महोदय, मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रम मंत्री महोदय के ऊपर जो जिम्मेदारी आई है वह पिछली सरकार की जिम्मेदारियों से भिन्न है । पहले की हुकूमत के श्रम मंत्री केवल वादे करते थे और अब की सरकार के मंत्री को केवल वादे नहीं करने हैं बल्कि वादे को निभाना है ।

यह श्रम मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जिसको पूंजीपतियों के पैसे, नौकरशाहों के पेट, सामन्तों के डंडे और श्रमिकों के पसीने के बीच में सामंजस्य और संतुलन कायम करना पड़ता है । यह श्रम मंत्रालय तीस वर्षों तक पूंजीपतियों के प्रभाव के नीचे दबा रहा और नौकरशाहों के बुद्धि-व्यूह के अन्दर भी फंसा रहा । आपको आश्चर्य होगा जान कर कानूनों के पहाड़ लगा दिये गये । 1947 के बाद से श्रम मंत्रालय के जरिए या यों कहें कि भारत सरकार के द्वारा कई दर्जन श्रमिक कानून बनाए गए । 1947 से 1957 के बीच कम से कम दो दर्जन कानून बने लेकिन उन कानूनों की वजह से मजदूरों को कोई राहत नहीं मिली बल्कि आप उनकी धाराओं को पढ़ें तो लगता है कि सचमुच में यह कानून श्रमिकों के लिए नहीं है । मैं श्रमिकों को दो खण्डों में बांट कर आगे बढ़ूंगा । एक वह

[श्री राम अवधेश सिंह]

श्रमिक जो कारखानों में और खदानों में काम करते हैं और दूसरे वे जो खेतों में काम करते हैं । उनकी असम अलग समस्यायें हैं ।

जहा पूजीपतियों के पैसे का प्रभाव चलता है वहां अनेक कानून-वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट, ट्रेड यूनियन ऐक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, प्राविडेंट फण्ड ऐक्ट, इन्श्योरेन्स ऐक्ट, वेलफेयर ऐक्ट करीब करीब इस तरह के दो दर्जन कानून बना दिए गए लेकिन सब का नतीजा क्या है । ये कानून लागू नहीं होते । आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा 31 पढ़ें उसमें लिखा है कि अगर पूंजीपति कानून को नहीं मानेगा तो उसको एक हजार रुपये जुर्माना या 6 महीने की सजा होगी । इसी तरह से फैक्ट्रीज ऐक्ट की धाराओं को नहीं मानेगा, मनमानी ढंग से तोड़ देगा तो उसके लिए अलग सजा लिखी हुई है । प्रोविडेंट फण्ड ऐक्ट के अन्दर जो प्रोविजन हैं उनको नहीं मानेगा, मजदूरों के खिलाफ काम करेगा तो उस के लिए फाइन और सजा लिखी हुई है । लेकिन उसमें जो एक शब्द "आर" है---सिक्स मंथ्स इम्प्रिजनमेंट आर वन थाउजैंड फाइन, इसमें आर शब्द के बदले अगर एण्ड शब्द हो जाये कि छः महीने की या तीन महीने की सजा के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा तब ये प्रोविजन लागू हो सकते हैं । नहीं तो सेक्शन 33 जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट का है उसके अन्दर वे यह कर सकते हैं कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही है लेबर ट्रिब्युनल के अन्दर या कंसीलिएशन बोर्ड के अन्दर या लेबर कोर्ट के अन्दर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उनके चलते हुए भी वे मजदूरों को काम से निकाल सकते हैं । इसके बदले में क्या होगा ? 6 महीने की सजा होगी या एक हजार जुर्माना होगा । तो क्या एक हजार और क्या दस हजार---वे एक लाख भी दे देंगे, उससे उन को कोई डर नहीं है । उनको अगर डर है तो इस बात का कि कहीं दो दिन के लिए भी जेल में न जाना पड़े । पूंजीपतियों का सब से बड़ा डर यही होता है कि एक दिन की भी सजा न हो जाय । इसलिये जितने भी इस प्रकार के ऐक्ट हैं उनमें यह व्यवस्था होनी चाहिये कि केवल सजा होगी क्योंकि दस-पांच हजार या एक-दो लाख उनके लिये कोई महत्व नहीं रखता हैं । उनके लिये आप केवल सजा की व्यवस्था करें कि 6 महीने की सजा होगी या 3 महीने की सजा होगी ।

दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट तो बना, लेकिन आज तक इण्डस्ट्रीयल रिलेशन्ज ऐक्ट नहीं बना । वास्तव में इण्डस्ट्रीयल रिलेशन्ज ऐक्ट बनना चाहिये था कि किस तरह से वर्कर्ज और मालिकों के बीच में अच्छे सम्बन्ध बनेंगे । इसमें तो यह है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो उसको दूर करने के लिये पांच-सात स्टेजेज हैं, जैसे वर्कर्ज कमेटी, कन्सीलिएशन आफिसर, कन्सीलिएशन बोर्ड, लेबर कोर्ट, कोर्ट आफ एन्क्वायरी, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्युनल । इन सात स्टेजेज को पार करते करते जिन मुद्दों को लेकर डिस्प्यूट खड़ा होता है, उन को छोड़ कर दूसरी नई समस्यायें खड़ी हो जाती हैं और इस तरह से मजदूर मारे जाते हैं । इसलिए श्रम मंत्री जी से मेरी जोरदार मांग है कि कानूनों में सुधार करने के लिये जरूरी है कि फाइन की व्यवस्था को हटा दिया जाय और उसकी जगह इम्प्रीजनमेंट कर दिया जाय । यह रख दिया जाय कि उन धाराओं को यदि कोई पूंजीपति तोड़ेगा तो उसको सजा दी जायेगी ।

इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि आजादी के पहले श्रमिकों के सम्बन्ध में केवल तीन कानून---पेमेन्ट आफ़

वेजेज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, आदि। लेकिन 1947 के बाद जो कानून बने, जो इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स एक्ट बनाया गया, मैं समझता हूं कि उसको नये ढंग से बनाना होगा। ट्रेड यूनियन एक्ट भी केवल यूनियन को रजिस्ट्रेशन करने का एक्ट है, केवल रजिस्ट्रेशन कर देनें से ही मजदूरों की समस्यायें सुलझ नहीं सकती है। रजिस्ट्रेशन तो केवल एक प्रक्रिया है। असल बात है—रिकगनीशन। अभी कोड आफ़ कंडक्ट के आधार पर रिकगनीशन होता है। मालिकों के ऊपर यह निर्भर करता है। अगर कारखाने का मालिक चाहे तो एक छोटी सी यूनियन को, जिसको हम पपेट-यूनियन कहते हैं, उसको रिकगनाइज़ कर सकता है और व्यवहार में ऐसा होता भी है कि केवल पपेट यूनियन ही काम करती है। सारे देश में इन्टक की पपेट यूनियन्ज है, उनकी मेम्बर-शिप पांच फीसदी या दस फीसदी से अधिक नहीं होती। पिछली हुकूमत के साथ में वही मजदूरों का रिप्रेजेन्टेशन करती थीं।

अब मैं मन्त्री जी का ध्यान एग्रीकल्चरल लेबर की ओर दिलाना चाहता हूं—जिससे मेरा ज्यादा सम्बन्ध रहा है। आज इस देश में सबसे बदतर हालत कृषि मजदूरों की ही है। वैसे श्रमिकों की हालत कारखानों में भी खराब ही है, लेकिन उनसे भी ज्यादा खराब इनकी है। इनको मिनिमम वेज तो कहीं मिलता ही नहीं, कहीं पर दो रुपया रोज, कहीं पर एक रुपया रोज और मेरे जिले में तो 1970 तक 8 रुपये महीने पर हल चलवाया जाता था। मैं शाहाबाद जिले के परछा प्रखण्ड की बात कह रहा हूं। इस सम्बन्ध में मैंने तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को पत्र भी लिखा था कि आप इसकी जांच करायें। अब यह जिला रोहतास जिला बन गया है, यहां 8 रुपये महीने पर हल चलवाया जाता था या डेढ़ सेर महुआ दिया जाता था। इतनी बदतर स्थिति उन लोगों की थी।

रहने की क्या स्थिति है, उसको भी सुन लीजिये। एक ही झोंपड़ी में एक ओर सूअर बच्चा जनता है और दूसरी ओर औरत बच्चा जनती है—ऐसी दर्दनाक स्थिति उन खेतिहर मजदूरों की है। दिन भर हल चलाने के बाद जब वह शाम को घर आता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसका बच्चा बीमार हो गया है, वह उस सामन्त के पास जाता है जिसके लिये वह हल चलाता है कि मेरा बच्चा बीमार पड़ गया है, मुझे दवा के लिये पैसे दे दीजिये। तो पांच बार तो वह उसको हटा देता है, जब देता है तो 25, 30 और 40 प्रतिशत सूद पर उसको पैसा देता है—इतनी बदतर हालत है। यहां पर मिनिमम वेजेज एक्ट की बात कही जाती है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं मेरे जिले शाहाबाद में चल कर देखिये, जिसको अब भोजपुरा रोहतास कहा जाता है—पिछली सरकार ने उस एरिये को रेड-एरिया घोषित कर दिया था, वह नक्सलाइट एरिया है, वहां नक्सलाइट बसते हैं। हमारे यहां अगर कोई खेतिहर मजदूर पट्ठा-नौजवान है, शरीर से पुष्ट है, अखबार पढ़ने लग गया है, वह यदि कहता कि कानून में जो लिखा है, हम को वही मजदूरी दो और कहीं 10-20 लोगों ने मिल कर सरकार के पास मांग रखी, तो वे सामन्त, जिनकी पहुंच पुलिस तक है, कहेंगे कि ये नक्सलाइट्स है, ये गोली-बारूद और बन्दूक बनाते हैं—इसका नतीजा यह होता है कि उनको घर से पकड़ कर गोली मार दी जाती है और कहा जाता है कि ये पुलिस के साथ एन्काउन्टर में मारे गये। अभी पिछले दिनों हमारे यहां चिलबिला काण्ड हुआ, जिसमें 11 आदमी मारे गये, जिनमें 8 साल का बच्चा भी शामिल है। इसी तरह का काण्ड गोरपा में हुआ। जब गृह मन्त्रालय पर बहस होगी, तब हम इस मामले को उठायेंगे कि वहां पर किस तरह की घटनायें हो रही हैं। जहां कहीं भी खेतीहर मजदूर अपनी इज्जत के लिये, रोटी के लिये, अपनी बेटी की इज्जत के लिये

[श्री राम अवधेश सिंह]

आवाज उठाते हैं, उनको नक्सलाइट कहा जाता है, क्रिमनल कहा जाता है, उसको गोली से उड़ा दिया जाता है ।

जो मजदूर कारखानों में काम करते हैं, उनकी ट्रेड यूनियन्ज हैं । बड़े-बड़े लोग उनके संरक्षक हैं, लेकिन जो खेती में काम करते हैं, जिनको नान्ह-रेयान कहा जाता है, आज उनकी स्थिति बहुत खतरनाक है, बहुत शोचनीय है, दयनीय है । मैं श्रम मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिहार के भोजपुर-रोहतास जिले की स्थिति का अध्ययन कराया जाय और हरिजनों के साथ, छोटी जाति कहे जाने वाले लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको रोका जाय । अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं । एक बात कह देना चाहता हूं कि पिछली हकूमत में एक तरफ़ खून और पसीना बहाने वाला श्रमिक वर्ग था और दूसरी तरफ पैसे पर चलने वाला श्रमिक वर्ग था । जहां हम लोग पसीने में लथपथ रहते थे वहां वह लोग इंदिरा गांधी के पैसे पर पलते थे । इसी कारण से पसीना बहाने वालों ने पंजाब से लेकर बंगाल तक कांग्रेस के तिरंगे झंडे को उखाड़ फेंका और दुरंगे झंडे को उस की जगह पर खड़ा कर दिया । अगर अब भी श्रमिक को न्याय नहीं मिलता तो फिर वह तिरंगा झंडा लहराने लग सकता है ।

*SHRI K. RAMAMURTHY (Dharmapuri): Madam Chairman, when the House is exhausted after a long discussion on the problems of labour in the country, I rise to say a few words on the Demands for Grants of the Ministry of Labour. Many hon. Members who preceded me pointed out poignantly the pitiable plight of labour prevailing throughout the country at the moment. They also spoke in great detail how far the existing labour laws have not proved beneficial to the labour. There was also no difference of opinion in the viewpoint expressed by several hon. Members that the labour laws which are in force now have become outdated and outmoded. The hon. Members from the Ruling Party decried the deficiencies of the previous Government in the implementation such labour legislations and they were sanguine in expressing that their Government would do well with the labour. I join myself unreservedly in their ejaculations and hope that their faith in the Government is not belied.

The Janata Party has delineated is its labour policy unequivocally during the recent Elections and it received universal acclaim. Sir, as pointed out by my hon. friend, Shri Vayalar Ravi, the labour in Tamil Nadu and other southern states is confronted with the fast approaching festival season. It is but natural that they hope to get their legitimate dues the bonus which has been denied to them so far. I appeal to the hon. Minister of Labour that he should expeditiously bring forward the Bonus Amendment Bill giving Bonus to the workers much ahead of the festivals. I have to regretfully say that the bonus is not decided either by the Administration or by the Labour. As it is said that the marriage is fixed in Heaven, the bonus is fixed by the Chartered Accountant. The perfidious role of the Chartered Accountant in cooking up the accounts was made public during the Emergency by the voluntary disclosure of taxable income of about Rs. 1,500 crores by the industrialists, which would otherwise have been window—dressed by these Chartered Accountants. The capitalists were benefitted by such bounties of black money bestowed upon them by the mercy of the Chartered Accountants

*The original speech was delivered in Tamil.

and the Labour was being denied of bonus. If this pernicious system is allowed to perpetuate, then the labour will never get bonus. I would like to request the hon. Minister of Labour that he should find out statutory ways and means for ensuring that the Trade Unions get the right of re-auditing the accounts audited by the Chartered Accounts. As we are demanding the right of participation for the labour on the management of industries, which is being implemented progressively, I urge upon the Labour Minister that the Labour should get the right of re-auditing the accounts once audited by the Chartered Accountants. The Trade Unions must be empowered to do this job.

Coming now to the labour legislations, whether it is the Industrial Disputes Act or any other labour law, I have no hesitation in saying that all of them do not ensure justice to the labour; in fact, they are the source of inordinate delay in getting justice and fairplay for the labour. I may also say that the industrialists have a free-play with the built-in loopholes in these laws. For example, after the judgment of Andhra Pradesh High Court, under the Gratuity Act of 1972, 15 days' or half month's salary has to be given as gratuity. But, somehow, the Textile Mill-owners in Tamil Nadu have manoeuvered to pay only 13 days' salary as gratuity, and not 15 days' salary. Inspite of varying judgments from other High Courts, I do now know why the Labour Ministry has not yet come forward with any clearcut idea about gratuity. The Trade Unions have made many representations in this regard and their appeals have so far fallen on deaf ears

The Janata Party members *ad nauseum* referred to the excesses committed during the Emergency, and they also pointed out the atrocities perpetrated on labour. But I have personal experience to narrate the benefits that came out of Emergency. In my constituency, the Defence of India rules came to the rescue of labour who were denied their wages by the industrialists and factory owners. The magnesite workers numbering 10,000 were on strike for 11 days during the emergency. I see in the official gallery many Labour Officials who were interceding in this strike then. At that time, with the help of Defence of India rules their wages were fixed without the usual delay. Now, what do we find? The monthly paid staff's wage has not yet been fixed even after two and a half years of bargaining.

As was pointed out by my friend, Shri Vayalar Ravi, the labour in the public sector is being deprived of their right to approach a Court for settling a dispute under the Industrial Disputes Act. A petty bureaucrat like an Under Secretary in the Ministry under whose charge such a public sector undertaking falls decides that the issue should not be taken to a Court and the Labour has to remain silent. Whether it is the public sector or the private sector, the labour has the statutory right to go to a Court for settling a dispute. They should not be deprived of this right by an official in a Ministry. This situation must change.

Sir, I need not narrate the tale of woe of the agricultural workers in the country. Some States have fixed their wages statutorily with different rates. I request the hon. Minister of Labour that he should take personal interest in the matter of fixing their wages on an All-India basis so that they get uniform wages throughout the country. The present implementation machinery is not enough to implement this Minimum Wages Act. I suggest that a competent and powerful administrative unit must be set up in each State for implementing this Agricultural Minimum Wages Act. There should be no delay in doing this.

In Tamil Nadu, millions of workers engaged in *Beedi* industry, matches manufacturing industry and in fire-

[Shri K. Ramamurthy]

works manufacturing industry do not come under the purview of any labour laws like the Factories Act, the Minimum Wages Act, etc. Consequently, they do not get even basic minimum wage. The hon. Minister of Labour should look into the genuine grievances of these millions of workers in *Beedi* industry, matches manufacturing industry and fire-works manufacturing industry in Tamil Nadu and give them statutory protection atleast for minimum wages.

The hon. Members on the Treasury Benches said that the Congress Party was a tool in the hands of the capitalists. I would like to quote from last week's Illustrated Weekly a few lines about our Health Minister, Shri Raj Narain, who questioned the parentage of people speaking in English recently on the floor of this House.

I quote:

> "For several years, Mr. Raj Narain has been acting as an agent or vested interests. To wreck the socialist movement in the country, he has been unabashedly corrupting the dedicated party workers with money taken from the capitalists."

That was why he was expelled from the Socialist Party by the U.P. Wing. Whether the previous Government was inclined towards the capitalists or nor, it is clear from the above that the Janata Party Government seems to favour the capitalists only.

In conclusion, I demand that the Labour Laws must be amended so that the genuine grievances of the labour can be redressed. I also appeal to the Labour Minister that the Bonus Amendment Bill must be brought up expeditiously so that the Labour is enable to get their bonus much before the festivals begin.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अधिष्ठात्री महोदया, हमारे देश में जो लोग गरीबी के जीवन बिताते हैं और कठिनाई में जीवन बिताते हैं उनमें श्रमिकों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । उनका जीवन बहुत ही कठिनाई और दुःख में बीतता है, जैसा कि तमाम माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में प्रकाश डाल चुके हैं । मैं यह बात बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश के मजदूरों का शोषण खासतौर से पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है । तमाम बड़े बड़े उद्योग धन्धे जो निजी क्षेत्रों में है उनमें काम करने वाले तमाम श्रमिकों का हमेशा शोषण होता रहता है और उन पर अत्याचार किये जाते हैं । सार्वजनिक क्षेत्र में जो मजदूर काम करते है वहां पर देश की नौकरशाही उनका शोषण करती है, और जब कभी प्राइवेट सैक्टर के तमाम मजदूरों से सम्बंधित मामले हमारे देश के अधिकारियों के पास जाते हैं न्याय के लिए तो वहां पर भी यह देखा जाता है कि फैसला यह नौकरशाही पूंजीपतियों के पक्ष में देती है और मजदूरों के शोषण में भूमिका अदा करती है । इसलिए श्रम मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना बहुत जरूरी है । आज एक विवाद चल रहा है कि 20 करोड़ रुपये की पूंजी और 50 करोड़ रुपए की पूंजी की लागत के प्रतिष्ठानों को क्या हमें बिग बिजनेस हाउसेज कहना चाहिये, मोनोपली हाउसेज कहना चाहिये ? या उससे कम को कहना चाहिये । आज यह विवाद चल रहा है । लेकिन मेरा सुझाव है कि 1 करोड़ की लागत से ऊपर के सभी हाउसेज को मोनोपली हाउस कहना चाहिये जिनमें श्रमिकों का शोषण किया जाता है और देश की पूंजी केन्द्रित की जाती है । आज देश की पूरी अर्थ-व्यवस्था इन पूंजीपतियों के हाथ में है और जैसा चाहते हैं देश की नीतियों को प्रभावित करते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि

इन सभी बड़े बड़े उद्योगिक प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । मैं यह बात इसलिए कहता हू कि ऐसा करने से मजदूर वर्ग की सेवा को हम अधिक सुरक्षित बना सकते है, पूंजी के एक बड़े भाग पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित कर सकते है । पूंजीपतियों के उद्योगों को अगर सार्वजनिक नियंत्रण में ले लिया गया तो हम शासन को पूंजीपतियों के प्रभाव से मुक्त रख सकते है जिससे मजदूरों के हितों के सरक्षण में सहायता मिलेगी । मैं समझता हू कि हमारी जनता पार्टी की सरकार इस बात पर ध्यान देगी, क्योंकि उसने जो वायदे किये हैं वह वायदे इसी के अनुरूप है ।

मैं बोनस के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के मजदूरों को पुरानी सरकार ने जो बोनस देने का फैसला किया था उसको समाप्त कर दिया है । उस फैसले पर पुन: विचार करना चाहिये और सरकार को मजदूरों के खोये हुये अधिकार को वापस देना चाहिये, उन्हें बोनस मिलना चाहिये ।

शूगर मिल्स के बारे में मेरा निवेदन है कि हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत सी ऐसी मिलें है जिनका कि राष्ट्रीयकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी कई मिलें है जिनके सम्बन्ध में मैंने श्रम मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था । जिन्हें सिक मिल डिक्लेयर करने के बाद वहां के वर्करों का भयकर रूप से शोषण किया गया । 13, 14 महीने तक उनको तनख्वाह नहीं दी गई । वह किस तरह से अपना जीवन बिताते थे , इन सारी बातों की तरफ मैंने माननीय श्रम मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था । आज भी ऐसे मिल है, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, मजदूरों का शोषण हो रहा है । वहां पूंजीपति पूरी तरह से मजदूरों को तबाह कर रहे हैं ।

मैं श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिलें है, वे उनको तुरन्त हाथ में लें और मैं यह प्रकाश डालना चाहता हूं कि उन चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । यह मामला कई बार उठ चुका है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है । इसमें अन्तिम निर्णय लिया जान चाहिये । अगर राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो यह मजदूरों के हित में होगा ।

हाथ करघा मजदूरों के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि तमाम हैंडलूम के कारखाने सूत का दाम बढ़ने से बहुत ज्यादा प्रभावित हुये है और मजदूरों की स्थिति बड़ी खराब हुई है । तमाम मजदूर वहां काम से निकाल दिये गये है । आज भी यदि उन्हें सुविधायें देने के लिए हम प्रयास कर सकें तो ठीक होगा । इसके लिए हमें सूत का दाम घटाना होगा ।

बिजली मजदूर यूनियन और रोडवेज यूनियन के बारे में जब भी वहां के मजदूर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते है तो उन्हें तरह-तरह से परेशान किया जाता है, उन्हें ट्रांसफर और निलम्बित किया जाता है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह उनकी कठिनाइयों की तरफ ध्यान दें ।

इसी तरह से रेलवे और एल० आई० सी० में केजुवल लेबर काम करते है, उन लोगों से बरसों तक डेली वेजेज पर काम कराया जाता है, लेकिन फिर भी उनको रेगुलर नहीं किया जाता है, हालांकि नियम के अनुसार उन्हें कुछ दिन बाद रेगुलर कर देना चाहिये ।

रेलवे और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन में एप्रेन्टिसेज के बारे में मैंने सवाल उठाया था ।

[श्री हरिकेश बहादुर]

माननीय पैट्रोलियम मंत्री ने कहा था कि इस विषय पर वह श्रम मंत्री का ध्यान आकृष्ट करेंगे । आज स्थिति यह है कि लोगों को एप्रेन्टिसेज की ट्रेनिंग के बाद छोड़ दिया जाता हैं और वे बेकार पड़े रहते है । उन्हें एब्जार्व करने की व्यवस्था करनी चाहिये या केवल इतने लोगों को ही एप्रेन्टिस की ट्रेनिंग देनी चाहिये, जिन्हें एब्जार्व किया जा सके ।

अगर हम नेशनल वेंज पालिसी के बारे निर्णय नहीं लेते हैं तो मजदूरों की बहुत हानि होती है । कृषि मजदूरों के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनका स्थिति बहुत खराब है, उन्हें 1, 2 रुपये प्रति दिन मिलता है, जिससे वह अपने जीवन को कठिनाई से बिताते हैं ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्कस पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके करनी चाहिये । आपने जो कृपापूर्वक मुझे समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं ।]

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon): I am happy as well as sorry that my young friend Shri Ravindra Varma is in charge of the Minister of Labour which I call the Ministry of 'Babaldom'. He inherited two curses: one is the Compulsory Deposit Scheme and the other is the Bonus. The Congress Government played ducks and drakes with the working class. First the 4 per cent bonus was enlarged to 8 1/3 per cent and, during the Emergency, they cut it down to zero. As my friend who spoke in Tamil has said, then entire working class is at the mercy of the monstrous employers and the cheating auditors.

Kerala is now going to face, even earlier than Tamil Nadu the question of Bonus. Last year, in spite of the terror infused by Smt Indira Gandhi and her Government, the United Front Government in Kerala decided to pay 4 per cent of the total wages as 'Customary Bonus'. Some of the other States also attempted to pay customary bonus. But this year the position is not only bad but impossible. Last year the Government had the Police to compel the employers to pay 4 per cent. But this time the police is not happy with the Government because of stringent action taken against them in the Rajan case. The employers are up in arms and the labour is in a fighting mood. So, the bonus policy has got to be spelt out very clearly. Otherwise, in August Kerala goes up in flames! Then, Madras, Karnataka, West Bengal and others would join the fray. Therefore, the bonus policy has got to be decided clearly and that too as early as possible.

Then there is the question of the public sector and my two cut motions are based on that. Shri Vayalar Ravi just mentioned about the system of reference. Even the right of reference is denied to one-third of the entire organized working class in the public sector, and all the troubles arise because of that. The judicial pronouncements in the capitalist system are always favouring the employers. Yet, the public sector is opposed to reference to tribunals. Some of the Departments are worse than the empolyers of bonded labour. They have found a way to shirk responsibility by introducing contract labour. The Atomic Energy Department, a much lauded Department, which has been praised all over the world, is the worst employer. They do not give provident fund, they do not give gratuity to the workers and when the labour offices report of the failure of

the conciliation proceedings, the Labour Ministry is helpless. They have to wait for sixty days to get a reply from the Ministry and if the reply is 'No', the whole question is placed in the cold storage. The disputes in the public sector in most of the cases were mainly due to the accumulation of the grievances of the workers. This is a matter which has got to be immediately settled and the Labour Ministry must have the right, when they feel that the workers cause is right to refer the dispute to the Tribunal and not cow down to the decision of an Under Secretary or a Joint Secretary or a Secretary in the Ministry. This is a matter which must be considered in all its seriousness and something must be done immediately. The workers who are denied statutory rights to provident fund and gratuity should get them; may it be in any Ministry, Atomic Energy Department, Home Ministry or Foreign Affairs Ministry.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister will reply tomorrow.

18.43 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 12, 1977/Asadha 21, 1896 (Saka).

GMGIPND—PMR—1421 LS—22-8-77 —998.